



निर्माण सिविल सर्विसेज मासिक पत्रिका

अप्रैल, 2019 (अंक: 9)

मुख्य संपादक :

कमलदेव सिंह

संपादक :

रजनीश कुमार

इम्रियाज खान

सहयोगी :

मनीष प्रियदर्शी, तरुनेन्द्र कुँवर, सुब्रत पाण्डेय,
शिल्पा देवी, सनी वर्मा, दुर्गा, गुंजन कुमार
एवं श्याम कुमार

ग्राफिक्स एंड डिजाइन :

संतोष कुमार झा, पंकज तिवारी, सुनील कुमार
संतोष झा एवं प्रियंका

© प्रकाशक

HEAD OFFICE

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi
Vihar Bandh) Delhi-110009

ENQUIRY OFFICE

631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar,
Delhi-09

Website: www.nirmanias.com

E-mail: nirmanias07@gmail.com

Ph.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797

विषय सूची

इस अंक में...

प्रश्नपत्र - (1)

कला एवं संस्कृति	1
सियोल शांति पुरस्कार	1
गांधी शांति पुरस्कार	2
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक	3
‘तितानवाला म्यूजियम’	3
ऑस्कर अवार्ड 2019	4
भारतीय समाज	5
नौकरी में महिलाएं अब भी पीछे: संयुक्त राष्ट्र	5
श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी	6
भूगोल	6
प्राचीन समुद्री दिशा सूचक यंत्र	7
भूगर्भ जल दोहन	7
वायुमंडल से पानी बनाने वाला वॉटर जेनरेटर	8

प्रश्नपत्र - (2)

राजव्यवस्था	9
आदर्श आचार-संहिता	9
स्वैच्छिक आचार संहिता	12
संविधान संशोधन आदेश, 2019 को स्वीकृति	13
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019	13
आधार तथा अन्य कानूनों के प्रख्यापन अध्यादेश, 2019	14
सामाजिक न्याय	15
दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र	15
लापता बच्चों से संबंधित भारत और अमरीका के बीच समझौता	16
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	16
शौचालयों का 96% से भी अधिक उपयोग	17
शिक्षक कैंडर आरक्षण अध्यादेश, 2019	17
महिला सशक्तिकरण हेतु करार	18
उच्च शिक्षा प्राप्ति पर पांच गुणा इंसेंटिव	18
वेस्ट नील वायरस	19
बधिरों के लिए शब्दकोश के दूसरे संस्करण का आरंभ	19
अंतर्राष्ट्रीय संबंध	20
GSP छूट वापस लेकर भारत के साथ ट्रेड वॉर की राह पर USA	20
भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता	22
भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता	23
भारत और जर्मनी के मध्य समझौता	23
भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी	24
शत्रु संपत्ति का ‘सार्वजनिक इस्तेमाल’	25

अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के रास्ते निर्यात	25	बोल्ड-क्यूआईटी परियोजना	50
भारत-कोरिया स्टार्ट-अप हब	26	भारत-बांग्लादेश सीमा पर 'स्मार्ट-फेंसिंग'	51
प्रश्नपत्र - (3)		NCRB 34वां स्थापना दिवस	51
भारतीय अर्थव्यवस्था	27	सरकार द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के जवानों का जोखिम/कठिनाई भत्ता बढ़ा	52
पीएम-किसान योजना	27	भारतीय वायु सेना ने पार की एलओसी	53
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास	28	बाढ़/नदी प्रबंधन गतिविधियों हेतु FMBAP	53
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग	29	आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा-2019 पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	54
पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम	29	समसामयिक मुद्दों से संबंधित लेख	
एयर इंडिया-जेवी के मध्य विनिवेश	30	भारत को बदलनी होगी आतंक और चीन से निपटने की रणनीति	55
फेम इंडिया योजना	30	जैव विविधता संरक्षण बनाम वनवासी	57
राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019	31	कला एवं संस्कृति (प्रारम्भिक परीक्षा विशेष)	
सेज अधिनियम, 2005 में संशोधन	32	भारतीय चित्रकला	60
प्रधानमंत्री जी-वन योजना	32	भारतीय संगीत कला	70
स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इंडिया 2019	33	भारत के लोकनृत्य	81
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	34	साक्षात्कार: विजय सिंह गुर्जर	
आकांक्षी जिलों में SDG लागू करने हेतु सम्मेलन	34	प्रारम्भिक परीक्षा : 2019	
अटल नवाचार मिशन	35	हरियाणा के मनेथी में नये एम्स की स्थापना	96
क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी	36	भारत निर्माण प्रौद्योगिकी-2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का प्रथममंत्री उद्घाटन करेंगे	97
रेलवे सौर पैनल	37	कर्तन रेजर : अल नागाह 2019	97
डिजिटल बैंकिंग	37	युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम	97
ऑडिटरी पर नियामकीय घेरे में वृद्धि	38	विश्वभर में 2017 से 2018 के बीच खसरे के मामले 48.4% बढ़े: यूनिसेफ रिपोर्ट	98
FAME-2 कार्यक्रम	39	वन नेशन, वन कार्ड योजना	98
IBBI और SEBI के मध्य आईबीसी सहमति	39	स्वच्छता सर्वेक्षण 2019	99
आयुष्मान भारत योजना	40	अंधकार में भविष्य की नींव	99
'रेल दृष्टि' नामक नई वेबसाइट लॉन्च	40	1700 जीव प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा	100
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	41	सऊदी अरब को 40% ज्यादा फ्लाईंग राइट्स	100
सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति-2019	42	'बोलो' एप	100
ईकोफ्रेंडली 'ग्रीन जेल'	42	भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 62.7 करोड़	100
BEE स्टार रेटिंग	43	चीन के रक्षा बजट में 7.5% की वृद्धि	101
कांबैट ड्रम्स	43	कुडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया	101
माइक्रोवेव सेंसर से हिमालय की निगरानी	44	पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा	101
इलेक्ट्रॉनिक त्वचा	44	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-III ए	101
चीन में रोबोट कर रहा चौकीदारी	45	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV	102
भारत में 4 करोड़ ग्रामीण लोग धातु-प्रदूषित पानी पीते हैं: रिपोर्ट	45	खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना	102
'क्विक रिएक्शन मिसाइल' का सफल परीक्षण	46		
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	47		
2030 तक दोगुना हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण	47		
विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में 22 भारत के	47		
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र	48		
जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु उपलब्धियों पर प्रकाशन जारी	49		
आंतरिक सुरक्षा	50		

तीस्ता चरण VI एचई परियोजना	102	‘सम्प्रीति’-2019	114
कीरू पनबिजली परियोजना	103	स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप जारी	114
ई-धरती ऐप और जियो पोर्टल	103	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	114
भारत-रूस मध्य परमाणु चालित पनडुब्बी करार	103	श्रेयस (SHREYAS)	115
दृष्टि बाधितों हेतु सिक्कों की नई श्रृंखला	104	दक्षिणी तटीय रेलवे	115
अभिनव मोबिलिटी सॉल्यूशंस	104	गुरिल्ला रेनस्टॉर्म	115
मांगंडेछू पनबिजली परियोजना	104	पृथ्वी के नीचे विशाल पर्वत खोजा	115
बक्सर ताप विद्युत परियोजना	104	विलुप्त सूची में ब्रैम्बल काय मेलोमी चूहा	116
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान	105	आठ चिकित्सा उपकरण को औषधि का दर्जा	116
कूलिंग एक्शन प्लान	105	प्रधानमंत्री जी-वन योजना	116
एस्ट्रोसैट ने खोजा सितारों का नया समूह	105	हिप्पोकैप-नेपच्यून ग्रह के नए चंद्रमा की खोज	117
पब्लिक से प्राइवेट शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनेगा फेसबुक	105	सेहुएनकास जल मेढक	117
पद्मा लक्ष्मी UNDP की गुडविल एम्बेसेडर बनीं	106	संचार उपग्रह जीसैट-31 का प्रक्षेपण	117
सबसे सस्ती/तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक कार	106	ग्रिड कनेक्टेड सौर पैनल	117
भारत में रूसी हथियारों के निर्यात में कमी	106	चतुरंगी ग्लेशियर	118
भारत और बांग्लादेश के मध्य चार परियोजनाओं का उद्घाटन	107	मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर को विदाई	118
पिनाका	107	विश्व को हरित बनाने में भारत-चीन की भूमिका	118
मोबाइल एप से दिव्यांगता मूल्यांकन	107	भारतीय सुंदरबन को रामसर स्थल का दर्जा	119
7,000 अतिसूक्ष्म समुद्री प्रजातियों की खोज	108	बायो-एनर्जी (TCP) का 25वां सदस्य	119
बोइंग 737 मैक्स विमानों पर रोक लगाई	108	किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए उपाय	119
यूएई समेत 10 देश काली सूची में	108	ब्लू प्लैग प्रमाणन समुद्र तट-चंद्रभाग	120
नाइस, वियना और लोकार्नो समझौता	108	मरुस्थलीकरण पर नया विश्व एटलस	121
पाक-चीन से निपटने के लिए भारत की नई रणनीति	109	बांध सुरक्षा विधेयक, 2018	121
‘मिशन रेट्रो-फिटमेंट’	109	भारत का प्रथम रोबोटिक टेलीस्कोप	122
छत्तीसगढ़ सरकार का विकास मॉडल	109	रेलगाड़ियों में बायो-टॉयलेट्स	122
प्रदूषण से मौत	110	पूर्वोत्तर परिषद की पुनर्संरचना	123
भारतीय क्रिकेटर्स का डोप टेस्ट	110	(Ka-wai- a Pele) -ग्रीन लेक	124
अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019	110	विलुप्ति के कगार पर विश्व के प्राइमेट्स	124
डोमिनिक थिएम बने इंडियन वेल्स चैंपियन	111	उपलब्ध जल के हिसाब से क्षेत्रीय फसल प्रतिरूप	124
जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल नियुक्त	111	संकट में अफ्रीका का बाओबाब पेड़	125
वीरता पुरस्कार	112	16 राज्यों का भूजल यूरैनियम से दूषित	125
अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन	112	जल संसाधन मंत्रालय व गूगल में समझौता	125
विश्व गौरैया दिवस	112	सांबा मसूरी चावल की नई रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित	126
संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति-6	113	क्लोरोफिल-A: प्रकाशसंश्लेषण की नई प्रक्रिया	126
मोजाबिक को सहायता	113	अटल भूजल योजना (ABY)	126
अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाईम एयरो एक्सपो (LIMA)	113	गंभीर जल संकट-नीति आयोग	127
रीजेनरॉन साईंस टैलेंट सर्च	113	राष्ट्रीय योजनाएं एवं कार्यक्रम	128

प्रश्नपत्र

1

कला एवं संस्कृति

यूनिट :

भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

प्र. राष्ट्रीय 'युद्ध स्मारक' के महत्व की चर्चा करते हुए, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।

संभावित प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा) :

प्र. सियोल शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इस पुरस्कार की स्थापना 24वें ओलंपिक खेलों के दौरान की गई थी।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

सियोल शांति पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी को उनकी आर्थिक नीतियों और विकासोन्मुखी कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने इसे 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है।
- पीएम मोदी से पहले यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और बान की-मून को भी मिल चुका है।
- पुरस्कार समिति ने भारत में अमीर और गरीब के बीच के सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करने के लिए उनकी 'मोदीनॉमिक्स' को सराहा है।
- सांस्कृतिक फाउंडेशन के चेयरमैन क्वॉन ई-हायोक् की अध्यक्षता में सियोल के जंग-यू में हुई चयन समिति की बैठक में सियोल शांति पुरस्कार नरेन्द्र मोदी को देने का फैसला किया गया।

➤ प्रधानमंत्री मोदी ने सियोल शांति पुरस्कार के तहत मिलने वाली 2,00,000 डॉलर की राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए देने की बात कही।

➤ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार देने का कारण:

1. चयन समिति के अध्यक्ष चोइ चुंग-हो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चयन भारत के 1.35 अरब लोगों का जीवन सुधारने की खातिर उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए किया गया है।



2. उन्होंने लोक कल्याण के क्षेत्र में सुधार के लिए कई देशों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं।
3. मोदी विश्व शांति और एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा योगदान कर रहे हैं। वह कूटनीति के जरिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। पुरस्कार चयन समिति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस पुरस्कार के लिए 'उत्तम दावेदार' बताया है।
मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले 14वें शख्स हैं।
4. समिति ने पीएम मोदी को सक्रिय विदेश नीति के जरिये वैश्विक और विश्व शांति में योगदान का श्रेय भी दिया है। समिति ने खास तौर पर 'मोदी डॉक्टरेन' और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का जिक्र किया है।

सियोल शांति पुरस्कार

- वर्ष 1990 में सियोल में आयोजित 24वें ओलंपिक खेलों के समापन के बाद सियोल शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जुआन एंटोनियो समरंच को सबसे पहले इस सम्मान से नवाजा गया था।
- यह पुरस्कार मानवता के कल्याण और विश्व शांति के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार दिया जाता है।
- यह पुरस्कार कोरियाई लोगों को देश और दुनिया में शांति बनाए रखने की इच्छा का प्रतीक है।
- इस पुरस्कार में, पुरस्कृत व्यक्ति को एक डिप्लोमा, एक पट्टिका और यूएस \$ 2,00,000 का मानदेय मिलता है।

सियोल शांति पुरस्कार के लिए चयन

- 12 सदस्यीय चयन समिति दुनिया भर के 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के बीच से एक कड़ी, उद्देश्यपरक और गहन मंत्रणा के बाद विजेता का चुनाव करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कोरियाई और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, एथलेटिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में विदेशी हस्तियां शामिल होते हैं।
- पुरस्कार देने वाले समारोह के लिए नामित तिथि से तीन महीने पहले उम्मीदवारों को अपने नाम और उपलब्धियों को भरने के बाद फॉर्म वापस भेजना होता है।
- समिति के सदस्यों द्वारा एक वोट के माध्यम से पुरस्कार के लिए व्यक्ति विशेष को चयनित किया जाता है।

गांधी शांति पुरस्कार

संदर्भ :

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 फरवरी 2019 को राष्ट्रपति भवन में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किये।
- यह पुरस्कार वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए प्रदान किये गये हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।
- राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र, संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, एकल अभियान न्याय और योहेई ससाकावा को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है।

गांधी शांति पुरस्कार समारोह के प्रमुख बिंदु

- योहेई ससाकावा को गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए दिया गया है।
- अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप 2016 के लिए जबकि एकल अभियान ट्रस्ट को वर्ष 2017 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है।



- विवेकानंद केंद्र को शिक्षा एवं ग्रामीण विकास, अक्षय पात्र को देशभर में बच्चों को मिड डे मील वितरण, सुलभ इंटरनेशनल को सिर पर मैला ढोने से मुक्ति दिलाने, एकल अभियान न्याय को आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार तथा योहेई को कुष्ठरोग उन्मूलन में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया।
- इसके तहत एक करोड़ रुपये, एक प्रशस्ति पत्र, एक बैज और हस्तशिल्प की एक वस्तु दी गई।
- इन पुरस्कारों के विजेताओं का फैसला एक ज्यूरी ने किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी शामिल थे।
- इससे पूर्व वर्ष 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को यह पुरस्कार दिया गया था।

गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जानकारी

- इस पुरस्कार की शुरुआत महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के मौके पर वर्ष 1995 में शुरू हुई थी। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है।
- यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है।
- पुरस्कार में 1 करोड़ रुपये की धनराशि, प्रशस्तिपत्र और एक हस्तशिल्प कलाकृति दी जाती है।
- प्रथम गाँधी शांति पुरस्कार 1995 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति के जूलियस न्येरेरे को प्रदान किया गया था।
- वर्ष 2009 में यह पुरस्कार द चिल्ड्रेन्स लीगल सेंटर को दुनिया भर में बाल मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को एक औपचारिक समारोह के दौरान राष्ट्र को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों को भी संबोधित किया।
- नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उन जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान किया।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में, एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय स्मारक के रूप में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अपना विजन प्रस्तुत किया था।



- इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बने इस युद्ध स्मारक की लागत 176 करोड़ रुपये आई है और यह रिकॉर्ड एक साल में बनकर पूरा हुआ है।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की विशेषताएं

- आजादी के बाद युद्धों और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न संकट की घड़ियों में जान देने वाले 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (National War Memorial) बनाया गया है।
- इसे 1947-48, 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन, 1962 में चीन से युद्ध, 1965 में पाक से जंग, 1971 में बांग्लादेश निर्माण, 1987 में सियाचिन, 1987-88 में श्रीलंका और 1999 में कारगिल में शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है।
- इस मेमोरियल में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों को एक साथ श्रद्धांजलि दी गई है। उन सभी वीर सैनिकों के नाम स्मारक में दर्ज हैं।
- इसमें चार वृत्ताकार परिसर होंगे और एक ऊंचा स्मृति स्तंभ भी होगा, जिसके नीचे अखंड ज्योति जलती रहेगी। चारों वृत्तों के नाम अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र होंगे।
- इसकी 16 दीवारों पर 25,942 योद्धाओं का जिक्र किया गया है। ग्रेनाइट पत्थरों पर योद्धाओं के नाम, रैंक व रेजिमेंट का उल्लेख किया गया है।
- मुख्य संरचना को चार चक्रों के रूप में बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक सशस्त्र बलों के विभिन्न मूल्यों को दर्शाता है।

‘तितानवाला म्यूजियम’

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 26 फरवरी 2019 को बगरू में हैंडब्लॉक प्रिंटिंग के ‘तितानवाला म्यूजियम’ का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद उन्होंने म्यूजियम की विभिन्न गैलरियों का भी अवलोकन किया।
- तितानवाला म्यूजियम में बड़ी संख्या में पारम्परिक वुडन ब्लॉक, कपड़ों की रंगाई व छपाई के काम आने वाले बर्तन व सहायक उपकरण तथा छिपा समुदाय के इतिहास को दर्शाने वाले पुराने फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गये हैं।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘तितानवाला म्यूजियम’ ने यह साबित कर दिया है कि कला व संस्कृति को आगे बढ़ाने अथवा संरक्षित करने के लिए सरकार पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह म्यूजियम बगरू को पूरे विश्व में पहचान दिलाएगा।
- ब्लॉक प्रिंटिंग की विरासत सूरज नारायण तितानवाला जैसे संग्राहकों की पहल के कारण ही संरक्षित है, जो स्वयं छिपा समुदाय से हैं।

बगरू की ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है?

- बगरू नामक स्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग प्राकृतिक रंग के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसका श्रेय राजस्थान के छिपा समुदाय को जाता है।
- बगरू के हाथ से की जाने वाली इस ब्लॉक प्रिंटिंग का इतिहास 1,000 वर्षों से भी पुराना है।
- इस तकनीक में पहले कपड़े को मुलतानी मिट्टी में धोया जाता है फिर इसे हल्दी मिले पानी में डुबोया जाता है ताकि यह पीली आभा हासिल कर सके।



- इसके बाद डाई किये गये इन कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स से छपाई की जाती है। यह सारा काम हाथ से किया जाता है।
- सागौन-लकड़ी से बनाये गये लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग डिजाइन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है।
- इन ब्लॉक्स को उपयोग से पहले रात भर तेल में भिगोया जाता है और फिर उपयोग में लाने से पहले धोया जाता है।
- जिस कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है उसे चिकनी मिट्टी में भिगोकर तथा कुछ अन्य केमिकल लगाकर नरम किया जाता है।
- कपड़े पर बेहद ध्यान से साफ-सुथरे तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग हो जाने के बाद कपड़े को धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है।

छिपा समाज के बारे में जानकारी

- छिपा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग हैं।
- छिपा शब्द नेपाली भाषा के दो शब्दों 'छि' अर्थात् डाई करना एवं 'पा' अर्थात् धूप में सुखाना से मिलकर बना है।
- इस समुदाय के लोग राजस्थान में काफी लंबे समय से ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। इनके ब्लॉक्स पर मिलने वाली बारीक कारीगरी के कारण यह छपाई काफी प्रसिद्ध है।

ऑस्कर अवार्ड 2019

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित डॉलबी थिएटर में सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड्स 2019 की घोषणा की गई।
- इस पुरस्कार समारोह में भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी 'पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस' को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सबजेक्ट का अवॉर्ड मिला है।



- बेस्ट फिल्म कैटेगरी में आठ फिल्म को आखिरी सूची में रखा गया था। इनमें ब्लैक पैन्थर, ब्लैक लेंसमैन, बोहिमिया रापसोडी, द फेवरेट, ग्रीन बुक, रोमा, ए स्टार इज बॉर्न और वाइस का नाम शामिल था।
- सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 'ग्रीन बुक' ने बेस्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया।
- फिल्म 'ग्रीन बुक' में एक पियानो वादक और उसके पार्ट टाइम ड्राइवर के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है।
- इसी फिल्म के लिए माहेरशाला अली को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवॉर्ड मिला।

ऑस्कर 2019 की पूरी सूची		
1.	बेस्ट फिल्म	ग्रीन बुक
2.	बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल	रामी मालेक
3.	बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल	ओलिविया कोलमन
4.	बेस्ट फॉरन फिल्म	रोमा
5.	बेस्ट डायरेक्टर	अलफॉन्सो क्यूरॉन (रोमा)
6.	बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्ट्रेस	रेजिना किंग, फिल्म: इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक

7.	बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर	माहेरशाला अली, (फिल्म-ग्रीन बुक)
8.	बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म	स्पाइडर-मैन: इनटू द स्पाइडर-वर्स
9.	बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म	बाओ (BAO)
10.	बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट	पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस
11.	बेस्ट विजुअल इफेक्ट	फर्स्ट मैन
12.	बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म	स्कन
13.	बेस्ट ऑरिजनल स्क्रीनप्ले	ग्रीन बुक
14.	बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले	ब्लैकलेंसमैन

15.	बेस्ट ऑरिजनल स्कोर	ब्लैक पैथर
16.	बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग	शैलो (लेडी गागा)
17.	कॉस्ट्यूम डिजाइन	रुथ कार्टर
18.	बेस्ट सिनेमेटोग्राफी	रोमा

ऑस्कर 2019 में भारत

- भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवॉर्ड मिला है।
- यह फिल्म भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है जिसमें पीरियड्स के मुद्दे को उठाया गया है।
- इस फिल्म को रयाक्ता जहताबची और मैलिसा बर्टन ने निर्देशित किया है तथा इसके निर्माता गुनीत मोंगा हैं।

भारतीय समाज

यूनिट :

महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या तथा सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- प्र. 1990 के बाद भारत में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, परंतु पुरुषों के समान या कई बार उनसे अधिक योग्य होने के बावजूद भी श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम होने के कारणों की चर्चा करें।

संभावित प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा) :

- प्र. निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें-
- भारत में प्रबंधकीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी वैश्विक स्तर से अधिक है।
 - 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद भी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर में धीमी वृद्धि हुई है।
 - महिलाओं के लिए कम रोजगार एवं कम वेतन का कारण शिक्षा नहीं है।
 - उपरोक्त विकल्प ILO की रिपोर्ट पर आधारित है।

नौकरी में महिलाएं अब भी पीछे: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रबंधक स्तर पर वैसी महिलाओं की संख्या केवल 10 प्रतिशत के करीब है, जिनके छह साल से कम उम्र के बच्चे हैं।
- वहीं पुरुषों के मामले में यह संख्या करीब 90 प्रतिशत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी के लिए कार्य के बेहतर भविष्य हेतु स्त्री-पुरुष समानता के लिए लंबी छलांग

शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के दशक से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर में नाममात्र सुधार हुआ है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष पदों पर महिलाओं की उपस्थिति अब भी बहुत कम है।
- पिछले 30 साल से स्थिति बहुत कम बदली है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के पास अपने पुरुष समकक्षों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक डिग्री होने के बावजूद यह स्थिति है।

- ❖ महिलाओं के लिए रोजगार के कम अवसर और कम वेतन के लिए शिक्षा मुख्य कारण नहीं है, बल्कि महिलाओं को अपनी पढ़ाई-लिखाई का वैसा लाभ नहीं मिलता जितना कि पुरुषों को मिलता है।
- ❖ रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं को मातृत्व का भी नुकसान उठाना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर वैसी प्रबंधक महिलाएं 25 प्रतिशत हैं जिनके छह साल से कम उम्र के बच्चे हैं।
- ❖ वहीं बिना छोटे बच्चे के प्रबंधक स्तर पर उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 31 प्रतिशत हुई है। वहीं भारत में प्रबंधक स्तर पर वैसी महिलाओं की संख्या केवल 10.2 प्रतिशत है। जिनके बच्चे छह साल से कम हैं जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या 90 प्रतिशत तक है।



श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी

चर्चा में क्यों?

- ❖ डिलॉयट के 'भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिये लड़कियों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण' रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में 95 प्रतिशत यानी 19.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो या तो बेरोजगार हैं या उन्हें काम के बदले पैसा नहीं मिलता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ❖ रिपोर्ट में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कम होने का कारण गुणवत्तीय शिक्षा तक पहुंच का अभाव और आर्थिक एवं सामाजिक बंधन को बताया गया है।

- ❖ रिपोर्ट में कहा गया, "एशिया और भारत में महिलाओं एवं लड़कियों के समक्ष मुख्य चुनौतियां शिक्षा की कमी, गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता का अभाव और डिजिटल विभाजन है जो उन्हें रोजगार योग्य कौशल पाने, श्रम बल में शामिल होने और उद्यम शुरू करने से रोकते हैं।"
- ❖ डिलॉयट के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रुकावटों से महिलाओं के लिये अवसर कम होते हैं।
- ❖ रिपोर्ट में भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा और पुनः कौशल प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया गया।
- ❖ रिपोर्ट में चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में कहा गया, "प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण और स्वचालन के उभार के दौर में यह आशंका प्रबल हो जाती है कि कम कौशल और कम वेतन वाले कार्यों में मुख्य तौर पर लगी अधिकांश महिलाओं का रोजगार प्रभावित होगा।"

भूगोल

यूनिट :

भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान-अति महत्वपूर्ण विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणि जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- प्र. हाल के एक रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल दोहन में भारत विश्व में शीर्ष पर है। जल की बढ़ती समस्या को देखते हुए भारत में भूगर्भीय जल दोहन के बेहतर प्रबंधन हेतु किए जा रहे उपायों की चर्चा करें।

संभावित प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा) :

- प्र. एटमॉस्फेरिक वॉटर जेनरेटर (AWG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. एटमॉस्फेरिक वॉटर जेनरेटर का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है।
2. यह वातावरण में मौजूद नमी को जल में परिवर्तित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

प्राचीन समुद्री दिशा सूचक यंत्र

चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना एस्ट्रोलेब यानी समुद्री दिशा सूचक यंत्र खोजने में सफलता पाई है।
- पुर्तगाल के खोजी नाविक वास्कोडिगामा ने 14वीं शताब्दी में भारत की खोज के लिए अपनी दूसरी यात्रा के दौरान इसी यंत्र का इस्तेमाल किया था।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- पुर्तगाली जहाज अरमाडा के मलबे के पास हुई खोदाई में मिले इस एस्ट्रोलेब को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया में अब तक का सबसे पुराना एस्ट्रोलेब बताया है।
- खुदाई के दौरान जहाज का एक घंटा भी मिला है। 1498 के उस घंटे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पुराने घंटे के तौर पर दर्ज किया गया है।
- एस्ट्रोलेब की पहचान के लिए वैज्ञानिकों ने लेजर इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि सोद्रे नामक इस यंत्र को 1496 से 1501 के बीच बनाया गया था। अन्य समुद्री दिशा सूचक यंत्रों के मुकाबले यह अनोखा है।
- प्राचीन समय के पुर्तगाल और स्पेन के खोजी नाविक समुद्री दिशा के ज्ञान के लिए एस्ट्रोलेब का इस्तेमाल किया करते थे।
- ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी के मुताबिक जहाजों के मलबों के पास इनका पाया जाना दुर्लभ है। दुनिया में इस तरह के 104 एस्ट्रोलेब होने का अनुमान है।
- 1481 में अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर समुद्री यात्रा करने वाले पुर्तगालियों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था।
- 15वीं शताब्दी के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियाज और वास्कोडिगामा अपनी कई महत्वपूर्ण यात्राओं के दौरान दिशा ज्ञान के लिए एस्ट्रोलेब पर ही निर्भर थे।
- अरमाडा जहाज के मलबे के पास से मिला सोद्रे एस्ट्रोलेब 175 मिलीमीटर के व्यास वाला डिस्क है जिसका वजन 344 ग्राम है।
- अब तक का यह पहला एस्ट्रोलेब है, जिसपर पुर्तगाल का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ था। विशेषज्ञों ने लेजर स्कैनिंग के बाद इसे अब तक सबसे पुराना एस्ट्रोलेब घोषित किया है।

भूगर्भ जल दोहन

चर्चा में क्यों?

- भूगर्भ जल दोहन पर गैर सरकारी संस्था वाटरएड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में भूगर्भ जल का जितना दोहन होता है, उसका करीब एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत

निकालता है। इतना जलदोहन अमेरिका और चीन मिलकर भी नहीं करते।

- भारत में वर्ष 2000-10 के बीच भूगर्भ जल के नीचे गिरने का स्तर 23 फीसदी हो गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- जल दिवस (22 मार्च) के मद्देनजर जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर भूगर्भ जल का 24 फीसदी अकेले भारत उपयोग करता है।
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अनाज और कपड़ों का निर्यात भारत की आमदनी का महत्वपूर्ण जरिया है।
- यदि इनके उत्पादन व्यवस्था को टिकाऊ नहीं बनाया गया तो समस्या बढ़ भी सकती है। गरीब वर्ग के लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा।
- वाटरएड ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक दिया है-‘बिनीथ द सरफेस : द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर 2019’।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में भारत भूगर्भ जल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वह 12 फीसदी भूगर्भ जल का निर्यात करता है।



- भारत में धान और गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। एक किलो गेहूं के लिए औसतन 1,654 लीटर और एक किलो चावल उपजाने के लिए औसतन 2,800 लीटर पानी की जरूरत होती है।
- अगर धान और गेहूं की जगह भारत में मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे अनाज का उत्पादन किया जाए तो इससे सिंचाई जल की जरूरत एक तिहाई कम हो जाएगी।
- वाटरएड इंडिया के मुख्य कार्यकारी के अनुसार विश्व जल दिवस अधिक पानी की खपत वाली वस्तुओं के उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाने और उपभोक्ताओं को उनकी खरीद को अधिक विचारशील बनाने का आह्वान करता है।
- स्वच्छ जल की कमी कमजोर तबके को गरीबी की तरफ धकेलती है।

वायुमंडल से पानी बनाने वाला वॉटर जेनरेटर

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्रालय की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) ने एक नए उत्पाद एटमॉस्फेरिक वॉटर जेनरेटर (AWG) का 21 फरवरी 2019 को एयरो इंडिया 2019 में अनावरण किया है।
- यह उत्पाद दुनिया में पेयजल की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए एक नवाचार समाधान उपलब्ध कराता है।
- सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने AWG का BEL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एम वी गौतम और कंपनी के निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उद्घाटन किया।



- BEL का यह एटमॉस्फेरिक वॉटर जेनरेटर (AWG) वायुमंडल में मौजूद नमी से सीधे ही पानी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- वह दिन दूर नहीं जब पेयजल इस ग्रह पर सबसे कीमती चीज बन जाएगा। वर्तमान में भूजल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है।

एटमोस्फेरिक वॉटर जेनरेटर

- AWG में वायुमंडल में मौजूद नमी से जल निकालने और इसे शुद्ध करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।

- यह वायुमंडल की नमी को संचनित करके स्वच्छ सुरक्षित और शुद्ध पीने योग्य पानी का उपयोग करने के लिए उष्मा के आदान-प्रदान का प्रयोग करता है।
- इसमें एक खनिज यूनिट लगी है जो पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें खनिज शामिल करने का काम करती है।
- एडब्ल्यूजी यूनिट को एक ही जगह पर स्थिर रूप में और गतिशील रूप में वाहनों में भी लगाया जा सकता है।
- यह 30 लीटर, 100 लीटर, 500 लीटर और 1000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता में उपलब्ध है।

एडब्ल्यूजी की उपयोगिता

- एडब्ल्यूजी का उपयोग समुदाय केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों जैसे- स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सैन्य प्रतिष्ठानों और दूर दराज के क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों तथा आवासीय परिसर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

वॉटर जेनरेटर का निर्माण

- एटमॉस्फेरिक वॉटर जेनरेटर (AWG) का निर्माण बीईएल द्वारा सीएसआईआर- आईआईसीटी और एमएआईटीएचआरआई CSIR- IICI & MAITHRI (हैदराबाद स्थित एक स्टार्ट-अप कंपनी) के सहयोग से किया जा रहा है।
- इसे एयरो इंडिया-2019 में हॉल-ई में BEL के स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया है।
- बीईएल भारत सरकार की स्टार्ट-अप इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में स्टार्ट-अप कंपनियों को सहायता प्रदान कर रहा है।



राज्यवस्था

यूनिट :

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- आदर्श आचार संहिता के महत्व को समझाते हुए इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु उपायों की चर्चा करें।
- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) वैकल्पिक विवाद समाधान को किस तरह प्रोत्साहित करेगा? NDIAC विवाद समाधान भारत की अकांक्षाओं को पूर्ण करने में किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा?

आदर्श आचार-संहिता

चर्चा में क्यों :

- भारत के निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च को 17वीं लोकसभा के लिये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि देशभर में चुनाव सात चरणों में 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेंगे।
- वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त होना है। इन चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा की विधानसभाओं के लिये भी मतदान होगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव अभी नहीं करवाए जा रहे हैं।
- चुनावों की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस आचार संहिता में प्रचार, रैली, मतदान केंद्र, सत्तारूढ़ दल और घोषणापत्र संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश होते हैं।

चुनावों के लिये उठाए जाएंगे ये 4 बड़े कदम

- **आपराधिक रिकॉर्ड का विज्ञापन:** लोकसभा के चुनावों में इस बार जो नया होने जा रहा है, वह यह है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को नामांकन करने के बाद अपने आपराधिक मामलों का विज्ञापन देना होगा।

- यह विज्ञापन व्यापक प्रसार वाले अखबारों में ही देना होगा यानी छोटे अखबारों में विज्ञापन देकर बचने की संभावना नहीं रहेगी। आपको बता दें कि यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सितंबर 2018 के फैसले को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
- **सभी मतदान केंद्रों पर VVPAT मशीनें:** EVM को लेकर राजनीतिक दलों की आशंकाएँ दूर करने के लिये इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) मशीन युक्त EVM इस्तेमाल की जाएंगी। VVPAT की मदद से मतदाता को उसके मतदान की पर्ची देखने को मिलती है कि उसका वोट उसी को मिला है जिसके नाम का बटन EVM में दबाया गया था।
- VVPAT और EVM से मिलान का कार्य पहले की तरह ही होगा और एक विधानसभा सीट के एक मतदान बूथ पर ही यह मिलान करवाया जाएगा। फिलहाल मिलान की संख्या बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। EVM और VVPAT की त्रिस्तरीय जाँच होगी।
- पहले स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने इसकी पड़ताल की जाएगी। दूसरे स्तर पर मतदान से पहले सभी मतदान केंद्रों पर इनका परीक्षण होगा और कुल वोटों का VVPAT से मिलान होगा। तीसरे स्तर पर मतदान के बाद प्रत्येक लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों में से एक-एक बूथ पर वोटों का VVPAT के जरिये मिलान कराया जाएगा।

- EVM में प्रत्याशियों की फोटो: इस बार सभी EVM और पोस्टल बैलेट पेपर पर सभी प्रत्याशियों की तस्वीरें होंगी, ताकि मतदाता उनकी आसानी से पहचान कर पाएँ।



- इससे चुनाव चिन्ह को लेकर पैदा होने वाला भ्रम भी दूर होगा। गौरतलब है कि कई बार एक जैसे नाम वाले प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं, जिस कारण मतदाताओं को भ्रम होता है। EVM में फोटो को शामिल कराने के लिये सभी प्रत्याशियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो तय मानदंडों के तहत रिटर्निंग अफसर को देना होगा।
- EVM की GPS ट्रैकिंग: मतदान के बाद EVM संबंधी आशंकाओं को दूर करने के लिये जिला मुख्यालय से EVM को बूथ तक पहुँचाने और उसे मतगणना केंद्र तक ले जाने के दौरान EVM वाहनों की GPS ट्रैकिंग की जाएगी। साथ ही बूथों के निर्वाचन अधिकारियों की भी ट्रैकिंग की जाएगी, ताकि पता चल सके कि चुनाव के दौरान उनकी गतिविधियाँ कहाँ-कहाँ रहीं।

कुछ अन्य कदम

- मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची: इसके अलावा, चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची तैयार कराई है। इसका इस्तेमाल 2009 से शुरू हुआ था, लेकिन तब असम, जम्मू-कश्मीर और नगालैंड के मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची तैयार नहीं हो पाई थी।
- अब सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में फोटोयुक्त मतदाता सूची का काम 99.36% पूरा हो गया है, जो चुनाव होने तक 100% पूरा हो जाएगा। चुनाव के पाँच दिन पहले मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुँच जाएगी।
- नया हेल्पलाइन नंबर : मतदाताओं के लिये नया हेल्पलाइन नंबर 1950 होगा, जिस पर कोई भी मतदाता सूची में अपने नाम की जानकारी ले सकता है।

उल्लंघन पर कार्रवाई

- इनके अलावा, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिये एप बनाया गया है। इस पर शिकायत मिलने के

100 मिनट के भीतर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे। यदि आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आदर्श आचार संहिता

- मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है।
- दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावों को एक उत्सव जैसा माना जाता है और सभी सियासी दल तथा मतदाता मिलकर इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं।
- चुनाव की तारीख का एलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव परिणाम आने तक जारी रहती है।
- दरअसल, ये वे दिशा-निर्देश हैं, जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है।
- इनका उद्देश्य चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष एवं साफ-सुथरा बनाना और सत्ताधारी दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है।
- सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के उद्देश्यों में शामिल है।
- आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है।
- आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, बल्कि यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है।
- सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता बनाया गया था कि क्या करें और क्या न करें।
- 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया।
- इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें और कमोबेश ऐसा हुआ भी।
- इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन कमोबेश होता रहा है।
- गौरतलब यह भी है कि चुनाव आयोग समय-समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है, ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे।

आवश्यकता क्यों ?

- एक समय ऐसा था जब चुनावों के दौरान दीवारें पोस्टरों से पट जाया करती थीं। लाउडस्पीकर्स का कानफोडू शोर थमने का नाम ही नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार धन-बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिये कुछ भी करने को तैयार रहते थे।
- चुनावी वैतरणी पार करने के लिये साम, दाम, दंड, भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने और बैलट बॉक्स लूट लेने जैसी घटनाएँ भी आम थीं।
- सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिंसा के दौरान हताहत होते थे। तब चुनावों में शराब और रुपए बाँटने का खुला खेल चलता था। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं, लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई।
- अब कहीं भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है।
- इसके अलावा, समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किये गए हैं। इनके तहत कामचलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का एलान नहीं कर सकती।
- चुनाव आयोग को यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के एस.आर. बोम्मई मामले में दिये गए ऐतिहासिक फैसले से मिला है। 1994 में आए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कामचलाऊ सरकार को केवल रोजाना का काम करना चाहिये और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिये।

विशेषताएँ

- भारत में होने वाले चुनावों में अपनी बात को वोटर्स तक पहुँचाने के लिये चुनावी सभाओं, जुलूसों और भाषणों में नारेबाजी और पोस्टरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है।
- वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिये दिशा-निर्देश दिये गए हैं।
- सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं।
- सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं।
- आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिये कुछ खास गाइडलाइंस दी गई हैं। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिये ना करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का एलान करने की मनाही है।

- मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाजत भी नहीं होती।
- यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
- चुनावी सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने तथा जुलूस निकालने के लिये भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं।
- किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिये चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है तथा इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है।
- हैलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं होना चाहिये। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिये।

आदर्श आचार संहिता : न्यायालय का नजरिया

- सर्वोच्च न्यायालय 2001 में दिये गए अपने एक फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा।
- इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो गया।
- अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहाँ चुनाव होने हैं, वहाँ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।
- यह सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती ही है, साथ ही संबंधित राज्य के लिये केंद्र सरकार पर भी लागू होती है।

आदर्श आचार संहिता : एडवांस तकनीकें

- 'cVIGIL' एप : जब डिजिटलीकरण और हाई-टेक होने का दौर चल रहा हो तो भला चुनाव आयोग क्यों पीछे रहता।
- आदर्श आचार संहिता को और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिये कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने 'cVIGIL' एप लॉन्च किया। हाल में हुए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल हुआ।
- cVIGIL के जरिये चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है।
- इसके लिये उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम दो मिनट की अवधि का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है।
- उल्लंघन कहाँ हुआ है, इसकी जानकारी GPS के जरिये ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिये यूनीक आईडी दी जाती है।

- ❖ यदि शिकायत सही पाई जाती है तो एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है।
- ❖ यह एप केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में काम करता है। तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिये केवल पाँच मिनट का समय मिलता है और इसमें पहले से ली गई फोटोज या वीडियो अपलोड नहीं किये जा सकते।
- ❖ हाई-टेक होने की दौड़ में cVIGIL एप के अलावा चुनाव आयोग ने और कई एडवांस तकनीकों को भी अपनाया है। इनमें नेशनल कंफ्लेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर, सुविधा, सुगम, इलेक्शन मॉनीटरिंग डैशबोर्ड और वन वे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- ❖ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद लगभग दो माह तक सरकारी कामकाज ठप पड़ जाते हैं।
- ❖ बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासन तो प्रभावित होता ही है, भारी मात्रा में पैसे की भी बर्बादी होती है।
- ❖ हमारे देश में सालभर कहीं-न-कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इसलिये 1999 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में देशभर में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की थी। अभी कुछ समय पहले भी विधि आयोग देशभर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर ड्राफ्ट पेश कर चुका है।
- ❖ इसके अलावा, भारत के उपराष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि सभी राजनीतिक दल आपसी सहमति बनाकर अपने मेंबर्स के लिये एक आदर्श आचार संहिता तैयार करें, जिस पर विधानमंडल और संसद के भीतर एवं बाहर अमल होना चाहिये।
- ❖ लेकिन यह भी सच है कि चुनावों के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश सरकार किसी-न-किसी तरीके से जरूर करती है। यदि चुनाव आयोग कड़ी निगाह ना रखे तो वह इस कोशिश में कामयाब भी हो जाती है।
- ❖ ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग के पास कार्रवाई करने का अधिकार भी होता है। इसके लिये चुनाव आयोग FIR दर्ज करा सकता है या उम्मीदवारी पर रोक तक लगा सकता है।
- ❖ चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता तथा अन्य उपायों के जरिये चुनावों को निष्पक्ष और साफ-सुथरा बनाने के प्रयास लगातार करता रहता है और इसके लिये उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत जैसे बड़े देश में चुनावों को केवल आदर्श आचार संहिता के रहमो-करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है।
- ❖ दरअसल, आदर्श आचार संहिता चुनाव सुधारों से जुड़ा एक

अहम मुद्दा है, जिससे और बहुत से चुनाव सुधारों का रास्ता खुलता है।

- ❖ देखा जाए तो हर चुनाव के साथ हमारी डेमोक्रेसी में और निखार आता जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने में चुनाव आयोग की कोशिशों के साथ देश के नागरिकों की भी यह जवाबदेही है कि इसे सफल बनाएँ।

स्वैच्छिक आचार संहिता

चर्चा में क्यों?

- ❖ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और इंटरनेट तथा मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने 20 मार्च को मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और निर्वाचन आयुक्त-श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चन्द्रा को 'आम चुनाव 2019 के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता' प्रस्तुत की।
- ❖ IMAI तथा फेसबुक, वाट्स अप, ट्विटर, गूगल, शेयरचैट और टिक-टॉक सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के निष्कर्ष के रूप में यह आचार संहिता विकसित की गई है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ❖ मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि इस संहिता का तैयार होना एक अच्छी शुरुआत है।
- ❖ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार भागीदारों के लिए इस आचार संहिता में उल्लेखित प्रतिबद्धताओं का अक्षरशः अनुसरण करना जरूरी है।
- ❖ सिन्हा समिति के सुझावों के अनुसार इन प्लेटफॉर्मों ने तीन घंटे के भीतर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी प्रकार की उल्लंघन की रिपोर्ट पर प्रक्रिया चलाने का संकल्प व्यक्त किया है।



- ❖ इन प्लेटफॉर्मों ने भारत निर्वाचन आयोग के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाली समर्पित रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार करने और आम चुनावों की अवधि के दौरान किसी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट के बारे में शीघ्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से समर्पित

- टीमों को नियुक्त करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है।
- भागीदारों ने राजनीतिक विज्ञापनदाताओं के लिए भी एक प्रणाली उपलब्ध कराने के बारे में सहमति व्यक्त की है, जो मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जारी पूर्व प्रमाणित विज्ञापनों को दाखिल करेंगे।
 - इस आचार संहिता में पेड राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने का भी वादा किया गया है।
 - IAMAI ने इस संहिता में उल्लेखित विभिन्न कदमों के बारे में भागीदारों के साथ समन्वय कायम करने पर सहमति व्यक्त की है। भागीदारों ने मतदाता जागरूकता अभियान को स्वैच्छिक रूप से चलाने के बारे में भी संकल्प व्यक्त किया है।
 - आम चुनाव 2019 में निर्वाचन प्रक्रिया में समग्रता कायम रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक इस्तेमाल के लिए यह आचार संहिता विकसित की गई है।
 - भागीदारों द्वारा सहमत स्वैच्छिक संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।

संविधान संशोधन आदेश, 2019 को स्वीकृति

संदर्भ :

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्यम से संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) आदेश, 1954 में संशोधन के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इससे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 द्वारा संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1955 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 से संशोधित भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

प्रभाव :

- अधिसूचित होने पर यह आदेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- जम्मू और कश्मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि: समानता और समावेश

- संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम 1955 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 4 के बाद धारा 4(ए) जोड़कर लागू किया गया।

- धारा 4(ए) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति लाभ देने का प्रावधान है।
- संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है और जम्मू और कश्मीर तक अधिनियम के विस्तार से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) की स्थापना के लिए एक विधेयक की घोषणा को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था निर्मित करना है।

लाभ :

- इस संस्थागत मध्यस्थता के लाभ सरकार, उसकी संस्था और परिवार के पक्षकारों को प्राप्त होंगे।
- विशेषज्ञता की गुणवत्ता और आने वाली लागत के लिहाज से यह केंद्र जनता और सरकारी संस्थानों के लिए फायदेमंद साबित होगा तथा भारत के संस्थागत मध्यस्थता की धुरी बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- NDIAC को जिन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया जाएगा वो हैं -
 - अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता संचालित करने के एक प्रमुख संस्थान के तौर पर खुद को विकसित करने के लिए लक्षित सुधार लाना।
 - समाधान मध्यस्थता और मध्यस्थता संबंधी कार्यवाहियों के लिए सुविधाएं और प्रशासकीय सहयोग प्रदान करना।
 - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मान्यता प्राप्त पंचों, मध्यस्थों व सुलहकारों या सर्वेक्षकों और जांचकर्ताओं जैसे विशेषज्ञों का पैनेल बनाकर रखना।
 - बड़े ही पेशेवर अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थताओं और सुलहों के संचालन को सुगम बनाना।
 - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और सुलह के संचालन के लिए कम खर्चीली और समयोचित सेवाएं प्रदान करना।
 - वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों के क्षेत्र में अध्ययन को प्रोत्साहित करना और झगड़ों के निपटारे की व्यवस्था में सुधारों को प्रोत्साहित करना।
 - वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाजों, संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना।

- NDIAC की स्थापना को सुगम करने की दिशा में इस विधेयक में, वैकल्पिक विवाद समाधान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICADR) के दायित्वों को केंद्र सरकार में स्थानांतरित और निहित करने की परिकल्पना की गई है। केंद्र सरकार बाद में ये दायित्व NDIAC में निहित करेगी।

मुख्य विशेषताएं :

- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी। जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों या फिर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों जिन्हें मध्यस्थता कानून के प्रशासन या प्रबंधन या संचालन में अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो। उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- दो पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य इसमें होंगे। जिन्हें उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से लिया जाएगा। जिन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के संस्थागत मध्यस्थता का ठोस ज्ञान और अनुभव हो।
- साथ ही, वाणिज्य और उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त निकाय के एक प्रतिनिधि को नियमित आवर्तन के आधार पर अंशकालिक सदस्य के तौर पर चुना जाएगा।
- विधि मामलों के विभाग के सचिव, व्यय विभाग द्वारा नामित वित्तीय सलाहकार और NDIAC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे।

आधार तथा अन्य कानूनों के प्रख्यापन (संशोधन) अध्यादेश, 2019

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार अधिनियम 2016, काला धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2005 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश के प्रख्यापन को मंजूरी दी है।
- प्रस्तावित संशोधन वैसे ही हैं जैसे 4 जनवरी, 2019 को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में निहित हैं।

प्रभाव:

- ये संशोधन (UIDAI) को जनहित की सेवा करने एवं आधार के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए अधिक मजबूत तंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनायेंगे।
- इस संशोधन के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से सत्यापन की प्रक्रिया के लिए आधार संख्या रखने का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबतक कि संसद द्वारा बनाये गए किसी

कानून द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

- इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- आधार नंबर धारक की सहमति से ऑफलाइन सत्यापन के प्रमाणीकरण द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग का प्रावधान करता है।
- किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए 12 संख्या के आधार नंबर एवं इसकी वैकल्पिक आभासी पहचान के उपयोग का प्रावधान करता है।
- उन बच्चों को, जो आधार कार्डधारी हैं, 18 वर्ष पूरे हो जाने पर अपना आधार नंबर रद्द करने के विकल्प का प्रावधान करता है।
- संस्थाओं को केवल तभी प्रमाणीकरण करने की अनुमति देता है जब वे प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट गोपनीयता एवं सुरक्षा मानदंडों के अनुपालक हों और प्रमाणीकरण की अनुमति संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून के तहत दी जा सकती है या वे केंद्र सरकार द्वारा देश के हित में अनुशंसित हो।
- स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देता है जैसा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 एवं काला धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य है।
- निजी संस्थाओं द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 के विलोपन का प्रस्ताव रखता है।
- यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड की स्थापना के लिए प्रावधान करता है।
- आधार पारिस्थितिकी तंत्र में कंपनियों द्वारा आधार अधिनियम एवं प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में नागरिक दंड, इसके अधिनियम एवं संबंधित अपील का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि:

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 के WP (सिविल) संख्या 494 में दिनांक 26.09.2018 के अपने निर्णय एवं अन्य चिह्नित याचिकाओं में आधार को संवैधानिक रूप से वैध माना।
- इसने आधार अधिनियम एवं विनियमनों के कुछ हिस्सों को वैध नहीं माना एवं गोपनीयता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई अन्य निर्देश दिए।
- इसके बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में आधार धारकों के व्यक्तिगत डाटा की रक्षा हो और आधार योजना संविधान के अनुरूप बनी

रहे। सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों एवं डाटा सुरक्षा पर न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के अनुसार आधार अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और काला धन शोधन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया।

- इस दिशा में, आधार एवं अन्य कानून (संशोधनों) विधेयक,

2018 को लोकसभा द्वारा 4 जनवरी, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में पारित कर दिया गया।

- इससे पहले कि राज्य सभा द्वारा इस पर विचार किया जाता और पारित किया जाता, राज्य सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई।

सामाजिक न्याय

यूनिट :

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- प्र. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की विशेषताओं की चर्चा करते हुए बताएं कि यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों की दशा में किस हद तक सुधार करेगी।
- प्र. शिक्षक कैंडर आरक्षण अध्यादेश, 2019 से जुड़े विवादों की चर्चा करते हुए, विवाद समाधान हेतु सरकारी प्रयासों की समीक्षा करें।

संभावित प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा) :

- प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
 1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगजनों द्वारा खेल-कूद में प्रभावी प्रतिभागिता हेतु ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान करता है।
 2. ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र की स्थापना की जा रही है।
 उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- प्र. वेस्ट नील वायरस के संबंध में सही विकल्प का चयन करें-
 - (a) यह एक मच्छर जनित रोग है।
 - (b) सबसे पहले यह युगांडा में पाया गया।
 - (c) अभी तक इससे बचाव हेतु टीके का विकास नहीं हुआ है।
 - (d) उपर्युक्त सभी

दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
- इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसका नाम दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र, ग्वालियर होगा।

- इस केंद्र को लगभग 170.99 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्ष में निर्मित किया जाएगा।

प्रभाव:

- इस केंद्र द्वारा खेल-कूद के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किए जाने से विभिन्न खेलों में दिव्यांगजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित होगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक सक्षम होंगे।
- इस केंद्र की स्थापना से दिव्यांगजनों के मन में सहजता से समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की भावना पैदा होगी।

विवरण:

- इस केंद्र के प्रबंधन और देख-रेख के लिए एक प्रबंध निकाय होगी, जिसके सदस्य 12 से अधिक नहीं होंगे। इनमें से कुछ पदेन सदस्य के तौर पर कार्य करेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स फेडरेशन के विशेषज्ञ और पैरा गेम्स के विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे।

पृष्ठभूमि:

- दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 की धारा 30 के तहत सरकार के लिए खेलों में दिव्यांगजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का विधान किया गया है।
- वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के अपने बजट भाषण में दिव्यांगजन खेल केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। वर्तमान में देश में दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट खेल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- प्रस्तावित केंद्र की स्थापना से इस कमी को पूरा किया जाएगा। इस केंद्र में दिव्यांगजन सही और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

लापता बच्चों से संबंधित भारत और अमरीका के बीच समझौता

संदर्भ :

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में ऑन लाइन खबरों तक पहुंचने के लिए भारत और अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
- समझौता ज्ञापन पर भारत की ओर से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और अमरीका की ओर से नेशनल सेन्टर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लायटेड चिल्ड्रन (NCMEC) ने हस्ताक्षर किये।

लाभ :

1. समझौता ज्ञापन NCMEC, अमरीका के पास उपलब्ध एक लाख से अधिक ऑन लाइन रिपोर्टों तक पहुंच और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार प्रदान करेगा।
2. इससे बाल अश्लील साहित्य और बच्चों के यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक नये तंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
3. यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल अश्लील साहित्य और बच्चों के यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री को साइबर स्पेस से हटाने का अधिकार प्रदान करेगा, जिससे मानव प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

संदर्भ :

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 05 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर से 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' का शुभारंभ किया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में की गई थी।
- इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' का शुभारंभ कर 11,51,000 लाभार्थियों तक 13,58,31,918 रुपये की धनराशि सीधे पेंशन खातों में ट्रांसफर की।

योजना के लाभार्थी :

- रिक्शा-ठेला चलाने वाले, फेरी लगा कर सामान बेचने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाली जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन देने की योजना है।

योजना से संबंधित खास बातें :

- श्रम मंत्रालय के मुताबिक 18 साल से 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड व्यक्ति को तीन हजार रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी।
- इस योजना का फायदा ऐसे मजदूरों को मिलेगा जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है। यानी, ऐसे लोग जो मासिक आधार पर 15 हजार से कम कमा पाते हैं, उनको इस दायरे में लाया जाएगा।
- अगर कोई 18 साल की उम्र में इससे जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा करने होते हैं। वहीं 40 साल के व्यक्ति को हर महीने 200 रुपए की रकम जमा करनी होगी।
- 29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपए प्रति महीना जमा करने होंगे। यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी है।
- इनमें मजदूरों को हर महीने एक निश्चित राशि का प्रीमियम देना होगा। जितना प्रीमियम होगा, उतने रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से भी दी जाएगी।
- इस योजना से जो भी व्यक्ति जुड़ेगा, उसके पास आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है।
- इस योजना के तहत, जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी

राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आते हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे। इनकम टैक्स भरने वाले भी अपात्र होंगे।

- ☞ इस स्कीम के लिए सरकार एक पेंशन फंड बनाएगी। इस फंड के जरिए ही सभी को पेंशन दी जाएगी।
- ☞ अगर किसी कामगार की योजना के दौरान निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है। यदि कामगार के निधन पर उसकी पत्नी या पति योजना से बाहर होना चाहते हैं तो वो दी गई कुल रकम पर ब्याज के साथ इसे वापस ले सकते हैं।
- ☞ यदि किसी की पेंशन शुरू हो गई है और उसके बाद उसका निधन होता है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन की 50 फीसदी रकम मिलेगी।
- ☞ राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन (NSSO) के आंकड़ों के मुताबिक देश में 40 करोड़ से ज्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से आधे से भी ज्यादा मजदूर कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। करीब पांच करोड़ लोग भवन निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

शौचालयों का 96% से भी अधिक उपयोग

चर्चा में क्यों?

- ☞ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBMG) की विश्व बैंक सहायता परियोजना के तहत एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (IVA) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS) से पता चला है कि ग्रामीण भारत के जिन 96.5 प्रतिशत से भी अधिक परिवारों की शौचालय तक पहुंच है वे इसका उपयोग कर रहे हैं।
- ☞ एनएआरएसएस ने यह भी पुष्टि की कि गांवों की खुले में शौच से मुक्ति (ODF) की स्थिति 90.7 प्रतिशत है।
- ☞ इन गांवों की विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा खुले में शौच से मुक्त होने की पूर्व घोषणाओं का सत्यापन किया गया था।



- ☞ यह सर्वेक्षण नवम्बर 2018 और फरवरी 2019 के बीच आयोजित किया गया था।
- ☞ इसमें भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 6136 गांवों के 92,040 परिवारों को शामिल किया गया था।
- ☞ NARSS 2018-19 के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-
 - सर्वेक्षण अवधि के दौरान 93.1 परिवारों की शौचालयों तक पहुंच पाई गई (नवम्बर 2018 में SBMG, NARSS के अनुसार समतुल्य आंकड़ा 96 प्रतिशत था)। जिन 96.5 प्रतिशत लोगों की शौचालय तक पहुंच है वे उसका उपयोग करते हैं।
 - पहले ODF घोषित और सत्यापित 90.7 गांवों की ODF की पुष्टि हुई।
 - शेष गांवों में भी स्वच्छता की कवरेज लगभग 93 प्रतिशत पाई गई।
 - 95.4 प्रतिशत गांवों के सर्वेक्षण में भी न्यूनतम कचरा और न्यूनतम जल ठहराव पाया गया।

पृष्ठभूमि :

- ☞ अक्टूबर 2014 में शुरुआत होने के बाद से भी SBMG दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है।
- ☞ इसने शौचालय पहुंच और उसके उपयोग के बारे में करोड़ों लोगों के व्यवहार को बदल दिया है।
- ☞ इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से 500 मिलियन लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है।
- ☞ इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- ☞ 30 ODF राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 615 जिलों के 5.5 लाख से अधिक गांवों को ODF घोषित किया गया है।

शिक्षक कैंडर आरक्षण अध्यादेश, 2019

चर्चा में क्यों?

- ☞ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान : शिक्षक कैंडर में आरक्षण: अध्यादेश 2019 को 7 मार्च को मंजूरी दे दी ।
- ☞ इस अध्यादेश में विभाग या विषय की बजाय विश्वविद्यालय या कॉलेज को इकाई माना गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ☞ इस निर्णय से शिक्षक कैंडर में सीधी भर्ती के तहत 5000 से अधिक रिक्तियों को भरते समय यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का पूरी तरह से अनुपालन हो सके और जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियत आरक्षण प्रावधान का पालन हो सके।

- ❖ इस विषय पर छात्रों और शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
- ❖ इन संगठनों की ओर से सरकार से आग्रह किया गया था कि शिक्षक पदों में आरक्षण इकाई के रूप में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट की रोस्टर प्रणाली को बहाल करने के लिये अध्यादेश लाया जाए।
- ❖ विश्वविद्यालय आरक्षण रोस्टर को लेकर यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण विवि को यूनिट मानकर तय करने की बजाय विभाग को यूनिट मानकर तय करने का निर्देश दिया था।
- ❖ इसके बाद यूजीसी ने सभी विवि को आदेश जारी कर विभागवार आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया था।

महिला सशक्तिकरण हेतु करार

चर्चा में क्यों?

- ❖ महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक करार किया है।
- ❖ इस समझौता ज्ञापन पर 8 मार्च को महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ❖ इस करार का क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (NSDC) के माध्यम से किया जाएगा।
- ❖ राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण वाले उन क्षेत्रों और उनकी भौगोलिक प्रासंगिकता की पहचान करेगा, जो स्व-रोजगार या नौकरियों के माध्यम से महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए उपयुक्त होंगे।
- ❖ राष्ट्रीय महिला कोष महिलाओं के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ गठबंधन करके आवश्यक मॉड्यूल भी विकसित करेगा।
- ❖ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दायरे में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिह्नित कौशल विकास कार्यक्रमों को मदद देगा।
- ❖ मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय को उन महिलाओं का ब्यौरा भी देगा, जिन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त

किया है और अपने प्रशिक्षण के बाद वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं या अन्य प्रकार की सेवाएं दे रही हैं।

- ❖ महिला और बाल विकास मंत्रालय, RMK के माध्यम से, ऐसी महिलाओं को महिला ई-हाट से जुड़ने में मदद करेगा।
- ❖ महिला ई-हाट और NSDC संयुक्त रूप से स्व-रोजगार/उद्यमियों आदि में रुचि रखने वाली NSQF प्रमाणित महिलाओं के लिए क्षमता विकास कार्यशालाओं का आयोजन भी करेंगे।
- ❖ इस कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण भागीदार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अनुमोदित भागीदारों में से ही होंगे।
- ❖ इसके लिए उनकी स्थानीय उपस्थिति और अनुभवों को ध्यान में रखा जाएगा।
- ❖ महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन तीन साल की अवधि के लिए किया गया है।

उच्च शिक्षा प्राप्ति पर पांच गुणा इंसेंटिव

चर्चा में क्यों?

- ❖ सरकारी नौकरी में रहते उच्च शिक्षा हासिल करने पर मिलने वाले इंसेंटिव को पांच गुणा बढ़ा दिया गया है। लेकिन शर्त यह है कि उच्च शिक्षा कर्मचारी के काम से संबंधित हो।
- ❖ कार्मिक मंत्रालय से मिली सूचना के अनुसार न्यूनतम इंसेंटिव 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक होगा।
- ❖ 1999 में जारी आदेश के मुताबिक पहले यह राशि दो हजार रुपये से 10,000 रुपये थी।
- ❖ कार्मिक मंत्रालय ने इसके लिए 20 साल पुराने मानदंडों में संशोधन किया है। नौकरी के दौरान अधिकतम दो बार इंसेंटिव मिल सकता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ❖ कार्मिक मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक तीन साल या उससे कम अवधि वाले डिग्री/डिप्लोमा हासिल करने पर 10,000 रुपये दिये जाएंगे।
- ❖ तीन साल से अधिक की अवधि वाले डिग्री/डिप्लोमा हासिल करने पर 15,000 रुपये दिये जाएंगे।
- ❖ एक साल या उससे कम अवधि वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा हासिल करने पर 20,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।
- ❖ जबकि, एक साल से अधिक की अवधि वाले डिग्री/डिप्लोमा हासिल करने पर 25,000 रुपये इंसेंटिव के रूप में दिये जाएंगे।
- ❖ पीएचडी या उसके बराबर की डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारी को सबसे ज्यादा 30,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। केंद्र सरकार में लगभग 48.41 लाख कर्मचारी हैं।

- शैक्षिक और साहित्यिक विषयों पर उच्च शिक्षा हासिल करने पर कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा।
- मौजूदा जिम्मेदारी या अगले पद की जिम्मेदारियों में मददगार उच्च शिक्षा हासिल करने पर भी इंसेंटिव मिलेगा।
- साथ ही नौकरी में रहते हुए उच्च शिक्षा हासिल करने पर ही कर्मचारी इंसेंटिव का पात्र होगा।

वेस्ट नील वायरस

चर्चा में क्यों

- हाल ही में केरल स्थित मालापुरम में वेस्ट नील वायरस (West Nile Virus - WNV) से लोग प्रभावित हुए हैं।
- वेस्ट नील वायरस मच्छर जनित बीमारी है और यह बीमारी अधिकतर द्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है।
- भारत सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केरल को सभी तरह का समर्थन देने का निर्देश दिया गया है।

वेस्ट नील वायरस

- वेस्ट नील वायरस एक मच्छर जनित रोग है।
- वेस्ट नील वायरस मनुष्यों में एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बन सकता है।
- हांलाकि, इससे संक्रमित लगभग 80% लोगों में इसके लक्षण पता नहीं लग पाते हैं।
- यह वायरस घोंड़ों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकता है।
- घोंड़ों को रोग से बचाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले टीके उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- पक्षी वेस्ट नील वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं।

वेस्ट नील वायरस की उत्पत्ति

- वेस्ट नील वायरस (WNV) पहली बार वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्ट नील जिले में एक महिला में पाया गया था।
- इसकी पहचान वर्ष 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों (कौवे और कोलम्बिफॉर्म) में हुई थी।
- वर्ष 1997 से पहले WNV को पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता था, लेकिन उस समय इजराइल में एक ही समय पर सैंकड़ों पक्षी प्रजातियों की मृत्यु हो गई थी, जो इंसेफेलाइटिस और पक्षाघात के लक्षण पेश कर रही थीं।

लक्षण

- लगभग 80% संक्रमित लोगों में WNV के साथ संक्रमण या तो स्पर्शोन्मुख (कोई लक्षण नहीं) होता है, या वेस्ट नील बुखार या गंभीर वेस्ट नील रोग हो सकता है।

- लगभग 20% लोगों में वेस्ट नील बुखार देखा जाता है।
- इसमें सिरदर्द, तेज बुखार, थकान, शरीर में दर्द, मितली, उल्टी, कभी-कभी त्वचा पर चकत्ते और लसीका ग्रंथियों (Lymph Glands) में सूजन।
- नील वायरस की गंभीर अवस्था में सिरदर्द, तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, स्तब्धता, मस्तिष्क भटकाव, कोमा, दौरे पड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी, और पक्षाघात जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं।
- यह अनुमान लगाया जाता है कि वेस्ट नील वायरस से संक्रमित लगभग 150 में से 1 व्यक्ति ही बीमारी के अत्यधिक गंभीर रूप में प्रवेश करेगा। यह वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को चपेट में ले सकता है।
- हांलाकि, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और कुछ प्रत्यारोपण के रोगियों का WNV से संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार होने का सबसे अधिक खतरा होता है।

बधिरों के लिए शब्दकोश के दूसरे संस्करण का आरंभ

समाचारों में क्यों?

- केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 27 फरवरी 2019 को बधिर लोगों के लिए आईएसएल (ISL) शब्दकोश के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया।
- इस शब्दकोश को इंडियन साईन लेंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (ISLRTC) ने तैयार किया है, जो सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।



- ISLRTC को शब्दकोश निर्माण के लिए 7-9 फरवरी, 2018 और 22-24 जनवरी, 2019 को दो कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें पूरे देश के बधिर प्रतिभागियों ने अपने सुझाव रखे थे।

बधिरों के लिए शब्दकोश की विशेषताएं

- शब्दकोश में शिक्षा, कानून, चिकित्सा, तकनीक आदि विषयों के 6000 शब्द हैं।

- ☛ ISL शब्दकोश ISLRTC के यू-ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। You-Tube चैनल में लगभग 1000 वीडियो हैं।
- ☛ इससे पूर्व 3000 शब्दों वाले पहले संस्करण को 23 मार्च, 2018 को लॉन्च किया गया था।
- ☛ यह शब्दकोश ISL शिक्षकों, ISL छात्रों, भाषा संकेतकों, बधिर व्यक्तियों और शोध करने वालों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।
- ☛ इस शब्दकोश को बधिर समुदाय के लोगों के सुझावों और समझ के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें अंग्रेजी और हिन्दी संकेतों की सूची भी दी गई है।
- ☛ इससे कोई भी व्यक्ति इस शब्दकोश को पढ़कर मूक-बधिरों के संकेतों को समझ सकेगा और उनसे संवाद स्थापित कर सकेगा।
- ☛ सांकेतिक भाषा के प्रत्येक संकेत को एक स्केच या कार्टून के माध्यम से बताया जायेगा। साथ ही उसे शब्दों और वाक्यों में भी बताया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूनिट:

- ☛ भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध।
- ☛ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- ☛ भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव।
- ☛ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- प्र. सामान्य प्राथमिकता प्रणाली क्या है? इसे समापन की अमेरिकी सरकार की घोषणा का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करें।
- प्र. 'पाकिस्तान से खराब होते संबंध ने भारत के लिए चाबहार के महत्व को और बढ़ा दिया है।' कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें।

GSP छूट वापस लेकर भारत के साथ ट्रेड वॉर की राह पर अमेरिका

चर्चा में क्यों ?

- ☛ अमेरिका ने सामान्य प्राथमिकता प्रणाली (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस-GSP) के तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट आगे और जारी ना रखने का एलान किया है।
- ☛ यह छूट 60 दिनों बाद खत्म हो जाएगी और भारत द्वारा इसका विरोध करने की संभावना नहीं है।
- ☛ अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने घोषणा की है कि भारत और तुर्की को GSP के तहत शुल्क में मिलने वाली छूट का फायदा अब और नहीं मिलेगा।
- ☛ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (US Trade Representative-USTR) ने भारत को लेकर GSP की समीक्षा की थी, जिसमें अमेरिका इसके तहत कुछ निश्चित निर्यात सीमा पर भारत से कोई शुल्क नहीं लेता।

क्या है GSP ?

- ☛ GSP विकसित देशों (प्राथमिकता देने वाले या दाता देश) द्वारा विकासशील देशों (प्राथमिकता प्राप्तकर्ता या लाभार्थी

देश) के लिये विस्तारित एक अधिमन्य प्रणाली है।

- ☛ 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत 1976 में शुरू की गई GSP इस व्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों को अमेरिका को निर्यात की गई कुछ सूचीबद्ध वस्तुओं पर करों से छूट मिलती है।
- ☛ GSP अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापार तरजीही योजना है, जिसका उद्देश्य हजारों उत्पादों को आयात शुल्क में छूट देकर विकासशील देशों को आर्थिक विकास में मदद करना है।
- ☛ इस प्रणाली के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है।
- ☛ विकसित देश इसके जरिये विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
- ☛ नामित लाभार्थी विकासशील देशों के लगभग 30-40 प्रतिशत उत्पादों के लिये वरीयता शुल्क मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। भारत भी एक लाभार्थी विकासशील देश है।
- ☛ ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कजाखस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्जरलैंड, तुर्की और अमेरिका GSP को प्राथमिकता देने वाले देशों में प्रमुख हैं।

- GSP को 1 जनवरी 1976 को अमेरिका के ट्रेड एक्ट-1974 के तहत शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनियाभर के विकासशील देशों के बाजारों को सहारा देना था।
- इस कार्यक्रम में शामिल देशों को अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने पर किसी तरह का आयात शुल्क नहीं देना होता है। इस कार्यक्रम में भारत सहित 121 देशों को शामिल किया गया है।
- सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका कुछ देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर ड्यूटी नहीं लगाता अर्थात् जिन देशों को GSP की सुविधा मिलती है, वे बिना किसी शुल्क के अपनी कुछ वस्तुएँ अमेरिकी बाजार में पहुँचा सकते हैं।
- इसे बिजनेस की भाषा में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब कोई देश किसी अन्य देश को कुछ सामान बेचता है तो उसे ड्यूटी अदा करनी पड़ती है।
- ऐसे में सामान की कीमत बढ़ जाती है और जब ड्यूटी नहीं लगती तो कीमत कम रहती है और वह वस्तु अधिक बिकती है। इससे मुनाफा तो बढ़ता ही है, व्यापार में भी वृद्धि होती है।
- यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए है और इसके बारे में कोई वार्ता संभव नहीं है।
- अल्फाफा, चौरा और पोर्क जैसे उत्पादों के बारे में अमेरिकी बाजार पहुँच के अनुरोधों की स्वीकार्यता से अवगत कराया गया था।
- भारत ने स्पष्टतः अमेरिका के हितों से जुड़ी विशेष वस्तुओं पर कर में रियायत देने की इच्छा से अवगत कराया।
- गौरतलब है कि तेल और प्राकृतिक गैस तथा कोयला जैसे सामानों की खरीद बढ़ने से भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे में 2017 और 2018 में काफी कमी हुई है। 2018 में 4 बिलियन डॉलर से अधिक कमी का अनुमान है।
- भारत में ऊर्जा और विमानों की बढ़ती मांग जैसे घटकों के परिणामस्वरूप भविष्य में इसमें और भी कमी होने का अनुमान है।
- अरबों डॉलर के राजस्व वाली अमेरिकी सेवाओं और एमेजन, उबर, गूगल तथा फेसबुक आदि जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये भी भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है।
- हांलाकि तुर्की को भी GSP से बाहर किया गया है, लेकिन USTR ने भारत की कड़ी आलोचना की है।
- उसके अनुसार, “भारत ने कई तरह की व्यापार बाधाएँ खड़ी कर रखी हैं। जिससे अमेरिकी कारोबार पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ रहा है।”

भारत और GSP

- भारत GSP का सबसे बड़ा लाभार्थी है, 2017-18 में 19 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ।
- GSP के तहत 5.6 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जो कुल निर्यात का 11% है।
- GSP के तहत 3700 उत्पादों को छूट मिली हुई है, परंतु भारत केवल 1900 उत्पादों का निर्यात करता है।

GSP के लिये कुछ अनिवार्य शर्तें

- इसके तहत मुकदमा होने पर अमेरिकी कंपनियों और नागरिकों को प्राथमिकता देना, सामान बनाने में बाल श्रम का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना, पेटेंट नियमों को मानना, अमेरिकी कंपनियों को अपने देश में बराबर के मौके देना आदि शामिल हैं।

अमेरिका की चिंताएँ

- भारत को होने वाले GSP लाभों के तहत अमेरिका प्रतिवर्ष 190 मिलियन डॉलर की कर छूट दे रहा था। लेकिन भारत को अपने यहाँ से निर्यात होने वाले स्टेंट जैसे कुछ मेडिकल उपकरणों को लेकर वह समय-समय पर चिंताएँ जाहिर करता रहा है।
- भारत सैद्धांतिक रूप से मेडिकल उपकरणों के बारे में अमेरिका की चिंताओं को हल करने के लिये तैयार था।
- इसी प्रकार दुग्ध उत्पादों की बाजार पहुँच से जुड़े मुद्दों पर भारत ने स्पष्ट किया कि इनके लिये यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि स्रोत पशुधन को अन्य पशुधन से प्राप्त रक्ताहार कभी नहीं दिया गया है।

भारत को WTO में भी चुनौती देता रहा है अमेरिका

- अमेरिका ने भारत की एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीमों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चुनौती देता रहा है। अमेरिकी शिकायत में 6 योजनाओं के नाम हैं।
- इसमें कहा गया है कि भारत निर्यातकों के अलावा स्टील प्रोडक्ट, फार्मा, केमिकल, IT और टेक्सटाइल निर्माताओं को इन्सेंटिव देता है।
- इन स्कीमों से इन्हें हर साल 7 अरब डॉलर (45,500 करोड़ रुपए) की मदद मिलती है। इस मदद से निर्यातक अपना सामान सस्ते में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे अमेरिकी निर्माताओं और कामगारों को नुकसान होता है।
- WTO के नियमों के मुताबिक जिन देशों की प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 डॉलर से कम है, वे एक्सपोर्ट इन्सेंटिव दे सकते हैं।
- इन्सेंटिव उन्हीं क्षेत्रों के लिये दिया जा सकता है जिनकी वैश्विक निर्यात में 3.25% से कम हिस्सेदारी है।
- अमेरिका का कहना है कि भारत 2015 में ही इस मानदंड से ऊपर आ गया था। नियम के अनुसार, यह छूट खत्म कर दी जानी चाहिये थी, लेकिन भारत ने इसका आकार और दायरा, दोनों बढ़ा दिया है।

- WTO के पहले के एक फैसले के मुताबिक GSP के तहत छूट की प्रकृति गैर-पारस्परिक है। भारत ने पहले कहा था कि अमेरिका ने यदि यह छूट वापस ली तो वह उसे WTO में खींचेगा। अब चूँकि यह पूरी तरह एक एकतरफा कदम ठहराया गया है, इसलिये अमेरिका के अपने फैसले से पलटने की कम ही उम्मीद है।

चीन की दमदार आर्थिक कूटनीति

- पिछले एक साल से चला आ रहा अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अब खत्म होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच इसके लिये एक समझौते पर बातचीत चल रही है।
- अगर दोनों देशों में सहमति बन जाती है तो चीनी उत्पादों पर लगभग 200 अरब डॉलर का शुल्क अमेरिका हटा लेगा, जबकि चीन ऑटोमोबाइल आदि पर लगाए जाने वाले औद्योगिक करों को घटाएगा।
- इसके अलावा, चीन एक नया विदेशी निवेश कानून बनाने पर भी विचार कर रहा है, जो वैश्विक निवेशकों को निवेश के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इस कानून में बौद्धिक संपदा अधिकारों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर कानूनी सुरक्षा उपायों का भी जिक्र होगा।
- चीन ने अपने यहाँ कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को लाभ पहुँचाने के लिये छह साल में 12 खरब अमेरिकी डॉलर की खरीद बढ़ाने की पेशकश भी की है।
- सरकारों के स्तर पर दोनों देश नियमित रूप से परामर्श तंत्र स्थापित करने की योजना भी बना रहे हैं, ताकि व्यापार संबंधी कठिनाइयाँ दूर की जा सकें।

भारत पर क्या होगा असर?

- अमेरिका के लिये भारत 11वाँ सबसे बड़ा व्यापार घाटे वाला देश है।
- 2017 में अमेरिका ने भारत से 76.7 अरब डॉलर का सामान खरीदा, लेकिन भारत ने इसी दौरान अमेरिका से 49.4 अरब डॉलर का सामान लिया।
- इस तरह से अमेरिका को 27.3 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।
- भारत से अपने व्यापार घाटे (Trade Surplus) को कम करने के लिये अमेरिका लगातार जोर देता रहा है।
- ऐसे में माना जा रहा है कि GSP छूट वापस लेने का पहला असर दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य व्यापार पैकेज पर पड़ेगा जिस पर लंबे समय से बातचीत चल रही है।
- भारत सरकार ने कहा है कि अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर से कर छूट वापस लेने से दोनों देशों के आपसी व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

- अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात में कर छूट वाले उत्पादों की संख्या कम है और इनका निर्यात मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है।
- इस प्रणाली से बाहर होने से भारतीय उत्पादों को मिलने वाली 19 करोड़ डॉलर की छूट समाप्त हो जाएगी। इससे लगभग 2000 भारतीय उत्पादों का 560 करोड़ डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा।
- इनमें मुख्यतः आभूषण, हस्तशिल्प और चमड़ा उत्पाद तथा परिधान शामिल हैं। अमेरिका के इस फैसले से भारत का निर्यात प्रभावित होगा।
- अमेरिका के जवाब में भारत उसके उत्पादों पर और ड्यूटी बढ़ा सकता है।
- इससे जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच चल रहा था, वही भारत और अमेरिका के बीच भी शुरू हो जाएगा।
- यह भी प्रासंगिक है कि भारत की ओर से लगाए गए शुल्क विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बाध्यताओं के तहत सीमित दरों के भीतर हैं और ये सीमित दरों से काफी कम औसत स्तर पर बने हुए हैं।
- ऐसे में भारत प्रमुख विवादित मुद्दों पर सार्थक और परस्पर स्वीकार्य पैकेज को मानने और शेष मुद्दों के बारे में भविष्य में विचार-विमर्श जारी रखने के बारे में सहमत हो सकता था।
- यह भी ठीक है कि GSP के लाभ सीमित हैं और इसे लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में इसका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन इसका पटाक्षेप उस तरह नहीं हुआ जैसा अपेक्षित था।

भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता

चर्चा में क्यों?

- 7 मार्च, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ऑस्ट्रिया के परिवहन, नवाचार और तकनीकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- इस समझौता ज्ञापन के जरिए दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास, प्रबंधन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन प्रणाली के लिए द्विपक्षीय सहयोग की एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।
- इससे भारत और ऑस्ट्रिया के बीच लंबे समय से चले आ

- रहे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे।
- इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और क्षेत्रीय निकटता भी बढ़ेगी।
 - भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सड़क परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने से सड़क सुरक्षा तथा इस क्षेत्र में बढ़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की संभावनाओं को बल मिलेगा।
 - परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से इससे दोनों देशों के बीच पहले से बने मजबूत संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे।
 - गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 1949 में राजनयिक संबंध बने थे जो समय के साथ लगातार मजबूत हुए हैं।
 - दोनों देश मैत्रीपूर्ण आर्थिक और राजनयिक संबंधों को साझा करते हैं। सड़क और राजमार्ग तकनीक के मामले में ऑस्ट्रिया काफी विकसित है।
 - ऑस्ट्रिया के पास खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली, अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था, यातायात प्रबंधन प्रणाली, भूमिगत मार्ग निगरानी व्यवस्था, भू-मानचित्र तथा भूस्खलन सुरक्षा के क्षेत्र में बेहद उन्नत तकनीक मौजूद है।

भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इस समझौता ज्ञापन पर 14 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- भारत/ब्रिटेन कैंसर शोध पहल क्लिनिकल शोध, जनसांख्यिकी शोध, नई टेक्नोलॉजी और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के अग्रणी विशेषज्ञों को साथ लाकर किफायती, रोकथाम तथा कैंसर देखभाल जैसी शोध चुनौतियों की पहचान करेगी।
- यह पहल नये शोध गठजोड़ विकसित करने में पहल करेगी और कैंसर परिणामों के विरुद्ध प्रगति को सक्षम बनाने में प्रभावी शोध कार्य करेगी।

धन पोषण व्यवस्था :

- 5 वर्षों में इस पहल के लिए कुल शोध धनकोष 10 मिलियन पाउंड (लगभग 90 करोड़ रुपये) का होगा।
- इस कोष में कैंसर रिसर्च यूके (CRUK) की हिस्सेदारी 5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की हिस्सेदारी भी 5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) की होगी।

- दोनों की बराबर निधियां वित्त वर्ष प्रारंभ होने के समय जारी दरों के अनुसार होंगी।

प्रभाव :

- कैंसर परिणामों में सुधार के उद्देश्य के साथ प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल, क्लिनिकल तथा फार्मास्युटिकल नवाचारों में वृद्धि के बावजूद कैंसर देखभाल पर बढ़ते खर्च को पूरा करने में विश्व के बोझ से दबी स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से लैस नहीं हो पाएगी।
- भारत-यूके कैंसर शोध पहल ने श्रेष्ठ शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य सेवा संगठनों तथा संस्थानों को एक-दूसरे से जुड़ने में सहयोग के लिए रूपरेखा तय की है, ताकि कैंसर देखभाल के लिए उच्च मूल्य और कम लागत के बहु-विषयक शोध मंच तैयार हो सके।
- इस पहल के माध्यम से डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल स्तर के शोधकर्ताओं और प्रारंभिक करियर के वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ेगी।
- ऐसे शोधकर्ता ना केवल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किए जाएंगे, बल्कि उन्हें आवश्यक नेतृत्व और परियोजना प्रबंधन कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें अकादमिक क्षेत्र और संबंधित बायो-फार्मा उद्योग में निश्चित अवधि के शोध कार्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

पृष्ठभूमि :

- भारत-ब्रिटेन कैंसर शोध पहल विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च यूके (CRUK) का 5 वर्ष का सहयोगी द्विपक्षीय शोध कार्यक्रम है।
- यह कार्यक्रम कैंसर के किफायती दृष्टिकोण पर फोकस करेगा। 5 वर्ष में CRUK और जैव प्रौद्योगिकी विभाग दोनों 5-5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) का निवेश करेंगे और संभावित धन देने वाले सहयोगियों से आगे निवेश की कोशिश करेंगे।
- भारत-ब्रिटेन कैंसर शोध कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री की 18 अप्रैल, 2018 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में की गई थी।
- भारत का जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च यूके ने 10 मिलियन पाउंड (लगभग 90 करोड़ रुपये) की द्विपक्षीय शोध पहल लांच करने का प्रस्ताव रखा है, जो कैंसर के इलाज के लिए कम लागत पर फोकस करेगी।

भारत और जर्मनी के मध्य समझौता

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत

और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन का 13 नवंबर, 2018 को नवीकरण किया गया था।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ❖ समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई प्रशिक्षण तकनीक अपनाने और जोखिमों से निपटने में काफी मदद मिली है।
- ❖ समझौता ज्ञापन के तहत निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के माध्यम से जर्मनी की सामाजिक दुर्घटना बीमा के जरिए काफी मदद मिल रही है।
- ❖ इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेहतर OSH सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही रोजगार से जुड़ी दुर्घटनाओं और बीमारियों से भी उनका बचाव हो सकेगा।
- ❖ इस समझौते से श्रम मंत्रालय के तकनीकी विभाग - कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के कौशल विकास और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य निरीक्षक कारखाना अधिकारी की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
- ❖ इससे भारतीय श्रम बल के लिए उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए OSH के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाओं का उन्नयन और सुरक्षा के मामले में OSH के मानकों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी

चर्चा में क्यों?

- ❖ भारत-अफ्रीका के बीच परियोजना साझेदारी पर CII-एक्जिम बैंक का 14वां सम्मेलन 17 से 19 मार्च, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- ❖ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ और एक्जिम बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया है।
- ❖ यह सम्मेलन भारत-अफ्रीका के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को और गहरा बनाने के साथ-साथ सीमा पार की परियोजनाओं में संपूर्ण साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- ❖ 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से इस वार्षिक सम्मेलन ने भारत और अफ्रीका के वरिष्ठ मंत्रियों, सांसदों, अधिकारियों, व्यवसायियों, बैंकरों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, स्टार्ट-अप उद्यमियों और अन्य पेशेवरों को साझेदारी की भावना से एक मंच पर लाने का काम किया है।

- ❖ 36 देशों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों के अलावा 21 अफ्रीकी देशों में से 31 से अधिक वरिष्ठ मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
- ❖ सम्मेलन 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के क्षेत्र में भारत और अफ्रीका के बीच उत्कृष्ट साझेदारी में योगदान देगा।



- ❖ सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो बढ़ते संरक्षणवाद और व्यापार टकरावों के कारण उत्पन्न हो रही है।
- ❖ भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी भारत के तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में प्रभुत्व कायम करने से संवर्धित हुई है।
- ❖ साथ ही सब सहारा की कुछ अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अफ्रीका की नई अर्थव्यवस्था में गतिशीलता देखने को मिली है, जो दुनिया की 10 तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- ❖ यह सम्मेलन भारत सरकार के अफ्रीका के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव की विस्तृत संकल्पना के अनुकूल है। सरकार भारत-अफ्रीका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ❖ यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी से स्पष्ट है जो वर्ष 2017-18 में 62.66 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।
- ❖ सम्मेलन के जानकारी सत्र में द्विपक्षीय, आर्थिक और व्यावसायिक साझेदारी के संभावित क्षेत्रों, भारतीय और अफ्रीकी उद्यमों की क्षमताओं तथा संयुक्त उद्यम के अवसरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- ❖ विचार-विमर्श के दौरान जिन दीर्घकालिक लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विशेष रूप से चर्चा होगी वे हैं -
 1. अगले कुछ वर्षों में भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 150 बिलियन तक पहुंचाना।
 2. भारतीय निर्यातकों को अफ्रीकी देशों तक पहुंच स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में उनकी उपस्थिति बढ़ाना।

3. अफ्रीका को भारत से निर्यात के लिए भौगोलिक और उत्पाद विविधता शुरू करना।
 4. भारत से शुल्क मुक्त सीमा शुल्क प्राथमिकता की योजना और क्षमता निर्माण सहायता के अधिकतम इस्तेमाल द्वारा अफ्रीका के निर्माण निर्यात को बढ़ावा देना।
 5. बुनियादी ढांचा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा सेवाओं, आईटी और ज्ञान उद्योगों जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश का विस्तार।
- ☛ सम्मेलन में B2B बैठकों में अफ्रीका के 500 से अधिक परियोजना प्रस्तावों के भविष्य के बारे में चर्चा होने की भी उम्मीद है।

शत्रु संपत्ति का 'सार्वजनिक इस्तेमाल'

चर्चा में क्यों?

- ☛ 11 मार्च को केंद्र सरकार ने बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए या फिर 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई कुछ शत्रु संपत्तियों के "सार्वजनिक इस्तेमाल" की इजाजत राज्य सरकारों को दे दी है।
- ☛ यह कदम केंद्र सरकार के उन प्रयासों के बीच आया है जिसके तहत वह एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की 9,400 शत्रु संपत्तियों और 3000 करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु हिस्सेदारी को बेचने का प्रयास कर रही है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ☛ गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक शत्रु संपत्ति आदेश, 2018 के निस्तारण के लिये दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है जिससे "राज्य सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति का इस्तेमाल खास तौर पर सार्वजनिक इस्तेमाल" के लिये किया जा सके।
- ☛ शत्रु संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो उन लोगों द्वारा पीछे छोड़ी गई जिन्होंने पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले ली।
- ☛ पाकिस्तानी नागरिकों की ऐसी 9,280 संपत्तियां हैं जबकि चीनी नागरिकों द्वारा 126 संपत्तियां यहां छोड़ी गई हैं।
- ☛ पाकिस्तानी नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में से 4,991 उत्तर प्रदेश में स्थित है जो देश में सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में ऐसी 2,735 संपत्तियां हैं जबकि दिल्ली में 487 संपत्तियां हैं।
- ☛ चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई सबसे ज्यादा संपत्तियां मेघालय में हैं जहां ऐसी 57 संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसी 29 और असम में 7 संपत्तियां हैं।
- ☛ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अनुसार शत्रु संपत्तियों का अनुमानित मूल्य लगभग एक लाख करोड़ रुपये है।

अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के रास्ते निर्यात

चर्चा में क्यों?

- ☛ अफगानिस्तान ने ईरान के चाबहार बंदरगाह से भारत को सामान निर्यात करना शुरू कर दिया है। काबुल से मेवा, टैक्सटाइल्स, कार्पेट और खनिज मिनरल प्रॉडक्ट्स 23 ट्रकों में भरकर चाबहार पोर्ट के लिए रवाना किया।
- ☛ यह खेप वहां से जहाज के जरिये मुंबई पहुंचेगी।
- ☛ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने निर्यात के लिए नये मार्ग की शुरुआत करते हुए कहा कि व्यापार घाटे को कम करने के लिए धीरे-धीरे निर्यात में सुधार किया जा रहा है।
- ☛ 'चाबहार पोर्ट भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच स्वस्थ सहयोग का परिणाम है और यह आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करेगा।'

अफगानिस्तान का चाबहार से निर्यात

- ☛ इस खेप में 570 टन ड्राई फ्रूट्स, टैक्सटाइल्स, कार्पेट और मिनरल उत्पाद शामिल है जो जहाज के जरिये मुंबई पहुंचेगी।
- ☛ अफगानिस्तान द्वारा चाबहार से किया गया निर्यात इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन समझौता पूरी तरह से क्रियान्वित हो गया है।
- ☛ मई 2016 में इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तेहरान में हस्ताक्षर किये थे।
- ☛ इससे पूर्व भारत ने भी चाबहार पोर्ट के जरिये अफगानिस्तान को 1.1 मिलियन टन गेहूँ और 2000 टन मसूर की दाल निर्यात किया था।
- ☛ दक्षिण एशिया में चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के साथ-साथ भारत के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ बनाये गये संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं।
- ☛ इस रास्ते के जरिए अफगानिस्तान और भारत के बीच से पाकिस्तान की बाधा दूर हुई है।
- ☛ ईरान का चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान को आसानी से समुद्र तक पहुंच देता है और भारत ने इस रूट को विकसित करने में मदद की है, जो कि दोनों देशों को पाकिस्तान को बाइपास करते हुए व्यापार की सुविधा देता है।

भारत के लिए चाबहार का महत्व

1. भारत और ईरान दोनों ही देशों के लिए चाबहार परियोजना का बहुत महत्व है।
2. ओमान सागर में अवस्थित यह बंदरगाह प्रांत की राजधानी जाहेदान से 645 किलोमीटर दूर है और मध्य एशिया व

अफगानिस्तान को सिस्तान-बलूचिस्तान से जोड़ने वाला एक मात्र बंदरगाह है।

3. चाबहार भारत के लिये अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार खोल सकता है। यह बंदरगाह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ जगह है।
4. भारत वर्ष 2003 से इस बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति अपनी रुचि दिखा रहा है।
5. चाबहार गहरे पानी में स्थित बंदरगाह है और यह जमीन के साथ मुख्य भू-भाग से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ सामान उतारने-चढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लगता।
6. चाबहार बंदरगाह के जरिये अफगानिस्तान को भारत से व्यापार करने के लिये एक और रास्ता मिल जाएगा। विदित हो कि अभी तक पाकिस्तान के रास्ते भारत-अफगानिस्तान के बीच व्यापार होता है।

चाबहार के बारे में

- चाबहार ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है। यह एक मुक्त बन्दरगाह है और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है।
- यह ईरान का सबसे दक्षिणी शहर है। इस नगर के अधिकांश लोग बलूच हैं और बलूची भाषा बोलते हैं। यहाँ मौसम सामान्य रहता है और हिंद महासागर से गुजरने वाले समुद्री रास्तों तक भी यहाँ से पहुँच बहुत आसान है।
- भारत ने मई 2015 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह बंदरगाह ईरान के लिए रणनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
- इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा और इस स्थान तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत-कोरिया स्टार्ट-अप हब

समाचारों में क्यों?

- ☛ इन्वेस्ट इंडिया और कोरियाई उद्योग और वाणिज्य मंडल (KCCI) की ओर से 21 फरवरी, 2019 को भारत-कोरिया व्यापार संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- ☛ इसका उद्देश्य कोरियाई कारोबारी समुदाय को भारत में मिली सफलता के लिए बधाई देना तथा उन्हें देश में और अधिक कारोबार के अवसर दिलाना था।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ☛ प्रधानमंत्री ने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कारोबारी समूह को संबोधित किया था।
- ☛ इस अवसर पर सीजे ग्रुप, हुंडई, यंगोन कॉर्पोरेशन, सैमसंग, एलजी, लॉटे ग्रुप, एसके ग्रुप और ह्योसंग सहित 400 से अधिक कोरियाई कम्पनियां और उद्योगपति उपस्थित थे।
- ☛ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर इंडिया-कोरिया स्टार्ट-अप हब और स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया।
- ☛ इंडिया-कोरिया स्टार्ट-अप हब इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। इसमें तीन लाख से अधिक स्टार्ट-अप्स और आकांक्षी उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है।
- ☛ यह हब भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच नवाचार साझा करने और संसाधन वाले बाजारों तक पहुँच का रास्ता उपलब्ध कराएगा।

अन्य पहलू :

1. स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज भारत और कोरिया के स्टार्ट-अप्स के बीच उद्यमिता कौशल का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि वे विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए मिलकर काम कर सकें।
2. ये मुख्य रूप से वित्तीय साख, आर्थिक भविष्यवाणियों, धोखाधड़ी की पहचान, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।

□□□□

प्रश्नपत्र-

3

भारतीय अर्थव्यवस्था

यूनिट :

- ☛ भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।
- ☛ समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।
- ☛ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशु-पालन संबंधी अर्थशास्त्र।
- ☛ बुनियादी ढांचा : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- प्र. कृषक ऋण की समस्या के समाधान तथा कृषक आय को 2022 तक दोगुना करने में प्रधानमंत्री-किसान योजना किस सीमा तक प्रभावकारी है? विश्लेषण करें।
- प्र. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 संपोषणीय तथा समावेशी विकास में कैसे सहायता करेगी? नीति के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करें।
- प्र. प्रधानमंत्री जी-वन योजना के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए बताएं कि यह योजना किस प्रकार से भारत में इथेनॉल को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।
- प्र. नीति आयोग द्वारा आकांक्षीय जिलों में सतत विकास लक्ष्य (SDG) लागू करने के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें।

संभावित प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा) :

- प्र. प्रधानमंत्री जी-वन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें-
 1. यह योजना लिग्नोसेलुलॉसिक बायोमास उत्पादन को वित्तीय मदद देगी।
 2. इस योजना के तहत दो चरणों में वित्तीय मदद की जाएगी
 उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

पीएम-किसान योजना

चर्चा में क्यों?

- ☛ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का शुभारंभ किया गया।
- ☛ लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाए जाने एवं उनके सुनहरे भविष्य के लिए इस योजना को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है।
- ☛ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का शुभारंभ किया है।



- ☛ इस दौरान उन्होंने बटन दबाकर एक करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी।

- इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत चुने हुए किसानों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये।
- विदित हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की घोषणा 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 को की गई थी।
- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/ स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमान्त कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे।

पीएम-किसान योजना के मुख्य बिंदु :

- बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि इसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिये 6,000 रुपए की आय समर्थन राशि दी जाएगी।
- यह राशि 2000 रुपए प्रत्येक को तीन किस्तों में दी जाएगी।
- यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। डीबीटी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और किसानों का समय बचाएगा।
- यह योजना छोटे एवं सीमान्त किसानों (SMF) की आय में संवर्धन के लिए लागू की गई थी। इससे 12 करोड़ छोटे एवं सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने का अनुमान है।
- प्रधानमंत्री-किसान योजना भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। योग्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरण हेतु यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी हो गई है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। 01 फरवरी 2019 तक जिनके भी नाम भूमि रिकॉर्ड में होंगे उन्हें इस योजना का लाभ लेने के पात्र माना जाएगा।

उद्देश्य

- प्रधानमंत्री-किसान योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति पर अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य एवं उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निविष्टियों को प्राप्त करने में एसएमएफ की वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है।
- यह उन्हें ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचाएगा तथा कृषि कार्यकलापों में उनकी नियमितता भी सुनिश्चित करेगा

कैसे नहीं मिलेगा लाभ?

- यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों, किसी संस्थागत पद पर पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व या मौजूदा सदस्य, नगर

निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन में आते हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

- केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
- ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने हिरासर, राजकोट (गुजरात) स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को 1405 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित करने के लिए अपनी मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- राजकोट का यह मौजूदा हवाई अड्डा शहर के मध्य में स्थित है और केवल 236 एकड़ (अनुमानित) भूमि में बना होने के कारण यहां भूमि की बहुत कमी है।
- इस हवाई अड्डे के चारों ओर आवासीय और व्यापारिक भवन स्थित होने के कारण इसकी क्षमता बहुत अवरूद्ध हो गई है। हवाई अड्डे की पूर्वी दिशा में रेलवे लाइन और राजमार्ग होने के कारण रनवे का विस्तार भी संभव नहीं है।
- इस हवाई अड्डे का नगरीय या हवाई विस्तार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कारण मौजूदा हवाई अड्डे की इस वर्तमान स्थिति में बड़ी बॉडी के हवाई जहाजों के परिचालन की कोई संभावना नहीं है।

अन्य बिन्दु :

1. अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के बाद राजकोट गुजरात राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का केंद्र है।
2. यह देश में 35 वां सबसे बड़ा शहरी समुदाय केंद्र है। 2015 के अनुसार इसकी जनसंख्या 1.2 मिलियन से अधिक है। यह दुनिया में 22 वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है।
3. मौजूदा हवाई अड्डे के संबंध में बाध्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजकोट में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने की इच्छा जाहिर की।

4. गुजरात सरकार ने नए हवाई अड्डे के लिए अपेक्षित भूमि की पहचान की है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से नए हवाई अड्डे के विकास, परिचालन और रख-रखाव का अनुरोध किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग

संदर्भ :

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र (MoU) से अवगत कराया गया। इस एमओयू पर 8 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

लाभ :

- इस MoU से आपसी लाभ, समानता एवं पारस्परिकता के आधार पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत और ताजिकिस्तान के बीच सहयोगात्मक संस्थागत संबंधों के लिए एक ठोस आधार की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- इसके तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास व उपयोग पर फोकस किया जाएगा। इससे विभिन्न उपायों के जरिये दोनों देशों के बीच सहयोग और अधिक बढ़ेगा।
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मियों का आदान-प्रदान एवं प्रशिक्षण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं तथा आंकड़ों का आदान-प्रदान, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों का आयोजन एवं कार्य समूहों का गठन, गैर-वाणिज्यिक आधार पर उपकरणों, आवश्यक जानकारीयों एवं प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, पारस्परिक हित वाले विषयों पर संयुक्त अनुसंधान अथवा तकनीकी परियोजनाओं का विकास एवं दोनों ही देशों द्वारा निर्धारित किए गए अन्य तरीके इन विभिन्न उपायों में शामिल हैं।

पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने 'एडीबी से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (NESRIP)' नामक परियोजना प्रस्ताव की संशोधित लागत के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसे 1353.83 करोड़ रुपये की पिछली स्वीकृत लागत के बजाय 2144.56 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के साथ 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया गया।

- यह परियोजना असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एवं त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में 433.7 किलोमीटर लम्बी सड़कों (स्टेट रोड) का निर्माण/ उन्नयन/ सुधार करने से जुड़ी है।
- इसके साथ ही परियोजना की अवधि को अगस्त, 2022 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। एशियाई विकास बैंक (ADB) दो किस्तों में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता मुहैया करा रहा है।

एशिया विकास बैंक

- एडीबी द्वारा अक्टूबर, 2005 में सड़क संबंधी सर्वेक्षण कराया गया था जिससे यह पता चला था कि लगभग 70 प्रतिशत सड़कें खराब हालत में हैं।
- एडीबी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए SMEC इंटरनेशनल पीटीवाई लिमिटेड की सेवाएं लीं। यह रिपोर्ट वर्ष 2008 में पेश की गई।
- 'NESRIP' नामक योजना को CCEA ने 19 मई, 2011 को मंजूरी दी थी जिसका कार्यान्वयन 5 वर्षों के अंदर किया जाना तय हुआ।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी है और उसे ही ADB एवं प्रतिभागी राज्यों के साथ समग्र समन्वय स्थापित करने और परियोजना की प्रगति की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- परियोजना से जुड़े प्रत्येक राज्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय स्तर की एक संचालन समिति एवं आंतरिक परियोजना प्रबंधन इकाई (IPMU) और राज्य स्तरीय संचालन समिति एवं परियोजना प्रबंधन इकाइयों (PIU) की स्थापना की गई है।
- प्रत्येक राज्य में पीआईयू को परियोजना के दैनिक कार्यान्वयन और सड़क विकास कार्यक्रम तथा संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण (IDCB) पहलों में समन्वय स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- PIU में इंजीनियरिंग से जुड़े परियोजना प्रबंधन कार्यों, खरीद, अनुबंध प्रबंधन, पर्यावरणीय नियोजन एवं प्रबंधन, सामाजिक विश्लेषण व प्रबंधन, पुनर्वास संबंधी नियोजन एवं कार्यान्वयन, सड़क रखरखाव, सड़क सुरक्षा और लेखांकन के कार्य करने वाले विभिन्न कर्मी (स्टाफ) शामिल हैं। PIU को अपने परिचालन में निर्माण व पर्यवेक्षण सलाहकारों द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जाता है।
- इस परियोजना को मूर्त रूप दे दिये जाने पर निम्नलिखित कार्य संभव होंगे :
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी,

- जिसे उन्नत राज्य राजमार्गों अथवा जिला सड़कों के जरिये सुगम्य होने वाले जिला/ब्लॉक मुख्यालयों की संख्या के आधार पर मापा जाएगा।
- परियोजना से जुड़ी सड़कों पर सफर करने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा।
 - परियोजना से जुड़ी सड़कों पर परिवहन लागत घट जाएगी। जिसे सार्वजनिक परिवहन से संबंधित यात्री किरायों और माल ढुलाई दरों के आधार पर मापा जाएगा।
 - पूर्वोत्तर के दूरदराज के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। जिससे बागवानी, वन उपजों और पर्यटन के क्षेत्र में कारोबार के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।
 - विशेषकर परियोजना से जुड़े क्षेत्र के साथ-साथ पूरे देश में लोगों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास संभव होगा।
- परियोजना से जुड़ी सड़कों के आसपास (10 किलोमीटर के भीतर) रहने वाले अनुमानित 4.8 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। वहीं, अन्य लोग परिवहन से जुड़े किरायों में कमी होने, आवाजाही की रफ्तार बढ़ जाने इत्यादि से लाभान्वित होंगे।

एयर इंडिया-जेवी के मध्य विनिवेश

संदर्भ :

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया और उसकी अधीनस्थ/जेवी के विनिवेश के लिए विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) नाम से एक SPV का मालखाने में जमा कार्यशील पूंजीगत ऋण के भंडारण के लिए सृजन किया गया है।
- इस पूंजीगत ऋण का चार सहायकों एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (AIATSL), एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (AASL), एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL) और होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (HCIL) के अलावा एयर इंडिया की कम महत्व वाली परिसंपत्तियों पेंटिंग और कलाकृतियों तथा अन्य गैर परिचालित परिसंपत्तियों में योगदान नहीं है।
- नागर विमानन मंत्रालय ने नये एसपीवी के सृजन के लिए आदेश जारी किया है।
- SPV, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) को

22 जनवरी, 2018 को शामिल किया गया था।

- SPV के निदेशक मंडल में सीएमडी, एयर इंडिया लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, दीपम (DIPAM) के संयुक्त सचिव और निदेशक (वित्त) एयर इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।
- अब तक एक सहायक AIATSL को AIAHL और एयर इंडिया लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौते के अनुसार AIAHL को हस्तांतरित किया गया है, जो शर्तों के अनुसार है जिसमें ऋणदाता की मंजूरी शामिल है।
- AIAHL के विनिवेश के लिए प्राथमिक सूचना ज्ञापन (PIM) AIAHL द्वारा 12 फरवरी, 2019 को जारी किया गया था जिसमें रूचि प्रकटन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च, 2019 है।
- सरकार ने निम्नलिखित को नवगठित SPV को हस्तांतरित करने का फैसला किया है :
 - एयर इंडिया लिमिटेड का 29,464 करोड़ रुपये का ऋण।
 - अधीनस्थ कंपनियां जो एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश यानी AIATSL, AIESL, AASL का हिस्सा नहीं हैं उन्हें SPV में डाल दिया जायेगा।
 - एयर इंडिया लिमिटेड की कम महत्व वाली परिसंपत्तियां, पेंटिंग और कलाकृतियां और गैर-परिचालन परिसंपत्तियां।

प्रभाव :

- इस मंजूरी से एयर इंडिया की अधीनस्थ कंपनियों AIATSL, AIESL, AASL और HCIL की माल गोदामी नव गठित SPV कंपनियों को एयर इंडिया से आसान हो जाएगी।
- विनिवेश की प्रक्रिया का इस्तेमाल एयर इंडिया की कार्यशील पूंजी देनदारी को शुरू करने के लिए किया जा सकेगा जिसे एसपीवी में रखी गई किसी परिसंपत्ति का सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

फेम इंडिया योजना

संदर्भ :

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
- कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी। यह योजना मौजूदा 'फेम इंडिया वन' का विस्तारित संस्करण है।
- 'फेम इंडिया वन' योजना 1 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी।

वित्तीय प्रभाव:

- ☛ फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।
- ☛ इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

प्रभाव:

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
2. इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है।
3. यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।

विवरण :

- ☛ बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर।
- ☛ इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाना, ऐसे खर्च राज्य और शहरी परिवहन निगमों द्वारा दिया जाना।
- ☛ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत 3 वॉट और 4 वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि।
- ☛ 2 वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में मुख्य ध्यान निजी वाहनों पर केन्द्रित रखना।
- ☛ इस योजना के तहत 2 वॉट वाले 10 लाख, 3 वॉट वाले 5 लाख, 4 वॉट वाले 55,000 वाहन और 7000 बसों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने की योजना है।
- ☛ नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जिनमें अत्याधुनिक लिथियम आयन या ऐसी ही अन्य नई तकनीक वाली बैट्रियां लगाई गई हों।
- ☛ योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
- ☛ इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों, छोटे शहरों और पर्वतीय राज्यों के शहरों में तीन किलोमीटर के अंतराल में 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।
- ☛ बड़े शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है।
- ☛ ऐसे राजमार्गों पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर दोनों तरफ भी ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019**चर्चा में क्यों?**

- ☛ नई राष्ट्रीय खनिज नीति अधिक प्रभावी नियमन सुनिश्चित करेगी। यह खनन क्षेत्र के स्थायी विकास में सहायता प्रदान करेगी तथा इससे परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद मिलेगी।

उद्देश्य :

- ☛ राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घवधि खनन अभ्यासों को समर्थन प्रदान करती है।
 - राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो खनन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, जैसे-
 - आरपी/पीएल धारकों के लिए पहले अस्वीकार के अधिकार की शुरूआत
 - अन्वेषण कार्य के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना
 - राजस्व-साझा के आधार पर समग्र आरपी-सह- पीएल-सह-एमएल के लिए नये क्षेत्रों में नीलामी
 - खनन कंपनियों में विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन तथा खनन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए खनन-पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति तथा समर्पित खनिज कॉरीडोर का निर्माण
 - 2019 नीति में प्रस्ताव दिया गया है कि खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इससे निजी क्षेत्र को खनन-संपत्ति अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा।
 - यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति के निर्माण से निजी क्षेत्र बेहतर नीतियां बनाने में सक्षम होगा और व्यापार में स्थिरता आएगी।
 - नीति में सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए आरक्षित क्षेत्रों को भी युक्तिसंगत बनाने का उल्लेख किया गया है।
 - ऐसे क्षेत्रों जहां खनन गतिविधियों की शुरूआत नहीं हुई है की नीलामी होनी चाहिए। इससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
 - नीति में निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक मानदंडों के आधार पर टैक्स, लेवी और रॉयल्टी को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

अन्य पहलू :

- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में कुछ बदलाव किये गए हैं जैसे नीति के विजन के रूप में मेक इन इंडिया और लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देना।
- खनिजों के विनियमन के लिए ई-प्रशासन, आई-टी सक्षम प्रणाली, जागरूकता तथा सूचना अभियान आदि को शामिल किया गया है। स्वीकृति मिलने में विलंब होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे प्रावधान शामिल किये गए हैं जिससे उच्च-स्तर पर मामलों को निपटाया जा सकेगा।
- MNP, 2019 का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है और इसके लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। खनन पट्टा-भूमि प्रणाली के तहत खनिज संसाधनों तथा पट्टे पर दी गई भूमि का डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
- नई नीति के तहत खनिजों के परिवहन के लिए तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीति में खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित खनिज कॉरीडोर का उल्लेख किया गया है।
- परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और निवासियों के न्यायसंगत विकास के लिए जिला खनिज निधि के उपयोग की बात कही गई है।
- MNP, 2019 में खनिज क्षेत्र के लिए लंबी अवधि के आयात-निर्यात नीति का प्रस्ताव दिया गया है। इससे खनिज गतिविधि में स्थिरता आएगी और बड़े पैमाने पर होने वाली वाणिज्यिक खनिज गतिविधि में निवेश आकर्षित होगा।
- नीति, 2019 में अंतर-पीढ़ी समानता के विचार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के कल्याण की बात कही गई है।
- नीति में अंतर-मंत्रालय निकाय के गठन का भी उल्लेख है जो सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।

सेज अधिनियम, 2005 में संशोधन**संदर्भ :**

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 2 की उप-धारा (ट) के तहत व्यक्ति की परिभाषा को संशोधित कर उसके स्थान पर ट्रस्ट को शामिल करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाए जाने को मंजूरी दे दी है।
- नई व्यवस्था होने से किसी भी ट्रस्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा।
- इसके अलावा केन्द्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना

जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करने की सहूलियत भी मिल जाएगी।

प्रभाव :

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 के तहत वर्तमान में किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई लगाने की अनुमति नहीं है। अधिनियम में संशोधन से किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई खोलने का अधिकार मिल जाएगा।
2. इसके अलावा केन्द्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित कर सकेगी। इससे विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना**संदर्भ :**

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है।
- इसके तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेलुलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती है, उसके लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है।

वित्तीय प्रभाव :

- जी-वन योजना के लिए 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 1969.50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
- परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल 1969.50 करोड़ रुपये की राशि में से 1800 करोड़ रुपये 12 वाणिज्यिक परियोजनाओं की मदद के लिए, 150 करोड़ रुपये प्रदर्शित परियोजनाओं के लिए और बाकी बचे 9.50 करोड़ रुपये केन्द्र को उच्च प्रौद्योगिकी प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिए जाएंगे।

विवरण :

- इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी :
 1. **पहला चरण (2018-19 से 2022-23) :** इस अवधि में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
 2. **दूसरा चरण (2020-21 से 2023-24) :** इस

अवधि में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को मदद की व्यवस्था की गई है।

- ☛ परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है।
- ☛ इसके लिए उसे वाणिज्यिक परियोजनाएं स्थापित करने और अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
- ☛ EBP कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मदद पहुंचाने के अलावा निम्नलिखित लाभ भी होंगे -
 1. जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।
 2. जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प लाकर उत्सर्जन के CHG मानक की प्राप्ति।
 3. बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का समाधान और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
 4. दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
 5. बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।
 6. दूसरी पीढ़ी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण।
- ☛ योजना के लाभार्थियों द्वारा बनाए गए इथेनॉल की अनिवार्य रूप से तेल विपणन कम्पनियों को आपूर्ति, ताकि वे ईबीपी कार्यक्रम के तहत इनमें निर्धारित प्रतिशत में मिश्रण कर सकें।

अन्य पहलू :

- ☛ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2022 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ☛ इथेनॉल की कीमत ज्यादा रखने और इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद 2017-18 के दौरान इथेनॉल की खरीद 150 करोड़ लीटर ही रही, हालांकि यह देशभर में पेट्रोल में इथेनॉल के 4.22 प्रतिशत मिश्रण के लिए पर्याप्त है।
- ☛ इसी वजह से बायोमास और अन्य कचरों से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्राप्त करने की संभावनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तलाशी जा रही हैं। इससे ईबीपी कार्यक्रम

के तहत किसी तरह होने वाली कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी-वन योजना इसी को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।

- ☛ इसके तहत देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल क्षमता विकसित करने और इस नए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।
- ☛ इस योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है।
- ☛ इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक प्रोजेक्ट डेवलपर्स को अपने प्रस्ताव समीक्षा के लिए मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति को सौंपने होंगे।
- ☛ समिति जिन परियोजनाओं की अनुशांसा करेगी उन्हें मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

पृष्ठभूमि:

- ☛ भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जरिए पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है।
- ☛ वर्तमान में EBP 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कम्पनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है।
- ☛ मौजूदा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीड स्ट्याक उत्पादों जैसे सेलुलोसेस और लिग्नोसेलुलोसेस जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इंडिया 2019

संदर्भ :

- ☛ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने घोषणा की कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इंडिया 2019 - सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले देश भर के 49 विभिन्न केंद्रों में एक साथ 2 और 3 मार्च, 2019 को होगा, जो 36 घंटे चलेगा। इसमें 34 हजार से अधिक विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- ☛ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इंडिया 2019 की शुरुआत 29 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें छात्रों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता को प्रोत्साहित किया गया।
- ☛ इसके तहत शासन और जीवन गुणवत्ता में सुधार के तरीकों को शामिल किया गया था। इसके जरिये छात्रों सहित सभी

नागरिकों को यह अवसर प्रदान किया गया कि वे भारत की समस्याओं का हल करने के लिए अभिनव विचार पेश करें।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, MIC, I4C और परसिस्टेंट सिस्टम्स के सहयोग से स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन इंडिया 2019 का आयोजन कर रहा है।
- इसमें 96 उद्योगों तथा केंद्र सरकार के 18 मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी हो रही है, जिसके कारण स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन इंडिया 2019 अपने पिछले संस्करणों के मुकाबले अधिक विशाल है।
- इसमें दो उप-संस्करण शामिल हैं - सॉफ्टवेयर संस्करण, जो 36 घंटे की सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्धा है जिसका आयोजन 2-3 मार्च, 2019 को किया जा रहा है।
- हार्डवेयर संस्करण के तहत हार्डवेयर समाधान तैयार करना है और इसकी प्रतिस्पर्धा बाद में इसी साल होगी।
- सॉफ्टवेयर संस्करण वाले ग्रैंड फिनाले के दौरान हजारों प्रौद्योगिकी छात्रों की टीमें विभिन्न उद्योगों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सामने आने वाली समस्याओं का अभिनव डिजिटल समाधान तैयार करेंगे।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

चर्चा में क्यों?

- औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) जनवरी 2019 में 6 अंक बढ़कर 307 अंक के स्तर पर आ गया।
- एक माह में हुए परिवर्तन के आधार पर CPI-IW में दिसम्बर, 2018 से लेकर जनवरी, 2019 तक की अवधि के दौरान (+)1.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान इसमें (+)0.70 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली थी।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- मौजूदा सूचकांक में सर्वाधिक वृद्धि आवासीय समूह के कारण आई है जिसने कुल परिवर्तन में (+) 5.16 प्रतिशत का योगदान दिया है।
- विभिन्न वस्तुओं के आधार पर चावल, अरहर दाल, ताजा मछली, बकरे का मांस, नारियल तेल, भिंडी, टमाटर, फूल/फूलों की माला आदि सूचकांक में वृद्धि के कारक हैं, लेकिन प्याज, बैंगन, गोभी, गाजर, फूल गोभी, फली, लौकी, रसाई गैस, बिजली शुल्क आदि ने सूचकांक को नियंत्रित किया, जिसके फलस्वरूप सूचकांक में नीचे का दबाव देखा गया।

- मासिक CPI-IW द्वारा मापी जाने वाली महंगाई दर पर वार्षिक आधार पर गौर करने से पता चलता है कि यह जनवरी, 2019 में 6.60 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले महीने 5.24 प्रतिशत और पिछले साल के समान महीने में 5.11 प्रतिशत थी।
- इसी तरह खाद्य महंगाई दर (+) 0.97 प्रतिशत रही, जबकि यह पिछले महीने (-) 0.96 प्रतिशत और पिछले वर्ष के समान महीने में 3.36 प्रतिशत थी।

अन्य पहलू :

- केन्द्रीय स्तर पर नागपुर में सर्वाधिक 21 अंकों की वृद्धि दर्ज की। इसके बाद नासिक (17 अंक) अमृतसर, किलोन, झरिया (प्रत्येक 13 अंक) तथा जयपुर (12 अंक) ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की।
- इसी तरह तीन केन्द्रों में 11 अंकों, 7 केन्द्रों में 10 अंकों, 3 केन्द्रों में 9 अंकों, 5 केन्द्रों में 8 अंकों, 9 केन्द्रों में 6 अंकों, 6 केन्द्रों में 5 अंकों, 7 केन्द्रों में 4 अंकों, 7 केन्द्रों में 3 अंकों, 7 केन्द्रों में 2 अंकों तथा 6 केन्द्रों में 1 अंक की वृद्धि देखी गई।
- 4 केन्द्रों में 2 अंकों की गिरावट तथा 2 केन्द्रों में 1 अंक की गिरावट देखी गई। शेष 4 केन्द्रों में सूचकांक स्थिर रहे।
- 35 केन्द्रों में सूचकांक दरअसल अखिल भारतीय सूचकांक से ज्यादा रहे हैं, जबकि 42 केन्द्रों में सूचकांक राष्ट्रीय औसत से कम रहे हैं।
- नोट:** राउरकेला केन्द्र का सूचकांक अखिल भारतीय सूचकांक के बराबर रहा।

आकांक्षी जिलों में SDG लागू करने हेतु सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

- देश के आकांक्षी जिलों को वैश्विक सतत विकास लक्ष्य (SDG) से जोड़ने के लिए नीति आयोग एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय है- आकांक्षी जिलों में एसडीजी कार्यान्वयन।
- सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक विकास लक्ष्यों व इनके सर्वोत्तम अभ्यास के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। राज्य की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संसाधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है।
- नीति आयोग उन 18 आकांक्षी जिलों को सम्मानित करेगा जो तेजी से कार्य पूरे कर रहे हैं। इन जिलों को पूरक कोष उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके लिए नवंबर, 2018 से जनवरी 2019 के दौरान अंतिम रूप दिए गए डेल्टा रैंकिंग को आधार बनाया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

1. डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य व पोषण, कृषि और जल संसाधन, शिक्षा, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेश और ढांचागत सुविधा के क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन को दर्शाता है।
2. नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों की घोषणा करेंगे।
3. सम्मेलन में स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव सुश्री रीना रे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव सुश्री प्रीति सूदन और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपर महानिदेशक शामिल होंगे।
4. इसके अलावा केंद्रीय विभागों के प्रमुख सचिवों तथा सभी 112 आकांक्षी जिलों के प्रमुख अधिकारियों के भी इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।

अटल नवाचार मिशन**चर्चा में क्यों?**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन (AIM) जारी रखने, स्कूली स्तर पर बड़ी सफलता को ध्यान में रखते हुए, 10,000 स्कूलों के लिये अटल टिकरिंग लैबों के विस्तार के लिये अटल नवाचार मिशन द्वारा वर्ष 2019-20 तक 1,000 करोड़ रुपये तक की लागत पूरी करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- अटल नवाचार मिशन के तहत देश में नवाचार को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिये बहुविध कार्यक्रम शामिल हैं।
- हजारों स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अटल टिकरिंग लैब स्थापित किये जा रहे हैं।
- विश्वविद्यालयों और उद्योगों के लिये विश्वस्तरीय अटल इंक्यूबेशन केंद्र (AIC) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र (ACIC) स्थापित किये जा रहे हैं।
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) के माध्यम से राष्ट्रीय प्रासंगिकता और सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में उत्पाद विकास बढ़ावा देना।

वित्तीय लागत

- प्रत्येक ATL को पहले वर्ष में 12 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है और ATL उपकरणों के रखरखाव तथा संचालनात्मक खर्च के तौर पर अगले चार वर्षों के लिये अधिकतम 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिये जाते हैं।
- प्रत्येक चयनित अटल इंक्यूबेशन केंद्र (AIC) को प्रतिवर्ष के

हिसाब से 3 से 5 वर्षों में अधिकतम 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा, जो उपलब्धियों की समीक्षा और प्रमाण के आधार पर होगा।

- अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) के तहत इन्नोवेटर्स को वाणिज्यीकरण और प्रौद्योगिकी अनुदान के रूप में अधिकतम 1 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

प्रभाव :

- मिशन के तहत अनेक सशक्त और अग्रगामी कदम उठाये गये हैं, जैसे अटल टिकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन केंद्र। इन पर काफी जोर दिया गया है।
- अटल नवाचार मिशन की मदद और तकनीकी सहायता से भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों ने नवाचार से जुड़ी गतिविधियां शुरू की हैं।
- अटल टिकरिंग लैब कार्यक्रम के तहत, 2020 तक 10,000 से अधिक स्कूलों में इन लैबों की स्थापना होने की संभावना है।
- देशभर में 100 से अधिक अटल इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित होने की संभावना है, जिससे पहले के 5 वर्षों में कम से कम प्रत्येक 50-60 स्टार्टअपों को सहायता मिलेगी।
- 100 से अधिक इन्नोवेटर्स/स्टार्टअपों को अपने नवाचारों को उत्पाद का रूप देने में कुछ सहायता मिलने की संभावना है।
- मंत्रालयों के माध्यम से समर्थित अन्य कार्यक्रमों से और भी अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
- प्रत्येक इंक्यूबेटर से प्रत्येक 4 वर्ष में प्रौद्योगिकी चालित 50-60 नवाचार स्टार्टअपों का पोषण होने की आशा है।
- इस प्रकार 100 से अधिक इंक्यूबेटर्स की स्थापना से 5,000-6,000 नवाचार स्टार्टअपों का पोषण हो सकेगा और नये इंक्यूबेटर्स की स्थापना से इसकी संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।
- इन नवाचार चालित स्टार्टअपों से रोजगार की अत्यधिक संभावना है।

रणनीति का कार्यान्वयन और लक्ष्य

- अटल नवाचार मिशन के तहत खुली, प्रतियोगिता, ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी का चयन किया जाता है और सीधे तौर पर अनुदान का वितरण किया जाता है।
- इतना ही नहीं, अटल टिकरिंग लैबों और अटल इंक्यूबेशन केंद्रों आदि में क्षमता निर्माण के लिये मौजूद अटल इन्नोवेशन मिशन के विशेषज्ञ और नेटवर्क से देशभर में अनेक प्रकार की जनसंख्या आपस में जुड़ती है।
- इसके अलावा, कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी अटल नवाचार मिशन के लाभार्थियों से जुड़े हैं, जिससे शिक्षाजगत, नवाचार और स्टार्टअप प्रणाली के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी

का प्रवाह सुनिश्चित होने के साथ-साथ अटल नवाचार मिशन की पहलों की सफलता सुनिश्चित होती है।

- अब तक, देशभर में 5441 अटल टिकरिंग लैबों का चयन किया गया है, जिनमें से 623 जिलों के 2171 अटल टिकरिंग लैबों को अपने संबंधित स्कूलों में लैबों की स्थापना के लिये अनुदान राशि की पहली किस्त का भुगतान हो चुका है।
- देशभर में 101 अटल इंक्यूबेशन केंद्रों का चयन किया गया है, जिसमें से 31 केंद्रों को अनुदान की पहली किस्त का भुगतान किया गया है।
- देशभर में 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) की शुरुआत की गयी है और 800 से अधिक आवेदन प्राप्त किये गये हैं।
- प्रत्येक एनआईसी से 2-3 विजेताओं का चयन किया जायेगा और निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा और प्रमाण के आधार पर तीन किस्तों में अधिकतम 1.0 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
- अटल नवाचार मिशन के मेंटर ऑफ चेंज कार्यक्रम में अटल टिकरिंग लैबों की सफलता सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से, विभिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमि के सुयोग्य वेटरों का चयन किया जाता है, जो अनेक कौशलों के बारे में अटल टिकरिंग लैबों के छात्रों को संरक्षण प्रदान करते हैं।
- ये मेंटर स्कूल के प्रशासकों का भी सहयोग करते हैं, ताकि अटल नवाचार मिशन के निर्देशों के अनुसार अटल टिकरिंग लैबों का संचालन सुनिश्चित हो।
- अब तक 2500 से अधिक मेंटर पूरी सक्रियता से 1,300 से अधिक स्कूलों में छात्रों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि :

- अटल नवाचार मिशन का लक्ष्य देशभर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता का एक वातावरण तैयार करना और उसे बढ़ावा देना है।
- वर्ष 2015 के बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, इस मिशन को नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया है।

क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी

चर्चा में क्यों?

- आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल एन्क्लेव तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU) की 'बगैर उपयोग' एवं 'कम उपयोग' वाली हवाई पट्टियों, हेलीपैड और

वाटर एयरोड्रोम के पुनरुद्धार व विकास हेतु समयसीमा एवं दायरा बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

- इस पर कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके लिए भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता प्राप्त होगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- इसके परिणामस्वरूप 'बगैर उपयोग' एवं 'कम उपयोग' वाले हवाई अड्डों के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू होने पर छोटे शहरों/कस्बों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाएगी तथा इससे रोजगार सृजन एवं संबंधित बुनियादी ढांचागत विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी आर्थिक विकास को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

विवरण :

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) के लिए बोलियों के अब तक के दो दौर में मंत्रालय को एयरलाइनों की ओर से व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
- 'उड़ान' से जुड़ी बोलियों के प्रथम दौर में 31 मार्च, 2017 को 'बगैर उपयोग' एवं 'कम उपयोग' वाले 43 हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के लिए पांच एयरलाइन ऑपरेटरों को कुल मिलाकर 128 मार्ग (रूट) सौंपे गए।
- RCS से जुड़ी बोलियों के दूसरे दौर में एयरलाइन ऑपरेटरों की ओर से और भी ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इसके तहत जनवरी, 2018 में 15 चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को 325 रूट सौंपे गए। ये रूट 86 प्रस्तावों के अंतर्गत आते हैं।
- RCS-उड़ान वर्जन 1.0 और 2.0 के दौरान 66 हवाई अड्डों और 31 हेलीपोर्टों ('बगैर उपयोग' वाले 28 हेलीपोर्ट एवं 'बगैर उपयोग' वाले 3 एयरपोर्ट) की पहचान की गई।
- उड़ान वर्जन 3.0 के दौरान तटीय क्षेत्रों में पर्यटन संभावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर कई पर्यटन रूटों और विभिन्न वाटर एयरोड्रोम को कनेक्ट करने के लिए समुद्री विमानों को इसमें शामिल किया गया।

पृष्ठभूमि :

- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में अन्य बातों के अलावा 'बगैर उपयोग' एवं 'कम उपयोग' वाले हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की घोषणा की।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), सिविल एन्क्लेव और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU) के 'बगैर उपयोग' एवं 'कम उपयोग' वाले 50 हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के पुनरुद्धार से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- ☞ हवाई पट्टियों/हवाई अड्डों का पुनरुद्धार 'मांग आधारित' होगा, जो विभिन्न रियायतें प्रदान करने के लिए एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर व्यक्त की जाने वाली ठोस प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा।
- ☞ इसका कारण यह है कि हवाई अड्डों की वित्तीय संभाव्यता अथवा लाभप्रदता पर विशेष जोर दिए बिना ही इन्हें विकसित किया जाएगा।
- ☞ भारत की तटीय रेखा अत्यंत विशाल है जो लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। इसमें ऐसे अनेक जल स्थल भी शामिल हैं जिनका उपयोग वाटर एयरोड्रोम की स्थापना के लिए किया जा सकता है।
- ☞ भूमि पर अवस्थित हवाई अड्डों के साथ-साथ विभिन्न वाटर एयरोड्रोम के नेटवर्क से हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ये विशेषकर स्थानीय स्तर की कम दूरी वाली यात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे।
- ☞ अतः AAI की विमानन विशेषज्ञता और राज्य सरकार के सहयोग से भारत में अनेक वाटर एयरोड्रोम को विकसित/संचालित करने का निर्णय लिया गया।

रेलवे सौर पैनल

चर्चा में क्यों?

- ☞ हरित ऊर्जा के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए भारतीय रेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।
- ☞ इसके तहत वो रेलवे ट्रैक के किनारे बड़े पैमाने पर सोलर पैनल स्थापित करेगा।
- ☞ रेलवे का इरादा अपनी जरूरत की सारी बिजली स्वयं बनाने और इसके लिए सौर पैनलों का उपयोग करने का है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ☞ शुरू में रेलवे 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इसके लिए 'मेक इन इंडिया' के तहत 18 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना तैयार की जा रही है।
- ☞ धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा ताकि अंततः 20 हजार मेगावाट बिजली का सौर ऊर्जा के जरिए उत्पादन किया जा सके।
- ☞ अभी रेलवे तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली की सालाना खपत करती है। जिस पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का खर्च आता है। अगले चार वर्षों में पूर्ण विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप इसे बढ़कर दो गुना हो जाने की संभावना है।
- ☞ उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस प्रोजेक्ट में देश-विदेश की सभी कंपनियों को शामिल किया जाएगा।
- ☞ लेकिन निविदा की शर्तों में 'मेक इन इंडिया' के साथ निश्चित प्रतिशत भारतीय उपकरणों और कलपुर्जों के इस्तेमाल की शर्त शामिल होगी।

- ☞ इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई विदेशी कंपनी संपूर्ण सोलर पैनल का निर्माण भारत में न करे तो भी चुनिंदा भारतीय कलपुर्जों का उपयोग कर वो परियोजना के लिए पात्र हो सकती है।
- ☞ परियोजना के लिए दो चरणों में लगभग दस राज्यों के लिए 2000-2000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।
- ☞ सरकार की सोलर पैनल खरीदने वाली नोडल एजेंसी सोलर एनर्जी कारपोरेशन (SECI) ये टेंडर जारी करेगी।
- ☞ पहले चरण में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और ओडिशा के लिए टेंडर मांगे जाएंगे।
- ☞ जबकि दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्य शामिल होंगे।
- ☞ रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष सितंबर में कैबिनेट द्वारा रेलवे के पूर्ण विद्युतीकरण को हरी झंडी दिए जाने के बाद हमारे लिए अपनी खुद की बिजली पैदा करना जरूरी हो गया है।
- ☞ विद्युतीकरण का निर्णय तिहरे मकसद से लिया गया है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के साथ ऊर्जा पर खर्च घटेगा तथा डीजल का उपयोग बंद होने से पर्यावरण भी स्वच्छ होगा।
- ☞ अभी लगभग 67 हजार रूट किलोमीटर ट्रैक में 31 हजार रूट किलोमीटर यानी 46 फीसदी ट्रैक ही विद्युतीकृत है। इस कारण दो अरब 80 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है।
- ☞ 2022 तक विद्युतीकरण होने पर इसके बंद हो जाने से सालाना 14 हजार करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
- ☞ अभी रेलवे को एक यूनिट बिजली के लिए 8-10 रुपये अदा करने पड़ते हैं। खुद के सौर ऊर्जा उत्पादन से ये लागत घटकर 3-4 रुपये प्रति यूनिट रह जाएगी।
- ☞ सौर पैनल स्थापित करने के लिए रेलवे के पास रेलवे लाइनों के दोनों तरफ की तकरीबन 47,300 एकड़ खाली जमीन है।
- ☞ एक अध्ययन के अनुसार इस पर सोलर पैनल लगाकर 20 हजार मेगावाट तक की बिजली बनाई जा सकती है।
- ☞ इसलिए शुरुआती प्रोजेक्ट के बाद रेलवे दूसरी कंपनियों और राज्य सरकारों को भी ट्रैक के किनारे सौर ऊर्जा उत्पादन का मौका देकर धन कमाएगी।

डिजिटल बैंकिंग

चर्चा में क्यों?

- ☞ बैंकिंग व्यवस्था के डिजिटल होने का लाभ चार बड़े बैंकों को ही मिल पाया है। देश में डिजिटल बैंकिंग कारोबार के दो तिहाई से अधिक हिस्से पर इन्हीं चार बैंकों का कब्जा है।
- ☞ इन चारों में तीन निजी क्षेत्र के और एक सरकारी बैंक है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- एक रिपोर्ट के मुताबिक HDFC बैंक, ICICI बैंक, AXIS बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन का हिस्सा इनके कुल कारोबार में 75 से 87 फीसदी के करीब है।
- ट्रांजैक्शन की संख्या के लिहाज से देखें तो इन चारों में एकमात्र सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अव्वल है।
- लेकिन ट्रांजैक्शन की कीमत के लिहाज से भारतीय स्टेट बैंक तीनों बैंकों से पीछे है। इस मामले में चारों बैंकों में HDFC बैंक का स्थान पहला है।
- देश में 2015-18 के बीच हुए वित्तीय ट्रांजैक्शन पर इलारा कैपिटल की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- जबकि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल इस अवधि में 14.2 प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की कीमत के लिहाज से देखें तो क्रेडिट कार्ड के मामले में 37 प्रतिशत और डेबिट कार्ड में 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट के मुताबिक डेबिट कार्ड के मामले में ट्रांजैक्शन की वृद्धि नोटबंदी की अवधि के दौरान अधिक रही। वैल्यू के लिहाज से RTGS और NEFT दोनों के ट्रांजैक्शन में HDFC बैंक शीर्ष दस बैंकों में सबसे आगे रहा है।
- इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक का स्थान रहा है। तीसरे स्थान पर एक्सिस और ICICI बैंक में होड़ रही। RTGS ट्रांजैक्शन के मामले में एक्सिस बैंक तीसरे स्थान पर रहा तो NEFT के मामले में ICICI बैंक ने बाजी मारी।
- बैंकिंग ट्रांजैक्शन के मामले में रिपोर्ट में मोबाइल बैंकिंग का जिक्र भी किया गया है।
- इसके मुताबिक NEFT और RTGS के मुकाबले मोबाइल बैंकिंग के कुल कारोबार का आकार सिकुड़ रहा है।
- पिछले एक साल में PYTM ने इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई है। SBI की हिस्सेदारी इस बाजार में 19.9 प्रतिशत की है तो PYTM 19.5 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
- HDFC बैंक 6.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ इनसे काफी पीछे है। हालांकि ट्रांजैक्शन की कीमत के लिहाज से अभी भी SBI और HDFC बैंक सबसे आगे हैं। दोनों की हिस्सेदारी 16-16 प्रतिशत है।

ऑडिटों पर नियामकीय घरे में वृद्धि**चर्चा में क्यों?**

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आगामी 1 अप्रैल से बैंकों के अंकक्षकों (ऑडिटर) के साथ तिमाही आधार पर औपचारिक बैठकों की शुरुआत करेगा।

- केंद्रीय बैंक पहली बार इस तरह का दूरगामी कदम उठाने जा रहा है। इस तरह आरबीआई ऑडिटों पर नियामकीय घेरा बढ़ाने जा रहा है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- अब ऑडिटर यह दावा नहीं कर सकते कि वे खास समय बाद ही बैंकों का बहीखाता टटोलते हैं।
- इस बारे में RBI के बैंकिंग निगरानी विभाग के अंकक्षण प्रभाग की तरफ से बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों, अनुपालन विभागों और ऑडिटों को सूचना भेजी गई है।
- सूचना में कहा गया है कि ऑडिटों के साथ होने वाली तिमाही बैठक में आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, उधार लेने वालों की पहचान, फंसे कर्ज, संचालन एवं अपवाद, सदिग्ध लेनदेन, तकनीक, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जैसे मामलों पर चर्चा होगी।
- इस बैठक की अध्यक्षता व्यक्तिगत बैंक का प्रभार देखने वाले RBI का वरिष्ठ अधिकारी करेगा। इस बैठक में संबंधित बैंक के अधिकारी उपस्थिति नहीं रहेंगे।
- फिलहाल RBI ऑडिटों के साथ सालाना और आवश्यकतानुसार बैठक करता है और पूरे साल में ऐसी बैठकों के लिए कोई संरचनात्मक ढांचा नहीं है।
- इस वजह से आरबीआई को किसी खास समय में बैंकों में चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं मिलती है।
- मौजूदा समय में जब ऑडिटर बैंकों की वित्तीय गतिविधियों पर सालाना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है तो उसके बाद RBI उनके साथ बैठक करता है।
- 1 अप्रैल, 2019 से नई पहल प्रभावी होने से स्थिति बदल जाएगी। इस नए कदम की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि पहले बैंकों द्वारा घोषित गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) और RBI की समीक्षा रिपोर्ट में खासा अंतर दिखता था।
- इसके अलावा बैंकों में पर्याप्त अनुपालन और संचालन मानकों का भी अभाव दिखा। RBI ने जब परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की तो ये सभी मुद्दे सामने आए।
- RBI और ऑडिटों के बीच औपचारिक संवाद में इन समस्याओं का समाधान होगा।
- दिसंबर, 2015 में जब परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की शुरुआत हुई और 18 अप्रैल, 2017 को प्रावधानों पर खुलासे पर परिपत्र आने के बाद ऑडिटर का काम-काज संतोषजनक नहीं रहा था।
- बैंकों को भेजे पत्र में उन्हें उनके बहीखाते में RBI द्वारा समीक्षा किए गए अतिरिक्त प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं या सकल NPA या दोनों का खुलासा करने के लिए कहा।

- जब RBI ने फंसे ऋणों के संबंध में ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई तो ऑडिटर्स ने केंद्रीय बैंक का ध्यान इस बात पर खींचा कि परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की घोषणा और प्रावधानों में भिन्नता पर परिपत्र आने के बाद दो बार ही बैंक निरीक्षण हुए हैं।

FAME-2 कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के FAME-2 कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की निगरानी, आवंटन तथा क्रियान्वयन के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है।
- इस योजना का मकसद स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। भारी उद्योग मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि परियोजना क्रियान्वयन और आवंटन समिति के प्रमुख मंत्रालय के सचिव होंगे।
- इसके अन्य सदस्यों में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा बिजली और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव होंगे।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार समिति का गठन योजना के तहत आवंटन, निगरानी और क्रियान्वयन करना है।
- समिति के लिए नियम और शर्तों में योजना के विभिन्न घटकों तथा उप-घटकों के कवरेज मानकों में संशोधन, मूल्य और प्रौद्योगिकी के रख के हिसाब से सालाना आधार पर या उससे पहले मांग प्रोत्साहनों की समीक्षा, कोष आवंटन सीमा में संशोधन, प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन की सीमा की समीक्षा शामिल है।
- फेम इंडिया योजना दूसरे चरण के तहत 10,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम का क्रियान्वयन एक अप्रैल, 2019 से तीन साल के लिए किया जाना है।
- देश में बिजली चालित वाहनों की तेजी से स्वीकार्यता और विनिर्माण (फेम-द्वितीय) के तहत कारखाने के गेट पर अधिकतम मूल्य वाले 10 लाख पंजीकृत दोपहिया वाहन 20,000-20,000 रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- योजना के तहत कारखाने के गेट पर पांच लाख रुपये तक के पांच लाख ई-रिक्शा को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- फेम-द्वितीय के तहत 15 लाख रुपये तक के 35,000 बिजली चालित चार पहिया वाहनों को 1.5-1.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।

- इसी तरह कारखाने गेट पर 15 लाख रुपये तक दाम वाले 20,000 हाइब्रिड चार पहिया वाहनों को 13,000-13,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इसी तरह दो करोड़ रुपये तक के मूल्य की 7,090 ई-बसों में प्रत्येक को 50-50 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपये, 2020-21 में 5,000 करोड़ रुपये और 2021-22 में 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

IBBI और SEBI के मध्य आईबीसी सहमति

चर्चा में क्यों?

- भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने 19 मार्च को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ एक सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- IBBI और सेबी दरअसल दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 और इससे संबंधित नियम-कायदों पर कारगर ढंग से अमल किए जाने के पक्ष में हैं, जिन्होंने कर्ज (डेट) एवं इक्विटी के आपसी ताल्लुकात को नए सिरे से परिभाषित किया है और जिनका उद्देश्य उद्यमिता एवं डेट मार्केट को बढ़ावा देना है।
- IBBI और सेबी ने सहमति पत्र के तहत संहिता के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई है। हालांकि, इस संबंध में लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को ध्यान में रखना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- दोनों पक्षों के बीच सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा। हालांकि, इस संबंध में लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को ध्यान में रखना होगा।
- एक-दूसरे के साथ उपलब्ध संसाधनों को उस हद तक साझा किया जा सकेगा। जिस हद तक यह व्यवहार्य और कानूनन उचित होगा।
- आपसी हितों वाले विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर बैठकें की जाएंगी। एक-दूसरे की जवाबदेही पर असर डालने वाली नियामकीय आवश्यकताएं, प्रवर्तन से जुड़े मामले, अनुसंधान एवं डेटा विश्लेषण और सूचना प्रौद्योगिकी एवं डेटा को साझा करना इन विषयों में शामिल है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा अन्य मुद्दा इनमें शामिल है जिनके बारे में संबंधित पक्षों को यह प्रतीत होता है कि उनकी संबंधित वैधानिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में वह एक-दूसरे के हित में होगा।

4. एक-दूसरे के कर्मचारियों या स्टाफ को प्रशिक्षण देना, जिससे प्रत्येक पक्ष को सामूहिक संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए दूसरे पक्ष के मिशन की बेहतर समझ हो सके।
 5. दिवाला से जुड़े प्रोफेशनलों और वित्तीय ऋणदाताओं का क्षमता निर्माण करना।
 6. संहिता के विभिन्न प्रावधानों, इत्यादि के तहत मुश्किलों से जूझ रहे विभिन्न तरह के कर्जदारों के लिए त्वरित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अहमियत एवं आवश्यकता के बारे में वित्तीय ऋणदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना।
- ❖ एमओयू पर सेबी के कार्यकारी निदेशक श्री आनंद बैवर और IBBI के कार्यकारी निदेशक श्री रितेश कावड़िया ने मुम्बई में हस्ताक्षर किए।

आयुष्मान भारत योजना

चर्चा में क्यों?

- ❖ गरीब परिवारों को इलाज के लिये पांच लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा कवर देने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत अब इलाज करने वाले अस्पतालों के प्रदर्शन पर नजर रखी जायेगी और उसके मुताबिक उन्हें 'स्टार रेटिंग' दी जायेगी।
- ❖ योजना का संचालन करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तरफ से 19 मार्च को यह जानकारी दी गई।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ❖ देश के करीब 11 करोड़ गरीब परिवारों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में नकदी रहित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने वाली PM-JAY यानी 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत अब तक देश भर में 15,000 अस्पताल जुड़ चुके हैं।

प्रदर्शन आधारित भुगतान प्रणाली

- ❖ योजना में शामिल अस्पतालों ने गुणवत्ता सुधार के लिये प्रदर्शन आधारित भुगतान प्रणाली भी विकसित की है।
- ❖ भुगतान प्रणाली को इस तरह डिजाइन किया है कि अस्पताल इलाज में लगातार गुणवत्ता में सुधार लाए और मरीजों को उसका लाभ मिले। इसमें NABH के तहत पूर्ण मान्यता प्राप्त अस्पतालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।
- ❖ आयुष्मान भारत योजना की घोषणा पिछले साल के आम बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को योजना की औपचारिक शुरुआत की।

- ❖ दिसंबर 2018 में देश के 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ योजना लागू करने के लिये सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- ❖ हालांकि, दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना ने अभी तक योजना को नहीं अपनाया।
- ❖ योजना लागू होने के पिछले पांच माह के दौरान 13 लाख से अधिक लाभार्थी 1,700 करोड़ रुपये से अधिक का चिकित्सा लाभ उठा चुके हैं।

'रेल दृष्टि' नामक नई वेबसाइट लॉन्च

संदर्भ :

- ❖ केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 25 फरवरी 2019 को यात्रियों के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया, जिसे वे ट्रेन के आने-जाने के समय पर निगरानी के साथ-साथ देश में कहीं भी ट्रेन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे।
- ❖ डैशबोर्ड को लॉन्च करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अब लोग कहीं भी जाते वक्त मात्र एक स्वाइप पर भारतीय रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल कर सकते हैं।



- ❖ यह डैशबोर्ड यात्रियों, रेलवे के अधिकारियों व स्टाफ के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसके जरिए यात्री रेलवे से जुड़ी हर तरह की जानकारी अब एक स्वाइप से प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्य बिंदु :

- ❖ 'रेल-दृष्टि' डैशबोर्ड को रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (CRIS) द्वारा विकसित किया गया है और इस पर <https://raildrihti.cris.org.in> के जरिए पहुंचा जा सकता है।
- ❖ इस वेबसाइट की मदद से रेल मंत्री मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों से होने वाली कमाई, मालगाड़ियों में सामान की लदाई और उसे उतारने, ट्रेनों के समय पर पहुंचने, बड़ी परियोजनाओं, शिकायतों, ट्रेनों का लाइव स्टेटस, स्टेशनों की जानकारी और अन्य तमाम चीजें देख सकेंगे।
- ❖ ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता से संबंधित लगातार शिकायतों के संबंध में डैशबोर्ड को भारतीय रेल खानपान एवं

पर्यटन निगम (IRCTC) के बेस रसोईघरों से भी जोड़ दिया गया है, जिससे लाइव वीडियो के जरिए IRCTC रसोईघरों में क्या चल रहा है, उसकी निगरानी की जा सकेगी।

- भारतीय रेलवे के मालभाड़ा व्यवसाय के बारे में जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। यह ग्राहकों को अपने खेप पर नजर रखने में मदद करती है।
- यह विभिन्न टर्मिनलों और संबद्ध शीर्ष अधिकारियों, मांगपत्र स्थिति, वर्तमान मालभाड़ा दरों, रेक आवंटन योजना, लागू प्रतिबंधों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

यात्रियों का लाइव स्टेटस :

- डैशबोर्ड ट्रेनों में यात्रा कर रहे आरक्षित एवं अनारक्षित यात्रियों का लाइव स्टेटस भी मुहैया कराएगा। इसके साथ यह सुविधा किसी भी वक्त ट्रेनों की सटीक स्थिति भी मुहैया कराएगी।
- इस ई-दृष्टि का लक्ष्य रेलवे को अधिक पारदर्शी बनाना है। साथ ही यात्री रेल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे।

रेल सेवाओं को और बेहतर बनाने के मांगे सुझाव :

- रेल मंत्री ने कहा कि 'ई-दृष्टि' का लक्ष्य है कि भारतीय

रेलवे को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए, उन्होंने लोगों से रेल सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु सुझाव भी मांगे हैं।

- इसे कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप किसी भी चीज से और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।
- इसकी मदद भारतीय रेल के कई विभागों के कार्यों की स्थिति की रियल टाइम बेसिस पर जानकारी मिल सकेगी।

यात्रियों को होगा फायदा :

- 'ई-दृष्टि' के तहत ट्रेन में मिलने वाले हर खाने के पैकेट पर बार कोड और फोन नंबर लिखा होगा।
- उस बार कोड के जरिये आप लाइव देख सकते हैं कि खाना किस तरह के किचन में तैयार किया गया है और वहां कितनी साफ सफाई है। अगर आप उस किचन से संतुष्ट नहीं हैं तो raildrishti.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।
- रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में समझौता हुआ है।
- समझौते के तहत रेलवे के अतिरिक्त 45 एकड़ जमीन धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए जाएंगे। धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस जमीन पर री-डेवलपमेंट का काम करेगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

यूनिट :

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- प्र. सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति- 2019 सॉफ्टवेयर उद्योग की समस्या के समाधान तथा भारत में इस उद्योग की विकास के लक्ष्य को पूर्ण करने में किस हद तक सहायक है। चर्चा करें।
- प्र. रोबोटिक्स क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग की चर्चा करते हुए इससे जुड़े नैतिक पहलुओं की समालोचनात्मक व्याख्या करें।

संभावित प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा) :

- प्र. ग्रीन जेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें-

1. यह अंतरिक्षयान का ईंधन है।

2. इसका विकास IIT कानपुर द्वारा किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- प्र. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के स्टैंडर्ड एंड लेब्लिंग कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करें-

(a) इसमें एक से लेकर सात स्टार रेटिंग दी जाती हैं।

(b) इस कार्यक्रम में 11 उत्पाद अनिवार्य तथा 10 उत्पाद स्वैच्छिक श्रेणी में हैं।

(c) अनिवार्य श्रेणी उत्पादों में ट्रांसफॉर्मर नहीं हैं।

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति-2019

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति-2019 को मंजूरी दे दी ताकि भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के तौर पर विकसित किया जा सके।

प्रमुख प्रभाव :

- सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र को इसके नवाचारों, बौद्धिक संपदा (IP) सृजन और उत्पादकता में विशाल मूल्य संवर्धन वृद्धि से परिभाषित किया जाता है।
- इसमें इस क्षेत्र के राजस्व और निर्यातों को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने, मूलभूत रोजगार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्यम संबंधी अवसरों को पैदा करने, और डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की संभावना है। जिससे समावेशी और स्थायी विकास में बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त होगा।

इसमें शामिल व्यय

- इस नीति के अंतर्गत सोची गई योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगले सात वर्षों के लिए 1500 करोड़ रुपये के व्यय को शुरुआती तौर पर शामिल किया गया है।
- इन 1500 करोड़ रुपये को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (SPDF) और अनुसंधान एवं नवाचार निधि में विभाजित किया जाएगा।

क्रियान्वयन रणनीति और लक्ष्य

- इस नीति के अंदर जिस रूपरेखा की परिकल्पना की गई है। उससे देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं और तौर-तरीकों के सूत्रीकरण की राह बनेगी।
- सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (NPSP-2019) के सपने को हासिल करने के लिए इस नीति में निम्नलिखित पांच मिशन रखे गए हैं -
 - बौद्धिक संपदा (IP) से संचालित होने वाले एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहित करना जिससे 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना बढ़ोतरी तक पहुंचा जा सके।
 - सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना जिसमें टीयर-2 और टीयर-3 नगरों व शहरों में ऐसे 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं और 2025 तक सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर 35 लाख

लोगों के लिए रोजगार निर्मित करना।

- सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक प्रतिभा समूह का निर्माण करना। इसके लिए ये किया जाएगा -
 - क) 10,00,000 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को अतिरिक्त कुशलताओं से सुसज्जित करना
 - ख) 1,00,000 स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और
 - ग) 10,000 विशेषीकृत पेशेवरों का निर्माण करना जो नेतृत्व प्रदान कर सके।
- एकीकृत आईसीटी आधारभूत ढांचे, मार्केटिंग, इनक्यूबेशन, अनुसंधान व विकास / परीक्षण मंच और परामर्श सहयोग वाले 20 क्षेत्रवार व रणनीतिक रूप से स्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- इस नीति की योजना और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उन्हें विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी। जिसमें सरकार, शिक्षा समुदाय और उद्योग की भागीदारी होगी।

ईकोफ्रेंडली 'ग्रीन जेल'

चर्चा में क्यों?

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आइआईटी) कानपुर ने स्वदेशी अंतरिक्ष यान के लिए लाजवाब ईंधन- ग्रीन जेल तैयार कर दिखाया है।
- गगनयान मिशन की दिशा में यह खोज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- IIT के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने अंतरिक्ष यान के लिए जो विशेष ईंधन 'ग्रीन जेल' तैयार किया है, वह न केवल उसकी रफ्तार दोगुनी करेगा बल्कि मौजूदा ईंधन के मुकाबले 40 फीसदी प्रदूषण कम करेगा।
- इसरो द्वारा मिले इस प्रोजेक्ट को IIT के वैज्ञानिकों ने दो साल में पूरा कर दिखाया।
- सभी परीक्षण सफल रहने के बाद 'फ्यूल' रिसर्च जनरल में यह शोध प्रकाशित हुआ।
- ग्रीन जेल को केरोसिन और जेलिंग एजेंट के साथ मिलाकर तैयार किया गया है।
- अभी स्पेस शटल उड़ाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पैरा ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल हो रहा है।

- ❖ कई बार अंतरिक्ष यान पर अधिक दबाव से लिक्विड ईंधन लीक हो जाता है। इससे शटल के फटने का खतरा बढ़ जाता है।
- ❖ वहीं नया ईंधन जेल के रूप में है। शटल पर अधिक दबाव के दौरान भी यह स्थिर रहता है। इंजन का तापमान कम रखने में भी सहायता करेगा।
- ❖ इससे ईंधन लीकेज या शटल फटने की आशंका नहीं रहेगी। IIT के वैज्ञानिक मेटल और नैनो मेटेरियल का इस्तेमाल कर ग्रीन जेल के 'सुपर एनर्जेटिक प्रोपेलेंट' वर्जन पर भी शोध कर रहे हैं।
- ❖ ग्रीन जेल का प्रयोग सेटेलाइट लांचिंग व्हीकल में भी किया जा सके, यह परीक्षण भी हो रहा है।
- ❖ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यह प्रोजेक्ट आइआइटी कानपुर को दिया था।
- ❖ IIT के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने इसमें दो वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त कर दिखाई।
- ❖ तकनीक को पेटेंट करा रिपोर्ट इसरो को भेज दी गई है। अब ग्रीन जेल फ्यूल का सुपर एनर्जेटिक वर्जन बनाने पर काम हो रहा है।
- ❖ अनिवार्य श्रेणी में आने वाले उत्पादों में रूम एयर कंडीशनर, एलईडी लैंप, रंगीन टीवी, ट्रांसफार्मर आदि शामिल हैं।
- ❖ वहीं स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत सीलिंग पंखें, एलपीजी स्टोव, कंप्यूटर (नोटबुक, लैपटॉप), प्रिंटर स्कैनर आदि जैसे ऑफिस में उपयोग होने वाले उपकरण आदि शामिल हैं।
- ❖ बिजली मंत्रालय के अनुमान के अनुसार स्टार रेटिंग वाले माइक्रोवेव ओवन और वाशिंग मशीन के उपयोग से 2030 तक 3 अरब यूनिट से अधिक बिजली की बचत होगी।
- ❖ यह 2030 तक 24 लाख टन कार्बन डाई आक्साइड (CO₂) के उत्सर्जन में कमी लाने के बराबर है।
- ❖ BEE ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुगमता लाने के मकसद से कंपनियों के लिये ऑनलाइन पंजीकरण तथा मंजूरी के लिये प्लेटफॉर्म बनाया है।
- ❖ इस मौके पर BEE ने देश में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिये रणनीतिक दस्तावेज 'उन्नति' (राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संभावनाओं का इस्तेमाल) जारी किया।
- ❖ इस दस्तावेज में देश को ऊर्जा दक्ष देश (2017-31) बनाने का खाका प्रस्तुत किया गया है।
- ❖ पीडब्ल्यूसी इंडिया के सहयोग से तैयार BEE की इस रणनीतिक दस्तावेज को विभिन्न विभागों, संगठनों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इस पर सभी पक्षों से राय मांगी गयी है।

BEE स्टार रेटिंग

चर्चा में क्यों?

- ❖ सरकार ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टार रेटिंग के दायरे को बढ़ाते हुए माइक्रोवेव ओवन को भी इसमें शामिल किया है।
- ❖ साथ ही वाशिंग मशीन को पानी खपत से जुड़े संशोधित मानदंड के साथ इस योजना में फिर से शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ❖ बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा तैयार स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग (स्टार रेटिंग) कार्यक्रम के तहत उत्पादों को ऊर्जा खपत के आधार पर बिजली बचत की स्टार रेटिंग दी जाती है।
- ❖ ऐसे उत्पादों पर एक से लेकर पांच तक स्टार के निशान दिये जाते हैं।
- ❖ फिलहाल ये दोनों उत्पाद 31 दिसंबर 2020 तक स्वैच्छिक आधार पर इस कार्यक्रम के दायरे में रहेंगे।
- ❖ वाशिंग मशीन पहले से स्टार रेटिंग कार्यक्रम की स्वैच्छिक श्रेणी में है। लेकिन BEE ने इसमें बिजली खपत के साथ अब पानी के कुशल उपयोग को लेकर भी मानदंड निर्धारित किया है।
- ❖ BEE के स्टार रेटिंग कार्यक्रम के तहत फिलहाल 10 उत्पाद अनिवार्य श्रेणी में जबकि 11 स्वैच्छिक श्रेणी में हैं।

कांभैट ड्रग्स

चर्चा में क्यों?

- ❖ गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मियों में से 90 प्रतिशत कुछ घंटे में दम तोड़ देते हैं।
- ❖ इसे ध्यान में रखते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की चिकित्सकीय प्रयोगशाला 'कांभैट कैजुअलिटी ड्रग्स' लेकर आई है, जिससे घायल जवानों को अस्पताल में पहुंचाए जाने से पहले तक के बेहद नाजुक समय को बढ़ाया जा सके, जिसे घायल जवानों की जान बचाने के लिहाज से 'गोल्डन' समय कहा जाता है।



महत्वपूर्ण तथ्य :

- DRDO की प्रयोगशाला इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस ने यह नई दवा बनाई है।
- 'कॉम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स' नाम की यह दवा घायल जवानों की जान बचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- गंभीर रूप से जखमी सुरक्षाकर्मियों में से 90% कुछ घंटे में दम तोड़ देते हैं, इसलिए यह दवा काफी अहम है।
- घायल को अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले तक का बेहद नाजुक समय 'गोल्डन टाइम' को यह दवा बढ़ा देगी।
- DRDO के वैज्ञानिकों के अनुसार इन दवाओं में रक्तस्राव वाले घाव को भरने वाली दवा, अवशोषक ड्रेसिंग और ग्लिसरेटेड सैलाइन शामिल हैं।
- ये सभी चीजें जंगल, अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध और आतंकवादी हमलों की स्थिति में जीवन बचा सकती हैं।

माइक्रोवेव सेंसर से हिमालय की निगरानी**चर्चा में क्यों?**

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी में इस सेमेस्टर से दो नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इसमें ऑप्टिकल एवं माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग से हिमालय क्षेत्र की निगरानी और जियोलॉजी एवं जियोमॉर्फोलॉजी शामिल हैं।
- दोनों कोर्सों से भावी इंजीनियर हिमालय क्षेत्र में भूकंप, भूस्खलन और बादल फटने जैसी विषम परिस्थितियों से निपटने में निपुण बनेंगे।
- दोनों कोर्स का संचालन संस्थान में अमेरिका के विजिटिंग फ़ैकल्टी स्मिड कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रो. रमेश पी. सिंह करेंगे।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ऑप्टिकल एवं माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग से हिमालय क्षेत्र की निगरानी के इस कोर्स का लक्ष्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के व्यापक प्रसार के मूल सिद्धांतों के साथ भूमि, भूमि आवरण, वनस्पति और हिम/हिमनद के बारे में गहन विमर्श करना है।
- विद्यार्थी संबद्ध डाटा का विश्लेषण कर तीव्र बदलाव और वातावरण/ मौसम परिवर्तन के कारणों का पता लगा कर हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण में हो रहे बदलावों के बारे में गहरी समझ का विकास करेंगे।
- कोर्स संस्थान में एमएस, एमटेक और पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए है। कोर्स बादल फटने, हिमस्खलन और तीव्र वर्षा जैसी अत्यधिक विषम परिस्थितियों से जुड़े भूमि, भूमि आवरण, वातावरण और मौसम विज्ञान के मानकों को आपस में जोड़ कर समझने पर केंद्रित होगा।

- कोर्स में इन मानकों के ऑप्टिकल और माइक्रोवेव गुणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हिमालय क्षेत्र अक्सर बादल से ढक जाता है जो ऑप्टिकल सेंसर से पता नहीं चलता है।
- माइक्रोवेव सेंसरों से अत्यधिक तीव्र बदलाव की इन घटनाओं का मानचित्रण भी किया जा सकता है।
- रिमोट सेंसिंग के डाटा का उपयोग कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में हो सकता है। जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी कोर्स का मकसद विद्यार्थियों को चट्टान बनने, चट्टान के प्रकार और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बुनियादी कांसेप्ट के बारे में जानकारी देना है।
- इसमें पृथ्वी की सतह बनने की प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए बुनियादी जानकारी दी जाएगी।
- पृथ्वी के निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक्स, चट्टान के प्रकार, चक्रीय विकास के साथ विभिन्न प्रकार की चट्टानों के मुख्य खनिजों, उनकी उपलब्धता, कमजोरी और गुण आदि को सामने रखना।
- साथ ही, पृथ्वी के विभिन्न फीचर्स बनने के बारे में और उन्हें नियंत्रित करने वाली परिघटनाओं के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा।
- यह कोर्स अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों, विशेष कर सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक त्वचा**चर्चा में क्यों**

- वैज्ञानिकों ने जेलीफिश से प्रेरित होकर एक खास इलेक्ट्रॉनिक त्वचा बनाने में सफलता हासिल की है।
- इस त्वचा में सेल्फ हीलिंग खूबी है यानी किसी खरोंच को यह खुद रिपेयर करने में सक्षम है।
- इसकी मदद से वाटर रेसिस्टेंट टचस्क्रीन से लेकर पानी में तैरने में सक्षम कई तरह के रोबोट बनाना संभव हो सकता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने इस खास पदार्थ को तैयार किया है। यह जेलीफिश की ही तरह पानी में अपनी खरोंचों को खुद ठीक करने में सक्षम है।
- NUS के अनुसार 'अभी जितने सेल्फ हीलिंग पदार्थ हैं, वे पारदर्शी नहीं हैं और पानी में सही काम नहीं करते हैं। इन खामियों के कारण इनका इस्तेमाल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नहीं हो पाता था, जिन्हें नम जगह पर प्रयोग के लिए बनाया जाता है।'
- वैज्ञानिकों ने एक फ्लोरोकार्बन आधारित पॉलीमर युक्त जेल और फ्लोरीन की अधिकता वाले लिक्विड की मदद से यह खास पदार्थ बनाने में सफलता हासिल की है।

- ❖ इस पदार्थ का इस्तेमाल 3D प्रिंटिंग में भी किया जा सकता है। इस खूबी के चलते इससे पारदर्शी सर्किट बोर्ड बनाना भी संभव हो सकता है।
- ❖ इस पदार्थ का प्रयोग कई तरह के सॉफ्ट रोबोट बनाने में करना संभव होगा।
- ❖ सॉफ्ट रोबोट आमतौर पर उन इलेक्ट्रॉनिक्स को कहा जाता है, जो मानव टिश्यू की तरह काम करने में सक्षम होते हैं। कई तरह के कृत्रिम अंग बनाने में इनकी अहम भूमिका रहती है।

इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम करने में सहायक

- ❖ दुनिया में हर साल टूटे हुए मोबाइल, टैबलेट आदि के कारण लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा तैयार हो जाता है।
- ❖ अगर इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऐसे पदार्थ से बनाया जा सके, जो खुद को रिपेयर करने में सक्षम हो, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा को नियंत्रित करना संभव हो सकता है।

चीन में रोबोट कर रहा चौकीदारी

चर्चा में क्यों?

- ❖ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर बनाने के बाद चीन ने घरों की निगरानी करने वाला रोबोट भी विकसित कर लिया है।
- ❖ राजधानी बीजिंग में एक आवासीय समुदाय ने अपनी तरह का पहला 'रोबोट चौकीदार' तैनात किया है जो लोगों की तस्वीरें कैद करने के साथ ही उनसे बातचीत भी कर सकता है।
- ❖ इसके बाद वहां अब किसी व्यक्ति को रात में चौकीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ❖ बीजिंग एयरोस्पेस ऑटोमैटिक कंट्रोल इंस्टीट्यूट (BAACI) के परियोजना निदेशक लियु गांगजुन के अनुसार, रोबोट 'मेइबाओ' ना केवल गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखता

है बल्कि बीजिंग में रह रहे मेइयुआन समुदाय के लोगों को उपयोगी जानकारी भी मुहैया कराता है।

- ❖ इस रोबोट का दिसंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक परीक्षण किया जा रहा है।
- ❖ BAACI ने चीन अकेडमी ऑफ लांच व्हीकल टेक्नोलॉजी की मदद से इसे विकसित किया है।
- ❖ इस रोबोट में बायोलॉजिकल रिकॉग्निजेशन, बिग डाटा एनालिसिस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम व अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।
- ❖ इसकी मदद से यह पैदल चलने वालों की जानकारी का सही ढंग से विश्लेषण कर पाता है।
- ❖ यह रोबोट मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकता है। इस रोबोट की सबसे खास बात है कि यह मजेदार कहानियां सुनाने के अलावा गाने भी बजा सकता है जिससे बच्चे उससे बात करने के लिए आकर्षित होते हैं।

भारत में 4 करोड़ ग्रामीण लोग धातु-प्रदूषित पानी पीते हैं: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- ❖ हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग धातु-प्रदूषित जल ग्रहण कर रहे हैं।
- ❖ यह लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं जिसमें किसी ना किसी रूप में धातु मिली हुई होती है।
- ❖ इस सर्वेक्षण में पाया गया कि प्रदूषित जल में पाए जाने वाली प्रमुख धातुएं फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट है।
- ❖ धातु प्रदूषित जल के आंकड़ों में पश्चिम बंगाल और राजस्थान टॉप पर पाए गये हैं।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु :

- ❖ मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक धातु से प्रदूषित पानी पीने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। यहां 39 प्रतिशत लोग इस जल का सेवन करने को मजबूर हैं।
- ❖ इसी क्रम में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है जहां 65 लाख ग्रामीण पीने के लिये प्रदूषित जल का प्रयोग करते हैं।
- ❖ इस जल के सेवन से उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है, जबकि बिहार में 43 लाख लोग दूषित जल का सेवन कर रहे हैं।
- ❖ इस सर्वेक्षण में जुटाए गये आंकड़ों में 16 राज्यों में एक लाख से अधिक ग्रामीण आबादी प्रभावित है। जबकि केवल सात राज्यों पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, पंजाब, असम, उत्तर

- प्रदेश और त्रिपुरा में 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं।
- इसे अलग-अलग श्रेणी के अनुसार बांटते हुए कहा गया है कि फ्लोराइड प्रदूषण के क्षेत्र में 33 लाख, लवणता प्रदूषण के क्षेत्र में 25 लाख तथा नाइट्रेट प्रदूषण के क्षेत्र में 7 लाख आबादी के साथ राज्यों की सूची में राजस्थान टॉप पर है।
- आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग 96 लाख लोग आर्सेनिक और 49 लाख लोग आयर्न से प्रदूषित जल का सेवन कर रहे हैं।



- पीने के पानी में सबसे अधिक प्रकार की धातुएं पंजाब में पाई गईं। यहां सभी तरह की धातुओं को पानी में देखा गया जबकि पश्चिम बंगाल में नाइट्रेट की मिलावट नहीं मिली थी।

पृष्ठभूमि :

- मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र ने आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिये सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों और पाइपलाइन की अनंतिम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये मार्च 2016 में 1,000 करोड़ रुपए जारी किये हैं।
- वर्ष 2017 में मंत्रालय ने 27,544 आर्सेनिक / फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन शुरू किया था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति राज्य सूची का विषय है, इसलिये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण आबादी हेतु सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

‘क्विक रिएक्शन मिसाइल’ का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारत ने 26 फरवरी 2019 को जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल (QRSAM) का ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने सेना के लिए विकसित की जा रही इन दो मिसाइलों का परीक्षण किया है।
- इस मिसाइल का निर्माण DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) और भारत डायनामिक लिमिटेड (BDL) के साथ मिलकर भारतीय सेना के लिए किया है।
- इस मिसाइल को भारतीय रक्षा पंक्ति में बेहद अहम और खास माना जा रहा है।

क्विक रिएक्शन मिसाइल की विशेषताएं

- हर मौसम में काम करने वाली इस स्वदेशी मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, जो तुरंत टारगेट को ध्वस्त कर सकती है।
- परीक्षण को पूरी तरह से सफल बताते हुए DRDO के एक अधिकारी ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया गया।
- अलग-अलग ऊंचाइयों और स्थितियों से दो मिसाइलों का परीक्षण किया गया।
- दो मिसाइलों का परीक्षण भिन्न परिस्थितियों में किया गया और दोनों कामयाब रहे। इस दौरान मिसाइल की एरोडायनामिक्स, प्रोपल्सन, ढांचागत प्रदर्शन और उच्च मैनुवर क्षमता को परखा गया।
- परीक्षण के दौरान मिसाइल के रडार, इलेक्ट्रोऑप्टिकल सिस्टम्स, टेलीमीट्री, आदि के परीक्षण पैमाने सटीक आंके गये।
- इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना जमीन से ही किसी भी संदिग्ध एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी-शिप मिसाइल, यूएवी, बैलेस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कॉम्बैट जेट को हवा में ही नेस्तानाबूत कर सकती है।



- इससे पहले डीआरडीओ ने लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली बराक-8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।
- बराक-8 मिसाइल को नेवल शिप से लॉन्च किया जा सकता है। यह परीक्षण भी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में किया गया था।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

यूनिट :

- ☛ संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।
- ☛ संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- प्र. बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) द्वारा 2030 तक इसके दोगुना होने की चेतावनी के संदर्भ प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु भारत में जारी प्रयासों की समालोचनात्मक चर्चा करें।
- प्र. भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर रहा है जिसमें सबसे बड़ा योगदान वाहन द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण है। फेम इंडिया कार्यक्रम इस समस्या के समाधान में कहां तक सफल होगा। चर्चा करें।

2030 तक दोगुना हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

- ☛ अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक प्लास्टिक प्रदूषण दोगुना हो जाएगा।
- ☛ ये न केवल इंसान, बल्कि जानवर और प्रकृति के लिए भी खतरनाक है।
- ☛ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में 1950 से 2016 के बीच के 66 वर्षों में जितना प्लास्टिक जमा हुआ है, उतना अगले केवल एक दशक में जमा हो जाएगा।
- ☛ इससे महासागरों में प्लास्टिक कचरा 30 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। समुद्र में 2030 तक प्लास्टिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का उत्सर्जन तिगुना हो जाएगा, जो हृदय संबंधी बीमारियों को तेजी से बढ़ाएगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ☛ हर साल उत्पादित होने वाले कुल प्लास्टिक में से महज 20 फीसदी ही रिसाइकिल हो पाता है।
- ☛ 39 फीसद को जमीन के अंदर दबाकर नष्ट किया जाता है और 15 फीसदी जला दिया जाता है।
- ☛ प्लास्टिक के जलने से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) की मात्रा 2030 तक तिगुनी हो जाएगी, जिससे हृदय रोग के मामले में तेजी से वृद्धि होने की आशंका चिंता का सबब बनी हुई है।
- ☛ WWF का लक्ष्य 2030 तक स्ट्रॉ और पॉलिथिन बैग जैसी सिर्फ एक बार प्रयोग की जा सकने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को इस्तेमाल से हटाने का है।
- ☛ निम्न उत्पादन लागत होने की वजह से हर साल बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उत्पादन होता है जिसमें से आधी मात्रा को तीन साल इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है और प्लास्टिक

की नई चीजों का इस्तेमाल होने लगता है।

- ☛ रिसाइकिल में कमी और अधिक मांग के चलते हर साल प्लास्टिक उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है।
- ☛ हर साल तकरीबन 10.4 करोड़ टन प्लास्टिक मलबा समुद्र में समा जाता है। 2050 तक समुद्र में मछली से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े होने का अनुमान है।
- ☛ प्लास्टिक के मलबे से समुद्री जीव बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कछुओं की दम घुटने से मौत हो रही है और व्हेल इसके जहर का शिकार हो रही हैं।
- ☛ प्रशांत महासागर में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच समुद्र में कचरे का सबसे बड़ा ठिकाना है।
- ☛ यहां पर 80 हजार टन से भी ज्यादा प्लास्टिक जमा हो गया है।
- ☛ WWF अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बैठक से पहले, प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए सभी देशों को बुला रही है।
- ☛ इसका लक्ष्य सांस लेने पर शरीर के अंदर पहुंचने वाले प्लास्टिक के बेहद सूक्ष्म कण और भोजन व पानी के जरिये पेट में जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक टुकड़ों से लेकर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की मांग को 2030 तक 40 फीसदी तक घटाना है।
- ☛ प्लास्टिक एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक समाधान की जरूरत है।
- ☛ यही कारण है कि महासागरों में समाने वाले प्लास्टिक मलबे पर कानूनी रूप से नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र से समझौते की कोशिश की जा रही है।

विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में 22 भारत के

चर्चा में क्यों?

- ☛ एयर विजुअल और ग्रीनपीस द्वारा जारी वायु प्रदूषण की रिपोर्ट में वर्ष 2018 के 12 महीनों में दुनिया के 73 देशों के 3095

शहरों में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

- रिपोर्ट में टॉप 10 प्रदूषित शहरों में भारत के अलावा 02 पाकिस्तान और 01 चीन का शहर शामिल है।
- अगर दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो इसमें 22 शहर भारत के, 05 शहर चीन के, 02 शहर पाकिस्तान के और 01 शहर बांग्लादेश का शामिल है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- NCR का प्रमुख औद्योगिक शहर गुडगांव को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है।
- वर्ष 2018 में गुडगांव का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 135.8 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) द्वारा निर्धारित मानक से तीन गुना ज्यादा है और बेहद खराब श्रेणी में आता है।
- नवंबर व दिसंबर 2018 में गुडगांव में PM 2.5 का स्तर 200 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा सबसे प्रदूषित शहरों की Top-10 सूची में एनसीआर का शहर गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिवाड़ी और नोएडा भी शामिल है।
- इनके अलावा पटना और लखनऊ भी Top-10 सूची में क्रमशः सातवें और दसवें नंबर पर हैं।

भारत-चीन लगभग बराबर

- रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने वायु प्रदूषण की स्थिति में काफी सुधार किया है।
- बावजूद अगर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो यहां भारत और चीन लगभग बराबरी पर हैं।
- Top-50 में भारत के 25 शहर, चीन के 22 शहर, पाकिस्तान के 2 और बांग्लादेश का 1 शहर शामिल है।

सबसे प्रदूषित देश में तीसरा स्थान

- सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान तीसरा है। इस वर्ग में सबसे ऊपर बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान है।
- इसके बाद क्रमशः अफगानिस्तान, बहरीन, मंगोलिया, कुवैत, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और नाइजीरिया Top-10 शहरों में शामिल है। सबसे प्रदूषित देशों की सूची में चीन 12वें स्थान पर है।

दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी

- दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में शामिल है।
- इसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, चौथे नंबर पर बहरीन की राजधानी मनामा, पांचवें नंबर पर मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर, छठवें नंबर पर कुवैत की राजधानी

कुवैत सिटी, सातवें नंबर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू, आठवें नंबर पर चीन की राजधानी बीजिंग, नौवें नंबर पर यूएई की राजधानी अबुधाबी और दसवें स्थान पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता सबसे प्रदूषित राजधानियों में शामिल है।



70 लाख मौतें हो रहीं प्रदूषण से

- प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में प्रति वर्ष तकरीबन 70 लाख लोगों की असमय मौतें हो रही हैं।
- अर्थव्यवस्था पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। साल दर साल मौतें और नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो विश्व के लिए एक बड़ी चिंता है।
- ग्रीनपीस संस्था में दक्षिण-पूर्वी एशिया के कार्यकारी निदेशक येब सनो (Yeb Sano) के अनुसार वायु प्रदूषण से हमारी आजीविका और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
- प्रदूषण से प्रतिवर्ष दुनिया भर में होने वाली आकस्मिक मौतों से करीब 225 बिलियन डॉलर्स (करीब 15,859 अरब रुपये) का श्रमिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा प्रदूषण की वजह से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर से ज्यादा दवाओं पर खर्च हो जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन है मुख्य वजह

- रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण की वजह जलवायु परिवर्तन भी है।
- पर्यावरण में बदलाव और जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं से पूरी दुनिया वायु प्रदूषण से जूझ रही है।
- इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और ईंधन के तौर पर कोयले का प्रयोग भी प्रदूषण की प्रमुख वजहों में शामिल है।
- प्रदूषण की सबसे कॉमन वजह ईंधन के तौर पर कोयले, तेल और गैस का अत्यधिक उपयोग करना और जंगलों का तेजी से कटना है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र

चर्चा में क्यों?

- दिन प्रतिदिन बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए

वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी खोज की है। इस खोज की मदद से ध्वनि प्रदूषण पर लगभग नियंत्रण पाया जा सकेगा।

- अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार एक खुले छल्ले जैसी डिवाइस से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- यह छल्ला मैथमेटिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। इस तकनीक के माध्यम से हवा के प्रवाह को जारी रखकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- यद्यपि वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण कम करने वाले बैरिकेड्स हैं जिन्हें हम साउंड बफेल कहते हैं, लेकिन इनकी एक कमी है कि यह वायु के प्रवाह को रोक देते हैं।
- चूँकि ध्वनि हमें वायु के माध्यम से ही सुनाई पड़ती है इसलिये वायु का प्रवाह रुकने से ध्वनि भी थम जाती है।
- यह ऐसा ही है जैसे कान में कोई ऑब्जेक्ट लगा लेने से वायु अंदर नहीं आती जिसकी वजह से आवाज भी नहीं आती।
- मैथमेटिक का उपयोग करके एकाॅस्टिक मेटामैटेरियल (ध्वनिक मेटामेट्री) का एक डिजाइन तैयार किया गया।
- एकाॅस्टिक मेटामैटेरियल एक ऐसी सामग्री है जिसके माध्यम से ध्वनि तरंगों को नियंत्रित और निर्देशित किया जा सकता है। साथ ही तरंगों में हेरफेर भी की जा सकती है।
- शोधकर्ताओं ने उन आयामों और विशिष्टताओं की गणना की जिसके माध्यम से मेटामैटेरियल को ध्वनि तरंगों में बेहतर तरीके से हस्तक्षेप करने में मदद मिले, जिससे कि खुले वातावरण में केवल ध्वनि को फैलने से रोका जा सके, जबकि हवा का संचार वैसे ही चलता रहे।
- शोधकर्ताओं के अनुसार मूल आधार यह था कि मेटामैटेरियल को इस तरह से डिजाइन किया जाए जिससे कि ध्वनि तरंगों को उसी जगह वापस भेजा जा सके जहाँ से वह उत्पन्न हो रही हैं।
- इस डिवाइस का खुले और बंद वातावरण दोनों में प्रयोग किया। इस डिवाइस के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को 94 फीसदी तक कम किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु उपलब्धियों पर प्रकाशन जारी

चर्चा में क्यों ?

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 फरवरी 2019 को भारत में जलवायु क्रियाओं के बारे में 'भारत - जलवायु समाधानों का नेतृत्व कर रहा है' नामक प्रकाशन जारी किया।

- इस प्रकाशन में जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलनता के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तहत भारत द्वारा की गई प्रमुख कारवाइयों का उल्लेख किया गया है।
- भारत दुनिया में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विविध पहलुओं पर कार्य करने वाला दुनिया का एक सक्रिय देश बन गया है।
- इस प्रकाशन में ना केवल जलवायु कारवाइ के बारे में हमारी उपलब्धियों को उजागर किया गया है बल्कि भविष्य के लिए हमारी तैयारी का भी उल्लेख किया गया है।
- इस प्रकाशन में जिन पहलों का उल्लेख है वे सतत विकास प्राथमिकताओं के साथ अच्छा संतुलन कायम करते हुए जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का समाधान करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

मुख्य तथ्य :

- पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई अनेक स्वच्छ और हरित विकास पहलों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलनता के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- ई-मोबिलिटी, हरित ढुलाई, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, वनीकरण और जल आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नई नीतियां और पहल शुरू की गई हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम से कम किया जा सके।
- अभी हाल में भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक पहल शुरू की हैं।
- भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहलों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलनता निधि (NAFCC), जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (CCAT) और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC) शामिल हैं।
- वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, स्मार्ट शहरों, विद्युत वाहनों, ऊर्जा दक्षता, पहलों तथा अप्रैल 2022 तक भारत स्टेज -4 से भारत स्टेज-5 उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने जैसे कार्यों को सक्रियता पूर्वक शुरू किया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम से कम किया जा सके।
- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 74 गीगावाट से अधिक है। जिसमें 25 गीगावाट सौर ऊर्जा भी शामिल है। भारत का वन और वृक्ष क्षेत्र 2015 के आकलन की तुलना में 1 प्रतिशत बढ़ा है।
- LED वितरण के लिए उज्ज्वला जैसी योजना ने 320 मिलियन की संख्या को पार कर लिया है जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए 63 मिलियन से भी अधिक

- परिवारों को स्वच्छ कुकिंग चूल्हों का वितरण कर दिया गया है।
- दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में ये तथ्य दर्शाया गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता 2005 से 2014 के बीच घटकर 21 प्रतिशत कम हो गई है।
 - जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC), ई-मोबिलिटी के लिए फेम योजना, स्मार्ट शहरों के लिए - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-स्वच्छ कुकिंग ईंधन के लिए पहुंच, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन है।
 - जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक समस्या बन गया है और पूरी दुनिया में लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन ने हमारे पर्यावरण और समाज के सामने गंभीर चुनौती पैदा कर दी है।

आंतरिक सुरक्षा

यूनिट :

- आपदा और आपदा प्रबंधन।
- विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध।
- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।
- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।
- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा) :

- प्र. 'स्मार्ट-फेंसिंग क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा करते हुए भारत के सीमा सुरक्षा प्रबंधन में इसकी भूमिका का विश्लेषण करें।

संभावित प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा) :

- प्र. राष्ट्रीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें-

1. इसकी स्थापना 1968 में की गई थी।
2. देश में फिंगर प्रिंट संबंधित मामलों की शीर्ष नोडल एजेंसी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

बोल्ड-क्यूआईटी परियोजना

संदर्भ :

- केन्द्रीय गृहमंत्री ने असम के धुबरी जिले में भारत- बांग्लादेश सीमा पर CIBMS (व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली) के तहत BOLD-GIT (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआईटी इंटरसेप्शन टेक्निक) परियोजना का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- सीमा सुरक्षा बल बांग्लादेश के साथ 4096km लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
- विभिन्न स्थानों पर भूगोलिक बाधाओं के कारण सीमा बाढ़ लगाना संभव नहीं है।

- असम के धुबरी जिले में सीमा क्षेत्र का 61 किलोमीटर का हिस्सा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, विशाल भू-भाग और अनगिनत नदी चैनलों से मिलकर बनता है जिससे इस क्षेत्र में विशेष रूप से बरसात के मौसम में, सीमा की रखवाली एक दुष्कर कार्य बन जाता है।

पृष्ठभूमि

- इस समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने वर्ष 2017 में बीएसएफ के जवानों की वास्तविक उपस्थिति के अतिरिक्त प्रौद्योगिकीय समाधान का भी निर्णय लिया।
- जनवरी 2018 में बीएसएफ की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा ने BOLD-GIT (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआईटी इंटरसेप्शन टेक्निक) परियोजना आरंभ की और विभिन्न

विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं की तकनीकी सहायता से इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया।

- BOLD-GIT CIBMS (व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली) के तहत तकनीकी प्रणाली स्थापित करने की एक परियोजना है जो ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों के बिना बाढ़ वाले नदी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेंसर से सुसज्जित करता है।
- अब ब्रह्मपुत्र नदी के समस्त क्षेत्र को माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ओएफसी केबल्स, डीएमआर कम्युनिकेशन, दिन और रात निगरानी कैमरों और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली द्वारा उत्पन्न डेटा नेटवर्क के साथ कवर कर लिया गया है।
- ये आधुनिक गैजेट सीमा पर बीएसएफ कंट्रोल रूम को फीड्स प्रदान करते हैं और अवैध सीमा पार करने / अपराधों की किसी भी आशंका को विफल करने में बीएसएफ त्वरित कार्रवाई टीमों को सक्षम बनाते हैं।
- इस परियोजना का कार्यान्वयन बीएसएफ को ना केवल सभी प्रकार के सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करेगा बल्कि टुकड़ियों को 24 घंटे मानव निगरानी से भी राहत मिलेगी।
- इससे पूर्व, गृहमंत्री ने पिछले वर्ष सितंबर महीने में जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रत्येक 5 किलोमीटर पर 2 स्मार्ट बाड़ लगाने वाली पायलट परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर 'स्मार्ट-फेंसिंग'

संदर्भ :

- गृह मंत्री भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग (बाड़) सिस्टम की शुरुआत की।
- असम के धुबरी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर इस सिस्टम की शुरुआत की गई है।
- लगभग 61 किलोमीटर लंबे इस सीमावर्ती इलाके में भारत-बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यू-आर-टी सिस्टम (BOLD-QIT) की शुरुआत के बाद से भारत बांग्लादेश सीमा पर कई तरीके के अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा।

स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम

- स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम में सेंसर लगे होते हैं, जिससे सीमाओं की प्रभावी निगरानी हो सकती है।
- धुबरी जिले के इस पूरे क्षेत्र को डाटा नेटवर्क पर काम करने वाली संचार, ओ एफ सी केबल्स, डी एमआर कम्युनिकेशन, दिन और रात निगरानी करने वाले कैमरों और घुसपैठ का पता

लगाने वाली प्रणाली से कवर किया गया है।

- यह आधुनिक उपकरण बॉर्डर पर बीएसएफ कंट्रोल रूम को फीडबैक प्रदान करते हैं और क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग/सीमावर्ती अपराधों की किसी भी संभावना को विफल करने के लिए बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीमों को सक्षम बनाते हैं।



- असम के धुबरी जिले का 61 किलोमीटर लंबे सीमा क्षेत्र में सीमा की निगरानी बेहद मुश्किल है। खासतौर पर बरसात के मौसम में इसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए यह बहुत अहम निर्णय है।
- गौरतलब है कि भारतीय सेना बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है।
- लगभग 61 किलोमीटर लंबे इस सीमावर्ती इलाके में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सिस्टम की शुरुआत की है।

लाभ

- भारतीय सेना बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, सीमाओं पर, दूसरी जगहों पर, भौगोलिक बाधाओं के कारण सीमा बाड़ को खड़ा करना संभव नहीं है।
- असम के धुबरी जिले का 61 किलोमीटर लंबे सीमा क्षेत्र में सीमा की निगरानी बेहद मुश्किल है। खासतौर पर बरसात के मौसम में इसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है।
- ऐसे में यह स्मार्ट फेंसिंग बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। इस परियोजना से ना केवल बीएसएफ को सभी प्रकार के सीमा पार अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि सीमा प्रहरियों को भी चौबीसों घंटे मानव निगरानी में व्यस्त रहने से राहत मिलेगी।

NCRB 34वां स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) 11 मार्च 2019 को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाएगा।

- 1986 में गठित NCRB भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारिता के लिए अधिदेशित है तथा देश के अपराध आंकड़ों के संग्रह, रखरखाव एवं विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है।
- यह जांच अधिकारियों को अद्यतन आईटी टूल्स एवं अपराधों की जांच में सूचना प्रदान करने में सहायक है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- NCRB नीतिगत मामलों एवं अनुसंधान के लिए अपराध, दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं तथा कारागृहों पर आंकड़ों के प्रमाणिक स्रोत के लिए एक नोडल एजेंसी है।
- देश में फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों के प्रत्यायन सहित सभी फिंगर प्रिंट संबंधित मामलों के लिए भी शीर्ष नोडल एजेंसी है।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना, अपराध एवं अपराधियों की ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के कार्यान्वयन के लिए क्रियान्वयन तथा निगरानी एजेंसी है।
- इस परियोजना का उद्देश्य देश में पुलिस कार्य की दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता में वृद्धि के लिए एक व्यापक एवं समेकित प्रणाली का सृजन करना है।
- NCRB भारतीय पुलिस अधिकारियों एवं विदेश पुलिस अधिकारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एवं फिंगर प्रिंट विज्ञान में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
- प्रशिक्षण के दौरान शामिल क्षेत्रों में साइबर अपराध जांच एवं डिजिटल फॉरेंसिक, CCTNS, उन्नत फिंगर प्रिंट विज्ञान, नेटवर्क एवं ई-सुरक्षा, कलर्ड पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम इत्यादि शामिल हैं।
- हैदराबाद, गांधी नगर, लखनऊ एवं कोलकाता में चार क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र (RCPTC) भी भारतीय पुलिस के निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए ऐसे ही पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं।
- इस अवसर पर NCRB, सीपीओ के वरिष्ठ अधिकारी एवं NCRB के पूर्व महानिदेशक भी उपस्थित रहेंगे।

सरकार द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के जवानों का जोखिम/कठिनाई भत्ता बढ़ा

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में तैनात अर्द्धसैनिक बल के जवानों के जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ा दिया है।
- जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के एक सप्ताह बाद गृह मंत्रालय का यह फैसला आया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे।

- गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF) या अर्द्धसैनिक बल के जवानों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है।
- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने कहा है कि इससे इन क्षेत्रों में तैनात 88 हजार से अधिक कर्मियों को फायदा होगा।



जोखिम और कठिनाई भत्ता:

- निचले स्तर के अधिकारियों का भत्ता विशेष लाभ के साथ हर महीने 7,600 रुपये और उच्च अधिकारियों का भत्ता 8,100 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
- इंस्पेक्टर रैंक तक के जवानों के लिए भत्ते को 9,700 रुपये से बढ़ाकर 17,300 रुपये कर दिया गया है जबकि अधिकारियों का भत्ता 16,900 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
- बढ़ा हुआ भत्ता जम्मू-कश्मीर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सभी अर्द्धसैनिकों पर लागू होगा। यह निर्णय अगस्त 2017 से लंबित था।
- पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आदेश सभी छह अर्द्धसैनिक बलों सीमा सुरक्षा बल (BSF), (CISF), (CRPF), (ITBP), (SSB) और असम राइफल्स पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

समिति का गठन:

- साल 2017 में CRPF में जोखिम और कठिनाई भत्ते के मामले को देखने और समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों को बढ़ा हुआ भत्ता:

- बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग जैसे दक्षिण कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों और बारामुला तथा कुपवाड़ा जैसे अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात सैनिकों को अब बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा।

- जोखिम और कठिनाई भत्ते के तहत आने वाले नये क्षेत्रों में कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़, डोडा, रामबन तथा उधमपुर और तेलंगाना में एक जिला शामिल हैं।
- ज्यादातर क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं हुआ है जहां अर्द्धसैनिक बल तैनात है लेकिन जम्मू और कश्मीर में नए जिलों को जोड़ा गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) के पास जम्मू में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे राज्य को कवर किया जा सके।
- हांलाकि, जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा (LOC) पर पड़ने वाले क्षेत्र इसमें शामिल हैं। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़), लातेहार (झारखंड), गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) और मल्कानगिरि (ओडिशा) जैसे नक्सल प्रभावित जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- नोट:** हाल में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जम्मू-कश्मीर में तैनाती पर हवाई सफर अनिवार्य करने का फैसला लिया था।
- इस आदेश से अर्द्धसैनिक बलों के 7,80,000 जवानों को लाभ होगा। इन जवानों को अब तक हवाई यात्रा करने का अधिकार नहीं था।

भारतीय वायु सेना ने पार की एलओसी

चर्चा में क्यों?

- भारत ने जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद यह कार्रवाई की है।
- भारतीय वायुसेना (IAF) ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पार जाकर एयर स्ट्राइक करते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने ध्वस्त कर दिए।



- जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकियों ने 14 फरवरी 2019 को हमला कर दिया था, जिसमें 44 जवान शहीद हो गए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- एक साथ 12 मिराज-2000 इंडियन फाइटर जेट के जरिये एलओसी पार आतंकियों के ठिकानों पर निशाना बनाया गया।

- भारत ने बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी के रास्ते ये हमले किए।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव

- पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है।
- पुलवामा का बदला लेने के लिए भारतीय वायु सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है।
- बताया जा रहा है कि भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया है।
- वायुसेना ने चार से पांच जैश के लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए हैं।

उरी के बाद दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक:

- बता दें कि 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना कैंप पर हमले के 11 दिनों बाद भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में आतंकियों के करीब सात लॉन्च पैड्स तबाह किए गए।
- 26 फरवरी 2019 को LOC के पार की गई एयर स्ट्राइक में 1971 की भारत-पाकिस्तान जंग के बाद पहला मौका रहा जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसीमा में प्रवेश किया हो।
- वर्ष 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान भी वायुसेना के इस्तेमाल को एलओसी के भारतीय हिस्से तक सीमित रखने का फैसला किया था।

बाढ़/नदी प्रबंधन गतिविधियों हेतु FMBAP

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) को मंजूरी दी है।
- इस कार्यक्रम का परिव्यय 3342.00 करोड़ रुपये है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- FMBAP योजना प्रभावी बाढ़ प्रबंधन भू-क्षरण नियंत्रण और समुद्र क्षरण रोकथाम के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी।
- यह प्रस्ताव देश में बाढ़ और भू-क्षरण से शहरों, गांव, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार जुड़ाव, कृषि क्षेत्रों, बुनियादी ढांचा आदि को बचाने में मदद करेगा।
- जलग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में तलछट भार को कम करने में सहायता मिलेगी।

वित्त पोषण पद्धति :

- सामान्य श्रेणी के राज्यों में किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्त प्रबंधन घटक के वित्त पोषण की पद्धति केंद्र और राज्य के 50-50 प्रतिशत अनुपात में जारी रहेगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण पद्धति 70 प्रतिशत (केंद्र) और 30 प्रतिशत (राज्य) के अनुपात में जारी रहेगी।
- RMBA घटक पड़ोसी देशों के साथ सीमा सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट होने और द्विपक्षीय कार्य प्रणाली के अनुरूप होने से परियोजनाएं/ कार्य शत प्रतिशत अनुदान सहायता/ केंद्रीय सहायता के रूप में वित्त पोषित होंगे।

विशेषताएं :

- FMBAP योजना को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) और नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (RMBA) नामक दो स्कीमों के घटकों को आपस में विलय करके तैयार किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक प्रयासों के अधिकतम संयोग और संबंधित क्षेत्रों में राज्य/ केंद्र सरकार के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ से उचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की मदद करना है।
- इस योजना के तहत कार्यों से भू-क्षरण और बाढ़ के प्रकोप से बहुमूल्य भूमि की रक्षा होगी और सीमा के साथ-साथ शांति बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
- इस योजना का उद्देश्य FMP के तहत पहले से ही मंजूर चल रही परियोजनाओं को पूरा करना है। यह योजना पन-मौसम संबंधी पर्यवेक्षणों और पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों में बाढ़ के पूर्वानुमान करने में भी मदद करेगी।
- इस योजना में पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर जल संसाधन परियोजनाओं जैसे नेपाल में पंचकेश्वर बहु उद्देशीय परियोजना, सप्त कोसी-सनकोसी परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण और जांच पड़ताल तथा डीपीआर आदि को तैयार करना शामिल है। इससे दोनों देशों को लाभ होगा।

आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा-2019 पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला**चर्चा में क्यों?**

- आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा-2019 पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (IWDR) 22 मार्च को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।
- कार्यशाला में 33 देशों के विकास और आपदा जोखिम विशेषज्ञ, बहुपक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और अन्य भागीदारों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- कार्यशाला में प्रमुख आधारभूत ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और पेयजल आदि में आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी श्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान की गई।
- इसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रकृति आधारित नवाचार और इसके आधारभूत ढांचे के सृजन, संचालन और रखरखाव में प्रभाव पर भी चर्चा की गई।
- कार्यशाला के दौरान आधारभूत ढांचे के लिए वित्त और बीमा संबंधी प्रायोगिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
- इसमें आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे के लिए प्रस्तावित गठबंधन (CDRI) को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए बातचीत का मंच तैयार हुआ।
- CDRI की परिकल्पना, सूचना के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण भागीदारी के रूप में की गई है।
- भारत ने नई दिल्ली में 2016 में आयोजित एशियन आपदा जोखिम कम करने पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के तुरंत बाद CDRI के सृजन की घोषणा की थी।
- दूसरे RWDRI का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कम करने संबंधी कार्यालय और ग्लोबल कमीशन ऑन एडोप्शन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा किया गया।

□□□□

सामाजिक मुद्दों से संबंधित लेख

भारत को बदलनी होगी आतंक और चीन से निपटने की रणनीति

13 मार्च की देर रात चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर जैश सरगना मसूदा अज़हर को वैश्विक आतंकी (Global Terrorist) घोषित करने वाले प्रस्ताव के विरोध में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे बचा लिया। जबकि परिषद के चार अन्य स्थायी सदस्यों—अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद में चौथी बार चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया है।

सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष अज़हर मसूदा को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिये फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने 27 फरवरी को प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद समिति ने सदस्य देशों को आपत्ति दर्ज करने के लिये 10 दिनों का समय दिया था। चीन ने इसे तकनीकी रोक बताया जो छह महीनों के

लिये वैध है और इसे आगे तीन महीने के लिये और बढ़ाया जा सकता है।

अनपेक्षित नहीं है चीन का रवैया

यह बिल्कुल अपेक्षित ही था, 'तकनीकी रोक' लगाने वाला यह चीन का चौथा वीटो है। अपने इस कदम से चीन ने भारत को यह जता दिया है कि आतंकवाद भारत की अपनी राष्ट्रीय समस्या है और इसे सुलझाने का जिम्मा भी उसी का है। साथ ही चीन ने यह भी दिखा दिया है कि 'वैश्विक आतंकवाद' और उसकी दक्षिण एशिया नीतियों में अंतर बरकरार है तथा भारतीय चिंताओं को लेकर उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है।

क्या है वीटो पावर?

वीटो (Veto) लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 'मैं अनुमति नहीं देता हूँ'। प्राचीन रोम में कुछ निर्वाचित

अधिकारियों के पास अतिरिक्त शक्ति होती थी, जिसका इस्तेमाल वे रोम सरकार की किसी कार्रवाई को रोकने में करते थे। तब से यह शब्द किसी काम को करने से रोकने की शक्ति के लिये इस्तेमाल होने लगा।

मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों—चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो पावर है। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। मसूदा अज़हर के मामले में यही हो रहा है। सुरक्षा परिषद के चार स्थायी सदस्य उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने के समर्थन में थे, लेकिन चीन उसके विरोध में था और उसने वीटो लगा दिया।

आपको बता दें कि फरवरी, 1945 में क्रीमिया, यूक्रेन के शहर याल्टा में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को याल्टा



सम्मेलन या क्रीमिया सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन में तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने वीटो पावर का प्रस्ताव रखा था।

याल्टा सम्मेलन का आयोजन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की योजना बनाने के लिये हुआ था। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी-रूजवेल्ट ने हिस्सा लिया। वैसे 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के बाद ही वीटो अस्तित्व में आ गया था। उस समय लीग काउंसिल के स्थायी और अस्थायी सदस्यों, दोनों के पास वीटो पावर थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 16 फरवरी, 1946 को पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) ने किया था। लेबनान और सीरिया से विदेशी सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव पर यह वीटो किया गया था।

बेहद मजबूत हैं पाक-चीन रिश्ते

हालिया चीनी वीटो से भारत को यह स्पष्ट संदेश मिला है कि पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध बेहद मजबूत हैं। यहाँ तक कि उभरती जिम्मेदार शक्ति के तौर पर प्रतिष्ठा से उसके लिये राष्ट्रीय हित अधिक मायने रखते हैं।

इसे अमेरिका और इज़राइल के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सुरक्षा परिषद में जब-जब इज़राइली हितों पर आँच आती है। अमेरिका अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करता है। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के लिये चीन कर रहा है।

दरअसल, वैश्विक आतंकवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। अमेरिका ने 9/11 की घटना के बाद अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर करने के लिये इसे गढ़ा था। इसी दौरान अमेरिका ने सबसे महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी के तौर पर पाकिस्तान की खोज की थी। अपनी राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की नीतियों से पाकिस्तान अब भारत में आतंकवाद को जारी रखे हुए है और अमेरिका उसे लगातार नजरअंदाज करता रहा है। इस दौरान पाकिस्तान नकदी

व हथियारों के रूप में लगातार अमेरिकी सहायता प्राप्त करता रहा।

चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध काफी गहरे हैं और अपने ऊपर पाकिस्तान की निर्भरता बनाए रखने में चीन के अपने हित हैं। दुनिया एक बात भली-भाँति जानती है कि चीन कोई भी नीति अपने दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखकर बनाता है। यही वजह है कि भारत-पाक संबंधों को सुधारने को लेकर भी उसने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इससे उसे अपने हितों पर चोट पहुँचने का अंदेशा है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

- पाकिस्तान को चीन की आर्थिक मदद के रूप में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) प्रोजेक्ट है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की प्रमुख परियोजना है।
- बेशक 62 बिलियन डॉलर की यह चीनी परियोजना पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य को नहीं बदल सकती, लेकिन यह चीन के लिये बेहद महत्वपूर्ण है।
- इसके माध्यम से चीन ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान, हिंद महासागर, ईरान और खुद के झिंजियांग प्रांत में अपने हितों को साध रहा है।
- ऐसे में चीन एक साथ अपने कई हितों को साधने वाले बहु-लाभकारी देश पाकिस्तान का साथ आखिर क्यों छोड़ेगा?

भारत क्या कर सकता है?

चीन के रुख से साफ है कि इस मामले में वह भारत की दलीलों को समझने को तैयार नहीं है। इस तरह के मामलों को सुरक्षा परिषद में ले जाने से पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनानी होगी। एक भी सदस्य छूटा तो फिर उसका नतीजा यही होगा जैसा चीन के मामले में है।

चीन जानता है कि पाकिस्तान ही इन आतंकी घटनाओं का स्रोत है, फिर भी वह पाकिस्तान का रक्षा कवच बना हुआ है। यह स्पष्ट है कि इस मामले ने भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर किया है।

भारत को बदलनी होगी रणनीति

भारत को यह बात अब अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि चीन और हमारा सिस्टम अलग है। हम कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया से चलते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी आंतरिक न्यायिक व्यवस्था है, चीन की न्यायिक व्यवस्था नहीं है।

अपने वीटो से चीन हमको यही समझाने की कोशिश कर रहा है और जब तक यह बात हमें समझ में नहीं आएगी, हम सुरक्षा परिषद में बार-बार जाते रहेंगे परिणाम लगभग एक जैसा ही मिलता रहेगा।

युद्ध की संभावना को हरसंभव टालते हुए भारत को पाकिस्तान पर निरंतर दबाव बनाए रखना होगा। हमें अमेरिका और चीन को लेकर इस गफलत में नहीं रहना चाहिये कि वे हमारे लिये पाकिस्तान पर एक सीमा से आगे जाकर दबाव डालेंगे। आखिर अमेरिका और चीन के अपने-अपने हित हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तानी मदद चाहिये। फिर चीन क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान के आतंकी भारत आने के बजाय उसके यहाँ आ जाएँ।

हमें यह बात भी अच्छी तरह से समझनी होगी कि पाकिस्तान की जो कानूनी-न्यायिक व्यवस्था है, उसमें डोजियर सौंपकर हम कानूनी रूप से कोई प्रभावी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इसी तरह सुरक्षा परिषद में भी हमारे प्रयास एक सीमा के आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि सुरक्षा परिषद की अलग-अलग शक्तियों के अपने-अपने हित हैं। हमें विश्व मंचों पर पड़ोसी देश की कारगुजारियों को उजागर करते रहना चाहिये, लेकिन यह अतिरिक्त प्रयास होना चाहिये, मुख्य नहीं।

हमें यह भी समझना होगा कि एक मसूदा अजहर के लिये हम चीन से अपने संबंधों में एक सीमा से अधिक खटास नहीं

आने दे सकते। आखिर जिस पाकिस्तान में मसूद अज़हर बैठा है, उससे ही कहाँ अपने सारे रिश्ते हम तोड़ पाए हैं। पिछले 70 वर्षों से हम पड़ोसी देश की हरकतों से परेशान हैं, लेकिन कूटनीति के अपने तकाज़े होते हैं।

वर्तमान परिदृश्य में भारत के विकल्प

वर्तमान में वैश्विक व्यवस्था अराजकता का प्रतिनिधित्व करती है और किसी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने या प्रतिबंधित करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया टूट चुकी है। यह प्रमुख शक्तियों के हितों की संरक्षक भर है। भारत संयुक्त राष्ट्र से जो अपेक्षा करता है, वह उसे स्वयं करना होगा। सीमा पार से जिस आतंकवाद का वह सामना करता है, उसे खत्म करने के लिये वह जो उपाय कर रहा है, वह सही है, लेकिन इसे लेकर भारत को व्यावहारिक होना होगा।

भारत की बदले की प्रतिक्रिया उपलब्ध विकल्पों का ही परिणाम है, जो पहले देखने को नहीं मिलता था। भारत को यह भी समझना होगा कि चीन कभी भी पाकिस्तान के मामले में असहज महसूस नहीं करता। ऐसे में भारत को अराजकता को पहचानने और खुद के बूते अपने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।

पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना होगा

भारत अब तक चार बार इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में वोटिंग के लिये ले जा चुका है, लेकिन हर बार चीन ने रास्ता रोक दिया। इस बार 13 देश भारत के साथ थे। विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज बीजिंग भी गई थीं, लेकिन चीन आतंक के खिलाफ बने जनमत के दबाव में नहीं आया।

लेकिन अभी हाल ही में मसूद अज़हर पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर चीन द्वारा वीटो करने के बाद फ्राँस ने आतंकवादी

संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर अब खुद एक्शन लिया है और अज़हर मसूद की संपत्ति को जब्त करने का फैसला किया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इसे दबाव बनाने का सांकेतिक प्रयास कहा जा सकता है।

ऐसे में भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिये अनेक मोर्चों पर एक साथ सक्रिय रहने पड़ेगा। मसूद अज़हर पर हम पाकिस्तान के ज़रिये ही दबाव बना सकते हैं।

कोई आतंकवादी संगठन वहाँ से हमारे यहाँ आतंकी कार्रवाई के षड्यंत्र कर रहा है, तो हम उस पर काउंटर अटैक करके उसके मनसूबे ध्वस्त कर सकते हैं। जहाँ तक चीन की बात है, तो उसके साथ हमें अपनी बातचीत जारी रखनी होगी।

हमें अपने बूते ही पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

जैव विविधता संरक्षण बनाम वनवासी

आमतौर पर वनों में निवास करने वाले एवं वनोत्पादों पर निर्भर आबादी को वनों एवं जैव विविधता का संरक्षक माना जाता रहा है। प्रयास यह भी रहा है कि इनके जीवन से छेड़छाड़ नहीं की जाए क्योंकि इससे ना केवल उनकी आजीविका प्रभावित होती है बल्कि जैव विविधता का संरक्षण भी प्रभावित होता है। अर्थात् दोनों एक-दूसरे के पूरक रहे हैं परंतु हाल में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से वनवासियों को उनके ही प्राकृतिक दुनिया से हटने का खतरा उत्पन्न

हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वजह जैव विविधता संरक्षण बनाम वनवासियों के अधिकार का मुद्दा है जिसे कभी एक-दूसरे का पूरक माना जाता रहा है। हालाँकि सिविल सोसायटी समूहों द्वारा विरोध के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने 28 फरवरी, 2019 को अपने पूर्व के आदेश पर रोक ज़रूर लगा दिया और स्पष्ट किया कि किसी को बलात खाली नहीं कराया जाएगा। परंतु अभी भी तथाकथित अवैध रूप से रह रहे लोगों के ऊपर से संकट पूरी तरह टला नहीं है।

क्या है मुद्दा?

13 फरवरी, 2019 को न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वन अधिकार एक्ट, 2006 के तहत पट्टे का दावा करने में असफल लोगों को अगली सुनवाई तक जमीन खाली करने का आदेश दिया था और खाली करवाने की जिम्मेदारी

राज्यों के मुख्य सचिव को दी गई।

न्यायालय ने अपने आदेश में राज्यों से उन जनजातियों एवं अन्य वनवासियों को खाली करने का आदेश दिया जिनका उन कानून के तहत अतिक्रमण की गई वन भूमि पर दावा खारिज कर दिया गया है जो इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। याचिका दायर होने के पश्चात 17 राज्यों ने 19 लाख दावों के खारिज होने संबंधी हलफनामा दायर किया था।

यह याचिका वाइल्डलाइफ फर्स्ट, नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी एवं टाइगर रिसर्च एंड कंजर्वेशन ट्रस्ट ने दायर की थी। यह याचिका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) एक्ट 2006 के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले संगठनों का तर्क है कि पट्टा समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से लोग राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों की बड़ी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इनका यह भी तर्क है कि वन अधिकार अधिनियम



के क्रियान्वयन से वन भूमियों पर बड़े पैमाने पर कब्जा जमाया जाएगा और वन भूमि पर और अधिक मानव बस्तियों की अनुमति दी जाएगी जिससे जैव संरक्षण प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अपने तर्क हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामा के अनुसार अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों द्वारा वन अधिकार कानून के तहत किए गए स्वामित्व दावों को विभिन्न कारणों से खारिज कर दिया गया। इनमें से एक यह भी पीढ़ियों से इस भूमि पर उनका अधिकार था। वन अधिकार कानून 2006 के तहत विगत तीन पीढ़ियों से वन भूमि पर रह रहे लोगों को भू-अधिकार प्रदान किया जाता है। इनके दावों की पुष्टि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करती है।

28 फरवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय के मुकाबले पर्यावरण संरक्षण एवं मानव अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। न्यायालय ने जहाँ एक ओर कहा कि कई ऐसे परंपरागत जनजातीय लोग भी हो सकते हैं जिनके दावों को खारिज

कर दिया गया हो वहीं ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहाँ अन्य वनवासियों की आड़ में प्रवासी, उद्योगपति एवं अन्य लोगों द्वारा जंगलों का अधिग्रहण किया जा रहा हो।

दरअसल वर्ष 2006 से पहले भारतीय वन एक्ट 1927 के तहत वनवासियों को 'कब्जा करने वाले' लोगों के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। ब्रिटिश काल की इस औपनिवेशिक सोच को सुधारने का ही प्रयास वर्ष 2006 के वन अधिकार कानून के द्वारा किया गया। इस कानून के द्वारा जनजातियों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास किया गया। कानून के तहत दावा करने वाले 44 लाख लोगों में से 23 लाख लोगों के जमीनों पर अधिकारों की मान्यता दी गई। इनमें वैसे लोग शामिल थे जो या तो विशेषीकृत जनजातीय लोग थे या जो परंपरागत रूप से जंगलों में रह रहे थे और 75 वर्षों से वनोत्पादों पर निर्भर थे। वर्ष निर्धारण के लिए कट ऑफ तिथि 2005 तय की गई।

दावों का निपटारा कैसे किया गया?

वन अधिकार एक्ट 2006 ग्राम सभा द्वारा दावा की गई सभी जमीन पर व्यक्तिगत

वन अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकार, दोनों को मान्यता प्रदान करता है। किसी के दावे की पुष्टि चार स्तरों से होकर गुजरती है: ग्राम सभा, अनुमंडल स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय कमेटी एवं राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी। इनमें राज्य स्तरीय कमेटी प्रक्रिया की निगरानी करती है तो जिला स्तरीय कमेटी निर्णायक कमेटी प्रक्रिया की निगरानी करती है। जहाँ जनजातीय लोगों को दो प्रमाण देने होते हैं कि 13 दिसंबर, 2005 तक जमीन उनके कब्जे में थे। वहीं अन्य परंपरागत वनवासियों को यह दर्शाना होता है कि वे कट ऑफ तिथि से 75 वर्ष पहले तक वहाँ रह रहे थे और अपनी आजीविका के लिए वनोत्पादों पर निर्भर थे। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के अनुसार 19.34 लाख दावे खारिज किए गए हैं।

जनजातीय कार्यकर्ताओं ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा है कि कई लोगों के दावों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया तो संरक्षणवादियों का तर्क है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात में कई दावे बोगस हैं। उन्होंने उपग्रह से लिए गए चित्रों के आधार पर दावा किया है कि जिन लोगों के दावे खारिज किए गए हैं उनमें से 14 लाख के



दावों को ग्राम सभा के स्तर पर ही खारिज किया गया है। इनका यह भी तर्क है कि जिस वन भूमि पर लोगों के दावे को खारिज किया गया है उनमें से लगभग सभी के पास वैधानिक भूमि है, उनसे केवल वही जमीन ली जा रही है जो अवैध रूप से कब्जा किए गए हैं। हालाँकि ये दोनों बातें पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होती। इसका एक उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय का 28 फरवरी का निर्णय है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 28 फरवरी, 2019 को पूर्व के निर्णय पर रोक लगाते हुए कहा कि, 'इस बात को दर्ज नहीं कराया गया है कि किसने दावों को खारिज किया है और किस कानून के प्रावधानों के तहत लोगों से जमीन खाली करावाया जाएगा और इस आदेश को जारी करने वाला सक्षम अधिकारी कौन है?' दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि 60 प्रतिशत वनवासी भूमिहीन हैं, जिसका मतलब है कि केवल 40 प्रतिशत ही संपूर्ण भूमि पर नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे इस तरह से अवैध रूप से अधिकार किए गए जमीन सामुदायिक वन अधिकार के तहत ग्राम सभा को सौंपने की मांग कर रहे हैं।

वनवासी हैं संरक्षण के पर्याय

यदि आज हम संरक्षित क्षेत्र के दृष्टिकोण से वन की बात करें तो यह महज 4.9 प्रतिशत रह गया है। सिमटते संरक्षित वनों के कारण ही वन्यजीवन अक्सर ही बस्तियों की ओर आ जाते हैं जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। परंतु संरक्षित क्षेत्र के सिमटने

के लिए हम वनवासियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। विगत कई वर्षों से वन व वन्यजीव क्षेत्रों में बाह्य मानवीय हस्तक्षेप बदस्तूर जारी है।

असम के गोलाघाट जिला में हाथी गलियारा में नूमालीगढ़ रिफायनरी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु दीवारें खड़ी की गई थी। मई 2015 में सात वर्षीय हाथी की मौत मस्तिष्क आघात से हो गई थी क्योंकि वह दीवार को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और 18 जनवरी, 2019 को नूमालीगढ़ रिफायनरी को 2.2 किलोमीटर लंबी बाड़ड़ी दीवार को तोड़ने का आदेश दिया।

- आधुनिक विनिर्माण कार्य (सड़क, बांध इत्यादि) की वजह से बड़े पैमाने पर भूमि का अतिक्रमण हुआ है और इस संदर्भ में कई मामलों अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
- इसके बावजूद राज्य सरकारों द्वारा ऐसी भूमि के अतिक्रमण का प्रयास बिना रोक के जारी है।
- पर्यावरणविदों द्वारा चिंता जताये जाने के बावजूद 30 नवंबर, 2018 को केरल सरकार ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व बैंक से होकर पाँच एलीवेटेड गलियारों के निर्माण के लिए धन आवंटित किए।

इसके विपरीत कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें जनजातियों एवं वनवासियों ने वन

भूमि के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओडिशा के नियामगिरी में वेदांत के बॉक्साइट खनन को रोकने में डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने महती भूमिका निभायी और सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में अपने निर्णय में बॉक्साइट खनन की अनुमति देने के संदर्भ में ग्राम सभाओं के अधिकारों को मान्यता प्रदान किया। इसी तरह 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के लिप्पा लोगों को यह निर्धारण करने का अधिकार दिया कि जल विद्युत परियोजना उनके हित में है या नहीं। इस परियोजना से बड़ी मात्रा में वन भूमि के डूबने का खतरा विद्यमान था। कई पर्यावरणविदों का मानना है कि कई बार सरकारें ही वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भू-कारण अधिकारों को देने में अनाकंक्षी करती हैं क्योंकि उसे पता होता है कि इन लोगों से परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराना कितना कठिन हो सकता है।

निष्कर्ष :

इसमें कोई दो राय नहीं कि जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है और इसको नुकसान पहुँचाने से सर्वाधिक खामियाजा आजीविका के लिए इस पर निर्भर आबादी को ही भुगतान पड़ेगा। परंतु इस संदर्भ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जैव विविधता संरक्षण में वनों में रहने वाले लोगों की महती भूमिका होती है। इस क्रम में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें संरक्षण एवं परंपरागत अधिकार तथा अतिक्रमण के बीच के भेद को समझना चाहिए।



कला एवं संस्कृति

प्रारम्भिक परीक्षा विशेष : 2019

भारतीय चित्रकला

भित्ति चित्रकला

- भारत में चित्रकला का विकास प्राचीन काल से ही हुआ है। प्राचीन काल में मनुष्य ने कन्दराओं को अपना आवास बनाया था। इन्हीं कन्दराओं में दीवार पर प्राचीन मानव द्वारा अंकित किए गये चित्र हैं, जिसका सबसे बड़ा भंडार विन्ध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका में मिलते हैं। भीमबेटका पुरापाषाण कालीन स्थल है। गुप्तकाल के पूर्व चित्रकला के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं।
- प्रारम्भिक चित्र प्रागैतिहासिक युग की पर्वत गुफाओं की दीवारों पर प्राप्त होते हैं। कुछ गुहा-मंदिरों की दीवारों पर भी चित्रकारियाँ मिलती हैं। गुप्तकाल तक आते-आते चित्रकारों ने अपनी कला को पर्याप्त रूप से विकसित कर लिया। इस काल के ग्रंथों में चित्रकला की उपयोगिता एवं उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यशोधर पंडित ने चित्रकला के सौंदर्यपरक आदर्श को व्यक्त करते हुए उसके छः अंग बताये हैं—
 1. रूपभेद (प्रकार)
 2. प्रमाण (माप अथवा अनुपात का उचित ज्ञान)
 3. भाव (चित्रों में भाव या रस का प्रकटीकरण)
 4. लावण्य-योजना (सौंदर्य-प्रदर्शन)
 5. सादृश्य (चित्र को उसी रूप में बनाना) तथा
 6. वर्णिका भंग (चित्रांकन में रंगों का उचित प्रयोग करना)
- विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रकला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसके विविध अंगों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें चित्र को समस्त कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है जो चार पुरुषार्थों का प्रदाता है।
- बुद्धघोष ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि चित्रकला से बढ़कर संसार में कोई दूसरी कला नहीं है। अतः इसमें संदेह नहीं कि गुप्तयुगीन चित्रकारों ने इन आदर्शों का पालन करते हुए उनके अनुरूप अपनी कला का प्रदर्शन किया।

- चित्रकला, कला के सर्वाधिक कोमल रूपों में से एक है जो रेखा और वर्ण के माध्यम से विचारों तथा भावों को अभिव्यक्ति देती है। प्राचीन मानव ने कंदराओं में अपनी सौन्दर्यपरक, अतिसंवेदनशील और सृजनात्मक प्रेरणा को संतुष्ट करने के लिए शैलाश्रय चित्र बनाये थे।

भीमबेटका

- भीमबेटका की चित्रकला में मानव जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रकट किया गया है जो निम्न हैं—
 1. शिकार के पूर्व का दृश्य
 2. मनोरंजन के नृत्य
 3. गर्भवती महिला का दृश्य
 4. गर्भवती गाय
 5. गैंडे का शिकार, जिसमें एक आदमी को गैंडे ने सींग से उठाकर पटक दिया है।
 6. मुखौटों में नृत्य
 7. मुखौटों में शिकार
- भीमबेटका के चित्रों को अपरिष्कृत लेकिन यथार्थवादी ढंग से तैयार किया गया है। ये सभी आरेखण स्पेन की उन प्रसिद्ध शैलाश्रय की चित्रकलाओं से मेल खाती हैं जिनके संबंध में यह माना जाता है वे नवप्रस्तर मानव की कलाकृतियाँ हैं।
- दलबन्द के शैलचित्रों में पक्षियों और वनस्पतियों के चित्रण के साथ ही एक चित्र ऐसा है जिसमें दो वयस्क और दो बालक पाँव-से-पाँव और हाथ-से-हाथ मिलाये आगे पीछे कतार में चले जा रहे हैं।
- एक अन्य चित्र में एक ऐसे मनुष्य का चित्रण किया गया है जिसके बायें हाथ में एक अर्द्ध-गोलाकार आकृति है जिसे सूर्य, चन्द्र अथवा ब्रह्माण्ड का प्रतीक माना जा सकता है उसका दूसरा हाथ कुहनी तक पृथ्वी के समानान्तर और उसके बाद कुहनी से उसके सिर की ओर मुड़ा है तथा सिर बायीं ओर किंचित सामने झुका है।

अजन्ता चित्रकला

- ❶ यहाँ चट्टान को काटकर उनत्तीस (29) गुफायें बनायी गयी थीं। इनमें चार चैत्यगृह तथा शेष विहार गुफाएँ थीं। पहले, निर्मित की गयी गुफाएँ सामान्य आकार-प्रकार की हैं जबकि बाद में निर्मित गुफाओं में खंभों का अधिक प्रयोग किया गया है। इनकी वास्तु-योजना अपेक्षाकृत अधिक विकसित है।
- ❷ अजन्ता में सभी गुफाओं में चित्र बनाये गये थे किंतु उचित संरक्षण के अभाव में अधिकांश चित्र नष्ट हो गये हैं तथा अब केवल छः गुफाओं (1-2, 9-10 तथा 16-17) के चित्र अवशिष्ट है।
- ❸ इनका समय अलग-अलग है। नवीं-दसवीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली-दूसरी गुफाओं के चित्र सातवीं शताब्दी ईस्वी के हैं तथा दसवीं गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र एवं सोलहवीं-सत्रहवीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं।
- ❹ अजन्ता के चित्रों के तीन प्रमुख विषय हैं— अलंकरण, चित्रण और वर्णन। विविध फूल-पत्तियों, वृक्षों तथा पशु-आकृतियों से अलंकरण का काम लिया गया है। ये इतने अधिक प्रकार के हैं कि किसी भी एक की पुनरावृत्ति नहीं हो पाई।
- ❺ किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा आदि अलौकिक एवं पौराणिक आकृतियों का उपयोग स्थान भरने के लिए किया गया है। अनेक बुद्धों एवं बोधिसत्त्वों का चित्रण हुआ है।
- ❻ बुद्ध के भौतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का सुन्दर ढंग से चित्रण हुआ है। पहली गुफा में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का दृश्य चित्रण कला के चरमोत्कर्ष का सूचक है।
- ❼ कहीं-कहीं लोकपालों एवं राजा-रानियों का भी चित्रण मिलता है। जातक ग्रंथों से ली गयी कथाएँ वर्णनात्मक दृश्यों के रूप में उत्कीर्ण हुई हैं। अजन्ता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाये गये हैं।
- ❽ प्रथम में गीले प्लास्टर पर चित्र बनाये जाते थे तथा चित्रकारी विशुद्ध रंगों द्वारा ही की जाती थी। द्वितीय विधि से सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाये जाते थे तथा रंग के साथ अंडे की जरदी एवं चूना मिलाया जाता था।
- ❾ शंखचूर्ण, शिलाचूर्ण, सीता मिश्रित गोबर, सफेद मिट्टी, चोकर आदि को एक साथ मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार किया जाता था। चित्र बनाने के पूर्व दीवार को भली-भाँति रगड़ कर साफ करते थे तथा फिर उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता था।
- ❿ चित्र का खाका बनाने के लिए लाल खड़िया का प्रयोग होता था। रंगों में लाल, पीला, नीला, काला तथा सफेद रंग प्रयोग में लाये जाते थे।
- ⓫ उल्लेखनीय है कि अजन्ता के पूर्व कहीं भी चित्रण में नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता है। लाल तथा पीले रंग का प्रयोग

अधिक किया जाता है तथा रंगों में अलौकिक चमक है जो अंधेरी रात में चाँद-तारे की भाँति चमकते हैं। कलाकारों ने कहीं भी उतावलापन नहीं दिखाया है अपितु रंगों के प्रयोग में गंभीरता का परिचय दिया गया है।

- ❶ अजन्ता के गुफाचित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों का चित्रण मिलता है। बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं तथा जातक कथाओं के दृश्यों का अंकन विस्तृत रूप में किया गया है। इनका विवरण इस प्रकार है—
- ❷ **गुफा संख्या 16 :** इसकी चित्रकारी 5000 ई. पू. के लगभग से प्रारंभ होती है तथा सत्रहवीं गुफा के कुछ पूर्व की है। अजन्ता की 16वीं गुफा के चित्रों में 'मरणासन्न राजकुमारी' (Dying Princess) नामक चित्र सर्वाधिक सुन्दर एवं आकर्षक है। यह पति के विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है।
- ❸ उसके चारों ओर परिवारजन शोकाकुल अवस्था में खड़े हैं। एक सेविका उसे सहारा देकर ऊपर उठाये हुए है तथा दूसरी पंखा झेल रही है। एक स्त्री अत्यन्त आतुर होकर राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए है।
- ❹ दूसरी ओर दो सेविकायें हाथ में कलश लिये खड़ी हैं। राजकुमारी का सिर गिर रहा है, आँखे बन्द हैं तथा शरीर का अंग-प्रत्यंग पीड़ा से कराह रहा है। समीप खड़े परिजनों के मुख मण्डल पर दुख का भाव अंकित है।
- ❺ 16वीं गुफा के एक दृश्य में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्रांकन है जिसमें वे अपनी पत्नी, पुत्र तथा परिचायिकाओं को छोड़कर जाते हुए दिखाये गये हैं। उनकी वैराग्य भावना दर्शनीय है।
- ❻ कुछ चित्र बुद्ध के सन्यासी जीवन से संबंधित भी हैं जिनमें सुजाता का खीर, अर्पण, माया का स्वप्न दर्शन आदि का अंकन कुशलतापूर्वक किया गया है।
- ❼ बायीं दीवार पर उन चार घटनाओं का अंकन है जिन्हें देखकर बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। वे हैं—वृद्ध पुरुष, रोगी, शवयात्रा तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी।
- ❽ **गुफा संख्या 17:** 17वीं गुफा के चित्र वर्णनात्मक प्रकार के हैं। इसे 'चित्रशाला' कहा गया है। ये अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित हैं।
- ❾ समस्त चित्रों में 'माता और शिशु' (Mother and Child) नामक चित्र आकर्षक है जिसमें संभवतः बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को उन्हें समर्पित कर रही है।
- ❿ असीम श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक माता तथा पुत्र दोनों एकटक रूप से बुद्ध को देख रहे हैं। इस चित्र से सहानुभूति एवं करुणा टपकती है। बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले चित्रों

में उनके महाभिनिष्क्रमण का एक चित्र अत्यन्त सजीवता के साथ उत्कीर्ण किया गया है।

- ☛ इसमें युवक सिद्धार्थ के सिर पर मुकुट है तथा शरीर सुडौल है। आंखों से अहिंसा, शांति, एवं वैराग्य झलक रहा है। मुखमुद्रा गंभीर एवं सांसारिकता से उदासीन प्रतीत होती है।
- ☛ ऐसी कल्पना कठिनता से दुबारा उत्पन्न हो सकती है। एक अन्य चित्र में कोई सम्राट एक सुनहले हंस से बातें करता हुआ चित्रित किया गया है।
- ☛ इसी गुफा में आकाश में विचरण करते हुए गंधर्वराज को अप्सराओं तथा परिचारकों के साथ चित्रित किया गया है। यह चित्रण अत्यन्त मनोहारी है।
- ☛ अन्य चित्रों में काले हाथी एवं सिंह के शिकार के दृश्यों का अंकन अत्यधिक कुशलता के साथ किया गया है। एक खण्डित चित्र के बीच बना हुआ एक अप्सरा का आवक्ष चित्र नारी सौंदर्य एवं गुप्तकालीन सम्भ्रांत वेशभूषा का सुन्दर उदाहरण है।
- ☛ अप्सरा के नेत्र अधखुले हैं, केश संवरे हुए हैं, कानों में गोल कुण्डल हैं तथा गले में मोतियों की माला है। उसके सिर पर अलंकृत पगड़ी बंधी हुई है।

बाघ चित्रकला

- ☛ मध्य प्रदेश के धार से 80 किलोमीटर तथा इंदौर से उत्तर-पश्चिम 144 किलोमीटर दूर नर्मदा की सहायक बाघिनी नदी के बायें तट पर बाघ की पहाड़ी स्थित है।
- ☛ अंजता के समान यहाँ भी बौद्ध विहार बनवाये गये। स्मिथ का अनुमान है कि अंजता में गुहा निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद बाघ में गुहायें उत्कीर्ण की गयीं।
- ☛ बाघ पहाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कुछ ताम्रपत्रों पर ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है जिनका समय चौथी-पाँचवीं सदी निर्धारित किया जाता है।
- ☛ संभव है इस क्षेत्र में शासन करने वाले गुप्तों के सामंतों द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया हो। बाघ की चौथी-पाँचवीं गुफा को संयुक्त रूप से 'रंग महल' कहा जाता है।
- ☛ इनका बरामदा परस्पर मिला हुआ है। इनके बरामदे तथा भीतरी दीवारों पर सर्वाधिक चित्र बनाये गये हैं। दृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
- ☛ पहला दृश्य राजभवन के एक खुले मण्डप में बैठी हुई दो युवतियों का है जिनमें एक राजकुमारी तथा दूसरी उसकी सेविका लगती है। राजकुमारी का शरीर आभूषणों से युक्त है।
- ☛ वह अपना हाथ सेविका के कंधों पर रखकर उसकी बातें ध्यान से सुन रही है। छत्र पर कबूतरों के दो जोड़े चित्रित किये गये हैं।
- ☛ दूसरा दृश्य दो जोड़ों का है जो एक दूसरे के सम्मुख बैठकर शास्त्रार्थ में लीन प्रतीत होते हैं। बायें ओर एक पुरुष-स्त्री है जिनके सिर पर मुकुट होने से उनका राजा-रानी होना सूचित होता है। दायें ओर दूसरा जोड़ा सामान्य जन है। पृष्ठ भाग पर वनस्पतियों का अंकन है।
- ☛ तीसरा एक संगीत का दृश्य है। इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों के दो अलग-अलग समूह हैं। पाँच या छः पुरुषों का समूह स्त्रियों के संगीत का आनंद उठा रहा है।
- ☛ वे अपना हाथ ऊपर किये हुए हैं। उनके सिर मुण्डित हैं, तथा शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। स्त्री समूह के मध्य एक स्त्री वीणा बजाते हुए चित्रित है। एक के सिर पर मुकुट है जिससे वह नायिका लगती है। सभी अलंकृत वस्त्र एवं आभूषण धारण किये हुए हैं।
- ☛ चौथा दृश्य संगीत युक्त नृत्य के अभिनय का है। इसमें स्त्रियों और पुरुषों को अलंकृत वेशभूषा में स्वच्छंदतापूर्वक नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है।
- ☛ उनके हाथों में मृदंग, करताल, कांस्यताल आदि वाद्य यंत्र हैं। बाघों और सात स्त्रियों के बीच विभिन्न वेशभूषा वाली कोई नर्तकी (अथवा नर्तक) है जो मोतियों की माला पहनी है।
- ☛ तीन स्त्रियाँ डंडे बजा रही हैं, एक मृदंग तथा तीन मजीरा बजाते हुए दिखाई गयी हैं। दायें समूह में छः स्त्रियों के घेरे में भी एक नर्तक अथवा नर्तकी है। स्त्रियों के केश विन्यास आकर्षक हैं।
- ☛ इस चक्राकार नृत्य को भारतीय परम्परा में 'हल्लीसक' कहा गया है जिसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण की रासलीला से माना जाता है।
- ☛ भारतीय संगीत का यह रूप गुप्तकाल के आमोदपूर्ण नगर जीवन के सर्वथा उपयुक्त था।
- ☛ पाँचवे दृश्य में सामूहिक नृत्य को सम्राट तथा उसके घुड़सवार सैनिक देखते हुए प्रदर्शित किये गये हैं। ऐसा लगता है कि घोड़ों पर सवार सैनिक किसी शोभायात्रा में जा रहे हैं।
- ☛ अश्व-आकृतियों को बड़ी सजीवता के साथ चित्रित किया गया है। सम्राट राजसी वेशभूषा में हैं तथा उसके सिर पर राजमुकुट (छत्र) है।
- ☛ छठा दृश्य हाथियों तथा घोड़ों पर सवार, स्त्री-पुरुषों की यात्रा का है। हाथी पर एक महाकाय पुरुष तथा तीन स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। बीच की स्त्री कंचुकी पहने हैं जबकि शेष के ऊपरी भाग नग्न हैं। वे कुण्डल, हार, कंगन जैसे आभूषण पहने हुए हैं।
- ☛ इनके पीछे एक दूसरा हाथी है। इस पर पहले जैसा ही महाकाय पुरुष एवं तीन स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। केश विन्यास, वेशभूषा, हाथियों पर शोभायात्रा का प्रदर्शन आदि का अंकन बड़ी कुशलता एवं सजीवता से किया गया है।
- ☛ गुफा की छत पर मनुष्य, पशु, पक्षी, पुष्प, लता पुत्र आदि का मनोहर चित्रण है।

- ❶ इस प्रकार अजंता के ही समान बाघ की चित्रकला भी प्रशंसनीय है। जहाँ तक चित्रण तकनीक का प्रश्न है गुफा की दीवारों पर लेप नहीं लगाये जाते थे। चिकनी दीवार पर चूने की सफेदी की जाती थी तथा उसके सूखने पर चित्र बनाये जाते थे।
- ❷ रात में उनमें नमी की जाती थी तथा सुबह पानी में रंग धोलकर चित्र बनाये जाते थे। रंगों में लाल, पीला, सफेद, खाकी तथा काले रंग का प्रयोग किया गया है।

बादामी चित्रकला

- ❶ अभी तक ज्ञात प्राचीनतम ब्राह्मणीय चित्रकलाएं अपने खंडित रूप में बादामी की गुफाओं के गुफा सं. 3 में पाई जाती है। उनका संबंध लगभग आठवीं शताब्दी ईस्वी से है। तथाकथित शिव और पार्वती कुछ भली-भाँति संरक्षित रूप में पाये जाते हैं।
- ❷ हालाँकि इसमें अजंता और बाघ तकनीक का पालन किया गया है। प्रतिरूपण संरचना और अभिव्यक्ति में कहीं अधिक संवेदनशील हैं और खाका कोमल तथा लचीला है।

सित्तनव सल चित्रकला

- ❶ अजन्ता, बाघ और बादामी चित्रकलाएं उत्तर तथा दक्षिण की शास्त्रीय परंपरा का उत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। सित्तनव सल चित्रकलाओं के केन्द्र दक्षिण में अपनी पैठ की सीमा को दर्शाते हैं। सित्तनव सल की चित्रकलाएं जैन विषयों और प्रतीक प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं।
- ❷ यह तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई शहर के उत्तर-पश्चिम में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई है। यहां की चित्रकला में अजंता के ही समान मानदण्डों को अपनाया गया। इनकी रूपरेखाओं को हल्की लाल पृष्ठभूमि पर गाढ़े रंग से चित्रित किया गया है।
- ❸ बरामदे की छत पर महान सौन्दर्य, पक्षियों सहित कमल के पुष्प, तालाब, हाथियों, भैंसों और फूल तोड़ते हुए एक युवक के एक विशाल सजावटी दृश्य को चित्रित किया गया।

एलोरा चित्रकला

- ❶ भित्तिचित्र की आगामी शृंखला एलोरा में जीवंत रूप में मिलती है, जो कि अत्यधिक महत्व और पवित्रता का एक स्थल है। 8 वीं से 10 वीं शताब्दी ईस्वी सन् के बीच अनेक हिन्दू, बौद्ध और जैन मंदिरों की खुदाई जीवित शैल से की गई थी।
- ❷ इन मंदिरों के अलग-अलग भागों की छतों पर और कुछ सहयोजित जैन गुफा मंदिरों की दीवारों पर चित्रकला के अनेक विखण्डित टुकड़े हैं।
- ❸ एलोरा की मोटे किनारे वाली चित्रकलाओं की संरचना को आयताकार फलकों द्वारा मापा जाता है। एलोरा की चित्रकलाएं

अजंता की चित्रकलाओं के शास्त्रीय मानदंड से भिन्न हैं।

- ❶ द्रव्यमान और वृत्ताकार कोमल बहिररेखा तथा साथ ही साथ गहराई से बाहर निकलने के भ्रम के प्रतिरूपण की शास्त्रीय परंपरा की निस्संदेह पूर्णरूपेण अवहेलना नहीं की गयी।

लेपाक्षी चित्रकला

- ❶ आन्ध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित विजयनगरकालीन चित्रकला। भारत में भित्तिचित्र की अंतिम शृंखला हिन्दपुर के निकट लेपाक्षी मंदिर में पाई जाती है। इसका सम्बन्ध 16 वीं शताब्दी से है।
- ❷ इन चित्रकलाओं पर व्यापक रूप से चित्रवल्लरियों के भीतर रहते हुए बल दिया गया है। इसमें शैव तथा धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया है।
- ❸ आकृतियों को पार्श्विका में कुछ असामान्य रूप में दर्शाया गया है। विशेष रूप से चेहरों के निरूपण को जिसमें द्वितीय नेत्र को आकाश में क्षैतिज देखते हुए दिखाया गया है।
- ❹ इन आकृतियों की वर्ण योजना तथा अलंकरण अति मनोहारी है और भारतीय कलाकारों की अति परिष्कृत रुचि को सिद्ध करते हैं।

लघु चित्रकारी

- ❶ 'Miniature' अर्थात् लघु शब्द लैटिन शब्द 'मिनियम' से लिया गया है। इसका अर्थ लाल रंग का शीशा होता है। इस रंग का उपयोग पुनर्जागरण काल के दौरान प्रदीप्त पांडुलिपियों में किया जाता था।

लघु चित्रकारी की विशेषताएं

- चित्र का विषय वास्तविक आकार के 1/6 भाग से अधिक पर नहीं चित्रित किया जाना चाहिए।
- चित्र 25 वर्ग इंच से बड़े नहीं होने चाहिए।
- अधिकांश भारतीय लघु चित्रों में मानव आकृति एकपृष्ठीय रूपरेखा के साथ दिखाई देती है। जिनमें बाहर की ओर उभरी आँखें, नुकीली नाक और पतली कमर हैं।

पाल शैली

- ❶ भारत में लघु चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन निष्पादित बौद्ध धार्मिक पाठों और 11 वीं - 12 वीं शताब्दी ईस्वी सन् के दौरान पश्चिम भारत में निष्पादित जैन पाठों के सचित्र उदाहरणों के रूप में विद्यमान हैं। नालन्दा, ओदन्तपुरी, विक्रमशिला और सोमपुरी के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा एवं कला के महान केन्द्र थे।
- ❷ पाल चित्रकला की विशेषता इसकी चक्रदार रेखा और वर्ण की हल्की आभाएं हैं। यह एक प्राकृतिक शैली है जो समकालिक कांस्य पाषाण मूर्तिकला के आदर्श रूपों में मिलती है।

पश्चिमी भारतीय शैली (12-16वीं शताब्दी)

- ❶ चित्रकला की पश्चिमी भारतीय शैली गुजरात, राजस्थान और मालवा क्षेत्र में प्रचलित थी। इस शैली में शरीर की कतिपय विशेषताओं, नेत्रों, वक्षस्थलों और नितम्बों की एक अतिशयोक्ति विस्तार को देख पाते हैं।
- ❷ नाक-नक्शे की कोणीयता सहित आकृतियां सपाट हैं और नेत्र बाहर निकले हुए हैं। पश्चिमी भारत में कलात्मक क्रियाकलापों का प्रेरक बल जैनवाद था।

अन्य शैलियां – (1500 - 1800 ईस्वी सन्)

- ❶ कल्पसूत्र की कुछ सचित्र पांडुलिपियों के किनारे पर दिखाई देने वाली फारसी शैली और शिकार के दृश्यों से स्पष्ट है कि 15वीं शताब्दी के दौरान चित्रकला की फारसी शैली ने चित्रकला की पश्चिम भारतीय शैली को प्रभावित करना आरंभ कर दिया था।
- ❷ पश्चिम भारतीय पांडुलिपियों में गहरा नीला और सुनहरा रंग का प्रयोग प्रारंभ हो जाना भी फारसी चित्रकला का प्रभाव समझा जाता है।
- ❸ भारत आने वाली ये फारसी चित्रकलाएं सचित्र पांडुलिपियों के रूप में थीं। इनकी भारत में नकल तैयार की गयी।
- ❹ नियतनामा शैली को मालवा के गयासुद्दीन खिलजी के समय लिखना प्रारंभ किया गया था। इसमें दासियों को भोजन पकाते हुए और गयासुद्दीन को पर्यवेक्षण करते हुए दिखाया गया है।
- ❺ नियतनामा शैली में फारसी प्रभाव घुमावदार जैसे बालों, फूलों से लदे वृक्षों, घास भरे गुच्छों, और पृष्ठभूमि में फूलों से लदे पौधों, महिलाओं की आकृतियों तथा परिधानों में दृष्टिगोचर होता है।

मुगल शैली (1560 - 1850 ई. सन्)

- ❶ अकबर: चित्रकला की मुगल शैली की शुरुआत को भारत में चित्रकला के इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना समझा जाता है। सम्राट अकबर को चित्रकला और वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थी।
- ❷ अकबर के शासन के प्रारंभ में दो फारसी अध्यापकों मीर सैय्यद अली और अब्दुस्मद खान की देख रेख में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी। मुगल शैली का विकास चित्रकला की स्वदेशी शैली और फारसी चित्रकला की सफाविद शैली के एक उचित संश्लेषण के परिणामस्वरूप हुआ था।
- ❸ प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखण पर आधारित सुनम्य प्रकृतिवाद, मुगल शैली की एक विशेषता है। यह सौन्दर्य के उच्च गुणों से परिपूर्ण है और प्राथमिक रूप से वैभवशाली और निरपेक्ष है।

- ❶ क्वीनलैण्ड कला संग्रहालय (अमेरिका) में तूती-नामा की एक सचित्र पांडुलिपि मुगल शैली की प्रथम कलाकृति प्रतीत होती है। हम्जानामा की शैली तूती-नामा की अपेक्षा अधिक विकसित और परिष्कृत है। हम्जानामा के सचित्र उदाहरण स्विट्जरलैण्ड के एक निजी संग्रहालय में हैं।
- ❷ यह एक मण्डप की ऊपरी मंजिल से एक बहुतलीय मीनार पर एक पक्षी के दुखद आखेट बाणों के साथ दिखाते हैं।
- ❸ वृक्षों की किस्मों को प्रमुख रूप से दक्कनी चित्रकला से लिया गया है और महिला आकृतियों का अनुकूलन राजस्थानी प्राचीन कला से किया गया है।
- ❹ महिलाओं ने चार कोनों वाले नोकदार लहंगे तथा पारदर्शी मुस्लिम बुर्के पहने हुए हैं। पुरुषों की पगड़ियां छोटी तथा कसी हुई हैं।
- ❺ **जहांगीर:** जहांगीर के अधीन चित्रकला ने अधिकाधिक आकर्षण, परिष्कार और गरिमा प्राप्त की। जहांगीर को प्रकृति के प्रति अधिक आकर्षण था और उन्हें पक्षियों, पशुओं तथा पुष्पों को चित्रित करने में प्रसन्नता होती थी। इस युग की कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं—
 1. अयार-ए- दानिश नामक पशुओं के किस्से कहानियों की एक पुस्तक
 2. अनवर-ए- सुहेली
- ❶ इस काल के दौरान दरबार के दृश्यों, प्रतिकृतियों, पक्षियों, पशुओं और पुष्पों का प्रयोग चित्रकला में किया गया है। 'जहांगीर की प्रतिकृति' जहांगीर के युग के दौरान निष्पादित लघु चित्रकलाओं का एक प्रतीकात्मक उदाहरण है।
- ❷ यह प्रतिकृति अपने उत्कृष्ट आरेखण और परिष्कृत प्रतिरूपण तथा वास्तविकता के लिए असाधारण है। फूलों के डिजाइन से सजे हुए किनारों पर सुनहरे रंग का उदारतापूर्वक प्रयोग किया गया है।
- ❸ किनारों पर फारसी शैली दिखाई देती है। मुगल सम्राट के उदाहरणों का पालन करते हुए दरबारियों और प्रांतीय अधिकारियों ने भी चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया।
- ❹ इन कलाकारों की कलाकृतियों को लोकप्रिय मुगल या प्रांतीय मुगल चित्रकला की संज्ञा दी गई। चित्रकला की इस शैली में राजसी मुगल चित्रकला की सभी चित्रकलाएं तो हैं लेकिन ये निम्न कोटि की हैं।
- ❺ 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामायण की एक श्रृंखला की प्रतीकात्मक लोकप्रिय मुगल शैली में लंका में राम और रावण के सैनिकों के बीच लड़ाई दिखाई गई है राम, लक्ष्मण के साथ अग्रभाग में बाईं ओर दिखाई दे रहे हैं।
- ❶ जबकि रावण अपने राजमहल में दानव प्रमुखों के साथ सुनहरे किले में विचार-विमर्श करते हुए दिखाई दे रहा है। आरेखण

अच्छा है लेकिन उतना परिष्कृत नहीं है जैसा राजसी मुगल चित्रकला में देखने को मिलता है।

- ☛ **शाहजहां:** शाहजहां के अधीन मुगल चित्रकला ने अपने अच्छे स्तर को बनाए रखा तथापि उनके राज्य की (शासन काल) अंतिम अवधि के दौरान शैली परिपक्व हो गयी थी।
- ☛ शाहजहां के चित्रकारों ने चित्रकला पर पर्याप्त ध्यान दिया था। उनके समय के जाने-माने कलाकार विचित्र, चैतरमन, अनूप चत्तर आदि हैं।
- ☛ चित्रकला के अतिरिक्त, तपस्वियों और रहस्यवादियों के समूहों को दर्शाने वाली अन्य चित्रकलाएं और अनेक निदर्शी पांडुलियां भी इस अवधि के दौरान निष्पादित की गईं। इनमें कुछ पांडुलिपियां इस प्रकार हैं—
 1. गुलिस्ता तथा साड़ी का बुस्तान
 2. विडंसर दुर्ग में शाहजहांनामा
- ☛ शाहजहां काल में लघु चित्रकला सूफियों की एक सभा को चित्रित करती है। सूफी खुले स्थान पर बैठे हुए हैं और चर्चा में व्यस्त हैं।
- ☛ यह शाहजहांकाल की मुगल शैली के ग्रहणशील प्रकृतिवाद को प्रदर्शित करती है। आरेखण परिष्कृत है, पृष्ठभूमि हरी है तथा आकाश सुनहरे रंग का है।
- ☛ **औरंगजेब:** औरंगजेब अति धर्मनिष्ठ था, इसलिए कला को प्रोत्साहित नहीं किया था। इसके शासन काल में चित्रकला के स्तर में गिरावट आई और इसकी पूर्ववर्ती गुणवत्ता कहीं विलुप्त हो गई।
- ☛ राजदरबार के असंख्य चित्रकार प्रांतीय राजदरबारों को पलायन कर गये।

दक्कनी चित्रकला शाखा-(1560-1800 ईस्वी)

- ☛ 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान दक्कन में चित्रकला के प्रारंभिक केन्द्र अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा में थे। दक्कन में प्रारंभ में चित्रकला का विकास मुगल शैली से स्वतंत्र रूप में होता रहा किंतु बाद में मुगल शैली का अधिकाधिक प्रभाव पड़ा था।
- ☛ **अहमदनगर:** इस चित्रकला के प्रारंभिक उदाहरण हसन निजाम शाह प्रथम (1553-65 ई.) और उनकी रानी की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं के एक खंड में निहित है। यह पांडुलिपि तारीफ-इन-हुसैन शाही के नाम से जानी जाती है। एक सचित्र उदाहरण में राजा को राजसिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है।
- ☛ चित्रकला में दृष्टिगोचर महिला उनका ध्यान रख रही है। महिला की आकृति का संबंध मालवा की उत्तरी परंपरा से है।
- ☛ लम्बी चोटी उत्तरी परिधान लेकिन शरीर से होता हुआ एक लंबा रुमाल दक्षिण का फैशन है। चित्रकला में प्रयोग वर्ण

भड़कीले तथा चटकीले हैं। ये उत्तरी में प्रयुक्त वर्णों से भिन्न हैं।

- ☛ **बीजापुर:** यहां की लघु चित्रकलाओं में से एक 'समृद्धि का राजसिंहासन' को दर्शाती है। महिला आकृति पर लेपाक्षी भित्ति चित्रकला का प्रभाव है।
- ☛ भड़कीले रंगों की योजना ताड़ के वृक्ष, पशु और पुरुष तथा महिलाएं सभी का संबंध दक्कनी परंपरा से है।
- ☛ राजसिंहासन में सबसे ऊपर सुनहरे रंगों के प्रचुर मात्रा में प्रयोग, फूलों के कुछ पौधे और अरबस्कों को फारसी परंपरा से लिया गया है।
- ☛ इब्राहिम शाह द्वितीय के काल के प्रारंभिक चित्रों पर फारसी चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।
- ☛ इसकी वेशभूषा पर उत्तर भारतीय (विशेष रूप से मालवा) शैली का प्रभाव पड़ा।
- ☛ यह शैली यथार्थवाद से काफी दूर थी, इसमें मुख्यतः प्रेम, संगीत आदि का चित्रण होता है।
- ☛ **गोलकुंडा:** राजा ने श्वेत लबादा पहना हुआ है जिस पर लम्बवत पट्टी पर काशीदाकारी की गई है, जो कि गोलकुंडा के राजदरबार से सहयोजित एक प्रारूपी परिधान है।
- ☛ भवन, परिधान, आभूषण और पोट आदि को चित्रित करते समय सुनहरे रंग का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है।
- ☛ गोलकुंडा चित्रकला के अन्य उत्कृष्ट उदाहरण चेस्टरनर बिट्टी पुस्तकालय, डबलिन में लगभग 1605 ई. की, मैना पक्षी के साथ महिला, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, एक सूफी कवि की एक सचित्र पांडुलिपि और दो प्रतिकृतियां जिनमें एक कवि को एक उद्यान में दिखाया गया है।
- ☛ एक सुरुचिपूर्ण पोषाक पहने हुए एक युवक सुनहरी चौकी पर बैठा हुआ है तथा पुस्तक पढ़ रहा है।
- ☛ प्रारंभिक दक्षिण चित्रकला ने, जैसा की महिला की आकृति और परिधान से स्पष्ट है, मालवा में फल-फूल रही मुगल पूर्व चित्रकला की उत्तरी परंपरा के और विजयनगर की भित्ति की दक्षिणी परंपरा के प्रभावों को आत्मसात कर लिया।
- ☛ क्षितिज सुनहरा आकाश और भूदृश्यांकन की अभिक्रिया के दौरान फारसी चित्रकला के प्रभाव को देखा गया है।
- ☛ **हैदराबाद:** औरंगजेब के शासनकाल में दक्कन में जाकर बसने वालों और वहीं संरक्षण मांगने वाले मुगल चित्रकार, दक्कन चित्रकला की मुगल शैली के प्रमुख केन्द्र हैदराबाद और अन्य केन्द्रों पर विभिन्न शैलियों के प्रभाव व विकास के मुख्य कारक थे।
- ☛ 18वीं और 19वीं शताब्दी की दक्कनी चित्रकलाओं की सुस्पष्ट विशेषताएं जातीय किस्मों, परिधानों, आभूषण, वनस्पति, जीव-जन्तु, भू-दृश्यांकन और वर्णों की अभिक्रिया

- में देखी जाती है। एक राजकुमारी को उसकी दासियों के साथ दिखाने वाली एक लघु चित्रकला, हैदराबाद चित्रकला विद्यालय का एक प्रतीकात्मक उदाहरण है।
- ❖ यह राजकुमारी छतरी से ढके हुए पूर्णतया सुसज्जित छज्जे पर लेटी हुई है। इस चित्रकला की शैली सजावटी है। हैदराबाद की चित्रकला भड़कीले रंग, दक्षिणी मुखाकृति किस्में और परिधान जैसी प्रारूपी विशेषताओं को लघु चित्रकला में देखा जा सकता है।
 - ❖ **तंजावुर/तंजौर:** 18वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर और 19वीं शताब्दी के दौरान, चित्रकला की एक शैली की विशेषताएं सुदृढ़ आरेखण, छायाकरण की तकनीकें और अभिवृद्धि तथा चटकीले वर्णों का प्रयोग करना था, जिसने दक्षिण भारत के तंजावुर में उन्नति की।
 - ❖ राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में तंजावुर चित्रकला का एक प्रतीकात्मक उदाहरण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का एक सचित्र काष्ठ फलक है जिस पर राम के राज्याभिषेक को दर्शाया गया है।
 - ❖ इस दृश्य को व्यापक रूप से सुसज्जित मेहराबों के नीचे मूर्त रूप दिया गया है।
 - ❖ राजसिंहासन पर मध्य में राम और सीता बैठे हैं, राम के अनुज और एक महिला उनकी देखभाल कर रहे हैं। बाएं और दाहिने पैनों में ऋषि, राजदरबारी और राजकुमार दिखाई दे रहे हैं।
- मध्य भारत और राजस्थानी शैली-(17-19वीं शताब्दी)**
- ❖ 16वीं शताब्दी में मध्य भारत और राजस्थान में पश्चिमी भारत और चौरपंचाशिका शैलियों के रूप में आदिम कला की परंपराएं पहले से ही विद्यमान थी। जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान चित्रकला की विभिन्न शैलियों के उद्गम तथा समृद्धि के लिए एक आधार के रूप में कार्य किया।
 - ❖ मुगल शैली के लोकप्रिय रूपान्तर, जिसे ये चित्रकार विभिन्न स्थानों पर ले गए थे, ने वहां चित्रकला की पहले से विद्यमान शैलियों को प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप 17वीं व 18वीं शताब्दियों में राजस्थान तथा मध्य भारत में चित्रकला की अनेक नई शैलियों का उद्भव हुआ था।
 - ❖ इनमें से चित्रकला के महत्वपूर्ण विद्यालय मालवा, मेवाड़, बूंदी-कोटा, आमेर, जयपुर, बीकानेर, मारवाड़ और किशनगढ़ में थे।
 - ❖ **मालवा:** मालवा शैली में निष्पादित की गई कुछ महत्वपूर्ण चित्रकलाएं हैं, 1634 ई. रसिकप्रिया की एक श्रृंखला, 1652 ई. में नसरतगढ़ नामक एक स्थान पर चित्रित की गई, अमरु शतक की एक श्रृंखला और 1680 ई. में माधोदास नामक एक कलाकार नरसिंह शाह द्वारा चित्रित की गई रागमाला की एक श्रृंखला।
 - ❖ 1680 ई. में रागमाला की एक श्रृंखला का उदाहरण मेघ राग का निरूपण करता है।
 - ❖ इस लघु चित्रकला में नीले वर्ण वाले राग को तीन महिला संगीतकारों द्वारा बजाए जा रहे संगीत की थाप पर एक महिला को नृत्य करते दिखाया गया है।
 - ❖ इस दृश्य की पृष्ठभूमि श्याम है, आकाश काले बादलों से घिरा हुआ है, और बिजली चमक रही है तथा वर्षा को श्वेत बिंदु रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। आलेख सबसे ऊपर नागरी-लिपि में लिखा गया है।
 - ❖ **मेवाड़:** मेवाड़ चित्रकला के प्रारंभिक उदाहरण के रूप में 1605 ई. सन् में मिसदीं द्वारा उदयपुर के निकट एक छोटे से स्थान 'चावंद' में चित्रित की गई रागमाला की एक श्रृंखला को देखा जा सकता है।
 - ❖ इस श्रृंखला की अधिकांश चित्रकलाएं श्री गोपी कृष्ण कनोडिया के संग्रह में हैं।
 - ❖ रागमाला की एक अन्य श्रृंखला को साहिलदीन ने चित्रित किया था।
 - ❖ मेवाड़ चित्रकला के अन्य उदाहरण 1651 ई. की रामायण की तृतीय पुस्तक (अरण्य काण्ड) का सचित्र उदाहरण जो सरस्वती भंडार उदयपुर में है।
 - ❖ साहिलदीन द्वारा चित्रित की गई रागमाला श्रृंखला का एक उदाहरण अब राष्ट्रीय संग्रहालय में है जो ललित रागनी को दर्शाने वाली एक चित्रकला है।
 - ❖ इस शैली के रंगों में पीला, लाल, तथा केसरिया प्रमुख है। मेवाड़ शैली में जैन व गुजरात की चित्रकलाओं का मिश्रण दृष्टिगोचर होता है।
 - ❖ लोक कला की रक्षता, मोटापन, रेखाओं का भारीपन इसकी विशेषताएं रही हैं।
 - ❖ मानवकृतियों में चेहरे लम्बी नुकीली नासिका, मीन नयन तथा आकृतियां छोटे कद की हैं। पुरुषों ने पगड़ी और स्त्रियों ने चोली, पारदर्शी ओढ़नी, भूरेदार अथवा सादा लहंगा पहना है।
 - ❖ ललित रागिनी को दर्शाने वाली एक चित्रकला में नायिका एक मंडप के नीचे बिस्तर पर लेटी है तथा आंखें बंद हैं। इसमें एक द्वार भी है। एक दासी उसके चरण दबा रही है।
 - ❖ **बूंदी:** चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ के अति निकट है लेकिन बूंदी शैली गुणवत्ता में मेवाड़ शैली से आगे है।
 - ❖ भैरवी रागिनी को दर्शाते हुए एक चित्रकला इलाहाबाद संग्रहालय में है जो बूंदी चित्रकला का प्रारंभिक उदाहरण है।
 - ❖ 17वीं शताब्दी के अंत में रसिकप्रिया की एक श्रृंखला में एक दृश्य है जिसमें कृष्ण एक गोपी से मक्खन लेने का प्रयास कर रहे हैं।
 - ❖ पृष्ठ भूमि में वृक्ष और अग्रभाग में एक नदी है जिसे तरंगी

- रेखाओं द्वारा चित्रित किया गया है। नदी में फूल और जलीय पक्षी दिखाई दे रहे हैं।
- ❶ उस चित्रकला का चमकीले लाल रंग का एक किनारा है, जैसा कि इस लघु चित्रकला से स्पष्ट होता है।
 - ❷ बूंदी चित्रकला के विशेष गुण भड़कीले तथा चमकीले वर्ण, सुनहरे रंग में उगता हुआ सूरज, किरमिजी लालरंग का क्षितिज, घने और अर्द्ध प्रकृतिवादी वृक्ष है।
 - ❸ चेहरे के परिष्कृत आरेखण में मुगल प्रमाण और वृक्षों की अभिक्रिया में प्रकृतिवाद का एक तत्व दृष्टिगोचर होता है।
 - ❹ कोटा: बूंदी शैली से काफी कुछ सदृश्य चित्रकला की एक शैली 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के दौरान बूंदी के निकट कोटा में प्रचलित थी।
 - ❺ बाघ और भालू के आखेट के विषय कोटा में अति लोकप्रिय थे। कोटा की चित्रकलाओं में अधिकांश स्थान पर्वतीय जंगल ने ले लिया जिसे असाधारण आकर्षण के साथ प्रस्तुत किया गया है।
 - ❻ आमेर-जयपुर: आमेर राज्य के मुगल सम्राटों से घनिष्ठ संबंध थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में आमेर राज्य की पुरानी राजधानी आमेर में चित्रकला के विद्यालय की स्थापना की गयी।
 - ❼ 18वीं शताब्दी में कलात्मक क्रियाकलाप का केन्द्र नई राजधानी जयपुर चला गया था।
 - ❽ जयपुर शैली के चित्रों में भक्ति तथा श्रृंगार का सुंदर समन्वय मिलता है। कृष्ण-लीला, राग-रागिनी, रासलीला के अतिरिक्त शिकार तथा हाथियों की लड़ाई के अद्भुत चित्र बनाये गये।
 - ❾ विस्तृत मैदान, वृक्ष, मंदिर के शिखर, अश्वरोही आदि प्रधानरूप ही चित्रित हैं। जयपुर के कलाकार उद्यान चित्रण में भी अत्यंत दक्ष थे।
 - ❿ उद्यानों में भली-भांति वृक्षों, पक्षियों तथा बंदरों का सुंदर चित्रण किया गया है।
 - ⓫ मारवाड़: मारवाड़ में चित्रकला के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक 1623 ई. में वीरजी नाम के एक कलाकार द्वारा पाली में चित्रित की गई रागमाला की एक श्रृंखला है जो कुमार संग्राम सिंह के संग्रह में है।
 - ⓬ लघु चित्रकलाओं को एक आदिम तथा ओजस्वी लोकशैली में निष्पादित किया जाता है। ये मुगल शैली से कदापि प्रभावित नहीं थे।
 - ⓭ प्रतिकृतियों, राजदरबार के दृश्य, रागमाला की श्रृंखला और बारहमास, आदि को शामिल करते हुए बड़ी संख्या में लघु चित्रकलाओं को 17वीं से 19वीं शताब्दी तक मारवाड़ में पाली, जोधपुर और नागौर आदि जैसे चित्रकला के अनेक केन्द्रों पर निष्पादित किया गया था।
 - ⓮ बीकानेर: बीकानेर राज्य के मुगलों से घनिष्ठ संबंध थे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुछ मुगल कलाकारों को बीकानेर के राजदरबार ने संरक्षण प्रदान किया और ये चित्रकला की एक ऐसी नई शैली को प्रारंभ करने के प्रति उत्तरदायी थे।
 - ⓯ जिसकी मुगल और दक्कनी शैलियों से काफी समानता थी। इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है मुस्लिम कलाकारों द्वारा हिंदू धर्म संबंधित एवं पौराणिक विषयों पर चित्रांकन करना।
 - ⓰ किशनगढ़ शैली: 18वीं शताब्दी के राजा सावंत सिंह (1748-57 ई.) के संरक्षणाधीन किशनगढ़ में राजस्थान की सर्वाधिक आकर्षक शैली का विकास हुआ।
 - ⓱ राजा सावंत सिंह श्रृंगारप्रिय व अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरीदास के नाम से जाने जाते थे।
 - ⓲ इस शैली पर मुगल प्रभाव भी पड़ा। इस कला का भारतीय लघुकला में अद्वितीय स्थान है।
 - ⓳ नारी चित्रण विशेष रूप से सुंदर हैं स्त्रियों के चेहरे कोमल हैं, कहीं भी भारीपन नहीं है। शरीर लताओं के समान पतला व छरहरा चित्रित किया गया है।
 - ⓴ गोवर्धन-धारण चित्र में अनेक आकृतियां बनाई गई हैं। चित्रों में काले, सफेद, नीले एवं हरे रंगों की प्रधानता है। पीला, लाल रंग संतुलित रूप में प्रयोग किए गए हैं।
 - ⓵ राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में किशनगढ़ विद्यालय की एक सुन्दर लघु चित्रकला को यहां सचित्र प्रस्तुत किया गया है।
 - ⓶ यह संध्या में कृष्ण को अपने गोपिकाओं और गायों के साथ गोकुल लौटने के सुन्दर ग्रामीण दृश्य को चित्रित करती है।
- पहाड़ी चित्रकला शैली (17-19वीं शताब्दी ई.)**
- ❶ पहाड़ी क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब के कुछ निकटवर्ती क्षेत्र, जम्मूक्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र शामिल हैं।
 - ❷ इस समूचे क्षेत्र को छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित किया गया है। इस क्षेत्र में विकसित इस चित्रकला शैली पर पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की भावनाओं तथा संगीत व धर्म संबंधी परंपराओं की स्पष्ट छाया दृष्टिगोचर होती है।
 - ❸ पहाड़ी शैली में प्रेम का विशिष्ट चित्रण दृष्टिगत होता है। कृष्ण-राधा के प्रेम के चित्रों के माध्यम से इनमें स्त्री-पुरुष प्रेम संबंधों को बड़ी बारीकी एवं सहजता से दर्शाने का प्रयास किया गया है।
 - ❹ बशोली शैली: पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का प्रारंभिक केन्द्र बशोली था जहां राजा कृपाल के संरक्षणाधीन एक कलाकार जिसे देवी दास नाम दिया गया था।
 - ❺ चित्रकला की बशोली शैली की विशेषता प्रभावशाली तथा सुस्पष्ट रेखा और प्रभावशाली चमकीले वर्ण है। बशोली शैली विभिन्न राज्यों तक फैली और 18वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही।

- ❖ मुखाकृति शैली में एक परिवर्तन आया जो कुछ भारी हो गया है।
- ❖ साथ ही वृक्षों के रूपों में परिवर्तन आया जिसमें कुछ-कुछ प्राकृतिक विशेषताओं को अपना लिया गया है। ऐसा मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण हो सकता है।
- ❖ बशोली शैली के प्रभावशाली तथा विषम वर्गों के प्रयोग, एक वर्णीय पृष्ठभूमि, बड़ी-बड़ी आंखें, मोटा व ठोस आरेखण, आभूषणों में हीरों को दिखाने के लिए बाहर निकले हुए पंखों के प्रयोग, तंग आकाश और लाल किनारा जैसी सामान्य विशेषताएं इस लघु चित्रकला में देखी जा सकती हैं।
- ❖ **गुलेर शैली:** बशोली शैली के अंतिम चरण के पश्चात् चित्रकलाओं के जम्मू समूह का उद्भव हुआ जिसमें मूल रूप से गुलेर से संबंध रखने वाले और जसरोटा में बस जाने वाले एक कलाकार नैनसुख द्वारा जसरोटा के राजा बलवन्त सिंह की प्रतिकृतियां शामिल हैं। उसने जसरोटा और गुलेर दोनों स्थानों पर कार्य किया।
- ❖ ये चित्रकलाएं नयी प्राकृतिक तथा कोमल शैली में हैं। जो बशोली कला की प्रारंभिक परंपराओं में एक परिवर्तन का द्योतक है।
- ❖ प्रयुक्त वर्ण कोमल तथा शीतल हैं। पहाड़ी क्षेत्र में सृजित लघु चित्रकलाओं का सर्वोत्तम समूह भागवत की सुप्रसिद्ध शृंखला, गीत गोविन्द, बिहारी सतसई, बारहमासा और 1760-70 ई. में चित्रित की गई रागमाला का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❖ इन शृंखलाओं के उद्गम का स्थान स्पष्ट ज्ञात नहीं है। इन्हें या तो गुलेर या कांगड़ा या फिर किसी अन्य निकटवर्ती स्थान पर चित्रित किया गया होगा।
- ❖ भागवत और अन्य शृंखलाओं सहित गुलेर प्रतिकृतियों की शैली के आधार पर गुलेर शैली नाम के एक सामान्य शीर्षक के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया है।
- ❖ इनकी शैली प्रकृतिवादी, सुकोमल और गीतात्मक है। इनमें महिला आकृति विशेष रूप से सुकोमल है जिनमें सुप्रतिरूपित चेहरे, छोटी और उल्टी नाक और बालों को सूक्ष्म रूप से बांधा गया है।
- ❖ **कांगड़ा शैली:** गुलेर शैली के पश्चात् कांगड़ा शैली चित्रकला की एक अन्य शैली का उद्गम 18वीं शताब्दी में हुआ जो पहाड़ी चित्रकला के तृतीय चरण का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❖ कांगड़ा शैली का विकास गुलेर शैली से हुआ। इसमें गुलेर शैली की आरेखण में कोमलता और प्रकृतिवाद की गुणवत्ता जैसी प्रमुख विशेषताएं निहित हैं।
- ❖ चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा शैली का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये कांगड़ा के राजा संसार चंद की प्रतिकृति की शैली के समान हैं।
- ❖ इन चित्रकलाओं में, पार्श्विका में महिलाओं के चेहरों पर नाक लगभग माथे की सीध में है, नेत्र लंबे तथा तिरछे हैं और टुड्डी नुकीली है और बालों का एक सपाट समूह बनाया गया है।
- ❖ कांगड़ा शैली कांगड़ा, गुलेर, बशोली, चम्बा, जम्मू, नूरपूर, गढ़वाल आदि विभिन्न स्थानों पर उन्नति करती रही।
- ❖ कांगड़ा शैली की चित्रकलाओं का श्रेय मुख्य रूप से नैनसुख परिवार को जाता है।
- ❖ **कुल्लू-मण्डी शैली:** पहाड़ी क्षेत्र के प्रकृतिवादी कांगड़ा शैली के साथ-साथ कुल्लू-मण्डी क्षेत्र में चित्रकला की एक लोक शैली ने भी उन्नति की तथा इसे मुख्य रूप से स्थानीय परंपरा से प्रेरणा मिली।
- ❖ इस शैली की विशेषता मजबूत एवं प्रभावशाली आरेखण और गाढ़ तथा हल्के रंगों का प्रयोग करना है।
- ❖ कुछ मामलों में कांगड़ा शैली के प्रभाव को देखा जाता है, फिर भी इस शैली ने अपनी विशिष्ट शास्त्रीय विशेषता को बनाए रखा।
- ❖ कुल्लू और मण्डी के शासकों की बड़ी संख्या में प्रतिकृतियां और अन्य विषयों पर लघु चित्रकलाएं इस शैली में उपलब्ध हैं।
- ❖ राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में भागवत की शृंखला से एक लघु चित्रकला को 1794 ई. सन् में श्री भगवान ने चित्रित किया था।
- ❖ इन सचित्र उदाहरणों में कृष्ण को अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाया गया है, जिससे गोकुलवासियों को इन्द्र के क्रोध से बचाया जा सके। कुल्लू चित्रकला का एक अन्य उदाहरण जिसमें दो युवतियां पतंग उड़ा रही हैं।
- ❖ यह लघु चित्रकला 18वीं शताब्दी की लोकशैली में है और ठोस व मजबूत आरेखण वर्ण योजना इसकी विशेषता है। पृष्ठभूमि हल्के नीले रंग की है।
- ❖ युवतियां प्ररूपी परिधान और आभूषण पहने हुए हैं। जो उस अवधि में कुल्लू क्षेत्र में प्रचलित थे। दो उड़ते हुए तोते आकाश को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं।

उड़ीसा शैली

- ❖ उड़ीसा में ताड़ के पत्ते का प्रयोग 19वीं शताब्दी तक होता रहा था। बहिरेंखा के आरेखण को ताड़ के पत्ते पर एक सुई से चित्रित किया गया है।
- ❖ फिर चित्र पर काष्ठ कोयला या स्याही को रगड़ कर चित्र को उभारा गया है।
- ❖ अभिकल्पों को भरने के लिए कुछ रंगों का प्रयोग किया गया

था तथापि कागज पर चित्रकारी करने की यह तकनीक भिन्न थी, पर चित्रकला के अन्य विद्यालयों द्वारा प्रयुक्त तकनीक के समान थी।

- ❶ प्रारंभिक पांडुलिपियां आरेखण में स्वच्छता को दर्शाती हैं। 18वीं शताब्दी में यह रेखा मोटी और कच्ची हो जाती है। लेकिन शैली सामान्य रूप से अति सजावटी तथा अलंकारी हो जाती है।
- ❷ राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में लगभग 1800 ईस्वी सन् की गीत गोविन्द की एक श्रृंखला में सचित्र उदाहरण राधा और कृष्ण को चित्रित करता है।
- ❸ वे एक लाल पृष्ठभूमि में एक कमजोर वृक्ष की इकहरी शाखाओं के नीचे आमने-सामने खड़े हैं।
- ❹ शैली अति अलंकृत है और सुदृढ़ आरेखण, वृक्ष का रूढ़ अंकन, आकृतियों का भारी अलंकरण और खूबसूरत चमकीली रंग योजनाओं का प्रयोग करना इसकी विशेषताएं हैं। सबसे ऊपर संस्कृत के लेख भी लिखे हैं।

आधुनिक चित्रकला

- ❶ कपोल-कल्पना से कुछ स्वतंत्र एक उदार दृष्टिकोण को स्वीकृति, जिसने कलात्मक अभिव्यक्ति को क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थापित कर दिया है।
- ❷ तकनीक का एक सकारात्मक उत्थान जो प्रचुर और सर्वोपरि दोनों ही हो गया है और कलाकार का एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उभरना।
- ❸ 19वीं शताब्दी के समाप्त होते-होते, भारतीय चित्रकला भारतीय वाद्य चित्रकला के एक विस्तार के रूप में, मुख्य रूप से राजनीतिक और समाज वैज्ञानिक दोनों प्रकार के ऐतिहासिक कारणों की वजह से बीच में ही रुक गई तथा इसमें गिरावट आने लगी एवं क्षीण और विवेकहीन अनुकृति के रूप में इसका हास होने लगा।
- ❹ देश के कई भागों में जीवित लोक कला के अधिक ठोस रूपों के अतिरिक्त चित्रकला की 'बाजार' और 'कंपनी शैलियों' के रूप में मध्यवर्ती अवधि के दौरान कला की कुछ छोटी-मोटी अभिव्यक्तियां ही देखने को मिलती हैं।
- ❺ इसके पश्चात् प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना का उदय हुआ।
- ❻ इसके सर्वप्रथम प्रतिवाद राजा रविवर्मा थे। भारतीय कला के समूचे इतिहास में इसके समकक्ष कोई नहीं है।
- ❼ जबकि भारतीय साहित्य में यदा-कदा कुछ संदर्भ मिलता है। राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला शैली का प्रवर्तक माना जाता था।
- ❽ इस शैली को पाश्चात्य तकनीकों और विषय वस्तुओं के भारी प्रभाव के कारण आधुनिक कहा जाता है।

- ❶ राजा रवि वर्मा केरल राज्य से संबंधित थे और अपने उत्कृष्ट कला कौशल और जीवंत चित्रकलाओं के कारण उन्हें पूर्व का राफेल नाम से जाना गया।
- ❷ उनके कुछ प्रसिद्ध कार्यों में लेडी इन द मून लाइट, मदर इंडिया इत्यादि सम्मिलित हैं।
- ❸ उन्हें रामायण, महाभारत, महाकाव्य पर आधारित अपनी चित्रकलाओं के लिए राष्ट्रव्यापी पहचान प्राप्त हुई, मुख्य रूप से रावण द्वारा सीता हरण नामक चित्रकारी के लिए।
- ❹ चित्रकार द्वारा बड़ी मात्रा में दृष्टि तथा इन्द्रिय स्तर अर्जित कर लिया गया, विशेष रूप से रंगों के प्रयोग के बारे में, अभिकल्प और संरचना की संकल्पना में और गैरपरंपरागत सामग्री को प्रयोग में लाने के संबंध में।
- ❺ हमने कला की समय के साथ अर्जित एकीकृत संकल्पना को खो दिया है, कला की आधुनिक अभिव्यक्ति ने वहां स्पष्टतः एक करवट ली है।
- ❻ जहां कोई एक तत्व, जिसने कभी कला को एक हितकारी अस्तित्व बना दिया था, अब शेष के आंशिक या समग्र अपवर्जन के प्रति असाधारण ध्यान का दावा करता है।
- ❼ व्यक्तिवाद में वृद्धि के परिणामस्वरूप और कला के सैद्धांतिक रूप से पृथक्करण के कारण कलाकारों की लोगों के साथ घनिष्टता की एक नई समस्या उत्पन्न हो गई।
- ❽ समकालीन भारतीय कला ने रविवर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके अनुयायियों तथा यहां तक कि अमृता शेरगिल के समय से एक लंबा सफर तय किया।
- ❹ लगभग सभी प्रतिष्ठित कलाकारों ने एक प्रकार की निरुपणीय या चित्र संबंधी कला से शुरुआत की थी।
- ❶ आकार और अन्तर्वस्तु के कष्टप्रद संबंध को सामान्यतः एक अनुपूरक स्तर पर रखा गया था।
- ❷ फिर विलोपन तथा सरलीकरण के विभिन्न चरणों के माध्यम से आयाम चित्रण और तन्मयता एवं अभिव्यक्तिवादी विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से, कलाकार लगभग गैर चित्र संबंधी या समग्र गैरचित्र-संबंधी स्तरों पर पहुंचे थे।

मधुबनी चित्रकला

- ❶ इस शैली के चित्र दो प्रकार के होते हैं—
 1. “भित्ति चित्र”
 2. अरिपन (रंगोली)
- ❶ प्रथम श्रेणी के चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं, जबकि दूसरे में प्रतीकों का उपयोग अधिक होता है।
- ❶ धार्मिक भित्ति-चित्रों में दुर्गा, राधा-कृष्ण, सीता-राम, शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी आदि का चित्रण होता है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं।

- ☞ इनमें कामदेव, रति, यक्षिणियों के अतिरिक्त पुरुष और नारी की जननेन्द्रियों के चित्र बनाये गये।
- ☞ पृष्ठभूमि के लिए पशु-पक्षियों और वनस्पतियों के चित्र बनाये जाते हैं, मगर इनका भी प्रतीकात्मक महत्व होता है।
- ☞ इस शैली के चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाये जाते हैं, लेकिन वर्तमान में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकन किया गया।
- ☞ चित्र अंगुलियों से या बांस की कलम कूची से बनाये जाते हैं और कल्पना की उड़ान, कला से गहरा भावात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया।
- ☞ इसमें मुख्यतः हरा, पीला, लाल, नीला, केसरिया, नारंगी, बैंगनी आदि रंगों का प्रयोग होता है।
- ☞ मधुबनी चित्रकला का एक प्रमुख प्रकार 'अरिपन' चित्र है। यह आँगन में या चौखट के सामने जमीन पर बनाये जाने वाले चित्र हैं।
- ☞ इन्हें बनाने में कूटे गये चावल को पानी और रंग में मिलाया जाता है।
- ☞ अरिपन चित्र प्रायः अंगुली से ही बनाये जाते हैं।

• अरिपन चित्रों में पांच श्रेणियाँ निर्धारित की जा सकती हैं-

1. मनुष्यों और पशु-पक्षियों को दर्शाये जाने वाले चित्र।
2. फूल, पेड़ और फलों के चित्र।
3. तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित चित्र।
4. देवी देवताओं के चित्र।
5. स्वास्तिक, दीप, आदि के चित्र।

- ☞ इस शैली के चित्रकारों के अनुसार, इसे विश्व ख्याति दिलवाने का श्रेय भास्कर कुलकर्णी तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र व उपेन्द्र महारथी को जाता है।
- ☞ इस कला के चित्रकारों में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं ही हैं इसी वजह से इस शैली को महिलाओं की शैली भी कहा जाता है।

मंजूषा शैली

- ☞ भागलपुर क्षेत्र में लोकगाथाओं में अधिक प्रचलित बिहुआ-विपहरी की कथाएं ही इस चित्रशैली में चित्रित होती हैं।
- ☞ मूलतः भागलपुर क्षेत्र में सुपरिचित इस चित्र शैली में मंदिर जैसी दिखने वाली एक मंजूषा पर बिहुला-विपहरी की गाथाओं से संबंधित चित्र कूचियों द्वारा बनाए जाते हैं।
- ☞ इसमें नाग का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है इसलिए इसे नाग चित्रकला भी कहा जाता है।
- ☞ इस चित्रकला को जूट और कागज के डिब्बों पर निर्मित किया जाता है।

पट्टचित्र शैली

- ☞ उड़ीसा की पारम्परिक चित्रकारी, जिसे पट्टचित्र कहा जाता है का नामकरण संस्कृत शब्द पट्ट अर्थात् कैनवास/कपड़ा और चित्र से मिलकर हुआ है।
- ☞ यह चित्रकला शास्त्रीय और लोक महत्व के तत्वों के मिश्रण को प्रदर्शित करती है। इस चित्रकला का आधार उपचारित वस्त्र होता है।
- ☞ इसमें प्रयोग किए गए रंग जलाए हुए नारियल के कवर, हिंगुला, रामाराजा और दीप कज्जल (काजल) इत्यादि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं।
- ☞ पेन्सिल और चारकोल के स्थान पर लाल और काले रंगों से बाह्य रेखा निर्मित करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता था और उसके बाद रंग भरे जाते थे।
- ☞ इस चित्रकला की विषय-वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव मत और शिव तथा कभी-कभी शक्ति मत से प्रेरित होती है।

भारतीय संगीत कला

संगीत

- ☞ संगीत शब्द गीत में सम् जोड़ने से बना है। सम का आशय है सहित और गीत का आशय गान। नृत्य और वादन के साथ किया गया गान ही संगीत है।
- ☞ भारतीय संगीत की अवधारणा में गायन, वादन और नृत्य अवश्य ही तीन अलग-अलग कलाएं स्वीकार की गयी हैं; लेकिन तीनों का मेल संगीत कहलाता है।

संगीत का इतिहास

- ☞ भारत में विद्यमान कलाओं में संगीत कला का अपना अलग ही महत्व है। इसका कारण है कि भारत में संगीत का अस्तित्व किसी-न-किसी रूप में इतिहास के सभी कालखंडों में विद्यमान रहा है।
- ☞ संगीत की सामाजिक जीवन में उपस्थिति के प्रारंभिक प्रमाण, हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलते हैं।
- ☞ खुदाई में ऐसी मूर्तियाँ और सीलें मिली हैं जिनमें ढोल बजाते हुए लोग बनाये गये हैं।
- ☞ कई मूर्तियों में नृत्य की भंगिमाएं हैं। नर्तकी की एक प्रसिद्ध मूर्ति, जो कमर पर हाथ रखकर, खड़ी है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह नृत्य करने के लिए तैयार है।
- ☞ प्राचीन काल से ही गंधर्व वेद को संगीत का पर्याय माना जाता रहा है। वैदिक काल में संगीत का खूब प्रचार-प्रसार हुआ।
- ☞ ऋग्वेद में संगीत संबंधी वाद्य यंत्रों यथा-मृदंग, वीणा, बंशी, डमरू आदि का उल्लेख मिलता है। सामवेद की रचना का मुख्य आधार संगीत ही है।

- ❖ सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना गया है। इस ग्रंथ में देवताओं की स्तुति करते हुए गाये जाने वाले मंत्रों का वर्णन मिलता है।
 - 'साम गायन' में केवल 3 स्वर प्रयोग किए जाते थे।
 1. स्वरति
 2. उदात्त
 3. अनुदात्त
 - धीरे-धीरे यह संख्या 7 तक विकसित हुई।
- ❖ कुछ विद्वानों के अनुसार 'ऊँ' शब्द संगीत का जनक है। अन्य मत के अनुसार संगीत की उत्पत्ति आरंभ में ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, ब्रह्मा जी से यह भगवान शिव को प्राप्त हुई और शिव जी से ये कला सरस्वती को मिली।
- ❖ जिसे संगीत की अधिष्ठात्री कहा जाता है। संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है।
- ❖ इस ग्रंथ में छह अध्यायों में संगीत पर चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न वाद्यों और उन्हें बजाने, लय, ताल और छंदों का सुस्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है।
- ❖ नाट्यशास्त्र में छह रागों यथा-राग भैरव, राग हिंडोला, राग कौशिक, राग दीपक, राग श्रीराग, और राग मेघ का वर्णन मिलता है।
- ❖ मतंग मुनि द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखित 'बृहदेशी' 'राग' की परिभाषा पर केन्द्रित है।
- ❖ यह काल संगीत का 'स्वर्ण काल' कहा गया है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से उनकी संस्कृति, सभ्यता और मुख्यतः संगीत का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा, जिससे उत्तरी संगीत था दक्षिणी संगीत में धीरे-धीरे भिन्नताएं आने लगी।
- ❖ दिल्ली सल्तनत: मुसलमानों का प्रभाव विशेषकर उत्तरी संगीत पर पड़ा। अमीर खुसरो संगीत का विद्वान था।
- ❖ उसने तबला, सितार, कव्वाली, तराना तथा झूमरा, सुल्तान, आड़ा करताल आदि का आविष्कार किया।
- ❖ बाबर: मुगल वंश का संस्थापक बाबर संगीत प्रेमी था। उसकी आत्मकथा तुजुके बाबरी में संगीत गोष्ठियों का वर्णन किया गया है।
- ❖ हुमायूँ: हुमायूँ को संगीत प्रेम विरासत में प्राप्त हुआ था। हुमायूँ प्रत्येक सोमवार तथा बुधवार को संगीत सुनता था। हुमायूँ के दरबार में 29 गायकों तथा वादकों की सूची मिलती है।
- ❖ अकबर: अकबर स्वयं संगीत कला का मर्मज्ञ था। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में हिंदू, ईरानी, तूरानी, कश्मीरी, स्त्री तथा पुरुष-अनेकों संगीतज्ञ थे।
- ❖ अकबर के समय ईरानी तथा भारतीय संगीत के सम्मिश्रण से एक नई शैली का उदय हुआ। आइने-अकबरी में 36 ऐसे संगीतकारों की सूची दी गई है।
- ❖ अकबर ने अपने दरबार में समकालीन भारत के श्रेष्ठ संगीतज्ञों को नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। अपने दरबार में ग्वालियर दरबार से संबद्ध तानसेन को सम्मानित कर उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया।
- ❖ तानसेन ने अनेक रागों की रचना की। वृंदावन के बाबा हरिदास तानसेन के गुरु थे।
- ❖ अकबर के समय के अन्य महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे बाबा रामदास, सुभान खां, मियां चांद, विचित्र खां, रंगसेन, बाजबहादुर इत्यादि।
- ❖ अकबर स्वयं नगाड़ा बजाने में अत्यंत कुशल था। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऋतुओं के जो प्रभाव प्रकट होते थे उसका मुगल दरबार में भरपूर स्वागत किया गया।
- ❖ जहांगीर: जहांगीर भी संगीत कला का उत्साही संरक्षक था। इसके दरबार में भी संगीतज्ञों को संरक्षण प्राप्त हुआ। इनमें शामिल थे, तानसेन के पुत्र विलास खां छतर खां, खुर्रम दाद, मक्खू तथा हमजान आदि।
- ❖ जहांगीर ने शौकी नामक गजल गायक को आनंद खां की उपाधि से सम्मानित किया था।
- ❖ जहांगीर ने हिंदी में कई गीत लिखे। इसके समय के प्रमुख गवैये जनार्दन भट्ट और जगन्नाथ थे। दरबारी समारोहों, जैसे नौरोज आदि के अवसर पर जहांगीर संगीत सभा का आयोजन कराता था।
- ❖ शाहजहां: शाहजहां को संगीत में विशेष रुचि थी। वह स्वयं कुशल संगीतज्ञ और आकर्षक आवाज का मालिक था। शाहजहां के दरबार में रामदास, जगन्नाथ, सुखसेन, और लाल खां महान संगीतज्ञ थे।
- ❖ विलास खां के दामाद लाल खां को शाहजहां ने गुनसमन्दर की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे।
- ❖ उन्होंने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की। शाहजहां द्वारा उन्हें राजकवि जैसे उच्च पद से सम्मानित किया गया था।
- ❖ औरंगजेब ने संगीतज्ञों को दरबार से निकाल दिया तथा संगीत समारोहों का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया।
- ❖ मुहम्मद शाह रंगीला: मुहम्मद शाह रंगीला के दरबार में गजल तथा ख्याल गायकी को नई दिशा प्राप्त हुई। इनके दरबार में नेमत खाँ, सदारंग तथा उसके भतीजे अदारंग ने ख्याल गायकी को परवान चढ़ाया तथा प्रसिद्धि प्राप्त कराई।
- ❖ उन्होंने विभिन्न रागों में ख्याल अंग की अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की जो आज तक प्रचलित हैं।
- ❖ जिस समय सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने तत्कालीन संगीत को एक नया मोड़ देने के उद्देश्य से ख्याल गायकी को प्रचार में लाने की कोशिश की, ध्रुपद धमार की गंभीर और मर्दानी

गायकी का स्थान ख्याल की मुलायम तथा चंचल गायकी ने ले लिया।

- 19वीं शताब्दी: बंगाल के 'सौरेन्द्रमोहन टैगोर' ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 'यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक' पुस्तक लिखी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में संगीत का प्रचार और प्रसार होने लगा।
- इसका मुख्य श्रेय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भारतखण्डे को है।
- स्वतंत्रता के बाद संगीत के प्रचार और प्रसार में सरकार का योगदान रहा। सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी स्थापित की गई जो अब तक संगीत की सेवा कर रही है।
- आकाशवाणी ने केवल शास्त्रीय संगीत को ही नहीं वरन् लोक संगीत भजन आदि को भी प्रोत्साहन दिया।

शास्त्रीय संगीत शैली

- शास्त्रीय संगीत ऐसे संगीत हैं जिनमें शास्त्रीय नियमों एवं सिद्धांतों विशेषकर भरत के नाट्यशास्त्र में दिए गए नियमों का पालन होता है, जो शास्त्रों पर आधारित होता है।
- शास्त्रीय संगीत कलाकारों, विद्वानों के अध्ययन व साधना का विषय बन गया। भारत में शास्त्रीय संगीत की मुख्यतः दो शैलियां हैं-
 1. हिंदुस्तानी शैली
 2. कर्नाटक शैली

हिंदुस्तानी शैली

- यह एक प्राचीन शैली है जिसका उद्गम वैदिक काल में हुआ था। बाद के काल में इस पर धार्मिक एवं लोक संगीत का प्रभाव पड़ा।
- हालांकि दोनों प्रकार की संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भरत के नाट्यशास्त्र में पाई जाती हैं।
- इनमें 14वीं सदी में विलगाव हो गया। 13वीं - 14वीं शताब्दी में यह अपने वर्तमान रूप में आया। इस शैली पर फारसी शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
- वस्तुतः वैदिक संगीत, लोक संगीत, फारसी संगीत के सामंजस्य से ही हिंदुस्तानी शैली का उदय हुआ।
- इन तीनों शैलियों में मूल स्वर सात ही माने गए हैं, जो निम्नवत् हैं,

• हिंदुस्तानी शैली	सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा
• कर्नाटक शैली	सा, रि, गा, मा, प, ध, नी, सा
• पाश्चात्य शैली	डो, रे, मि, फा, सो, ला, टी, डो

- पाश्चात्य शैली के विपरीत हिंदुस्तानी शैली में समान भाव वाले स्वरों का प्रयोग समान राग एवं ताल में होता है। स्वरों के आरोह, अवरोह में भी अंतर है।

- कर्नाटक शैली की अपेक्षा हिंदुस्तानी शैली में वाद्यों को अधिक महत्व दिया जाता है तथा गायकों को संगीत के केन्द्रीय भावों पर अपने विचारों के अनुरूप प्रयोग करने की अधिक स्वतंत्रता होती है।
- हिंदुस्तानी संगीत का आरंभ मंद गति के साथ होता है जिसे बढ़त (बधत) कहते हैं। बाद में इसकी गति तीव्र हो जाती है जिसे 'द्रुत' कहते हैं।
- वाद्य यंत्रों की गति में तीव्रता को 'जोर' कहा जाता है। इस शैली के गायन के केन्द्रीय भाव के लिए 'पल्लवी' शब्द आता है।
- इस शैली में विशिष्ट राग के लिए विशिष्ट गायन काल निर्धारित होती है।
- तानपुरा, तबला, हारमोनियम, हिंदुस्तानी संगीत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र हैं। सितार, सरोद, वीणा, सुरबहार, बाँसुरी, शहनाई, संतूर, पखावज तथा वायलिन का भी प्रयोग होता है।

हिंदुस्तानी संगीत की विशेषताएं

- इसके अंतर्गत मौलिक स्वर पर जोर (वादी एवं समवादी स्वरों पर जोर) दिया जाता है।
- गायक अलाप का तीव्र अनुसरण करता है जिसे 'जोद' कहा जाता है। इसके बाद पुनः ताल नहीं होता।
- शुद्ध स्वरों का घाट बिलावल है।
- स्वर में परास और विसर्पण होता है।
- समय सिद्धांत का अनुपालन होता है।
- सुबह और शाम के लिए अलग-अलग राग होते हैं।
- सामान्य ताल होते हैं।
- राग का लिंगात्मक विभाजन होता है।
- शुद्ध स्वर पूर्व माने जाते हैं, उसके पश्चात् ही विकृत स्वर प्रारंभ होते हैं।
- इस शैली में विलंबित चरण से द्रुत चरण तक पहुँचने में कोई कालिक अनुपात नहीं है।

हिंदुस्तानी संगीत की गायन शैलियां

- ध्रुपद: यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। ध्रुपद का आरंभ 15वीं - 16वीं शताब्दी में हुआ।
- इस शैली का मुख्य संबंध रूपक प्रबंध गीत से रहा है। रूपक में एक प्रबंध ध्रुव होता है जिसके आधार पर ध्रुपद की रचना होती है।
- यह नाम 'ध्रुव' और 'पद' से निकलता है।

इसके चार खंड होते हैं	
1. स्थायी,	3. संचारी
2. अंतरा	4. अभोग

- ध्रुपद शैली का प्रथम गायक 'गोपाल नायक' को माना जाता है। जिसमें भीम पलासी राग एवं सूल तालबद्ध में गाया था।
- ध्रुपद गायकी का आरंभ स्वामी हरिदास से माना जाता है जिसे इनके शिष्य तानसेन द्वारा विकसित किया गया। अकबर ने स्वामी हरिदास और तानसेन जैसे संगीताचार्यों को नियोजित और संरक्षण दिया था।
- तानसेन मुगल दरबार के नौ रत्नों में से एक थे। मानसिंह ग्वालियर के महाराजा ही ध्रुपद की व्यापक लोकप्रियता के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे।
- ध्रुपद की अनिवार्य विशेषता इसकी गंभीरता और लय पर बल है।

ध्रुपद को गाने की चार शैलियां या वाणियां	
I. गौहर वाणी	III. कंधार वाणी
II. डागर वाणी	IV. नौहर वाणी

- गौहर वाणी में राग या अलंकृत रागात्मक आकृतियों का विकास है। डागर वाणी में रागात्मक वक्रताओं और शालीनताओं पर बल दिया गया है।
- कंधार वाणी में स्वरों के शीघ्र अलंकरण की विशेषता है। गौहर वाणी अपने व्यापक संगीतात्मक लंघन (आकस्मिक परिवर्तनों) के लिए जानी जाती है।
- धमार:** इसे धमार ताल में गाया जाता है तथा इसमें अधिकतर राधा-कृष्ण और गोपियों की होली का वर्णन मिलता है। अतः कुछ लोगों द्वारा इसे 'होरी' भी कहा जाता है।
- इसमें ध्रुपद के समान नोम-तोम का अलाप तथा लयकारी दिखाते हैं। इसमें दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़ आदि लयकारियां अधिकतर गीत के शब्दों द्वारा दिखाते हैं।
- इसे संगीतज्ञ सरगम भी बोलते हैं, किंतु यह ख्याल के सरगमों से भिन्न रहता है। धमार के साथ पखावज बजाने की परंपरा है। इसमें 14 तालों का चक्र होता है।
- ख्याल:** 'ख्याल' (ख्याल) शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका तात्पर्य विचार या कल्पना होता है। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है।
- ख्याल को सुनेंगे तो यह महसूस करेंगे कि यह ध्रुपद से अधिक गीतात्मक है।
- 15वीं शताब्दी के सुल्तान मोहम्मद शर्की को ख्याल को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है तथापि इसे 18वीं शताब्दी में नियामत खान सदारंग और अदारंग के हाथों परिपक्वता मिली।

- विलम्बित को धीमी लय में गाया जाता है और द्रुत को तेज लय से गाया जाता है। तकनीक की दृष्टि से इसका प्रतिपादन ध्रुपद की तुलना में कम महत्वपूर्ण है।
- अधिक कोमल गायक और अलंकरण होते हैं। दोनों प्रकार के ख्यालों के दो अनुभाग होते हैं स्थाई और अंतरा।
- स्थायी अधिकांशतः निम्न और मध्यम सप्तक तक सीमित रहती है।
- अंतरा सामान्यतः मध्यम और ऊपरी सप्तकों में चलता है। स्थाई और अंतरा मिल कर एक गीत, रचना या बाशिन्द बनाते हैं जिसे हम चीज कहते हैं।
- ख्याल के प्रमुख गायक- सदारंग, अदारंग, मनरंग, मुहम्मद शाह, देवदास, कुमारगंधर्व हैं।

ख्याल के भारत में चार प्रमुख केन्द्र हैं	
I. ग्वालियर घराना	III. जयपुर-अतरौली घराना
II. आगरा घराना	IV. किराना घराना

- ठुमरी:** यह गीत का वह प्रकार है जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी प्रकृति ख्याल की तुलना में चपल होती है।
- ठुमरी, खमाज, देश, तिलक, कामोद, तिलंग, पीलू, काफी, भैरवी, झिझोरी, जोगिया आदि रागों में गाई जाती है। इसके साथ दीपचंदी अथवा जत ताल बजाया जाता है।
- ठुमरी में शब्द कम होते हैं। शब्दों के भाव को विविध स्वर-समूहों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठुमरी के लिए बनारस, लखनऊ तथा पंजाब विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।
- ठुमरी अपनी संरचना और प्रस्तुति में अति गीतात्मक है। इन गायन प्रकारों को अर्द्ध या सुगम शास्त्रीय नाम दिया जाता है। ठुमरी एक प्रेम गीत है इसलिए शब्द रचना अति महत्वपूर्ण है।
- यह संगीतात्मक वादन से घनिष्ठ रूप से समन्वित है, और ठुमरी को गाए जाने के लिए मनोदशा को ध्यान में रखते हुए इसे खमाज, काफी, भैरवी इत्यादि जैसे रागों में प्रस्तुत किया जाता है।
- संगीतात्मक व्याकरण का सख्ती से पालन नहीं किया जाता। रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी इस शैली की प्रमुख गायिकाएं रही हैं।
- टप्पा:** यह गीत का वह प्रकार है जिसके शब्द अधिकतर पंजाबी भाषा के होते हैं तथा जिसकी प्रकृति बहुत चपल होती है।
- पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में अविभूति तथा अवध के दरबार में ठुमरी के साथ-साथ विकसित 'टप्पा' वास्तव में हिन्दी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार प्रधान गीत है।
- लोक संगीत ने परिष्कृत और सुगम शास्त्रीय संगीत के लिए इसने कच्चे माल की आपूर्ति की।

- यह एक कठिन तथा सूक्ष्म गायन शैली है।
- इसके विकास में शोरी मियां तथा उनके शिष्यों मियां गम्भू और तारा चंद का योगदान उल्लेखनीय है।
- इसके गायन में छोटी-छोटी तानों का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रृंगार रस, राग भैरवी, राग खमाज, राग काफी का प्रयोग होता है।
- गजल:** गजल गायन की इस लोकप्रिय शैली में विशेष रूप से उर्दू में लिखित रचना को गाया जाता है। मिर्जा गालिब को गजलों का जनक माना जाता है।
- इस शैली में गालिब, जफर, शकील, बदायूनी, कैफी, आजमी, शाहिर लुधियानवी, आदि प्रसिद्ध शायरों की रचनाओं को स्वरबद्ध किया जाता है।
- वर्तमान में हिंदी में भी गजल लिखने की परंपरा चल रही है। इसमें दादरा, कहरवा आदि प्रचलित तालों का प्रयोग किया जाता है।
- दादरा:** गजल के समान इस शैली में श्रृंगारिक रचनाएं की जाती हैं। इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग रस में रचनाएं की जाती हैं। इस शैली में कैरवा ताल प्रयोग किया जाता है।
- होरी:** सुगम संगीत गायन शैली होरी एक श्रृंगारिक रचना है, जिसका संबंध राधाकृष्ण तथा ब्रज क्षेत्र से है। इसका गायन होली के त्यौहार पर होता है।
- कव्वाली:** इस शैली में ऊर्दू शायरी को संगीतमय ढंग से गाया जाता है। यह शैली पहले सूफी संतों द्वारा ईश्वर की आराधना हेतु प्रयोग की जाती थी किंतु बाद में इसकी विषय वस्तु में सांसारिकता शामिल हो गई।
- लोकगीत:** यह लोक अंचल की भाषा में गायी जाने वाली विधा है। इसमें आंचलिक भाषाओं के गीत आते हैं। इस शैली में संबंधित क्षेत्र की संस्कृति व जलवायु का वर्णन किया जाता है।
- लांगरिया, वैवाहिक गीत, कजरी, बन्ना, घोड़ा-भात, सोहर बिदाई आदि लोकगीत के उदाहरण हैं।

कर्नाटक शास्त्रीय संगीत

- यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल राज्यों में प्रचलित है। अपने वर्तमान रूप में यह 15वीं - 16वीं शताब्दी में आया।
- वर्ष 1484 में पुरन्दर दास के आगमन से कर्नाटक संगीत के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्होंने कला में पूर्ण व्यवस्था और शुद्धीकरण के जरिए यह कार्य किया।
- यह स्थिति आज तक वैसी ही बनी हुई है। उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाना ठीक ही है।
- वह ना केवल एक रचनाकार थे बल्कि सर्वोच्च कोटि के लक्षणकार भी थे।

- हिन्दुस्तानी संगीत की अपेक्षा कर्नाटक शैली में स्वरों को अधिक महत्व दिया जाता है।

कर्नाटक शैली में गायन के तीन भाग

वर्णम	रागम्	थालम
-------	-------	------

- कर्नाटक संगीत मूलतः वैदिक संगीत और स्थानीय संगीत से मिलकर बना है। जब वैदिक ऋचाओं को इन गीतों के साथ गाया जाता है उसे 'कृतिम' कहते हैं।
- कर्नाटक संगीत का नियमन मेलकर्ता द्वारा होता है, जिसमें 72 राग होते हैं। सामान्यतः आरंभ पल्लवी से होता है। इसका उदाहरण कीर्तन है।

कीर्तन के तीन भाग

पल्लवी	अनुपल्लवी	चरण
--------	-----------	-----

- 18-19वीं शताब्दी को कर्नाटक संगीत का स्वर्णयुग माना जाता है। त्यागराज, श्यामशास्त्री, एवं मुत्तुस्वामी दीक्षितार जिन्हें कर्नाटक शैली का त्रिरत्न माना जाता है, इसी काल के थे।
- वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायक-सुब्बालक्ष्मी, बाल मुरली, आंयगर, संजय सुब्रह्मण्यम, येसुदास, प्रपंचम, सिवारमन, एम नागराज आदि हैं।
- कर्नाटक शैली के गायन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य हैं-वेण, गोदूवाद्ययम (घटवाद्यम), वीणा, मृदंग, कंजिरा, घंटम, वायलिन इत्यादि।

कर्नाटक संगीत पद्धति की विशेषताएं निम्न हैं

- ध्वनिगुण के महत्व को घटाने-बढ़ाने की परिपाटी है। राग में काफी स्वतंत्रता है।
- स्वतंत्र तथा जटिल प्रकृति के राग हैं। ताल का भी काफी जटिल प्रयोग किया जाता है।
- गायक 'आलायन' 'तानम' का अनुसरण करता है।
- विकृत स्वर को श्रुति संख्या के आधार पर नाम दिया जाता है।
- शुद्ध स्वरों का घाट 'मुखारी' है।

- सुलादी:** संगीत प्रणाली और व्यवस्था में गीतम की तरह ही सुलादी का स्तर गीतम से उच्च स्तर का होता है। सुलादी एक तालमलिका है, खण्ड भिन्न-भिन्न तालों में होते हैं।
- साहित्य अक्षर, गीतों की तुलना में कम होते हैं तथा स्वर विस्तारों का समूह होता है।
- विषय भक्ति होता है। सुलादी की रचना भिन्न-भिन्न गीतों में की जाती है, जैसे विलंबित, मध्य और द्रुत। पुरंदर दास ने बहुत सी सुलादियों की रचना की है।
- जातिस्वरम:** संगीत प्रणाली में स्वराजाति के समान ही जातिस्वरम का कोई साहित्य या शब्दावली नहीं है।
- अंशों को केवल सोल्फा अक्षरों के साथ गाया जाता है।

- ❶ यह अपनी लय उत्कृष्टता और इसमें प्रयुक्त जाति पद्धति के लिए उल्लेखनीय है।
- ❷ **वर्णम:** वर्णम, कर्नाटक संगीत की एक संगीत शैली है तथा कीर्तन, कृति, जवाली, तिल्लाना आदि जैसी संगीत शैली हिन्दुस्तानी संगीत की तरह ही है।
- ❸ वर्णम सभी प्रमुख रागों को मिलाकर रचित किया जाता है तथा सभी प्रमुख तालों में अधिकांश छोटे-मोटे राग होते हैं।
- ❹ **कीर्तनम:** कीर्तनम की उत्पत्ति लगभग चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी।
- ❺ यह सरल संगीत में रचित साहित्य की भक्ति भावना के लिए जाना जाता है, कीर्तनम भक्ति भाव से ओत-प्रोत है। यह सामूहिक गायन और अलग-अलग प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त है।
- ❻ **कृति:** कृति कीर्तन से विकसित हुआ रूप है। यह रूप अत्यंत विकसित संगीत शैली है। कृति संरचना में सौन्दर्य उत्कृष्टता की उच्चतम सीमा प्रस्तुत की जाती है। इस शैली में सभी समृद्ध और विविध रागभावों को प्रस्तुत किया जाता है।
- ❼ **पद:** पद, तेलुगु और तमिल में विद्वत्तापूर्ण रचनाएँ हैं। यद्यपि ये मुख्यतः नृत्य रूपों में रचित होती हैं तथापि ये संगीत कार्यक्रमों में भी गाई जाती हैं जिसके कारण संगीत में उत्कृष्टता और सुन्दरता पैदा होती है।
- ❽ **जवाली:** जवाली, सुगम शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित एक रचना है।
- ❾ इसे सामूहिक संगीत कार्यक्रमों और नृत्य समारोहों दोनों में गाया जाता है। जवाली तेलुगु, कन्नड़ और तमिल में रचित होती है।
- ❿ **तिल्लाना:** हिन्दुस्तानी संगीत में तराना के अनुरूप ही तिल्लाना भी एक लघु और संकुचित शैली है।
- ⓫ यह मुख्यतः एक नृत्य शैली है, किन्तु तेज और आकर्षक संगीत के कारण इसे कभी-कभी अन्तिम अंश में शामिल किया जाता है।
- ⓬ रामनाथपुरम् श्रीनिवास आर्यंगर, पल्लवी शेषाय्यर और स्वाति तिरुनाल तिल्लानाओं के कुछेक प्रमुख रचयिता हैं।
- ⓭ **पल्लवी:** यह रचनात्मक संगीत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है।
- ⓮ मनोधर्म संगीत की इस शाखा में ही संगीतज्ञों के लिए अपनी रचनात्मक प्रतिभा, विचारात्मक दक्षता और संगीत प्रबुद्धता प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है।
- ⓯ पल्लवी शब्द का विकास तीन शब्दों यथा पदम जिसका अर्थ शब्द है, लयम जिसका अर्थ समय है और विनयासम, जिसका अर्थ भिन्नताएँ हैं, से हुआ है।
- ⓰ 'निरावल' का शाब्दिक अर्थ समायोजनों द्वारा भराव है। संगीत

- पद्धति में, इसका अर्थ संगीत विषय में सुधारों के साथ लयात्मक गायन के अन्दर साहित्य के गायन की कला से है।
- ❶ **तनम:** यह राग अल्पना की एक शाखा है। यह मध्यम गति में राग अल्पना है।
- ❷ आकर्षक पद्धतियों का पालन करते हुए, संगीत का लयात्मक प्रवाह, तनम गायन को राग का सर्वाधिक आकर्षक भाग बना देता है।
- ❸ संक्षेप में—कर्नाटक संगीत की विशेषता इसकी राग पद्धति है जिसकी अवधारणा में 'पूर्णसंगीत' अथवा आदर्श निहित होता है तथा यह अत्यंत विकसित और जटिल ताल पद्धति है जिसने इसे अत्यंत वैज्ञानिक और रीतिबद्ध तथा सभी दृष्टिकोणों से अनूठा बना दिया है।

हिन्दुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने

- ❶ 'घराना' हिन्दुस्तानी संगीत की अनोखी विशेषता है। जिसके द्वारा संगीतज्ञों के एक विशेष वर्ग का सामुदायिक विकास होता है। हिन्दुस्तानी संगीत बहुत विशाल भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत है।
- ❷ कालांतर में इसमें अनेक भाषायी तथा शैलीगत बदलाव आये। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत की गुरु-शिष्य परंपरा में प्रत्येक गुरु व उस्ताद हाव-भाव अपने शिष्यों को दे जाते हैं।
- ❸ कोई भी घराना अपनी शैली से जाना जाता है। घराने वादक या गायक द्वारा जानबूझकर नहीं बनाये जाते हैं।
- ❹ **जयपुर घराना:** ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध इस घराने की स्थापना काली खाँ और चांद नामक भाइयों ने की।
- ❺ 19वीं-20वीं सदी के महान गायक अल्लादिय खान ने इस घराने को प्रसिद्धी दिलाई।
- ❻ यह घराना कठिन तानों, अप्रचलित और दुर्लभ रागों के लिए प्रसिद्ध है।
- ❼ राग परज, टंक, सुहा, सिंदूर आदि कुछ ऐसे राग हैं जो जयपुर घराने की धरोहर है।
- ❽ इस घराने के प्रमुख संगीतकार— रजब अली खाँ, सवाल खाँ, आशिक अली खाँ, आजिद हुसैन, सादिक अली खाँ, मुशरफ खाँ आदि हैं।
- ❾ **आगरा घराना:** इस घराने की स्थापना हाजी सुजान खाँ ने की। फैयाज खाँ ने 20वीं शताब्दी में इस घराने को नये आयाम दिये।
- ❿ इस घराने की दो शाखाएँ हैं, जिसमें पहली शाखा ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना श्यामरंग द्वारा की गयी।
- ⓫ जबकि दूसरी शाखा, जो कि सुश्रम संगीत के लिए प्रसिद्ध है, की स्थापना इमदाद खाँ ने की।
- ⓬ इसका गायन अत्यधिक मधुर है, इसलिए आगरा घरानों को रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है।

आगरा घराने की विशेषताएं

- नोम-तोम में आलाप करना
- खुली जोरदार आवाज में गाना
- लय ताल पर विशेष जोर

- **ग़ालियर घराना:** यह सर्वाधिक प्राचीन घराना है। यह ख्याल गायकी का जन्मदाता है। इस घराने की स्थापना अब्दुल्ला खां, तथा कादिर खां नामक भाईयों द्वारा की गई।
- इस घराने की शैली सर्वाधिक रोचक एवं सरल है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है।
- नत्थन खां, पीर बख्श, दहू खां, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मनोहर जोशी देवधर आदि इस घराने के प्रसिद्ध संगीतकार हैं।

ग़ालियर घराने की विशेषताएं

- खुली आवाज का गायन
- ध्रुपद अंग का गायन
- आलापों का निराला ढंग
- सीधी-सपाट तानों का प्रयोग
- गमक का प्रयोग

- **किराना घराना:** उस्ताद बंदे अली खां द्वारा स्थापित यह घराना सबसे बाद में विकसित हुआ।
- किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की परंपरा को वहन करने वाले हिंदुस्तानी घराने में चतुर्थ प्रमुख स्कूल है।
- इस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के एक जिले की किराना तहसील के नाम पर किया गया।
- इस घराने को प्रसिद्धि दिलाने और विकसित करने का श्रेय अब्दुल वाहिद खान और उनकी पीढ़ी के अंतिम गायक अब्दुल करीम खां को जाता है। वर्तमान में इस घराने की दो शैलियां पूर्वी शैली और पंजाबी शैली है।
- उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद बेहरे अब्दुल वहीद खां, सुरेश बाबू, भीमसेन जोशी, हीराबाई बड़ोदकर, शकूर खां, गंगूबाई हंगल आदि इस घराने के प्रसिद्ध संगीतकार हैं।
- **बनारस घराना:** यह घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध घरानों में गिना जाता है।
- शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इस घराने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है।
- इस घराने के गायक ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं। साथ ही तबला वादकों की भी अपनी एक स्वतंत्र शैली रही है।

- इस घराने की विशिष्ट तबला वादन शैली है जिसे आज 'बनारस - बाज' कहते हैं।
- वर्तमान में बनारसी तबला घराना अपने शक्तिशाली रूप के लिए प्रसिद्ध है, बनारस घराने के वादक हल्के और कोमल स्वरों के वादन में भी सक्षम है।
- बनारस घराने के तबला वादन की सभी शैलियों में जैसे एकल, संगत, गायन एवं नृत्य संगीत आदि में पारंगत होते हैं।
- **सहसवान-रामपुर घराना:** सहसवान बदायूँ जिले की तहसील है और यह रामपुर जिले के निकट है। सहसवान 13 वीं सदी से ही संगीत के लिए प्रसिद्ध रहा है।
- 18वीं सदी में सहसवान के दो संगीतज्ञ कुतुबुद्दौला और शाहबुद्दौला थे तथा उनके शिष्य महबूब हुसैन खां थे और उनसे अली हुसैन, मोहम्मद हुसैन और इनायत हुसैन ने भी संगीत सीखा।
- इसमें धीमे और द्रुत ख्याल सामान्यतः एक तराने के बाद गाते हैं। इस घराने की गायन शैली अति गीतात्मक है और स्वर अलंकरण से परिपूर्ण होते हैं।
- हाल के इस घराने के दो प्रमुख गायक निसार हुसैन खां और रशीद खां रहे हैं।
- **दिल्ली घराना:** दिल्ली घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में एक है। तानरस खान और सब्बू खान इस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं।
- तानरस खान की तान बहुत मशहूर थी। इन्होंने तानों का बहुत अभ्यास किया था।
- इनके पुत्र उमरान खां थे जिन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाया।

संगीत के तत्व/अंग

- संगीत के विविध तत्वों या अंगों को समझे बिना संगीत को नहीं समझा जा सकता। भारतीय संगीत के प्रमुख अंगों में ध्वनि, नाद, स्वर, थाट, राग-रागिनी, ताल, लय आदि शामिल है।
- **ध्वनि:** कान के ज्ञान तंतुओं के स्पंदन के बाह्य भौतिक कारण को ध्वनि कहते हैं।
- ध्वनि के माध्यम से ही विभिन्न भाव प्रकट किए जाते हैं और ध्वनियां ही संगीत में प्रयुक्त होकर स्वर का रूप धारण करती है।
- संगीत में सिर्फ 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकण्ड तक वाली ध्वनि ही सुनने में हम सक्षम होते हैं।
- **नाद:** संगीत का आधार नाद है। वास्तव में, जब किसी वस्तु के नियमित कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे नाद कहा जाता है।
- किंतु, जब ध्वनि की उत्पत्ति अनियमित कंपन के कारण होती है, तो उसे शोर, कोलाहल या कटु ध्वनि कहते हैं।

- नाद से ही धुतियों की, धुतियों से स्वर की और स्वरों से राग की उत्पत्ति की अभिव्यक्ति होती है।
- वस्तुतः जगत का संपूर्ण व्यवहार ही नाद पर आधारित होता है। योगशिखोपनिषद् में कहा गया है नाद से बड़ा ना कोई मंत्र है, ना देव और ना ही इससे बड़ी कोई पूजा ही है।
- स्वर:** 22 धुतियों में से मुख्य 12 धुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी-थोड़ी दूरी पर फैले हुए हैं। इन स्वरों के नाम हैं- षडज, ऋषभ, पंचम, धैवत, गंधार, मध्यम और निषाद।
- व्यवहार में इन्हें सा, रे, गा, मा, प, ध, नी कहा जाता है। स्वरों के मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं-
 - शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर
 - विकृत स्वर
- शुद्ध स्वर:** बारह स्वरों में से सात मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, तो शुद्ध स्वर कहलाते हैं।
- विकृत स्वर:** पांच स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं साथ-ही-साथ विकृत भी होते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं, वे विकृत स्वर कहलाते हैं।

संगीत स्वरों की उत्पत्ति					
स्वर	संस्कृत नाम	देवता	ग्रह	ध्वनि	रंग
सा	षडज	अग्नि	चंद्र	मोर	गुलाबी
रे	रिषभ	ब्रह्मा	बुध	गाय-बैल	हल्का हरा-पीला
गा	गांधार	सरस्वती	शुक्र	बकरा	हल्का श्वेत-लाल
मा	मध्यम	विष्णु	सूर्य	क्रौंच	गहरा-लाल
प	पंचम	लक्ष्मी	मंगल	कोयल	गहरा-लाल
ध	धैवत	गणेश	गुरु	घोड़ा	हल्का-पीला
नी	निषाद	सूर्य	शनि	हाथी	गहरा भूरा

- सप्तक:** क्रमानुसार सात शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। इसमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन-संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है।
- दूसरे शब्दों में सा से जैसे-जैसे बढ़ते हैं, स्वरों की आंदोलन-संख्या बढ़ती जाती है।
- सा से नी तक एक सप्तक होता है। नी के बाद दूसरा सा, (तारसा) आता है और इसी स्थान से दूसरा सप्तक भी शुरू होता है।

- दूसरा सप्तक भी 'नी' तक रहता है और पुनः नी के बाद अति तारसा आता है, जहां से तीसरा सप्तक प्रारंभ होता है।

सप्तक के तीन प्रकार		
मंद सप्तक	मध्य सप्तक	तार सप्तक

- थाट:** सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं, जिससे राग उत्पन्न होते हैं।
- थाट को मेल भी कहा जाता है। 'थाट' वैसे स्वर समूह को कहते हैं, जो रागों के निर्माण में सक्षम होते हैं। सुरों को मिलाना या इकट्ठा करना ही थाट कहलाता है।
- थाट द्वारा राग का निर्माण विभिन्न तरीकों से होता है। कभी पूर्ण थाट लेकर एक स्वर को बार-बार दोहराया या उस पर रुका जाता है, जिसे वादी स्वर या राग का प्रमुख स्वर कहते हैं।
- राग:** कम से कम पांच और अधिक-से-अधिक सात स्वरों की वह सुंदर रचना, जो कानों को सुंदर अनुभूति दे, राग कहलाती है।
- मुनि मतंग के अनुसार "सर्वसाधारण के मन को रंजित करने वाली विशिष्ट स्वर वर्णों से विभूषित ध्वनि को राग कहते हैं।" भारतीय संगीत में राग का महत्वपूर्ण स्थान है। राग स्वर-देह और भाव-देह दोनों में समन्वित होता है।
- हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समयानुसार गायन प्रस्तुत करने की पद्धति है और यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। संगीत आचार्यों ने दिन के 24 घंटों को पहले दो भागों में बांटा।
- प्रथम भाग दिन के 12 बजे से रात्रि के बारह बजे तक और दूसरा रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक माना गया है।

प्रमुख राग, संबंधित वाद्ययंत्र एवं कलाकार		
राग	वाद्ययंत्र	कलाकार
राग शाहना बहार और पहाड़ी धुन	बाँसुरी	हरिप्रसाद चौरसिया
राग हमीर	शहनाई	बिस्मिल्ला खाँ
राग सिंदूर और राग मिश्र काफी	सितार	रविशंकर
राग बसंत	संतूर	शिवकुमार शर्मा
मल्हार रागिनियाँ	सितार	रविशंकर
राग मेघ	संतूर	शिवकुमार शर्मा
राग मधु मल्हार	बाँसुरी	हरिप्रसाद चौरसिया
मल्हार और कजरी का मिश्रण	शहनाई	बिस्मिल्ला खाँ

भारत के संगीत वाद्य यंत्र

- भारत विश्व में, सबसे प्राचीन और विकसित संगीत तंत्रों में से एक का उत्तराधिकारी है।

- हमें इस परंपरा की निरंतरता का ज्ञान संगीत के ग्रंथों और प्राचीन काल से लेकर आज तक की मूर्तिकला और चित्रकला में संगीत वाद्यों के अनेक दृष्टांत उदाहरणों से मिलता है।
- हमें संगीत संबंधी गतिविधि का प्राचीनतम प्रमाण मध्यप्रदेश के अनेक भागों और भीमबेटका की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों से प्राप्त होता है।
- इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से भी नृत्य तथा संगीत गतिविधियों के प्रमाण मिले। संगीत वाद्य, संगीत का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं।
- 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन् के समय में भरतमुनि द्वारा संकलित नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्यों को ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है-

तत् वाद्य - तारदार वाद्य

- यह वाद्यों का ऐसा वर्ग है, जिनमें तार अथवा तंत्र वाद्य के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तत् वाद्यों का प्राचीनतम प्रमाण धनुष के आकार की वीणा या वीणा है।
- इसके प्रत्येक स्वर के लिए एक तार होती थी, जिन्हें या तो उंगलियों से छेड़कर या फिर कोना नामक मिजराब से बजाया जाता था।
- संगीत ग्रंथों में तत् वाद्यों के लिए सामान्य रूप से वीणा शब्द का प्रयोग किया जाता था और हमें एक-तंत्री, संत-तंत्री वीणा आदि वाद्यों की जानकारी मिलती है।
- प्राचीन समय की बहुत-सी-मूर्तियों और भित्ति चित्रों से इनका उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे भरहुत और सांची स्तूप, अमरावती के नक्कासीदार स्तंभ आदि।
- दूसरी शताब्दी ईस्वी के प्राचीन तमिल ग्रंथों में ताड़ का उल्लेख प्राप्त होता है। धार्मिक अवसरों और समारोहों में ऐसे वाद्यों को बजाना महत्वपूर्ण है।
- गज वाले तार वाद्य आमतौर पर गायन के साथ संगत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
- इन्हें दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है- पहले वर्ग में सारंगी के समान डांड को सीधे ऊपर की ओर रखा जा सकता है और दूसरे वर्ग में तुंबे को कंधे की ओर रखा जाता है तथा 'डंडी' या डांड को वादक की बांह के पार रखा जाता है।

कमैचा

- कमैचा पश्चिम राजस्थान के मंगनियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजायी जाने वाली वीणा है। यह संपूर्ण वाद्य लकड़ी के एक टुकड़े से बना होता है।
- गोलाकार लकड़ी का हिस्सा गर्दन तथा डांड का रूप लेता है। लंबवत् गजयुक्त वाद्यों के प्रकार सामान्यतः देश के उत्तरी भागों में पाये जाते हैं।

सुषिर वाद्य (वायु वाद्य)

- सुषिर वाद्यों में एक खोखली नलिका में हवा भर कर (अर्थात् फूंक मार कर) ध्वनि उत्पन्न की जाती है।
- हवा के मार्ग को नियंत्रित करके स्वर की ऊंचाई सुनिश्चित की जाती है और वाद्य में बने छेदों को उंगलियों की सहायता से खोलकर और बंद करके क्रमशः राग बजाया जाता है।
- इन सभी वाद्यों में सबसे सुरीली वाद्य है- बांसुरी।
- आमतौर पर बांसुरियां बांस अथवा लकड़ी से बनी होती हैं और भारतीय संगीतकार संगीतात्मक तथा स्वर-संबंधी विशेषताओं के कारण लकड़ी तथा बांस की बांसुरी को पसंद करते हैं।
- ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर मोटे तौर पर सुषिर अथवा वायु वाद्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है-
- बांसुरी:** इकहरी बांसुरी अथवा दोहरी बांसुरी केवल एक खोखली नलिका के साथ, स्वर की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए अंगुली रखने के छिद्रों सहित होती है।
- लंबी, सपाट, बड़े व्यास वाली बांसुरियों का निचले (मंद) सप्तक के आलाप जैसे धीमी गति के स्वर समूहों को बजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- कम्पिका वाद्य:** कम्पिका या सरकंडा युक्त वाद्य जैसे शहनाई, नादस्वरम् आदि वाद्यों में वाद्य की खोखली नलिका के भीतर एक अथवा दो कम्पिका को डाला जाता है, जो हवा के भर जाने पर कम्पित होती है।
- शहनाई:** शहनाई एक कम्पिका युक्त वाद्य है। इसमें नलिका के ऊपर सात छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को अंगुलियों से बंद करने और खोलने पर राग बजाया जा सकता है।
- इस वाद्य को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। इसे प्रसिद्ध बनाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है।

अवनद्ध वाद्य

- अवनद्ध वाद्यों (ताल वाद्य) में पशु की खाल पर आघात करके ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। जो मिट्टी, धातु के बर्तन या फिर लकड़ी के ढोल या ढांचे के ऊपर खींच कर लगायी जाती है। हमें ऐसे वाद्यों के प्राचीनतम उल्लेख वेदों से प्राप्त होते हैं।
- वेदों में 'भूमि दुंदुभि' का उल्लेख है। यह भूमि पर खुदा हुआ एक खोखला गड्ढा होता था जिसे बैल या भैंस की खाल से खींच कर ढंका जाता था। इस गड्ढे के खाल ढंके हिस्से पर आघात करने में पशु की पूंछ को प्रयोग में लाया जाता था।
- उर्ध्वक:** उर्ध्वक ढालों को वादक के समक्ष लंबवत् रखा जाता है और इन पर डंडियों या फिर उंगलियों से आघात करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। इनमें मुख्य है तबले की जोड़ी और चेंडा।

- ❶ **तबला:** तबले की जोड़ी दो लंबवत् उर्ध्वक ढोलों का एक समूह है।
- ❷ इसके दायें हिस्से को तबला कहा जाता है और बायें हिस्से को नांदा अथवा डग्गा कहते हैं। तबला लकड़ी का बना होता है। इस लकड़ी के ऊपरी हिस्से को पशु की खाल से ढका जाता है।
- ❸ वर्तमान समय के कुछ प्रमुख तबला वादक हैं- उस्ताद अल्ला रक्खा खां, और उनके पुत्र जाकिर हुसैन, शफात अहमद और सामता प्रसाद।
- ❹ **आलिंग्य:** इन ढोलों में पशु की खाल को लकड़ी के एक गोल खांचे पर लगा दिया जाता है और गले या इसे एक हाथ से शरीर के निकट करके पकड़ा जाता है।
- ❺ जबकि दूसरे हाथ को ताल देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस वर्ग में डफ, डफली आदि आते हैं, जो बहुत प्रचलित वाद्य हैं।
- ❻ **डमरू:** डमरू ढोलों का एक अन्य प्रमुख वर्ग है। इस वर्ग में हिमाचल प्रदेश के छोटे 'हुडुका' से लेकर दक्षिणी प्रदेश का विशाल वाद्य 'तिमिल' तक आते हैं।
- ❼ पहले वाद्य को हाथ से आघात देकर बजाया जाता है, जबकि

दूसरे को कंधे से लटकाकर डंडियों और उंगलियों से बजाया जाता है।

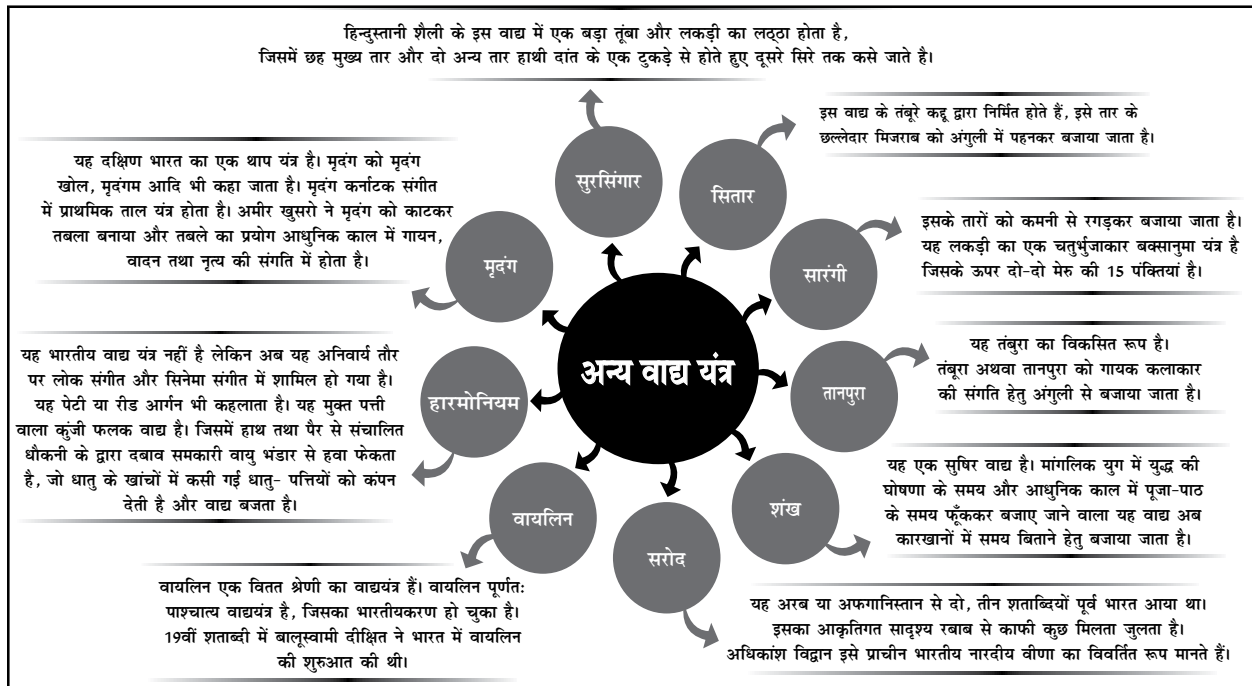
- ❶ इस प्रकार के वाद्यों को रेतघड़ी वर्ग के ढोलों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका आकार रेतघड़ी से मिलता जुलता प्रतीत होता है।

घन वाद्य

- ❶ मनुष्य द्वारा अविष्कृत सबसे प्राचीन वाद्यों को घन वाद्य कहा जाता है। एक बार जब यह वाद्य बन जाते हैं तो फिर इन्हें बजाने के समय कभी भी विशेष सुर में मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राचीन काल में यह वाद्य मानव शरीर के विस्तार जैसे डंडियों, तालों तथा छड़ियों आदि के रूप में सामने आये और ये दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं जैसे पात्र, कड़ाही, झांझ, तालम् आदि के साथ बहुत गहरे जुड़े हुए थे।

झांझ वादक

- ❶ उड़ीसा के कोर्णाक स्थित सूर्य मंदिर में एक 8 फुट ऊंचा शिल्प है जिसमें एक स्त्री को झांझ बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है।



क्षेत्रीय संगीत

- ❶ देश में लोक संगीत की विशद परंपरा रही है। लोक जीवन से निकला यह संगीत त्यौहारों आदि अवसरों पर गाये जाते हैं।
- ❷ यह किसी जटिल नियम से बंधे नहीं होते हैं। संगीत वाद्य प्रायः शास्त्रीय संगीत में पाए जाने वाले वाद्यों से भिन्न है।

- ❶ यद्यपि तबला जैसे वाद्य यंत्र कभी-कभी अपरिष्कृत ढोल, जैसे डफ, ढोलक अथवा नाल से अधिक पसंद किए जाते हैं।
- ❷ सितार और सरोद, जो शास्त्रीय संगीत में अत्यंत सामान्य हैं, लोक संगीत में उनका अभाव होता है।
- ❸ शास्त्रीय संगीत वाद्य कलाकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं

जिनका कार्य केवल संगीत वाद्य निर्मित करना है। इसके विपरीत लोक वाद्यों को सामान्यतः खुद संगीतकारों द्वारा विनिर्मित किया जाता है।

- सामान्यतः यह देखा जाता है कि लोक वाद्य यंत्र आसानी से उपलब्ध सामग्री से ही बनाये जाते हैं।
- कुछ संगीतिक वाद्य यंत्रों को बनाने में आसानी से उपलब्ध चर्म, बांस, नारियल खोल और बर्तनों आदि का प्रयोग भी किया जाता है।

लोटिया, राजस्थान

- 'लोटिया' त्योहार के दौरान चैत्र मास में गाया जाता है। स्त्रियां, तालाबों और कुओं से पानी से भरे 'लोटे (पानी भरने का एक बर्तन) और कलश (पूजा के दौरान पानी भरने के लिए शुभ समझा जाने वाला एक बर्तन) लाती हैं। वे उन्हें फूलों से सजाती हैं और घर लाती हैं।

पंडवानी, छत्तीसगढ़

- पंडवानी में, महाभारत से एक या दो घटनाओं को चुन कर कथा के रूप में निष्पादित किया जाता है।
- मुख्य गायक पूरे निष्पादन के दौरान सतत रूप से बैठा रहता है और सशक्त गायन व सांकेतिक भंगिमाओं के साथ एक के बाद एक सभी चरित्रों की भाव-भंगिमाओं का अभिनय करता है।

शकुनाखर, मंगलगीत, कुमाऊँ

- हिमालय की पहाड़ियों में शुभ अवसरों पर असंख्य गीत गाए जाते हैं। शकुनाखर, शिशु स्नान, बाल जन्म, छठी (बच्चे के जन्म से छठे दिन किया जाने वाला एक संस्कार), गणेश पूजा आदि के धार्मिक समारोहों के दौरान गाया जाता है।
- ये गीत केवल महिलाओं द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। प्रत्येक शुभ अवसर पर शकुनाखर में अच्छे स्वास्थ्य और लम्बे जीवन की प्रार्थना की जाती है।

बारहमास, कुमाऊँ

- कुमाऊँ के इस आंचलिक संगीत में वर्ष के बारह महीनों का वर्णन प्रत्येक माह की विशेषताओं के साथ किया जाता है।
- एक गीत में घुघुती चिड़िया चैत मास की शुरुआत का संकेत देती है।
- एक लड़की अपनी ससुराल में चिड़िया से ना बोलने के लिए कहती है क्योंकि वह अपनी माँ की याद से दुःखी है और दुख महसूस कर रही है।

मन्डोक, गोवा

- गोवाई प्रादेशिक संगीत, भारतीय उपमहाद्वीप के पारम्परिक संगीत का भण्डार है। 'मन्डों' गोवाई संगीत की परिशुद्ध रचना

एक धीमी लय है और पुर्तगाली शासन के दौरान प्रेम, दुख और गोवा में सामाजिक अन्याय और राजनीतिक विरोध से संबंधित एक छंद बद्ध संरचना है।

कव्वाली

- मूलतः कव्वालियाँ ईश्वर की प्रशंसा में गाई जाती थीं। भारत में कव्वाली का आगमन तेरहवीं शताब्दी के आस-पास फारस से हुआ है और सूफियों ने अपने संदेश का प्रसार करने के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान कीं।
- अमीर खुसरो (1254-1325), एक सूफी संत तथा एक प्रवर्तक ने, कव्वाली के विकास में योगदान दिया। यह संरचना के एक स्वरूप की बजाए गायन की एक विधि है।
- कव्वाली एकल और सामूहिक विधियों का एक मोहक एवं परस्पर बदलता उपयोग है।

टप्पा, पंजाब

- यह पंजाब क्षेत्र में ऊँटों पर सवारी कर विचरने वालों द्वारा प्रेरित अर्ध-शास्त्रीय कंठगीत का स्वरूप है।
- टप्पा, पंजाबी और पश्तो भाषा में रागों में गाया जाता है जिसका सामान्यतः उपयोग अर्ध-शास्त्रीय स्वरूप के लिए किया जाता है। लयबद्ध और द्रुतगति स्वर के साथ तेजी से ऊपर उठना इसकी विशेषता है।

पोवाडा, महाराष्ट्र

- यह महाराष्ट्र की एक पारम्परिक लोक कला शैली है। पोवाडा शब्द का अर्थ, 'शानदार शब्दों में एक कहानी का वृत्तान्त-वृत्तान्त सदैव किसी वीर अथवा घटना अथवा स्थान की प्रशंसा में सुनाया जाता है।
- मुख्य वृत्तान्तकर्ता को शाहीर के नाम से जाना जाता है जो लय बनाए रखने के लिए डफ बजाता है। गीत तीव्र होता है और मुख्य गायक द्वारा नियंत्रित होता है।
- प्राचीनतम उल्लेखनीय पोवाडा अगिन्दास द्वारा रचित अफजल खानचा वध (अफजल खाँ का वध) (1659) था, जिसने अफजल खाँ के साथ शिवाजी के संघर्ष का वर्णन किया था।

तीज गीत, राजस्थान

- तीज, राजस्थान की महिलाओं की बड़ी भागीदारी के साथ मनाई जाती है। सह श्रावण मास के नए चन्द्र अथवा आमावस्या के बाद तीसरे दिन मनाई जाती है।
- त्योहार के दौरान गाए जाने वाले गीतों का विषय शिव और पार्वती का मिलन, मानसून की मनमोहक छटा, हरियाली मौसम, मयूर नृत्य आदि के इर्द-गिर्द होता है।

बुराकथा, आन्ध्र प्रदेश

- बुराकथा, गाथा रूप में एक उच्च कोटि की नाटक शैली

है। इसमें मुख्य कलाकार द्वारा गाथा वर्णन के दौरान बोलत आकार का एक ड्रम (तम्बूरा) बजाया जाता है।

- ☛ गाथा गायक, मंच नायक की तरह अत्यंत बनी बनाई आकर्षक पोशाक पहनता है।

भाखा, जम्मू और कश्मीर

- ☛ लोक संगीत की भाखा शैली जम्मू क्षेत्र में लोकप्रिय है। भाखा का गायन ग्रामवासियों द्वारा फसल काटने के समय किया जाता है।
- ☛ इसे सर्वाधिक मोहक और सुरीला क्षेत्रीय संगीत समझा जाता है। यह, हारमोनियम जैसे वाद्यों के साथ गाया जाता है।

दसकठिया, उड़ीसा

- ☛ दसकठिया उड़ीसा में प्रचलित गाथा गायन की एक शैली है। दसकठिया शब्द 'काठी' अथवा 'राम ताली' नामक एक काष्ठ से बने संगीत वाद्य से लिया गया नाम है, जिसका उपयोग प्रस्तुतीकरण के दौरान किया जाता है।
- ☛ प्रस्तुतीकरण एक प्रकार की पूजा है तथा भक्त 'दास' की ओर से भेंट है।

बिहू, गीत (असम)

- ☛ बिहू गीत अपनी साहित्यिक विषयवस्तु और सांगीतिक विधि दोनों ही दृष्टि से असम की अति विशिष्ट शैली के लोक गीत हैं।
- ☛ बिहू गीत एक खुशहाल नव वर्ष के लिए शुभकामनाओं का प्रतीक हैं तथा नृत्य के साथ-साथ सुख-समृद्धि हेतु एक प्राचीन उपासना की परम्परा से जुड़ी है।
- ☛ बिहू गायन का समय ही एक ऐसा अवसर है जब विवाह योग्य युवा पुरुष और महिलाएं अपनी भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और अपने साथी का चुनाव भी करते हैं।

साना लामोक, मणिपुर

- ☛ मणिपुर की पहाड़ियां और घाटियां दोनों ही संगीत और नृत्य की शौकीन हैं। साना लामोक 'माईबा (पुजारी)' द्वारा राज्याभिषेक समारोह के दौरान गाया जाता है। यह बादशाह का स्वागत करने के लिए भी गाया जाता है।
- ☛ इसे पाखंगबा, प्रधान देवता, की आत्मा को जाग्रत करने के लिए गाया जाता है।

लाई हरोबा त्यौहार के गीत, मणिपुर

- ☛ लाई हरोबा शब्द का अर्थ देवी और देवताओं का त्यौहार है। इसे उमंग-लाई (वनदेवता) के लिए गाया जाता है।
- ☛ औगरी हेंगेन, सृजन का गीत और हेईजिंग हिराओ, एक आनुष्ठानिक गीत, लाई हरोबा त्यौहार के अन्तिम दिवस पर गाया जाता है।

साईकुती जई (साईकुती के गीत), मिजोरम

- ☛ मिजो लोगों को पारम्परिक रूप से, एक 'गायक जनजाति' के रूप में जाना जाता है।
- ☛ मिजोरम के क्षेत्रीय लोक गीत मिजो लोगों की एक समृद्ध परम्परा है।
- ☛ साईकुती मिजोरम की एक कवियित्री द्वारा रचित गीत हैं जिन्हें योद्धाओं, बहादुर शिकारियों तथा महान योद्धा और शिकारी आदि बनने के इच्छुक युवा व्यक्तियों की प्रशंसा में गाया जाता है।

घसियारी गीत, गढ़वाल

- ☛ पहाड़ों में युवा महिलाओं को अपने पशुओं के लिए घास लाने के लिए दूर-दूर वनों में जाना पड़ता है। वे वन में समूहों में नाचते और गाते हुए जाती हैं।
- ☛ मनोरंजन के साथ-साथ घसियारी गीत में श्रम के महत्व पर बल दिया जाता है।

भारत के लोकनृत्य

- ☛ राजाओं और शासकों के संरक्षणाधीन, कुशल नर्तक और गायकों तथा कारीगरों की संपूर्णता तथा परिष्करण के उच्चतर स्तरों तक अपनी कुशलताओं में विशेषज्ञता हासिल करने एवं परिष्कृत करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।
- ☛ धीरे-धीरे मंदिर और महल के लिए विकसित कला के शास्त्रीय रूप द्वितीय ईस्वी शताब्दी के आस-पास और तत्पश्चात् शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के अधीन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए।
- ☛ इस प्रकार जहां शास्त्रीय कलाएं अपनी लोक जड़ों से भिन्न हो गईं।
- ☛ वहीं वे इनसे कभी भी पूरी तरह से विमुख भी नहीं हुईं, यहां तक कि आज भी एक ओर जनजातीय और लोक शैलियों के बीच तो दूसरी ओर शास्त्रीय कला में एक पारस्परिक समृद्धिकारी संवाद चल रहा है।
- ☛ इसके अतिरिक्त, कला संबंधी इनकी जड़ों से जुड़ाव इन्हें कला के क्षेत्रीय शास्त्रीय रूपों से पृथक कर देता है।
- ☛ भारत में धर्म, दर्शन और मिथक को उनके कला रूपों से पृथक नहीं किया जा सकता। नृत्य और संगीत किसी प्रकार के समारोह से अनिवार्य रूप से बंधे हुए हैं।
- ☛ संगीत और नृत्य संभवतः कला के सबसे अधिक सशक्त रूप हैं तथा ये मानव के मनोभावों तथा अनुभवों की समूची स्थिति को सहज ही व्यक्त करते हैं।
- ☛ समूचे भारत में जनजातीय क्षेत्र हैं और प्रत्येक जनजाति का अपना विशिष्ट संगीत तथा नृत्य होते हुए भी एक समान रूप से सभी के लिए है।

- ❖ जिसमें पुरुष एवं महिलाएं हाथ पकड़ कर अलग-अलग कतार बनाते हैं एवं पग थिरकते हैं।
- ❖ कृषि से जुड़े समुदाय का लोक संगीत और नृत्य दैनिक जीवन की लय, ऋतुओं के बदलने, कृषि चक्र की विशिष्टताओं, धार्मिक पर्वों और जन्म तथा विवाह जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटे हुये हैं।
- ❖ नृत्य नाटक या लोक रंगशाला के अन्य अनेक रूप भी हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की नौटंकी, गुजरात का भवाई, महाराष्ट्र का तमाशा, बंगाल का जात्रा, कर्नाटक का भव्य यक्षगान, केरल का तथथम ये सभी स्थानीय वीरों, राजाओं तथा देवताओं की दन्तकथाओं का वर्णन करते हैं।

नृत्य कलाएं

भारतीय शास्त्रीय नृत्य

- ❖ भारत में प्राचीन काल से एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा रही है। विभिन्न कालों की खुदाई, शिलालेखों, ऐतिहासिक वर्णन, राजाओं की वंश परंपरा तथा कलाकारों, साहित्यिक स्रोतों, मूर्तिकला और चित्रकला से व्यापक प्रमाण उपलब्ध होते हैं।
- ❖ पौराणिक कथाएं और दंतकथाएं भी इस विचार का समर्थन करती हैं कि भारतीय कला के धर्म तथा समाज में नृत्य ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया।
- ❖ साहित्य में पहला संदर्भ वेदों से मिलता है, जहां नृत्य व संगीत का उद्गम है। नृत्य का एक ज्यादा संयोजित इतिहास महाकाव्यों अनेक पुराण, कवित्व, साहित्य तथा नाटकों का समृद्ध कोष जो संस्कृत में काव्य और नाटक के रूप में जाने जाते हैं, से पुनर्निर्मित किया जा सकता है।
- ❖ शास्त्रीय संस्कृत नाटक का विकास एक वर्णित विकास है, जो मुखरित शब्द, मुद्राओं और आकृति, ऐतिहासिक वर्णन, संगीत तथा शैलीगत गतिविधि का एक सम्मिश्रण है।
- ❖ खुदाई से दो मूर्तियां प्रकाश में आई - एक मोहनजोदड़ो की कांसे की मूर्ति और दूसरा हड़प्पा का एक टूटा हुआ धड़। यह दोनों मूर्तियां नृत्य मुद्राओं की सूचक है।
- ❖ बाद में नटराज आकृति के अग्रदूत के रूप में इसे पहचाना गया, जिसे आमतौर पर नृत्य करते हुए शिव के रूप में पहचाना जाता है।
- ❖ नाट्यशास्त्र में सूत्रबद्ध शास्त्रीय परंपरा की शैली में नृत्य और संगीत नाटक के अलंघनीय भाग है।
- ❖ नाटक की कला में इसके सभी मौलिक अंशों को रखा जाता है और कलाकार स्वयं नर्तक तथा गायक होता है।
- ❖ प्रस्तुतकर्ता स्वयं तीनों कार्यों को संयोजित करता है। समय के साथ-साथ जबकि नृत्य अपने आप नाटक से अलग हो गया और स्वतंत्र तथा विशिष्ट कला के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

- ❖ **नाट्य:** नाट्य में नाटकीय तत्व पर प्रकाश डाला जाता है। 'कथकली नृत्य-नाटक रूप' के अतिरिक्त आज अधिकांश नृत्य रूपों में इस पहलू को व्यवहार में कम लाया जाता है।
- ❖ **नृत्य:** नृत्य मौलिक अभिव्यक्ति है और यह विशेष रूप से एक विषय या विचार का प्रतिपादन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- ❖ **नृत्त:** नृत्त दूसरे रूप से शुद्ध नृत्य है, जहां शरीर की गतिविधियां ना तो किसी भाव का वर्णन करती हैं, और ना ही वे किसी अर्थ को प्रतिपादित करती हैं।
- ❖ **नवरस:** नृत्य और नाटक को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक नर्तकी को नवरसों का संचार करने में प्रवीण होना चाहिए।

- | | | |
|-----------|---|-------------------------|
| 1. शृंगार | - | प्रेम के लिए |
| 2. हास्य | - | हास्य/विनोद नाटक के लिए |
| 3. करुणा | - | दुःखान्त के लिए |
| 4. वीर | - | शूरता के लिए |
| 5. रौद्र | - | क्रोध के लिए |
| 6. भय | - | संत्रास के लिए |
| 7. वीभत्स | - | घृणा के लिए |
| 8. अद्भुत | - | आश्चर्य के लिए |
| 9. शांत | - | शांति के लिए |

- ❖ सभी नृत्य शैलियों में प्राचीनकालीन वर्गीकरण तांडव और लास्य का अनुकरण किया जाता है। ये हैं—
- ❖ **तांडव:** तांडव पुरुषोचित, वीरोचित, निर्भीक और ओजस्वी नृत्य है। यह नृत्य की नर अभिमुखताओं का प्रतीक है तथा इसमें लय तथा गति पर अधिक बल दिया गया है।
- ❖ **लास्य:** लास्य स्त्रीयोचित, कोमल, लयात्मक और सुंदर नृत्य है। कला का यह रूप नृत्य की नारी सुलभ विशेषताओं का प्रतीक है।
- ❖ अभिनय का विस्तारित अर्थ अभिव्यक्ति है। यह आंगिक, शरीर और अंगों, वाचिक और कथन; अहार्य, वेशभूषा और अलंकार; और सात्विक, भावों और अभिव्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है।

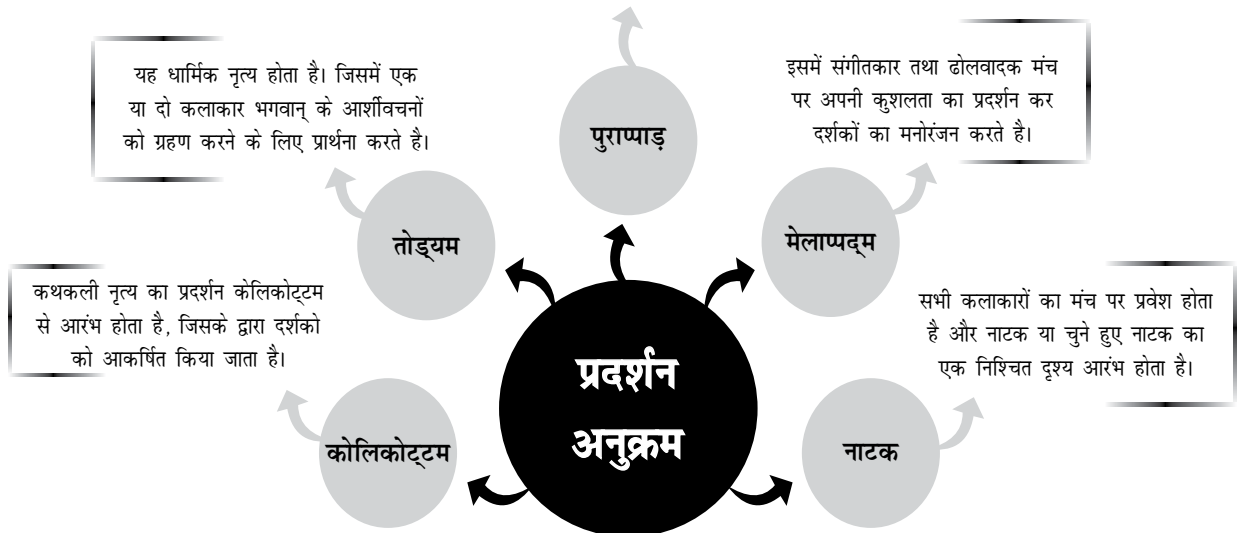
शास्त्रीय नृत्य

कथकली नृत्य

- ❖ कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आज कथकली एक प्रचलित नृत्य रूप है।
- ❖ यह एक कला है जो प्राचीन काल में दक्षिणी प्रदेशों में प्रचलित बहुत से सामाजिक और धार्मिक रंगमंचीय कला रूपों से उत्पन्न हुई है।
- ❖ केरल के मंदिरों के शिल्पों और लगभग 16वीं शताब्दी के

- मट्टानचेरी मंदिर के भित्तिचित्रों में वर्गाकार तथा आयताकार मौलिक मुद्राओं को प्रदर्शित करते नृत्य के दृश्य देखे जा सकते हैं, जो कथकली की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।
- ❶ कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का वर्णन है। इसमें अधिकतर भारतीय महाकाव्यों से ली गई कथाओं का नाटकीकरण किया जाता है।
 - ❷ यह शैलीबद्ध कला रूप है, इसमें अभिनय के चार पहलू - अंगिका, अहार्य, वाचिका, सात्विका और नृत्त, नृत्य तथा नाट्य पहलुओं का सम्मिश्रण है।
 - ❸ नर्तक अपने भावों को विधिबद्ध हस्तमुद्राओं और चेहरों के भागों से अभिव्यक्त करता है। कथकली नृत्य शैली अपनी मूल पाठ-विषयक स्वीकृति बलराम भरतम् और हस्तलक्षण दीपिका से प्राप्त करती है।
 - ❹ आट्याक्कथा या कहानियों को महाकाव्यों तथा पौराणिक कथाओं से चुना जाता है।
 - ❺ इन्हें उच्च स्तरीय संस्कृत पद्य रूप में मलयालम् भाषा में लिखा जाता है। कथकली नृत्य का संगीत केरल के परंपरागत सोपान संगीत का अनुसरण करता है।
 - ❻ सोपान संगीत के अंतर्गत मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ियों की पंक्तियों पर अष्टपादियों का अनुष्ठानिक गान होता है।
 - ❼ कथकली नृत्य में कर्नाटक रागों का भी प्रयोग होता है और कर्नाटक राग के अंतर्गत राग और ताल, भाव, रस और नृत्य के प्रतिरूपों नृत्त और नाट्य की पुष्टि होती है।
 - ❶ कथकली एक दृश्यात्मक कला है, जहां पात्र के अनुसार अहार्य वेशभूषा और श्रृंगार नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है।
 - ❷ कलाकार (नर्तक) के चेहरे को कुछ इस प्रकार रंग दिया जाता है कि वह मुखौटे का आभास देता है। होठों, भौंहों और पलकों को उभार कर दिखाया जाता है।
 - ❸ कथकली नृत्य मुख्यतः व्याख्यात्मक होता है। इसके प्रस्तुतिकरण में पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिक और तामसिक वर्गों में विभक्त किया जाता है।
 - ❹ **सात्विक:** सात्विक चरित्र कुलीन, वीरोचित, दानशील और परिष्कृत होते हैं। पाचा (नायक) में हरा रंग प्रमुख होता है और सभी पात्र किरिट (मुकुट) धारण करते हैं।
 - ❺ कृष्ण और राम मोर पंख से अलंकृत मुकुट पहनते हैं। इंद्र, अर्जुन और देवताओं जैसे कुछ कुलीन पाचा पात्र होते हैं।
 - ❻ **राजसिक:** इस वर्ग में कई प्रकार के पात्र खलनायक पात्र होते हैं, फिर भी ये राजसिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
 - ❼ कभी-कभी ये रावण, कंस और शिशुपाल जैसे महान योद्धा और विद्वान भी होते हैं।
 - ❶ मूँछे और चुट्टीप्प नामक छोटी मूठ (घुण्डी) को नाक के अग्रभाग और एक अन्य को माथे के बीच में लगाया जाता है।

अंतः भाग के रूप में पुराणाड् विशुद्ध नृत्य खंड प्रदर्शित किया जाता है।



विशेषताएं

1. श्रेष्ठ मानवीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वेशभूषा और श्रृंगार विस्तृत तथा डिजाइन युक्त होता है। कथकली

नृत्य के लिए श्रृंगार की प्रक्रिया को तेप्प चुट्टीकुत्त और उडुत्तुकेट्ट में वर्गीकृत किया जाता है। तेप्प को कलाकार स्वयं ही कर लेता है।

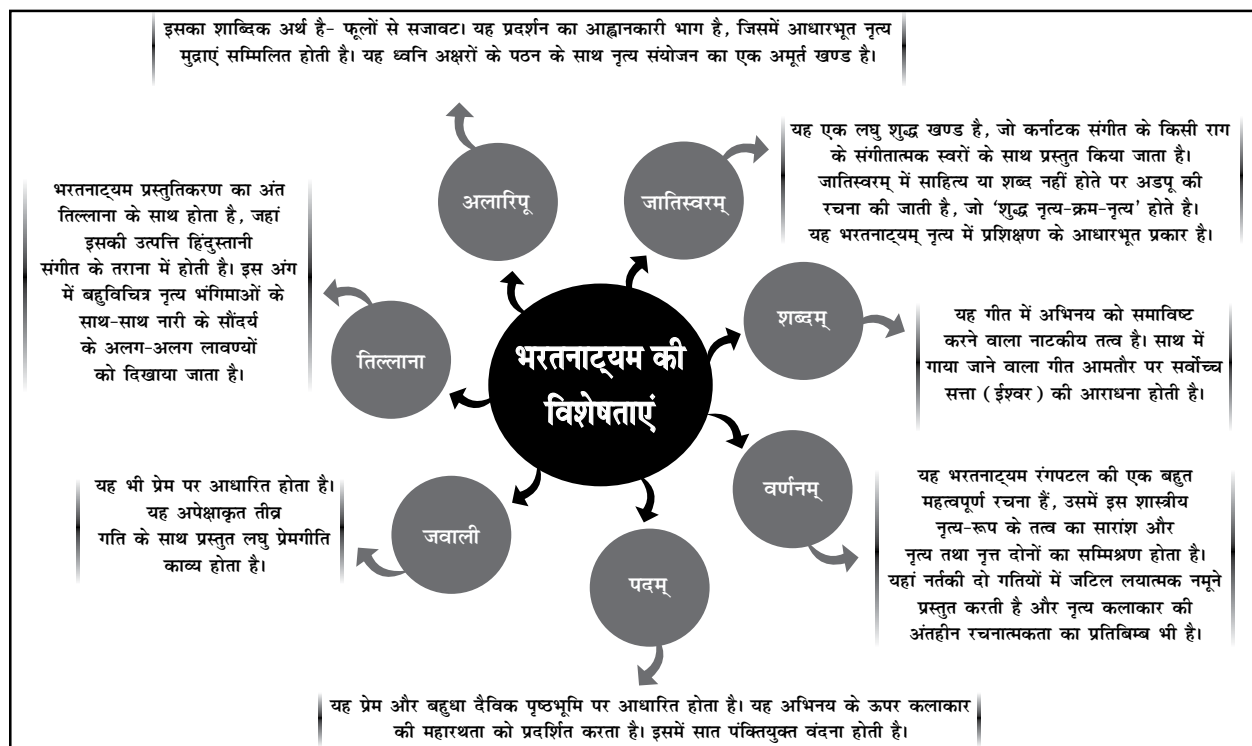
2. कथकली के अतिरिक्त अन्य किसी नृत्य शैली में पूरी तरह से शरीर के सभी अंगों का उपयोग नहीं होता। इस नृत्य शैली के तकनीकी विवरण में चेहरे की मांस-पेशियों से लेकर अंगुलियाँ, आँखें, हाथ और कलाई सभी कुछ आ जाता है। चेहरे की मांसपेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. नाट्यशास्त्र के वर्णन के अनुसार अन्य किसी भी नृत्य शैली में भौहों, आँख की पुतलियों और निचली पलकों की गति का इतना प्रयोग नहीं किया जाता जितना कथकली में किया जाता है। शरीर का सारा भार पैरों के बाहरी किनारों पर होता है जो थोड़े झुके और मुड़े होते हैं।

भरतनाट्यम्

- भरतनाट्यम् नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से इस नृत्य की जानकारी प्राप्त होती है। भरतनाट्यम् का नाम भरत मुनि तथा नाट्यम् शब्द से मिलकर बना है।
- तमिल में नाट्यम् शब्द का अर्थ नृत्य होता है। नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम् नृत्य में, शरीर की गतिविधि के व्याकरण और तकनीकी अध्ययन के लिए ग्रंथीय सामग्री का एक प्रमुख स्रोत है।
- चिंदबरम मंदिर के गोपुरमों पर भरतनाट्यम् नृत्य की भंगिमाओं

की एक श्रृंखला और मूर्तिकार द्वारा पत्थर को काटकर बनाई गई प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं।

- भरतनाट्यम् नृत्य को एकहार्य के रूप में भी जाना जाता है, जहां नर्तकी एकल प्रस्तुति में अनेक भूमिकाएं करती हैं।
- देवदासियाँ मंदिर के प्रांगण में देवताओं को अर्पण के रूप में संगीत व नृत्य प्रस्तुत करती थीं।
- इस सदी के कुछ प्रसिद्ध गुरुओं और अनुपालकों का संबंध देवदासी परिवारों से है जिनमें बाला सरस्वती एक बहुत परिचित नाम है।
- भरतनाट्यम् का रंगपटल बहुत विस्तृत होता है, जबकि प्रस्तुतिकरण में नियमित ढांचे का अनुकरण किया जाता है। सबसे पहले यहां स्तुति-गान होता है।
- यह एक अनुनादी (गुंजायमान) नृत्य है, जो साहित्य की कुछ पंक्तियों के साथ तथा संगीत के कुछ अक्षरों के साथ-साथ प्रस्तुत किया जाता है।
- विशिष्ट रूप से अभिकल्पित लयात्मक पंक्तियों के एक चर्मोत्कर्ष पर पहुंचने के साथ खण्ड का समापन होता है।
- प्रस्तुतिकरण का अंत मंगलम्, भगवान के आशीर्वचन मांगने के साथ होता है।
- भरतनाट्यम् नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक मृदंगम वादक, एक वीणा वादक और एक करताल वादक होता है। जो व्यक्ति नृत्य का कविता-पाठ करता है, वह नट्टुवनार होता है।



कथक नृत्य

- कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एक कहानी से है। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विधा है।
- कथाकार प्रायः दंतकथाओं, पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों की उपकथाओं के विस्तृत आधार पर कहानियों का वर्णन मौखिक रूप से करते हैं।
- बाद में इसे ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें स्वांग और मुद्राएं जोड़ी गईं। भक्ति आंदोलन ने लयात्मक और संगीतात्मक रूपों के एक संपूर्ण नव प्रसार के लिए सहयोग दिया।
- राधा-कृष्ण की विषयवस्तु मीराबाई, सूरदास, नंददास और कृष्णदास के कार्य के साथ बहुत प्रसिद्ध हुई। रासलीला अपने आप में संगीत, नृत्य और व्याख्या का संयोजन है।
- मुगल काल में हिन्दू और मुस्लिम दोनों दरबारों में कथक उच्च शैली में उभरा और मनोरंजन के एक मिश्रित रूप में विकसित हुआ।
- मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत यहां नृत्य पर विशेष बल दिया गया और भाव ने इस नृत्य को सौंदर्यपूर्ण, प्रभावकारी तथा भावनात्मक (इंद्रिय) आयाम प्रदान किए गए।

कथक के प्रसिद्ध घराने

- लखनऊ घराना:** 19 वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है।
- नवाब ने लखनऊ घराने को अभिव्यक्ति तथा भाव पर उसके प्रभावशाली स्वरूप सहित स्थापित किया। इस घराने के नृत्य पर मुगल प्रभाव के कारण नृत्य में श्रृंगारिकता के साथ-साथ अभिनय पक्ष पर भी विशेष ध्यान दिया।
- इस घराने को पहचान दिलाने में पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का विशेष योगदान रहा है।
- जयपुर घराना:** जयपुर घराना अपनी लयकारी या लयात्मक प्रवीणता के लिए जाना जाता है। इस घराने के नृत्य के दौरान पाँव की तैयारी, अंग संचालन तथा नृत्य की गति पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- इसे शीर्ष पर पहुँचाने में उमा शर्मा, प्रेरणा श्री माली, शोभना नारायण, राजेन्द्र गंगानी और जगदीश गंगानी ने पर्याप्त योगदान दिया है।
- बनारस घराना:** इस घराने में श्रृंगारिकता के स्थान पर प्राचीन शैली पर अधिक बल दिया गया। यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ।
- इस घराने के नाम पर प्रख्यात नृत्यगुरु सितारा देवी के पश्चात्

उनकी पुत्री जयंतीमाला ने इसकी छवि को बनाये रखने का प्रयास किया।

- रायगढ़ घराना:** अन्य सभी घरानों से नया माना जाता है। इसकी स्थापना रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह के आश्रय में पंडित जयलाल, पंडित सीताराम, हनुमान प्रसाद और लखनऊ घराने के पंडित अच्छन महाराज तथा पंडित लच्छू महाराज द्वारा की गयी।
- यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने हेतु महत्वपूर्ण है।

विशेषताएं

- कथक में गतिविधि (नृत्य) की विशिष्ट तकनीक है। शरीर का भार क्षितिजीय और लंबवत् धुरी के बराबर समान रूप से विभाजित होता है।
- पाँव के संपूर्ण संपर्क को प्रथम महत्व दिया जाता है जहाँ सिर्फ पैर की एड़ी या अंगुलियों का उपयोग किया जाता है।
- यहाँ कोई झुकाव नहीं होता और शरीर के निचले हिस्से के वक्रों या मोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता।
- धड़ गतिविधियाँ कंधों की रेखा के परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं, नीचे कमर की मांसपेशियों और ऊपरी छाती या पीठ की रीढ़ की हड्डी के परिचालन से ज्यादा उत्पन्न होती है।
- मौलिक मुद्रा में संचालन की एक जटिल पद्धति के उपयोग द्वारा तकनीक का निर्माण होता है। शुद्ध नृत्य (नृत्त) सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण अनुक्रम

- थाट:** नर्तकी एक क्रम थाट के साथ आरंभ करती है जहाँ गले, भावों और कलाइयों की धीरे-धीरे होने वाली गतिविधियों की शुरुआत की जाती है।
- इसका अनुसरण अमद (प्रवेश) और सलामी (अभिवादन) के रूप में परिचित एक परंपरागत औपचारिक प्रवेश द्वारा किया जाता है।
- चक्कर नृत्य:** यह नृत्य शैली की एक बहुत विलक्षण विशेषता है।
- लयात्मक अक्षरों का वर्णन सामान्य है; नर्तकी अक्सर एक निर्दिष्ट छंदबद्ध गीत का वर्णन करती है और उसके बाद नृत्य गतिविधि के प्रस्तुतिकरण द्वारा उसका अनुसरण करती है।
- कथक के नृत्त भाग में नगमा को प्रयोग में लाया जाता है। ढोल बजाने वाले और नर्तकी-दोनों एक सुरीली पंक्ति की आवृत्ति पर निरंतर संयोजनों का निर्माण करते हैं।
- जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है।
- यह जुगलबंदी सामान्यतः ध्रुपद संगीत के साथ होती है।

मणिपुरी नृत्य

- मणिपुरी नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राज्य मणिपुर में उत्पन्न हुआ। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण मणिपुर के लोग बाहरी प्रभाव से बचे रहे हैं।
- इसी कारण यह अपनी विशिष्ट परंपरागत संस्कृति को बनाये रखने में समर्थ रहा। मणिपुरी नृत्य धार्मिक और परंपरागत उत्सवों के साथ जुड़ा है।
- यहां शिव और पार्वती के नृत्यों तथा अन्य देवी-देवताओं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, की दंत कथाओं के संदर्भ मिलते हैं।
- 'लाई हरोबा' मुख्य उत्सवों में से एक है और आज भी मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है, पूर्व वैष्णव काल से इसका उद्भव हुआ था।
- लाई हरोबा नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्य के रूपों का आधार है।

विशेषताएं

- सामूहिक गान का कीर्तन रूप नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है जिसे मणिपुर में संकीर्तन के रूप में जाना जाता है।
- पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का पुरुषोचित पहलू-चोलोम, संकीर्तन परंपरा का एक भाग है।
- मणिपुर का 'युद्ध संबंधी नृत्य-थांग टा' उन दिनों उत्पन्न हुआ जब मनुष्य जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी क्षमता पर निर्भर रहना शुरू किया।
- आज मणिपुर युद्ध संबंधी नृत्यों, तलवारों, ढालों और भालों का उपयोग करने वाले नर्तकों का उत्सर्जक तथा कृत्रिम रंगपटल है।
- मणिपुर नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समावेशन है। इसकी पहचान बहुत वीरतापूर्ण पुरुषोचित पहलुओं से लेकर शांत तथा मनोहारी स्त्रीयोचित पहलू तक है।
- मणिपुरी नृत्य की एक दुर्लभ विशेषता है, जिसे लयात्मक और मनोहारी गतिविधियों के रूप में जाना जाता है।
- मणिपुरी अभिनय में मुखाभिनय को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। चेहरे के भाव स्वाभाविक होते हैं और अतिरंजित नहीं होते।
- मणिपुरी गायन की शास्त्रीय शैली को 'नट' कहा जाता है, जो उत्तर तथा दक्षिण भारतीय संगीत-दोनों से बहुत अलग है।
- यह शैली निश्चित प्रकार के स्वर और अनुकूलन सहित उच्च स्वरमान के साथ जल्दी पहचानी जा सकती है।
- मुख्य संगीत वाद्य यंत्र पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ढोल है।

- इसका शब्दिक अर्थ है- देवताओं का आमोद-प्रमोद। मणिपुरी नृत्य का एक विस्तृत रंगपटल होता है तथापि रास, संकीर्तन और थांग-टा इसके बहुत प्रसिद्ध रूप हैं। यहां पांच मुख्य रास नृत्य हैं जिनमें से चार का संबंध विशिष्ट ऋतुओं से है, जबकि पांचवां साल में किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। मणिपुरी रास में राधा, कृष्ण और गोपियां मुख्य पात्र होते हैं।

सत्रिया नृत्य (असम)

- इस नृत्य परंपरा को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु प्रस्तुत किया गया।
- यह असमी नृत्य और नाटक का नया खजाना शताब्दियों तक सत्रों द्वारा संरक्षित किया गया है।
- शंकरदेव द्वारा स्थानीय लोक नृत्यों जैसे विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए अपने स्वयं की नई शैली में इस नृत्य शैली की रचना की।

विशेषताएं

- सत्रिया प्रस्तुतियों का मुख्य ध्यान नृत्य के भक्तिपूर्ण पहलू को उजागर करने तथा विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन करने पर केन्द्रित है।
- परंपरागत हस्तमुद्राओं, पाद कार्यों, अहार्य संगीत आदि के संबंध में सख्ती से बने सिद्धांतों के द्वारा सत्रिया नृत्य की परंपरा संचालित होती है। इस परंपरा की विशिष्ट रूप से भिन्न दो धाराएं होती हैं-
- प्रथम गायन बायनार नाच से खरमारनाच का आरंभ नाटकीय प्रस्तुतियों से युक्त भाओना संबंधित रंगपटल से होता है, तथा दूसरे ऐसे नृत्य जो स्वतंत्र हैं जैसे चाली, राजस्थानी चाली, झुमरा, नादु भंगी आदि।
- चाली को लालित्यपूर्ण एवं शानदार-वीरोचित जुदाई को प्रस्तुत करते पुरुष चरित्र द्वारा निष्पादित किया जाता है।
- इस नृत्य को कई विधाओं में विभाजित किया गया है- बेहर नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, रास नृत्य, अप्सरा नृत्य आदि।
- इसमें भी नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर और अभिनय दर्पण के सिद्धांतों का प्रयोग होता है जिसे 'बारेगीत' कहते हैं जो शास्त्रीय रागों पर आधारित है।
- इसमें खोल (ढोल), ताल, और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है।
- हाल के दिनों में वायलिन और हारमोनियम का प्रयोग भी होने लगा है।
- नर्तकों द्वारा रेशमी कपड़े जिसे पट कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है।

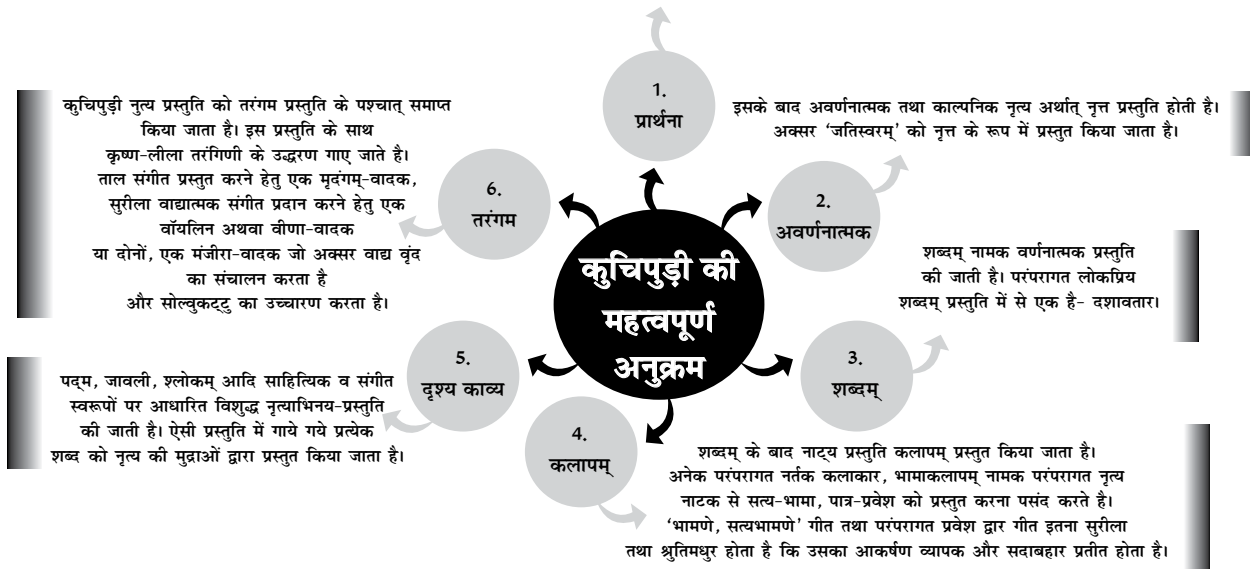
कुचिपुड़ी नृत्य

- कुचिपुड़ी आन्ध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है। यह भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है।
- मूलतः कुस्सेल्वा के नाम से विख्यात ग्राम-ग्राम जा कर प्रस्तुति देने वाले अभिनेताओं के समूह के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विधा है।
- आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव है। 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि तथा दृष्टा सिद्धेन्द्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की, जिनमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त एवं साकार रूप प्रदान करने की अद्भुत क्षमता थी।
- इस शैली में एकल नृत्य-प्रस्तुति व स्त्री नर्तकियों के प्रशिक्षण सहित अनेक नए तत्वों का समावेशन लक्ष्मी नारायण शास्त्री

ने किया।

- पहले भी एकल नृत्य-प्रस्तुति विद्यमान थी, पर वह केवल समुचित कार्यों में नृत्य-नाटकों के एक भाग के रूप में की थी।
- कभी-कभी तो नाटक की प्रस्तुति में आवश्यक ना होने पर भी अनुरोध अथवा आग्रह में वृद्धि करने तथा प्रस्तुति को बीच में रोकने हेतु एकल नृत्य प्रस्तुत की जाती थी।
- तीर्थ नारायण योगी की कृष्ण-लीला-तरंगिणी से प्रेरित तरंगम् ऐसी ही प्रस्तुति है।
- शरीर संतुलन तथा पादकौशल तथा उसके नियंत्रण में नर्तक कलाकारों की दक्षता प्रदर्शित करने हेतु पीतल की थाली की किनारी पर नृत्य करना तथा सिर पर पानी से भरा घड़ा लेकर नृत्य करने जैसी कुशलताओं को जोड़ा गया।

कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति एक प्रार्थनामयी प्रस्तुति से आरंभ होती है, जैसा अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों में होता है। प्रार्थना में गणेश वंदना तथा अन्य देवताओं का भी आह्वान किया जाता है।



विशेषताएं

- कुचिपुड़ी की अधिकांश प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं, किंतु उनका केन्द्रीय भाव पंथ-निरपेक्ष रहा है।
- इसमें प्रधानतः श्रृंगार रस होता है।
- कुचिपुड़ी नृत्य विधा में लास्य तथा तांडव दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं।

मोहिनीअट्टम

- मोहिनीअट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है, हिन्दू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल

का शास्त्रीय एकल नृत्य-रूप है। मोहिनी अर्थात् सुन्दर नारी तथा अट्टम अर्थात् नृत्य है।

- पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में लोगों का मनोरंजन करने के लिए "मोहिनी" का वेष धारण किया था।
- यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है।
- केरल के इस नृत्य की संरचना त्रावणकोर राजाओं महाराजा कार्तिक तिरुनल और उसके उत्तराधिकारी महाराजा स्वाति तिरुनल द्वारा वर्तमान शास्त्रीय स्वरूप में की गई थी।
- इसका उद्भव केरल के मंदिरों में हुआ।

विशेषताएं

- मोहिनीअट्टम की विशेषता बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के लालित्यपूर्ण, ढलावदार शारीरिक अभिनय है।
- यह लास्य शैली से संबंधित है जो स्त्रीत्वपूर्ण, मुलायम और सुन्दर है।
- अभिनय में सर्पण द्वारा बल दिया जाता है, पंजो पर ऊपर और नीचे अभिनय होता है, जो समुद्र की लहरों तथा कोकोनट पाम वृक्षों अथवा खेत में धान के पौधों के ढलान से मिलता-जुलता है।
- पादकार्य संक्षिप्त नहीं तथा कोमलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हस्त भंगिमाओं को महत्व दिया जाता है तथा मुखाभिनय विलक्षण अभिव्यक्ति के साथ है।
- बहुत से स्त्री अभिनय मंदिर नृत्यों से नकल किए गए हैं जैसे कि ननगियर कुथु और लोक नृत्य जैसे कि 'कई कोत्तीकली' जिसे 'तिरुवतिराकली' के नाम से भी जाना जाता है। 'तिरुवतिराकली' एक विशुद्ध नृत्य है।
- हस्त भंगिमाएं मुख्यतः 'हस्तालक्षण दीपिका' से अपनाई गई हैं, जो एक पाठ है, जिसका पालन कथकली द्वारा किया जाता है।
- भंगिमाएं और मुखीय अभिव्यक्ति स्वाभाविक (ग्राम्य) और वास्तविक (लोक धर्मी) के साथ मिलती-जुलती है, ना कि नाट्य अथवा कठोर परंपरा (नाट्यधर्मी) के साथ। पारंपरिक रंगपटल के अंतर्गत "चोल्लुकेतु" "पदमावरण" "पैदम तिलाना" और "श्लोकम्" सम्मिलित है।
- इसके अलावा इन दो मदों के अंतर्गत पंडाट्टम और ओमानातिकल (लुल्लबी) भी, जिसे वलाटोल द्वारा प्रारंभ किया गया था, लोकप्रिय है और उसे प्रायः गायन में शामिल किया जाता है।

ओडिसी नृत्य

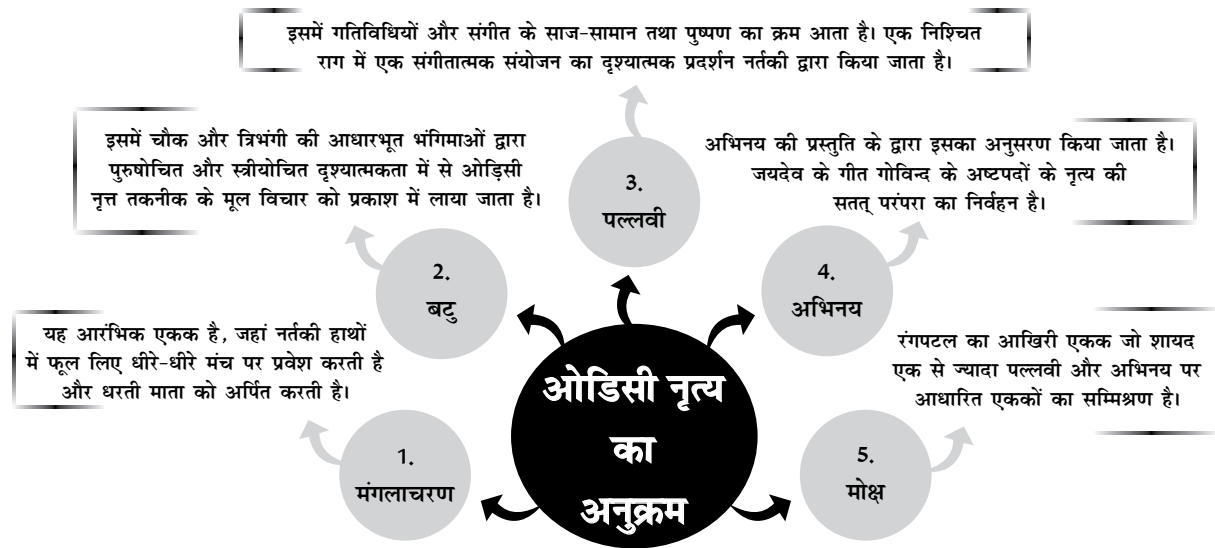
- ओडिसा के इस नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुरातन जीवित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है।
- इंद्रिय और गायन के रूप में ओडिसी प्रेम और भाव, देवताओं और मानव से जुड़ा सांसारिक और लोकोत्तर नृत्य है।
- दक्षिणी-पूर्वी शैली उधरा मगध शैली के रूप में जानी जाती है, जिसमें वर्तमान ओडिसी के प्राचीन अग्रदूत दूत के रूप

में पहचाना जा सकता है। भुवनेश्वर के पास उदयगिरि और खण्डगिरि की गुफाओं से इस नृत्य रूप के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं।

- भारत के अन्य भागों की तरह, रचनात्मक साहित्य ओडिसी नर्तकियों को प्रेरणा प्रदान करता है और नृत्य के लिए विषय-वस्तु भी उपलब्ध कराता है।
- यह बात विशेषतः जयदेव द्वारा रचित 12वीं सदी के गीत गोविन्द के बारे में सत्य है।
- इसकी साहित्य शैली और कविता शैली की विषय सूची में अन्य उत्कृष्ट कविताएं और नायक-नायिका भाव का एक गहन उदाहरण है।

विशेषताएं

- ओडिसी गुप्त रूप से नाट्यशास्त्र द्वारा स्थापित सिद्धांतों का अनुसरण करता है।
- चेहरे के भाव, हस्त-मुद्राएं और शरीर की गतिविधियों का उपयोग एक निश्चित अनुभूति एक भावना या नवरसों में से किसी एक संकेत के लिए किया जाता है।
- **चौक:** एक वर्ग (चौकोर) की स्थिति है। यह शरीर के भार के समान संतुलन के साथ एक पुरुषोचित मुद्रा है।
- **त्रिभंग:** त्रिभंग एक बहुत स्त्रीयोचित मुद्रा है, जिसमें शरीर, गले, धड़ और घुटने पर मड़ाव होता है।
- धड़ संचालन ओडिसी शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक विशिष्ट लक्षण है।
- इसमें शरीर का निचला हिस्सा स्थिर रहता है और शरीर के ऊपरी हिस्से के केन्द्र द्वारा धड़ धुरी के समानान्तर एक ओर से दूसरी ओर गति करता है।
- इसमें कंधों या नितंबों की किसी भी गतिविधि से बचा जाता है।
- पैरों की गतिविधियां धरती पर या अंतराल में पेचदार या वृत्ताकार होती हैं।
- पैरों की गतिविधियों के अतिरिक्त यहां छलांग या चक्कर के लिए चाल की एक विविधता है और निश्चित मुद्राएं मूर्तिकला द्वारा प्रेरित है।
- हस्तमुद्राएं नृत्य एवं नृत्य दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।
- ओडिसी वादक मंडल में मूलतः एक पखावज वादक, एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक सितार या वीणा वादक और एक मंजीरा वादक होता है।



भारत के लोकनृत्य

- वे नृत्य जो जीवन के विविध रंगों के प्रकाश के कारण आभासित हैं, लोकनृत्य कहा जाता है।
- भारत के विविध भागों में प्रचलित लोक-कथाओं, किंवदंतियों तथा स्थानीय गीत और नृत्य परंपराओं के मेल से मिश्रित कलाओं की समृद्ध परंपरा तैयार हुई है।
- ये नृत्य विशेष अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें धर्म, व्यवसाय और जाति के आधार पर अंतर पया जाता है।
- जीवन चक्र और ऋतुओं के वार्षिक चक्र के लिए अलग-अलग नृत्य हैं।
- ये नृत्य दैनिक जीवन और धार्मिक अनुष्ठानों का अंग हैं। ये कला विधाएं एक विशेष वर्ग या किसी विशेष स्थान तक सीमित रह गयी हैं।

भारतीय लोकनृत्यों को सामान्य तौर पर चार वर्गों में विभाजित किया जाता है

- | | |
|--|---------------|
| 1. सामाजिक | 2. धार्मिक |
| 3. आनुष्ठानिक | 4. वृत्तिमूलक |
| (वृत्तिमूलक- जुताई, बुआई, कटाई, शिकार आदि) | |

राज्यों के अनुसार प्रमुख लोकनृत्य

बारदोधाम (अरुणाचल प्रदेश)

- यह नृत्य अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी केमांग जिले में 'शारदुकपेन जनजाति' समुदाय द्वारा किया जाता है। यह त्यौहारों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। बारदोधाम का अर्थ होता है- कुंडलियों का नृत्य।
- इसे करते समय रंगीन मुखौटे का प्रयोग करते हैं। इनके

अनुसार ईश्वर कर्म के अनुसार फल देता है।

बिहू (असम)

- यह मिरी, कचारी, तथा खासी जनजाति के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ढोल, पीपा, गगन इत्यादि इसमें प्रयुक्त प्रमुख बाद्य हैं।
- बिहू का आयोजन वर्ष में तीन बार होने वाले त्यौहारों पर किया जाता है।
- इस नृत्य के सफल प्रदर्शन में समूह निर्माण, तीव्र हस्त-चालन तथा फुर्तीले पैरों की भूमिका होती है।

वर्ष में आयोजन का समय

- नववर्ष के स्वागत हेतु वर्ष के पहले दिन बोहाग बिहू
- धान की फसल पकने पर माघ बिहू
- बसंत उत्सव पर वैशाख बिहू
- यह नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है।

कोलाट्टम या कोलानाथु (आंध्र प्रदेश)

- इसे डंडा नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य त्यौहारों के अवसरों पर ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। यह 8 से 40 नर्तकों के दल द्वारा आयोजित किया जाता है।

कर्मा मुंडा (झारखंड)

- यह मुंडा जनजातियों द्वारा किया जाता है। कर्मा नामक वृक्ष के नाम पर इसका नामकरण किया गया, जिसे मुंडा सौभाग्य का सूचक मानते हैं।
- यह स्त्री एवं पुरुषों द्वारा वृत्त बनाकर किया जाता है। इसमें ढोल के थाप के साथ-साथ नृत्य की गति में वृद्धि होती जाती है।

पंथी (छत्तीसगढ़)

- ☞ यह अनुष्ठानिक नृत्य है।
- ☞ इसमें गायन में सतगुरु की प्रशस्ति की जाती है। यह नृत्य सतनामी समुदाय का नृत्य है।
- ☞ पुरुष समूह ढोल व झाँझ की लय के साथ गाता है, धीरे-धीरे लय तेज होती जाती है, फिर नर्तक पद संचालन के साथ विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं।

पांडवानी (छत्तीसगढ़)

- ☞ यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख नृत्य है। पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इसे पांडवानी कहा जाता है।
- ☞ नर्तक वाद्ययंत्रों की धुन पर नृत्य एवं अभिनय कर पांडवों की कथा का प्रदर्शन करते हैं।
- ☞ इस नृत्य में इकतारा (एकतारा) वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है।

तरगमल (गोवा)

- ☞ यह दशहरा और होली के अवसर का ओजस्वी नृत्य है।
- ☞ इसमें रम्मत, ढोल एवं ताशे के थाप के साथ रंग-बिरंगे पोशाकों में नर्तकों की टोलियां ध्वज लिए हुए गलियों में घूमते हैं।

गरबा (गुजरात)

- ☞ यह गुजरात का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इसका आयोजन नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है।
- ☞ इस नृत्य में स्त्री बीच में खड़ी होती है उसके सिर पर मिट्टी का छिद्रयुक्त घड़ा रखा जाता है जिसके अंदर दीपक जलता रहता है।
- ☞ शेष स्त्रियां वृत्त बनाकर नृत्य करती रहती हैं। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य दुर्गा देवी की आराधना करना होता है।

डांडिया (गुजरात)

- ☞ इस नृत्य में हाथ में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य किया जाता है।
- ☞ इसीलिए इसे डांडिया कहा जाता है।
- ☞ पुरुष और स्त्रियां घेरे बनाकर हाथ में रंगबिरंगी डांडिया लेकर नृत्य करते हैं।
- ☞ यह मुख्यतः नवरात्र के अवसर पर आयोजित होता है।

थय्यम नृत्य (केरल)

- ☞ इस नृत्य के द्वारा पूर्वजों, ऐतिहासिक विभूतियों, तेजस्वी एवं धार्मिक चरित्रों को याद किया जाता है।
- ☞ इसके लगभग 150 स्वरूप हैं और प्रत्येक थय्यम नृत्य की अलग श्रृंगार सामग्री होती है।

पादयानी (केरल)

- ☞ यह नृत्य ग्रामीण क्षेत्रों में देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। इसमें कलाकार विभिन्न मुखौटे लगाकर देवी-देवताओं के स्वांग करते हैं।
- ☞ इस नृत्य का कार्यक्रम पूरी रात चलता है। इसमें संगीत एवं गायन का भरपूर प्रयोग किया जाता है।

मुडिपेट्ट (केरल)

- ☞ यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य-नाट्य है जिसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया है।
- ☞ इसमें देवी काली तथा राक्षस दारिका के बीच में युद्ध होता है।

किन्नूर नटी (हिमाचल प्रदेश)

- ☞ यह हिमाचल के पहाड़ी भागों में प्रचलित नृत्य है। 'लोसर शोना चुकसम' इनमें सबसे लोकप्रिय नृत्य है।
- ☞ लोसर 'लोसाई' शब्द से बना है जिसका अर्थ है— नववर्ष। इसकी नृत्य मुद्राएं फसल बोने और काटने को व्यक्त करती हैं।

छाम छाँक (हिमाचल प्रदेश)

- ☞ यह लाहौल-स्पीति क्षेत्र में लामाओं द्वारा किया जाने वाला आनुष्ठानिक नृत्य है।
- ☞ यह भगवान बुद्ध को समर्पित 'चाखर उत्सव' के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। चाखर उत्सव तीन वर्षों में एक बार मनाया जाता है।
- ☞ इसमें नर्तकों द्वारा एक विशेष प्रकार की टोपी पहनी जाती है जो छाँक कहलाती है।

नटी (हिमाचल प्रदेश)

- ☞ यह हिमाचल प्रदेश का आनुष्ठानिक फसल कटाई नृत्य है। यह स्त्री एवं पुरुष दोनों करते हैं।
- ☞ इसमें आस-पास गांवों से पूज्य देवी-देवताओं को रंग-बिरंगे जुलूस में उत्सव स्थल तक लाया जाता है।

बेलाट बोमलाट (कर्नाटक)

- ☞ यह यक्षगान का ही प्रकार है। महाकाव्य एवं पुराणों की कथाएं इसका विषय हैं।
- ☞ फसलों के मौसम के समाप्त होने के बाद इसका आयोजन किया जाता है।

चेरोकान (मिजोरम)

- ☞ इसे बांस व चेरों नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में चार लोगों का समूह दो जोड़ा बांस लेकर लहरदार तरीके से घूमते हुए नृत्य करता है।
- ☞ इस नृत्य को विदेशी मूल का माना जाता है। फिलीपींस में इससे मिलता-जुलता नृत्य प्रचलित है।

घुमुरा/घुमरा नृत्य (आंडिसा)

- यह नृत्य कालाहांडी क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह राजदरबारों में किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। इसमें सामाजिक संदेश दिया जाता है।

गोतिपुआ (ओडिसा)

- यह पुरी के अखाड़ा के छात्रों के द्वारा किया जाने वाले अखाड़ा नृत्य है। 'गोति' का अर्थ है एक और 'पुआ' का अर्थ लड़का होता है। यह स्त्रियों की पोशाक पहने पुरुषों द्वारा किया जाता है।

लांगी नृत्य (मध्य प्रदेश)

- यह नृत्य मध्यप्रदेश के बंजारों द्वारा राखी की पूर्णिमा को किया जाता है। यह नृत्य काली माता की उपासना हेतु किया जाता है।

जावरा (मध्य प्रदेश)

- यह बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। यह नृत्य कृषि से संबंधित है। इसमें फसल अच्छी होने पर उत्साह एवं प्रसन्नता व्यक्त की जाती है।
- स्त्रियां सिर पर ज्वार से भरी टोकरियां रखकर नृत्य करती हैं। इसमें पुरुषों की भागीदारी भी होती है।

रउफ (जम्मू-कश्मीर)

- यह जम्मू कश्मीर का फसल कटाई के पश्चात् स्त्रियों द्वारा आयोजित किया जाने वाला नृत्य है।
- इस नृत्य में ग्रामीण स्त्रियां दो पंक्तियों में विभाजित हो आमने-सामने खड़ी हो जाती हैं।
- प्रत्येक पंक्ति में लगभग पंद्रह लड़कियां होती हैं, जो एक-दूसरे के गले में बांधे डालकर नृत्य करती हैं।
- इसमें एक व्यक्ति झंडा लेकर नृत्य दल का नेतृत्व करता है।

हिक्कात (कश्मीर)

- इसमें युवा लड़के-लड़कियाँ आपस में जोड़ा बनाकर नृत्य करते हैं।
- इसमें नर्तक जोड़ा एक-दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए एक पैर आपस में जोड़ता है और शरीर को थोड़ा पीछे झुकाकर नृत्य करता है।
- नर्तक एक-दूसरे का चेहरा देखते हुए गोल घूमते हैं। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है।

गौफ नृत्य (महाराष्ट्र)

- यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय एवं कलात्मक लोक नृत्य है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है।
- इस नृत्य में हाथों तथा पैरों का संचालन ही मुख्य होता है।

लावणी (महाराष्ट्र)

- यह गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों का विशेष प्रकार का लोक नृत्य है जो गांवों में तमाशा के अंग होते हैं।
- गुजरात में डांडिया तथा उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में इसका प्रयोग रास में किया जाता है।

गौरीचा (महाराष्ट्र)

- यह किसानों का धार्मिक लोकनृत्य है। इस नृत्य में गौरी के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है।
- नृत्य मंडलियां घर-घर घूमकर इस नृत्य को करती हैं।

थांगटा नृत्य (मणिपुर)

- यह एक आनुष्ठानिक नृत्य है, जो मणिपुर के मनोर प्रांत के साहसी निवासियों द्वारा तलवार एवं भाले के साथ किया जाता है।

रासलीला (मणिपुर)

- मणिपुर में रासलीला की एक विशिष्ट शैली प्रचलित है। इसमें नर्तक को नृत्य एवं संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है।
- इसमें ब्रज की रास परंपरा का अनुगमन किया जाता है।

भांगड़ा (पंजाब)

- यह फसल कटाई और शुभ अवसरों के समय किया जाने वाला नृत्य है। यह लोकनृत्य वीर रस प्रधान होता है।
- इसमें पंजाबी गीतों की धुन पर एक घेरे में लुंगी और पगड़ी पहनते हैं।
- प्रारंभ में इसकी लय धीमी होती है परंतु धीरे-धीरे बहुत तेज हो जाती है।
- इस नृत्य में ढोल, नगाड़े और करतालों आदि का प्रयोग संगीत के लिए किया जाता है।

गिद्दा (पंजाब)

- यह नृत्य सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।
- इस लोकनृत्य का आयोजन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है।

सिंधी छाम/मुखौटा नृत्य (सिक्किम)

- यह नृत्य हिम शेर का मुखौटा लगाकर किया जाता है।
- हिम शेर सिक्किम राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक एवं राज्य की जनता का अभिभावक देवता माना जाता है।

कालबेलिया (राजस्थान)

- यह राजस्थान के सपेरा समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
- यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुलाबो बाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार है।

कच्छी घोड़ी नृत्यनाट्य (राजस्थान)

- ☞ इस नृत्यनाट्य की प्रायः दो शैलियां प्रचलित हैं।
- ☞ प्रथम युद्ध प्रदर्शन की और दूसरी प्रश्नोत्तर की।
- ☞ प्रश्नोत्तर प्रकार का नृत्य राजस्थान में मुख्यतः विवाहोत्सवों पर देखने को मिलता है।
- ☞ इस नृत्य में एक स्त्री और एक पुरुष अश्वारोही होते हैं।

घूमर (राजस्थान)

- ☞ यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनृत्य है।
- ☞ इस नृत्य का आयोजन मांगलिक अवसरों तथा पारंपरिक उत्सवों के अवसर पर होता है।
- ☞ यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। इसे घूम-घूमकर किया जाता है।

कुम्मी (तमिलनाडु)

- ☞ इस नृत्य में स्त्रियां ताली और डंडा बजाते हुए वृत्त बनाकर नृत्य करती हैं।

कमांडी (तमिलनाडु)

- ☞ भगवान शिव द्वारा कामदेव दहन एवं कामदेव की पत्नी रति

के विलाप के पौराणिक कथा को इस नृत्य नाटिका में प्रदर्शित किया जाता है।

छाऊ नृत्य (पश्चिम बंगाल)

- ☞ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, झारखंड के सरइकेला एवं उड़ीसा के मयूरभंज में छाऊ नृत्य लोकप्रिय है।
- ☞ इस नृत्य का आयोजन चैत्र पर्व पर किया जाता है।
- ☞ इस नृत्य का आयोजन आदिवासी खेतिहर समुदाय खुशहाली के लिए एवं शिकार के समय देवी-देवताओं की स्तुति में भी किया जाता है।
- ☞ इस शैली में 16 प्रकार के श्रृंगार का प्रदर्शन किया जाता है।

जाट-जटिन (बिहार)

- ☞ यह नृत्य बिहार के उत्तरी भागों और विशेषतः मिथिलांचल में प्रसिद्ध है।
- ☞ इस नृत्य में एक विवाहित दंपति के बीच के प्रेम और मीठी नॉक-झोंक को अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।



साक्षात्कार



नाम : विजय सिंह गुर्जर

रैंक : AIR-574 (2017)

विजय सिंह गुर्जर को जमीन से आसमान तक का सफर उनके संघर्षों की कहानी कहता है और सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 574वां स्थान प्राप्त करना किसी

उपलब्धि से कम नहीं। 2010 में दिल्ली पुलिस में सिपाही पद से कैरियर की शुरुआत कर विजय का अगला कदम दिल्ली पुलिस में ही उप-निरीक्षक पद पर चयन रहा। फिर अगले वर्ष 2011 में SSC CGL में सफलता के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में निरीक्षक और अगली सफलता SSC CGL, 2012 के द्वारा आयकर विभाग में निरीक्षक बना दिया। अपने लक्ष्य की खोज में विजय राज्य सेवा परीक्षा में भी भाग लेते रहे और RAS 2013 (रैंक 556) में चयन के साथ सामान्य सुरक्षा अधिकारी (राजस्थान) पद प्राप्त कर सके। फिर RAS 2016 में भी सफल रहे और 456वां रैंक मिला। यह और कुछ नहीं एक जुझारू व्यक्तित्व दर्शाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना मेहनत और धैर्य के साथ विजय ने आगामी उम्मीदवारों के लिए एक मिसाल कायम की है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : सिविल सेवा तैयरी के दौरान क्या कठिनाइयां आती हैं?

विजय सिंह गुर्जर : मेरा मानना है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए चुनौतियां और कठिनाइयां भी भिन्न-भिन्न होती हैं। यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि कॉर्पोरेट क्षेत्र में पिछले छः वर्षों से कार्य कर रहा था।

निर्माण सिविल सर्विसेज : सिविल सेवाओं की ओर आप कैसे आकर्षित हुए?

विजय सिंह गुर्जर : मेरा मानना है कि, सिविल सेवा एक प्रमुख सेवा है और सरकारी मशीनरी का हिस्सा बन कर आप जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं। यह अन्य नौकरियों से थोड़ा भिन्न है। यद्यपि कोई व्यक्ति अन्य नौकरियों के माध्यम से भी राष्ट्र की सेवा

कर सकता है। लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डालने के संदर्भ में सिविल सेवा कुछ विभिन्न प्रकार की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मैं नहीं समझता कि कोई अन्य जॉब इस मामले में इसके समतुल्य है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : उम्मीदवारों के बीच एक आम धारणा यह है कि यह परीक्षा निष्कासन या एलिमिनेशन प्रक्रिया पर आधारित है न कि चयन प्रक्रिया पर, क्या आप इस प्रकार की अवधारणाओं से सहमत हैं? इस परीक्षा में सफल होने के बाद इस संदर्भ में आप क्या समझते हैं?

विजय सिंह गुर्जर : मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। इस परीक्षा में लगभग 5 से 8 लाख उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें लगभग 15,000 मुख्य परीक्षा के लिए सफल हो पाते हैं। मेरा मानना है कि, असल प्रतियोगिता 50,000 से 1 लाख उम्मीदवारों के मध्य होती है, जो गंभीर उम्मीदवार होते हैं। अतः गंभीर उम्मीदवारों के लिए मैं यह नहीं कह सकता कि यह परीक्षा एक निष्कासन या एलिमिनेशन प्रक्रिया है। यह उम्मीदवारों में कुछ निश्चित योग्यताओं एवं व्यक्तित्व संबंधी विशिष्टताओं की मांग करता है। यदि आपके अंदर ये विशिष्टताएं और योग्यताएं हैं, तो आप एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं।

निर्माण सिविल सर्विसेज : आपने इस परीक्षा को सफलता में कैसे परिवर्तित किया? आपने क्या विशिष्ट रणनीति अपनाई? इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप किन रणनीतियों की सिफारिश करना चाहेंगे?

विजय सिंह गुर्जर : निरंतरता तथा तैयारी के संदर्भ में दृष्टिकोण की स्पष्टता महत्वपूर्ण चीजें हैं। परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है यह एक अन्य बात है। जब कभी आप यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि अंतिम उद्देश्य क्या है, जिसे आप हासिल करना चाह रहे हैं। निरंतर यूपीएससी के पाठ्यक्रम देखते रहने और पूछे जा रहे प्रश्नों पर नजर रखने, उन्हें हल करते रहने से कोई भी इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकता है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : आपका प्रेरणा स्रोत क्या था? अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे?

विजय सिंह गुर्जर : मैं अपनी सफलता में माता-पिता को श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सक्षम बनाया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकूँ। उनके द्वारा प्रदान किये गये अवसर और समर्थन के लिए मैं उनका आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं सर्वशक्तिमान

ईश्वर, अध्यापकों, मित्रों तथा अपने कठिन परिश्रमों को भी अपनी सफलता में श्रेय देना चाहूँगा।

निर्माण सिविल सर्विसेज : प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए लंबे सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या आपने एकीकृत किया था? या आपने दोनों की अलग-अलग तैयारी की थी?

विजय सिंह गुर्जर : पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा वास्तव में मुख्य परीक्षा में जो कुछ भी पूछा जाता है, उसका सबसेट या उप समुच्चय है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ प्रश्न केवल मुख्य परीक्षा में ही पूछा जाता है, जैसे विश्व इतिहास एवं इथिक्स। लेकिन संपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम दोनों पक्षों को कवर करता है। अतः प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एकीकृत तैयारी रणनीति की आवश्यकता होती है।

व्यक्तित्व विशेषताएँ

पसंदीदा व्यक्तित्व : एपीजे अब्दुल कलाम

सबल पक्ष : मैं हार नहीं मानता

दुर्बल पक्ष : आलसी हूँ

रुचियाँ : बाइक चलाना, बैड-मिंटन खेलना, तथा गाने सुनना आदि।

निर्माण सिविल सर्विसेज : क्या आपने इथिक्स प्रश्न-पत्र के लिए कोई विशिष्ट रणनीति अपनाई थी? इस प्रश्न-पत्र के केस अध्ययन खंड की तैयारी आपने कैसे की?

विजय सिंह गुर्जर : इथिक्स प्रश्न-पत्र सबसे सरल भी और कठिन भी है। अतः इस प्रश्न-पत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको जहाँ तक हो सके अपने उत्तरों को बेसिक ही रखना चाहिए। इथिक्स प्रश्न-पत्र में सामाजिक मामलों के बारे में आपकी राय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्व वर्षों के इथिक्स प्रश्न-पत्रों की अध्यापकों और सहपाठियों के साथ चर्चा इस प्रश्न-पत्र की संपूर्ण तैयारी में अत्यंत सहायक है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : भारी भरकम और लंबे पाठ्यक्रम को देखते हुए आपने प्रासंगिक सामग्री का चुनाव कैसे किया?

विजय सिंह गुर्जर : पिछले पाँच वर्षों के प्रश्नों का प्रिंट आउट लेकर मैंने प्रचलित रुझानों पर फोकस किया। इस प्रक्रिया के माध्यम से पुस्तकों एवं सामग्री का चुनाव करना इतना मुश्किल नहीं है, साथ ही टॉपर्स की बताई गई रणनीतियों में कॉमन बिन्दुओं की पहचान के जरिए भी पाठ्य सामग्री का चुनाव किया जा सकता है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : तैयारी के दौरान वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्रों के बीच आपने समय विभाजन या प्रबंधन कैसे किया?

विजय सिंह गुर्जर : तैयारी के दौरान समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैंने लगभग 50 प्रतिशत समय वैकल्पिक विषय को समर्पित किया तथा बाकी समय सामान्य अध्ययन के लिए। मैंने 8 से 10 घंटे प्रतिदिन अध्ययन के लिए समय सारणी बनाई, क्योंकि इससे अधिक समय तक एकाग्रता नहीं बनाई जा सकती है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : आपने प्रतिदिन कितने घंटे अध्ययन किया? आपकी राय में एक औसत उम्मीदवार को इस परीक्षा की तैयारी के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है?

विजय सिंह गुर्जर : ईमानदारी से, छः घंटे प्रतिदिन अध्ययन पर्याप्त होता है, लेकिन वास्तव में समर्पित प्रयास होना चाहिए। कितने घंटे आप पढ़ते हैं इससे कोई मतलब नहीं, जो कुछ जितने भी समय में अध्ययन किया जाता है उसकी गुणवत्ता/उत्पादकता/प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। स्वयं पर विश्वास और एक अच्छी रणनीति इस परीक्षा में आपको सफलता दिला सकती है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : आपकी लेखन-शैली क्या थी? क्या यह पैराग्राफ के रूप में थी या बिन्दुवार रूप में?

विजय सिंह गुर्जर : उत्तर का प्रस्तुतिकरण ही अंततः सर्वप्रमुख भाग है। मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन के लिए हमें यथोचित ढाँचे की आवश्यकता होती है, ताकि उत्तर व्यवस्थित तथा पूछे गये प्रश्न की मांग के अनुसार हो। उत्तर 2 से 3 लाइनों की भूमिका के साथ शुरू होना चाहिये। उत्तर के मुख्य भाग में सभी उप-बिन्दुओं का समावेश करना चाहिये। उप-शीर्षक, बुलेट पॉइंट में देना चाहिये, साथ ही निष्कर्ष विश्लेषणात्मक शैली में समाप्त करना अधिक बेहतर होता है। उत्तर के अंतर्गत निम्नांकित घटकों का ध्यान रखना आवश्यक है -

- उत्तर बहु आयामी होना चाहिए।
- उत्तर में 'मुख्य शब्दों' (की-वर्ड्स) को रेखांकित करना चाहिए।
- उत्तर में आशावादी तत्व होना चाहिए।

निर्माण सिविल सर्विसेज : उत्तर लेखन के दौरान 200 शब्द सीमा को आपने कैसे मैनेज किया?

विजय सिंह गुर्जर : उत्तर लेखन का निरंतर अभ्यास आपको वास्तविक परीक्षा के लिए बेहतर तैयार कर सकता है। इसके अतिरिक्त निरंतर रणनीति को अद्यतन करने की भी जरूरत होती है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपके अनुसार ये टेस्ट सीरीज कितने सहायक और प्रासंगिक हैं?

विजय सिंह गुर्जर : टेस्ट सीरीज परीक्षा में आने वाले संभावित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रश्नों के प्रति छात्रों को सजग बना सकती है। टेस्ट सीरीज एक मॉडल प्रश्न-प्रदान करते हैं, जससे आप परीक्षा में अपने उत्तरों को सहजता से लिख सकें। यह वास्तव में मुख्य परीक्षा से पूर्व स्वयं के आकलन का अच्छा माध्यम है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : पूर्व वर्षों के प्रश्न-पत्रों के अभ्यास के संदर्भ में आपकी क्या राय है?

विजय सिंह गुर्जर : पूर्व वर्षों के प्रश्न-पत्र विभिन्न दृष्टिकोणों से काफी सहायक हो सकते हैं। यह आपको विशिष्ट रुझानों के विश्लेषण में सहायता करता है तथा इसके माध्यम से आप यूपीएससी की वास्तविक मंशा या डिमांड को जान सकते हैं।

निर्माण सिविल सर्विसेज : तैयारी की संपूर्ण अवधि के दौरान आपने उत्साह और एकाग्रता को कैसे प्रबंधित किया? सामान्य दिनचर्या के एकाग्रता भंग करने वाले कारकों को आपने कैसे नजर अंदाज किया?

विजय सिंह गुर्जर : खुद का उत्साह बनाये रखने के लिए, आपके सामने सदैव लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए स्वयं को कुछ विशेष प्रकार की हॉबी में संलग्न करना चाहिए, जैसे मैं दौड़ लगाना या ऑनलाइन शतरंज खेलना पसंद करता था। इसके अतिरिक्त कुछ घनिष्ठ मित्रों से बातें करना तथा माता-पिता आपके उत्साहवर्द्धन में सहायक हो सकते हैं।

निर्माण सिविल सर्विसेज : आपके अनुसार इंटरनेट एवं ऑनलाइन अध्ययन सामग्री कितनी उपयोगी है? आप किन वेबसाइटों की सिफारिश करना चाहेंगे?

विजय सिंह गुर्जर : यथोचित रणनीति अपनाकर विशेष रूप से टॉपर्स द्वारा सुझाई गई रणनीतियां आपका मार्गदर्शन कर सकती है। किन अध्ययन सामग्री का चुनाव करें? और क्या पढ़ें? जैसे प्रश्नों का उत्तर टॉपर्स द्वारा अच्छे से समझाया जाता है। मैंने सोशल मीडिया को तैयारी के दौरान जानबूझ कर नजर अंदाज किया, क्योंकि सोशल मीडिया साइटें एकाग्रता भंग करती है। मैं सरकारी वेबसाइटों का नियमित विजिटर रहा हूँ, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो

(PIB) एवं विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइटें यूपीएससी की तैयारी में अत्यंत उपयोगी होती है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : साक्षात्कार की तैयारी कैसे महत्वपूर्ण है और आपने इसकी तैयारी कैसे की?

विजय सिंह गुर्जर : साक्षात्कार सिविल सेवा की तैयारी का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण है। यह आपको सफलता दिला सकता है या आपकी सफलता के प्रयासों को कम कर सकता है। साक्षात्कार की तैयारी के संबंध में निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय हैं-

- आपको अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फार्म (DAF) के संबंध में सहज होना चाहिए।
- स्वयं को अद्यतन बनाये रखें (समसामयिकी घटनाओं के संदर्भ में)।
- शांत, ईमानदार और आशावादी होने के साथ चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए।

निर्माण सिविल सर्विसेज : विभिन्न सर्वग्राही और व्यापक पत्रिकाओं और पुस्तकों के संदर्भ में आपकी क्या राय है? विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा हेतु निर्माण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका और पुस्तकों के विषय में।

विजय सिंह गुर्जर : यूपीएससी की तैयारी रणनीति के लिए पूर्व वर्षों के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे काफी सहायता मिलती है। समसामयिकी पर निर्माण प्रकाशन की पत्रिकाओं ने मेरी तैयारी के दौरान उत्साह बनाये रखने में सहायक हुई है।

निर्माण सिविल सर्विसेज : भविष्य में सिविल सेवा ऐस्पिरेंट्स को आपकी क्या सलाह है? इस परीक्षा की थकाऊ और लंबी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार किस प्रकार स्वयं के उत्साह को बनाये रखें?

विजय सिंह गुर्जर : आपको अपनी तैयारी के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, वो भी स्पष्ट उत्साहवर्द्धक लक्ष्यों के साथ। अपने दृष्टिकोण एवं दैनिक अध्ययन में आपको अनुशासित होना चाहिए। आपका अध्ययन अत्यधिक चयनात्मक होना जरूरी है, साथ ही अत्यधिक लेखन अभ्यास इस परीक्षा को पास करने की पूर्व शर्त है।

□□□

प्रारम्भिक परीक्षा विशेष : 2019

हरियाणा के मनेथी में नये एम्स की स्थापना

संदर्भ :

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है:
 1. हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मनेथी में 1299 करोड़ रुपये की लागत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना तथा
 2. 2,25,000 रुपये (निर्धारित) बेसिक वेतनमान+एनपीए (लेकिन वेतन + एनपीए 2,37,500 रुपये से अधिक नहीं) में निदेशक के एक पद का सृजन।

प्रमुख विशेषताएं :

- नये एम्स में 100 स्नातक (MBBS) सीटें तथा 60 बीएससी (नर्सिंग) सीटें जोड़ी जाएंगी।
- नये एम्स में 15-20 सुपर स्पेशियलिटी विभाग होंगे।
- नये एम्स में लगभग 750 बिस्तरों का अस्पताल होगा।
- वर्तमान कार्यरत एम्स के डाटा के अनुसार प्रत्येक नये एम्स प्रतिदिन 1500 वाह्य रोगी विभाग (OPD) के रोगियों की चिकित्सा होगी तथा प्रति महीने अस्पताल में दाखिल लगभग 1000 रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी।

विवरण :

- नये एम्स की स्थापना में एम्स नई दिल्ली तथा PMSSY चरण-1 के अंतर्गत शुरू किए गए 6 नये एम्स की तर्ज पर अस्पताल, मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण ब्लॉक, आवासीय परिसर निर्माण तथा संबंधित सुविधाएं/सेवाएं शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र में ऊपरी तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में नया एम्स स्थापित करना है।
- प्रस्तावित संस्थान में 750 बिस्तरों का एक अस्पताल होगा, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा/अभिघात बिस्तर, आयुष बिस्तर, निजी बिस्तर तथा आईसीयू स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी बिस्तर शामिल होंगे।
- इसके अतिरिक्त, एक मेडिकल कॉलेज, आयुष ब्लॉक, ऑडोटीरियम, नाईट शल्टर, अतिथि गृह, छात्रावास तथा

आवासीय सुविधाएं होंगी। नये एम्स की स्थापना से पूंजी संपत्ति का सृजन होगा।

- इसके लिए रखरखाव तथा देखभाल के लिए 6 नये एम्स की तर्ज पर विशेषज्ञ मानव शक्ति का सृजन किया जाएगा।
- इन संस्थानों पर होने वाले खर्च स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की PMSSY योजना के बजट मद से दी जाने वाली अनुदान सहायता से पूरे किए जाएंगे।

लाभ :

- नये एम्स की स्थापना से ना केवल स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में परिवर्तन होगा बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी की समस्या भी हल होगी।
- नये एम्स की स्थापना से दोहरा उद्देश्य पूरा होगा।
- आबादी को जहां सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। वहीं डाक्टरों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का बड़ा पूल तैयार होगा, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत तैयार की जा रही प्राथमिक और द्वितीय स्तर के संस्थानों/सुविधाओं में उपलब्ध कराया जा सकता है।
- नये एम्स का संचालन और रखरखाव खर्च पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

रोजगार सृजन :

- नये एम्स की स्थापना से प्रत्येक एम्स में विभिन्न फैकल्टी तथा गैर-फैकल्टी पदों पर लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त नये एम्स के आसपास के क्षेत्रों में शॉपिंग सेंटर, कैटीन आदि जैसी सुविधाओं और सेवाओं के कारण अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा।
- नये एम्स के लिए आधारभूत संरचना सृजन से भी निर्माण के चरणों में अच्छी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

पृष्ठभूमि

- केंद्र की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में ऊपरी तृतीय स्तर की किफायती स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में असंतुलन दूर करना है और सुविधा से वंचित राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है। वित्त मंत्री ने 2019-20 के अपने अंतरिम बजट भाषण में है।

भारत निर्माण प्रौद्योगिकी-2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे

- माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एक ग्लोबल आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (GHTC-India) की अवधारणा तैयार की है, जिसका उद्देश्य ऐसी अभिनव प्रौद्योगिकियां विकसित करना है जो टिकाऊ हो और आपदा का मुकाबला कर सके।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक एक करोड़ आवासीय इकाईयां बनाना है, जिसमें से 79 लाख मकानों को मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
- इसके अलावा 41 लाख से अधिक मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है और 16 लाख मकानों को पूरा करके लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। इस समय 12 लाख से अधिक मकान नई प्रौद्योगिकियों के साथ बनाए जा रहे हैं।
- प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है जो 2-3 मार्च, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ। इसमें दुनिया भर में मान्य प्रौद्योगिकियों पर भारतीय संदर्भ में विचार किया गया।
- इस दो दिवसीय आयोजन में प्रौद्योगिकी प्रदाता, अनुसंधानकर्ता, स्टार्टअप, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां और अन्य विशेषज्ञ भाग लिए।

कर्टन रेजर : अल नागाह 2019

- भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यासों की शृंखला में तीसरा अल नागाह III अभ्यास 12 से 15 मार्च 2019 तक ओमान की जबल अल अखदर पहाड़ियों में किया गया।
- इस सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं अर्द्ध शहरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में पारस्परिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ युद्धकौशल, हथियारों के संचालन और गोलाबारी में विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगी।
- भारत-ओमान के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंध 2006 में भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग की बैठकों के बाद से निरंतर विकसित हो रहे हैं।
- अभ्यास अल नागाह III से पहले दो संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया जा चुका है। जिनका आयोजन क्रमशः ओमान में जनवरी 2015 तथा भारत में मार्च 2017 में किया गया था।
- इस प्रकार, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के दोनों महत्वपूर्ण देशों के बीच बढ़ती सैन्य तथा सामरिक साझेदारी पर बल देते हुए इसी तरह के अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं और वायु सेनाओं के बीच भी प्रचलन में हैं।

- भारतीय सेना के दस्ते का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की 10वीं बटालियन के 4 अधिकारियों, 9 जूनियर कमिश्नड अधिकारियों और 47 अन्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा।
- रॉयल आर्मी ऑफ ओमान (RAO) की जबल रेजीमेंट की ओर से भी इतने ही सैन्य कर्मी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
- पर्यवेक्षक शिष्टमंडल में दोनों देशों की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो 25 मार्च, 2019 को इस अभ्यास के समापन के गवाह बनेंगे।
- यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच उनकी क्षमताओं की समझ को बढ़ाने तथा मैत्री को मजबूती प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों के लिए “युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम” (युविका) नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है।
- इसरो ने इस कार्यक्रम को ‘उन्हें कम उम्र में ही ज्ञान प्रदान करने’ के लिए चुना है।
- आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग दो सप्ताह की अवधि का होगा और प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से 3 छात्रों का चयन करना प्रस्तावित है, जो CBSE, ICSE और राज्य पाठ्यक्रम को कवर करते हैं।
- जो छात्र 8 वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9 वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।
- चयनित छात्रों को इसरो के अतिथिगृह/ हॉस्टल में ठहराया जाएगा।
- पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्र द्वारा यात्रा (निकटतम रेलवे स्टेशन से रिपोर्ट करने वाले केंद्र तक आने एवं जाने हेतु रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी का किराया), पाठ्य सामग्री, रहने एवं खाने, इत्यादि में किए गए व्यय का वहन इसरो द्वारा किया जाएगा।
- छात्र को रिपोर्टिंग केंद्र तक लाने एवं ले जाने हेतु एक अभिभावक/माता-पिता को भी रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी का किराया प्रदान किया जाएगा।
- इसरो ने त्रिपुरा में इनक्यूबेशन केंद्र विकसित किया है। ऐसे ही चार और केंद्रों को त्रिची, नागपुर, राउरकेला और इंदौर में विकसित किये जायेंगे।

- ❖ इसरो ने भारत में राज्यों के संबंधित मुख्य सचिव/ केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित प्रशासनिकों से प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से तीन छात्रों के चयन हेतु व्यवस्था करने और उनकी सूची इसरो को प्रदान करने हेतु संपर्क किया है।
- ❖ चयन की प्रक्रिया शैक्षणिक प्रदर्शन एवं पाठ्यक्रम गतिविधियों पर आधारित होगी, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों/ केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासनिकों को पहले से परिचालित चयन मानदंडों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। चयन प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को विशेष महत्व दिया जाएगा।

विश्वभर में 2017 से 2018 के बीच खसरे के मामले 48.4% बढ़े: यूनिसेफ रिपोर्ट

- ❖ यूनिसेफ के मुताबिक, दुनियाभर में 2017-2018 के बीच खसरे के मामले 48.4% बढ़े और 2018 में खसरे के कुल मामलों में से तकरीबन तीन-चौथाई फ्रांस, ब्राजील व फिलीपीन्स समेत 10 देशों में सामने आए।
- ❖ यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2017-18 में खसरे का सबसे ज्यादा संक्रमण यूक्रेन, फिलीपींस और ब्राजील में बढ़ा है। यूनिसेफ कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने कहा की खसरे के वैश्विक मामले खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं।
- ❖ यह संक्रमण 10 देशों में ज्यादा बढ़ा है, जो कुल संक्रमण का 74% से ज्यादा है। इनमें कई ऐसे देश भी हैं, जो पहले खसरा मुक्त घोषित हो चुके हैं। अकेले यूक्रेन में खसरे के 30,338 नए मामले सामने आए, जो पिछले वर्ष से 30,000 अधिक है।
- ❖ वर्ष 2019 के पहले दो महीनों में 24,042 लोग खसरे से संक्रमित हुए हैं। फिलीपींस में खसरे से संक्रमित 12,736 नए मामले सामने आए और 203 लोगों की मौत हुई है। यूनिसेफ ने कहा कि हमें अभी से खसरे के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए संभल जाना होगा।

खसरा क्या है?

- ❖ खसरा श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोर्बिलीवायरस के जीन्स पैरामिक्सोवायरस के संक्रमण से होता है। मोर्बिलीवायरस भी अन्य पैरामिक्सोवायरसों की तरह ही एकल असहाय, नकारात्मक भावना वाले RNA वायरसों द्वारा घिरे होते हैं।
- ❖ इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, बहती हुई नाक, लाल आंखें और एक सामान्यीकृत मेकुलोपापुलर एरीथेमाटस चकत्ते भी शामिल है।
- ❖ खसरा श्वसन के माध्यम से फैलता है। 90% लोग जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और जो संक्रमित व्यक्ति के साथ एक ही घर में रहते हैं, वे इसके शिकार हो सकते हैं।
- ❖ यह संक्रमण औसतन 14 दिनों (6-19 दिनों तक) तक

प्रभावी रहता है। अंग्रेजी बोलने वाले देशों में खसरा का एक वैकल्पिक नाम रुबेओला है, जिसे अक्सर रुबेला (जर्मन खसरा) के साथ जोड़ा जाता है; हालांकि दोनों रोगों में कोई संबंध नहीं है।

यूनिसेफ (UNICEF) के विषय में

- यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसम्बर 1946 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
- यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन फंड है जिसकी पूरी दुनिया में कई ब्रांच हैं।
- वर्ष 1953 तक यूनिसेफ का पूरा नाम United Nations International Children's Emergency Fund था। इसकी स्थापना पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए की गई थी।
- यूनिसेफ विश्वभर में मौजूद स्वास्थ्य सेवा संस्थानों खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, इंफेक्शंस से बचाने के कैंपेन चलाती है।
- यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था।

वन नेशन, वन कार्ड योजना

चर्चा में क्यों?

- ❖ प्रधानमंत्री ने स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) का शुभारंभ किया।
- ❖ लोगों को देशभर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए यह सेवा आरंभ की गई है।
- ❖ अलग-अलग परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले 'एक राष्ट्र एक कार्ड' से धारक अपनी बस का किराया, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, रिटेल खरीदारी कर सकेंगे और यहां तक कि पैसा भी निकाल सकेंगे।

वन नेशन, वन कार्ड की विशेषताएं

- इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो, बस, उप नगरीय रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा दुकानों में भी किया जा सकेगा।
- पीओएस मशीन पर स्वाइप करने के साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर मौजूद AFC गेट पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस नई पहल को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट 'स्वागत' ने डेवलप किया है जहां एक ओपन लूप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम 'स्वीकार' का इस्तेमाल किया गया है।

- यूजर्स इस दौरान इस कार्ड की मदद से एटीएम पर 5 प्रतिशत और दूसरे आउटलेट्स पर 10 प्रतिशत तक का कैश बैक पा सकते हैं।
- वन नेशन वन कार्ड बिल्कुल रुपये, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह ही है जिसे आपका बैंक ही जारी करता है।
- रुपए वन नेशन कार्ड रेगुलर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह कांटेक्टलेस कार्ड होता है जो ठीक मेट्रो रेल स्मार्ट कार्ड की तरह ही है।
- वन नेशन वन कार्ड को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से भी जारी किया जाएगा।
- सिंगापुर, लंदन, पेरिस, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न जैसे शहरों में इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2019

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश के सबसे स्वच्छ और साफ शहरों के नाम की घोषणा 6 मार्च को राष्ट्रपति भवन में किया गया।
- सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर इंदौर के नाम रहा जबकि सबसे स्वच्छ राजधानी वर्ग में भोपाल पहले स्थान पर रहा।
- छत्तीसगढ़ को स्वच्छता की दिशा में सबसे तेज व संयोजित तरीके से काम किए जाने को लेकर राज्य को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड दिया गया है।
- 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले स्थान पर रहे।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 पुरस्कारों के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने देश के अलग अलग राज्यों के 4,237 शहरों में सर्वे किया। इसके बाद अलग-अलग कैटेगरी में रैंकिंग जारी की गई है।

इंदौर को क्यों मिला पहला स्थान?

- देश का पहला ऐसा शहर है जहां लाखों लोगों की मौजूदगी में दो जीरो वेस्ट आयोजन हुए।
- देश का पहला डिस्पोजल फ्री मार्केट है जिसमें हाल ही में 56 दुकान क्षेत्र को शामिल किया है।
- देश का पहला ऐसा शहर जिसने ट्रेडिंग ग्राउंड को पूरी तरह खत्म कर वहां नए प्रयोग शुरू किए। 29 हजार से अधिक घरों में गीले कचरे से होम कम्पोस्टिंग का काम।

- कचरा गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस, कंट्रोल रूम और 19 जोन की अलग-अलग 19 स्क्रीन।
- 100 फीसदी कचरे की प्रोसेसिंग और बिल्डिंग मटेरियल और व्यर्थ निर्माण सामग्री को जमा कर निस्तारण किया गया।

शहरों को सात वर्गों में दिया गया पुरस्कार

- सबसे स्वच्छ शहर : इंदौर
- सबसे स्वच्छ राजधानी : भोपाल
- सबसे स्वच्छ बड़ा शहर : अहमदाबाद (10 लाख से ज्यादा आबादी वाला)
- सबसे स्वच्छ मध्यम आबादी वाला शहर : उज्जैन (3 -10 लाख की आबादी)
- सबसे स्वच्छ छोटा शहर : NDMC दिल्ली (3 लाख से कम आबादी)
- सबसे स्वच्छ कैटोनमेंट : दिल्ली कैट
- सबसे स्वच्छ गंगा टाउन : गौचर, उत्तराखंड

अंधकार में भविष्य की नींव

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में यूनेस्को ने विभिन्न देशों में 2017 में बिजली के अभाव में संचालित प्राथमिक स्कूलों की सूची जारी की है।
- सूची में छठे पायदान पर भारत है जहां 51 फीसदी प्राथमिक स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं।
- सूची में अंतिम पर सिएरा लियोन है, जहां महज चार फीसदी स्कूलों तक बिजली की पहुंची है।
- शीर्ष पायदान पर चीन है जहां 100 फीसदी यानी सभी प्राथमिक स्कूलों में बिजली पहुंच चुकी है।
- बिजली की पहुंच से दूर प्राथमिक स्कूलों का वैश्विक औसत 31 फीसदी है।
- प्राथमिक स्कूलों में पीने योग्य शुद्ध पानी की उपलब्धता का वैश्विक औसत 79 फीसदी है।
- सिर्फ पुरुष शौचालय वाले प्राथमिक स्कूलों का वैश्विक औसत तकरीबन 82 फीसदी है।
- 2016 में विश्व के अन्य देशों में 46 फीसदी से अधिक प्राथमिक स्कूल इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं।

सतत आर्थिक विकास लक्ष्य

- संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास का चौथा लक्ष्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी, इंटरनेट और बिजली की पहुंच बढ़ाने का है।

1700 जीव प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा

- मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए भूमि प्रयोग लगातार बढ़ाकर अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास छीन रहा है।
- इसके चलते 1700 जीव प्रजातियों पर आगामी 50 वर्षों में विलुप्त होने का खतरा मंडरा सकता है।
- नेचर क्लाइमेट चेंज नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात कही गई है कि मनुष्य द्वारा लगातार बढ़ रहे भूमि इस्तेमाल का खामियाजा अन्य जीवों को भुगतना पड़ सकता है।
- दरअसल, इसके कारण अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास कम हो रहा है और इनके विलुप्त होने का खतरा है।
- अध्ययन में यह पाया गया कि मनुष्यों द्वारा भूमि प्रयोग बढ़ाए जाने से 2070 तक इन प्रजातियों का करीब 30 से 50 प्रतिशत प्राकृतिक आवास छिन सकता है।

सऊदी अरब को 40% ज्यादा फ्लाईंग राइट्स

- भारत के कड़े फ्लाईंग राइट्स सिस्टम से सऊदी अरब को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। सरकार सऊदी अरब की एयरलाइंस की उड़ानों का कोटा 1 अप्रैल से 40 पैसे बढ़ा रही है।
- यह कदम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पिछले महीने के भारत दौरे के बाद उठाया गया है।
- इससे भारत से 5,000 किलोमीटर के दायरे में आने वाला सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसका फ्लाइट कोटा भारत सरकार ने बढ़ाया है।
- इससे पहले दुबई, कतर, चीन, सिंगापुर और मलेशिया की ओर से फ्लाईंग राइट्स बढ़ाने के निवेदनों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।
- क्राउन प्रिंस के दौरे के दौरान सऊदी अरब ने भारत में 100 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करने की घोषणा की थी।
- ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) की हाल की मीटिंग में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तवज्जो ना देते हुए भारत का समर्थन किया था।
- नियमों के अनुसार, दो देशों के बीच फ्लाइट्स के लिए एयर सर्विसेज एग्रीमेंट का पालन किया जाता है। इसे बाइलैटरल फ्लाईंग राइट्स भी कहा जाता है।
- भारत सरकार अतिरिक्त बाइलैटरल राइट्स की अनुमति देने में सतर्क रही है क्योंकि पिछली सरकारों के दौरान फ्लाईंग राइट्स को लेकर विवाद हुआ था और उसकी जांच भी हुई थी।
- नई एविएशन पॉलिसी के तहत, भारत से 5,000 किलोमीटर की दूरी के अंदर किसी देश को अतिरिक्त सीटों की तब तक अनुमति नहीं मिलेगी। जब तक भारतीय एयरलाइंस अपने फ्लाईंग राइट्स कोटा का 80 पैसे इस्तेमाल नहीं कर लेती।

- सऊदी अरब के मामले में भारतीय एयरलाइंस की ओर से कोटा का इस्तेमाल अभी भी लगभग 74 पैसे है। हालांकि, एविएशन मिनिस्ट्री को अप्रैल तक इसके 80 पैसे को पार करने की उम्मीद है।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार सऊदी अरब एयर इंडिया को अपने वायुक्षेत्र का इस्तेमाल कर इजरायल की उड़ान की अनुमति देता है। केवल एयर इंडिया को ही इस सुविधा की अनुमति है।

‘बोलो’ एप

- तकनीकी दिग्गज गूगल ने 6 मार्च को एक नया एप ‘बोलो’ लांच किया है।
- आवाज पहचानने और टेक्स्ट-टू-स्पीच (आवाज सुनकर लिखने की सुविधा) तकनीक पर आधारित यह एप प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा।
- एप को सबसे पहले भारत में लांच किया गया है और यह ऑफलाइन भी काम करेगा।
- इस एप में एक एनिमेटेड पात्र दिया है जो बच्चों को तेज आवाज में कहानियां पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और किसी शब्द का उच्चारण करने में दिक्कत आने पर बच्चों की मदद करती है।
- कहानी पूरा करने पर यह बच्चों का मनोबल भी बढ़ाती है।
- 50 एमबी के इस एप में हिंदी और अंग्रेजी की करीब 100 कहानियां हैं।
- यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और यह एंड्रायड 4.4 (किटकैट) तथा इसके बाद के संस्करण वाले सारे डिवाइस पर चल सकता है।
- एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट (SER) 2018 का हवाला देते हुए कश्यप ने कहा कि ग्रामीण भारत में कक्षा पांच में पढ़ने वाले आधे बच्चे ही सही से कक्षा दो की पाठ्यपुस्तक पढ़ पाते हैं।

भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 62.7 करोड़

- ग्रामीण भारत में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण, इस साल के अंत तक देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 62.7 करोड़ को पार कर जाएगी जो 2018 के 56.6 करोड़ यूजर्स से 11 फीसदी ज्यादा होंगे। 6 मार्च को एक नई रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
- मार्केट रिसर्च कंपनी IMRB द्वारा जारी रिपोर्ट ICUBETM 2018 के अनुसार, जहां शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या सात फीसदी बढ़कर 2018 में 31.5 करोड़ हो गई थी, वहीं ग्रामीण भारत में 35 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- अनुमान है कि ग्रामीण भारत में 25.1 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं

- और यह संख्या 2019 के अंत तक 29 करोड़ हो सकती है।
- भारत में मोबाइल डाटा की कीमतें दुनियाभर में सबसे सस्ती है।
 - आंकड़ों के अनुसार, गांवों और शहरों में पिछले साल इंटरनेट यूजर्स की संख्या में वृद्धि के मामले में बिहार 35 फीसदी वृद्धि के साथ सबसे ऊपर रहा।
 - भारत में इंटरनेट उपयोग करने के मामले में स्त्री-पुरुष असमानता की खाई कम हुई है और महिलाएं देश में कुल इंटरनेट उपयोग का 42 फीसदी उपयोग करती हैं। वे इंटरनेट पर पुरुषों के बराबर समय देती हैं।

चीन के रक्षा बजट में 7.5% की वृद्धि

चर्चा में क्यों?

- चीन लगातार अपने रक्षा बजट में इजाफा कर रहा है। इस साल भी रक्षा बजट में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- ज्ञातव्य है कि चीन अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है, जो अपने रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। चीन का रक्षा बजट भारत से लगभग तीन गुना है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- साल 2018 में चीन ने अपने रक्षा बजट में 8.1 प्रतिशत तक का इजाफा किया था।
- इससे रक्षा क्षेत्र पर उसका व्यय बढ़कर 175 अरब डॉलर हो गया, जो भारत की तुलना में तीन गुना अधिक था।
- चीन की संसद में दर्ज की गई ड्राफ्ट बजट रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 का रक्षा बजट 1.19 ट्रिलियन यूआन है।
- हालांकि, चीन के रक्षा बजट में पिछले साथ के अनुपात में कम इजाफा हुआ है। चीन के रक्षा बजट में पिछले साल 8.1 फीसदी की वृद्धि हुई थी।
- साल 2015 में चीन ने विश्व को उस समय चौंका दिया था, जब उसने अपना रक्षा बजट दोगुना कर दिया था।
- इसके बाद से चीन अपने रक्षा बजट में लगातार इजाफा कर रहा है।
- भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से पांच गुना है
- भारत का रक्षा बजट 58 अरब डॉलर है।
- पाकिस्तान का रक्षा बजट सिर्फ 11 अरब डॉलर है। अगर चीन के रक्षा के बजट से पाकिस्तान के रक्षा बजट की तुलना की जाए तो ये करीब 16 गुना ज्यादा है।

कुडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया

- युवा मामले तथा खेल मंत्रालय ने कुडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया (KIFI) को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय खेल महासंघ

के रूप में अस्थायी मान्यता दे दी है।

- यह मान्यता भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के प्रावधानों के परिपालन के अधीन होगी।
- इस संहिता में समय-समय पर महासंघ द्वारा संशोधन किए जाते हैं।
- संशोधनों में मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रकट करना शामिल है।
- मान्यता का अर्थ भारत में कुडो खेल के प्रोत्साहन तथा विकास के लिए KIFI एसोसिएशन को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना है।
- कुडो खेल 'अन्य' श्रेणी में रखा गया है।

पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च को पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को मंजूरी दे दी।
- इनमें गैर-सोलर अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता (RPO) के हिस्से के रूप में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की घोषणा शामिल है।
- सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, बड़ी पनबिजली योजनाओं की घोषणा अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि मौजूदा प्रचलन के अनुसार, केवल 25 मेगावॉट से कम क्षमता वाले पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।
- इन उपायों की अधिसूचना के बाद शुरू की गई बड़ी पनबिजली योजनाएं गैर-सोलर अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता के तहत पनबिजली योजनाएं इनमें शामिल होंगी।
- लघु पनबिजली परियोजनाएं पहले से ही इनमें शामिल हैं।
- पनबिजली क्षेत्र में अतिरिक्त परियोजना क्षमता के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के वार्षिक लक्ष्यों के बारे में अधिसूचित किया जाएगा।
- बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के संचालन के लिए शुल्क नीति और शुल्क नियमनों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
- इससे विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिलने से क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
- इससे परिवहन, पर्यटन और अन्य छोटे कारोबारी क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार और उद्यमिता के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-III ए

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 7 मार्च मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-III ए को मंजूरी दी गई।
- इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 30,849 करोड़

रुपये होगी और इसकी पूर्णता लागत 33,690 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के पांच साल के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।

- यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए ऑटोमेटिक डोर ऑपरेशन सहित एयरकंडीशन युक्ती कोच शामिल किए जाएंगे।
- लंबी दूरी वाले उपनगरीय यात्रियों की यात्रा सुचारु बनाने के लिए गलियारों का विस्तार और निर्माण।
- यात्री सुविधाओं में सुधार, स्टेशनों पर यात्रियों की बेहतर आवाजाही।
- स्टेशनों के प्रवेश/निकास पर भीड़-भाड़ में कमी लाई जाएगी।
- संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत के द्वारा उपनगरीय नेटवर्क की सुरक्षा, क्षमता और दक्षता में वृद्धि।
- मध्य और पश्चिमी रेलवे में उपनगरीय रेल परिचालन का पृथक्करण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV (NACP- IV) को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अप्रैल, 2017 से मार्च, 2020 तक तीन साल की अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी दी गई। इसके लिए कुल परिव्यय 6434.76 करोड़ रुपये होगा।
- 99 प्रतिशत से ज्यादा आबादी HIV मुक्त रहेगी।
- समग्र एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम के जरिये वार्षिक तौर पर प्रमुख आबादी के 70 लाख से ज्यादा लोगों को कवर किया जाएगा।
- तीन साल की इस परियोजना में लगभग 15 करोड़ असुरक्षित आबादी (5 करोड़ गर्भवती महिलाओं सहित) की HIV जांच की जाएगी।
- तीन साल की इस परियोजना के दौरान नाको समर्थित ब्लड बैंकों में 2 करोड़ 32 लाख यूनिट खून एकत्रित किया जाएगा।
- तीन साल की इस परियोजना के दौरान यौन संचारित संक्रमणों के 2 करोड़ 82 लाख मामलों की देखरेख की जाएगी।
- परियोजना अवधि समाप्त होने तक 17 लाख PLHIV को निःशुल्क एंटीरेट्रोवायरल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 7 मार्च को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 11,089.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2×660 मेगावाट क्षमता वाले खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (STPP) तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खान के लिए निवेश की

मंजूरी को स्वीकृति प्रदान की गई।

- यह परियोजना 1587.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित की जाएगी और इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSU) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
- खुर्जा STPP प्रति 660 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयों के साथ सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी।
- यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकी से लैस होगी। यह दक्षता संपन्न होगी और विद्युत का उत्पादन करने के लिए ईंधन की कम मात्रा का इस्तेमाल करेगी।
- खुर्जा STPP से उत्तरी क्षेत्र में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के परिदृश्य में सुधार आएगा, जो पहले ही परियोजना से 60 प्रतिशत बिजली की खरीद के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है।
- लाभान्वित होने वाले अन्य राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। खुर्जा एसटीपीपी 2023-24 से लाभ प्रदान करना प्रारंभ करेगा।

तीस्ता चरण VI एचई परियोजना

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 7 मार्च को मैसर्स लेंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड (HTHPL) के अधिग्रहण के लिए निवेश की मंजूरी तथा एनएचपीसी द्वारा सिक्किम में तीस्ता चरण VI एचई परियोजना के शेष कार्य के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई।
- तीस्ता चरण VI एचई परियोजना सिक्किम के सिरवानी गांव में रन ऑफ रिवर (आरओआर-जल संग्रहण के बिना) योजना है, जो तीस्ता नदी की विद्युत क्षमता का जल प्रपात प्रणाली में उपयोग करती है।
- इसमें तीस्ता नदी पर 26.5 मीटर ऊंचे बैराज, 9.8 मीटर व्यास और 13.76 किलोमीटर लम्बाई वाली घोड़े की नाल के आकार की दो हेड रेस टनल या पावर टनल सुरंगें, प्रति 125 मेगावाट क्षमता की चार इकाइयों वाले एक भूमिगत पावर हाउस का निर्माण शामिल है।
- 500 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली इस परियोजना के तहत 90 प्रतिशत डिपेंडेबल ईयर में 2400 एमयू बिजली का उत्पादन होगा।
- इस परियोजना का दायित्व लेने से विफल लागत का उपयोग किया जा सकेगा और अब तक के इस निवेश का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकेगा।
- इतना ही नहीं, निविदा की राशि का उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों आदि की देनदारी चुकाने में किया जाएगा।

- ❖ इस परियोजना से ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने, ग्रिड की बैलेंसिंग और रैम्पिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा सिक्किम राज्य के विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

कीरू पनबिजली परियोजना

- ❖ आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने जम्मू-कश्मीर में मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स CVPPPL) द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना (624 मेगावाट) के निर्माण के लिए निवेश करने को मंजूरी दे दी है।
- ❖ मेसर्स CVPPPL दरअसल NHPC, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (JKSPDC) और (PTC) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिनकी इक्विटी शेयरभागीता क्रमशः 49.49 एवं 2 प्रतिशत है।
- ❖ उपर्युक्त परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इसमें सबसे गहरे नींव स्तर के ऊपर 135 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी डैम, 4 सर्कुलर, 5.5 मीटर के आंतरिक व्यास एवं 316 से लेकर 322 मीटर तक की लंबाई वाले प्रेशर शाफ्ट, एक भूमिगत बिजलीघर और 7 मीटर के व्यास व 165 से लेकर 190 मीटर तक की लंबाई तथा घोड़े की नाल के आकार वाली 4 टेल रेस सुरंगों का निर्माण करना शामिल है।
- ❖ इस परियोजना से उत्तरी ग्रिड को आवश्यक बिजली सुलभ होगी और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। यह परियोजना साढ़े चार वर्षों में पूरी की जाएगी।
- ❖ कीरू पनबिजली परियोजना की परिकल्पना एक 'रन ऑफ रिवर (ROR) यानी जल भंडारण के बगैर' योजना' के रूप में की गई है।
- ❖ इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है जिससे कि 624 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 की जरूरतों को पूरा करे।
- ❖ यह परियोजना 90 प्रतिशत डिपेंडेबल ईयर के दौरान 2272.02 एमयू का उत्पादन करेगी।
- ❖ इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 3 फरवरी, 2019 को रखी गई थी।

ई-धरती ऐप और जियो पोर्टल

- ❖ आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने ई-धरती ऐप लॉन्च किया है।
- ❖ यह एक नई ऑनलाइन प्रणाली है जहां सभी तीन मुख्य मॉड्यूल यानी परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज को ऑनलाइन किया गया है।

- ❖ एल एंड डीओ में भुगतान प्रणाली को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। बिक्री अनुमति, गिरवी अनुमति और उपहार अनुमति जैसे अन्य तीन छोटे मॉड्यूल पर भी काम चल रहा है और वह जल्द ही पूरा हो जाएगा।
- ❖ जनता अब एल एंड डीओ वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती है।
- ❖ उन्हें आवेदन जमा करने और उसके बाद की प्रक्रियाओं एवं पूछताछ के लिए इस कार्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी।
- ❖ भूमि एवं विकास कार्यालय (L & DO) उन सार्वजनिक आवेदनों को निपटाता है जो मुख्य तौर पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम का प्रतिस्थापन और खरीदार के नाम पर दाखिल खारिज आदि से संबंधित होते हैं।
- ❖ इसके अलावा यह कार्यालय बिक्री अनुमति, गिरवी अनुमति और उपहार अनुमति से संबंधित आवेदनों को भी निपटाता है।
- ❖ व्यवस्था को कहीं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इस कार्यालय द्वारा तमाम पहल की गई है ताकि आम जनता, विशेषकर वृद्ध, गरीब, बीमार और वंचित व्यक्तियों के साथ-साथ महिलाओं और विधवाओं को भी इसका फायदा मिल सके।
- ❖ ई-धरती जियो पोर्टल एक अन्य महत्वपूर्ण ऐप्लिकेशन है जिस पर (L & DO) ने काम करना शुरू किया है। यह जीआईएस आधारित 65000 संपत्तियों की मैपिंग पर आधारित है।
- ❖ इस ऐप्लिकेशन के माध्यम से L & DO के तहत प्रत्येक सरकारी संपत्ति, चाहे वह आवंटित हो या खाली पड़ी संपत्ति हो, को 'ई-धरती जियो पोर्टल' नामक पोर्टल पर मैप किया जाना प्रस्तावित है।

भारत-रूस मध्य परमाणु चालित पनडुब्बी करार

- ❖ भारत ने 8 मार्च 2019 को रूस से परमाणु चालित हमलावर पनडुब्बी को दस साल के लिए पट्टे पर लेने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- ❖ भारत को यह पनडुब्बी तीन अरब डॉलर (करीब 20 हजार करोड़ रुपये) में दस साल के लिए मिलेगी। महीनों चली बातचीत के बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच यह समझौता हुआ है।
- ❖ समझौते के अनुसार रूस अकुला श्रेणी की पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सन 2025 में देगा। भारत में यह चक्र तृतीय के नाम से जानी जाएगी।
- ❖ यह रूस से भारत को पट्टे पर मिलने वाली तीसरी पनडुब्बी होगी।
- ❖ इससे पहले भारत ने 1988 में परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी आइएनएस चक्र तीन साल के पट्टे पर रूस से ली थी। दूसरी

आइएनएस चक्र पनडुब्बी 2012 में दस साल के लिए रूस से ली गई।

- चक्र द्वितीय का पट्टा 2022 में खत्म होगा। भारत सरकार उसका पट्टा बढ़वाने पर भी विचार कर रही है।

दृष्टि बाधितों हेतु सिक्कों की नई श्रृंखला

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 मार्च को दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखलाओं को जारी किया।
- ये सिक्के एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए और बीस रुपए मूल्य के हैं और इन्हें नई श्रृंखलाओं के हिस्से के रूप में जारी किया गया है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित एक समारोह में दृष्टि बाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे।
- सिक्कों की डिजाइनिंग राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय ने मिलकर किया है।
- गौरतलब है कि नई श्रृंखलाओं के सिक्कों में कई नई विशेषताएं शामिल की गई हैं, ताकि दृष्टि बाधित लोगों के उपयोग के लिए आसान हो।
- सिक्कों के आकार और भार कम से अधिक मूल्य के सिक्कों के अनुसार हैं।
- बीस रुपये मूल्य का नया सिक्का 12 दिशाओं का होगा और इसमें किसी तरह का नुकीला कटाव नहीं होगा। शेष मूल्य के सिक्के गोल आकार के होंगे।

अभिनव मोबिलिटी सॉल्यूशंस

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है:
 - स्वच्छ, आपस में जुड़ी, साझा, सतत एवं समग्र गतिशीलता पहलों को बढ़ावा देने के लिए 'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन' की शुरुआत करने को स्वीकृति दी गई है।
 - भारत में कुछ व्यापक निर्यात-प्रतिस्पर्धी क्षमता वाले एकीकृत बैटरी एवं सेल-निर्माता गीगा संयंत्रों की स्थापना में सहयोग देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) वर्ष 2024 तक 5 वर्षों के लिए मान्य है।
 - इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी समूची मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में होने वाले उत्पादन के स्थानीयकरण के लिए पीएमपी बनाने को मंजूरी दी गई है जो वर्ष 2024 तक 5 वर्षों के लिए मान्य है।

- दोनों ही PMP योजनाओं को 'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन' द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

मांगेछू पनबिजली परियोजना

- 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मांगेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (MHEP) के संबंध में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि दो वर्ष बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के बीच अनुबंध के अनुच्छेद 3 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
- ऐसा भूटान में इस परियोजना का कार्यान्वयन 15 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष करने के लिए किया जा रहा है।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य भूटान में 720 मेगावाट (MHEP) से विद्युत आयात के लिए पहले साल की दर सूची 4.12 भारतीय रुपया प्रति यूनिट बनाना तथा (MHEP) से भूटान द्वारा भारत को अधिशेष विद्युत की निश्चित रूप से आपूर्ति करना शामिल है।
- इसके तहत भारत-भूटान आर्थिक संबंधों और विशेष रूप से पन-विद्युत सहयोग के क्षेत्र में परस्पर संबंधों और समग्र रूप से भारत-भूटान संबंधों को अधिक मजबूत बनाना है।

बक्सर ताप विद्युत परियोजना

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने बिहार के बक्सर जिले में 2×660 मेगावाट की बक्सर ताप विद्युत परियोजना (बक्सर टीपीपी) के लिए निवेश प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।
- यह परियोजना 10,439.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरी की जाएगी। परियोजना SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लागू की जाएगी।
- SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न प्रतिष्ठान एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- बक्सर ताप विद्युत परियोजना सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और इसमें 660 मेगावाट की दो इकाइयां होगी।
- यह परियोजना पर्यावरण रक्षा के लिए नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण टेक्नोलॉजी से लैस होगी और इसमें उच्च क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन में ईंधन का कम उपयोग होगा।
- बक्सर टीपीपी बिहार तथा पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी की स्थिति में सुधार लाएगी। बिहार सरकार ने उत्पादित विद्युत का 85 प्रतिशत सप्लाई के लिए विद्युत खरीद समझौता पर पहले ही हस्ताक्षर किया है।
- इस परियोजना से क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास के अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की आशा है। बक्सर टीपीपी 2023-24 से लाभ देने लगेगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान

- प्रधानमंत्री 9 मार्च, 2019 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अन्तर्गत है और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-2 में स्थित है।

कूलिंग एक्शन प्लान

- आने वाले सालों में लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिल सकती है। सरकार ने इसे लेकर एक कूलिंग एक्शन प्लान पर काम शुरू किया है।
- जिसके तहत वर्ष 2037-38 तक देश में कूलिंग की मांग को 20 से 25 फीसदी तक कम करना है।
- फिलहाल इससे राहत का अनुभव अगले कुछ सालों में ही किया जा सकेगा। दुनिया में इस तरह का कूलिंग एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत पहला देश है।
- केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ हर्षवर्द्धन ने 7 मार्च को कूलिंग एक्शन प्लान को लांच करते हुए कहा इससे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी।
- उनके स्वास्थ्य और खेती के उत्पादन में सुधार होगा। मौजूदा समय में बढ़ते तापमान और उत्सर्जन के चलते लोगों के जन-जीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है।
- साथ ही लोगों की कूलिंग पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि एसी और रेफ्रिजरेटर की मांग बढ़ती जा रही है।
- लेकिन अब वह इस प्लान के जरिए वर्ष 2037-38 तक एसी और रेफ्रिजरेटर की मांग में भी 25 से 30 फीसदी तक की कमी लाएंगे।
- कूलिंग की बढ़ती मांग को कम करने के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाएंगे, उनमें गर्मी से बचाव के लिए घरों की निर्माण, खेती की आय को बढ़ाने के लिए बेहतर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना बनाई गई है। जिस पर जल्द ही अमल शुरू होगा।
- वहीं जलवायु में होने वाले बदलाव का आकलन लोगों के जीवन स्तर में देखे जाने वाले बदलाव और खेती की बढ़ती पैदावार से आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा इसे लेकर शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

एस्ट्रोसैट ने खोजा सितारों का नया समूह

- शोधकर्ताओं को विभिन्न पराबैंगनी फिल्टरों के माध्यम से ली गई छवियों में 12000 से अधिक तारों की अलग-अलग

पहचान करने में सफलता मिली है।

- सितंबर 2015 में प्रक्षेपित की गई भारतीय मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसैट' निरंतर रोमांचक जानकारी दे रही है। इस वेधशाला का उपयोग करते हुए तिरुवनंतपुरम और मुंबई के खगोलविदों ने तारों के गोलाकार गुच्छे (ग्लोब्यूलर क्लस्टर) एनजीसी-2808 में पराबैंगनी तारों की एक नई श्रेणी की खोज की है।
- तारों के गोलाकार गुच्छों (ग्लोब्यूलर क्लस्टर) में हजारों से लाखों तारे होते हैं, इन तारों के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप वह गुच्छा अपनी आकृति बनाए रखता है और यह माना जाता है कि इन सब तारों का जन्म लगभग एक ही समय में एक साथ हुआ होगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 150 गोलाकार गुच्छे हैं।
- इनमें से कुछ संभवतः आकाशगंगा के सबसे पुराने पिण्ड होंगे। तारे जन्म लेते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। विकास की इन विभिन्न स्थितियों के आने में जो समय लगता है वह हमारी कल्पना से परे है।

पब्लिक से प्राइवेट शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनेगा फेसबुक

- कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का है कि वह लोगों को पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की जगह प्राइवेट कनवरसेशन की तरफ मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- सोशल मीडिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहां हम अपनी बातों को पूरे विश्व के साथ साझा कर सकते हैं। हम जो भी पोस्ट अपडेट करते हैं या फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं।
- वह उन लोगों तक भी पहुंचती हैं। जिन्हें हम शायद निजी तौर पर नहीं जानते हों। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक अब इसमें बड़ा बदलाव करने जा रहा है।
- कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि वह लोगों को पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की जगह प्राइवेट कनवरसेशन की तरफ मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- ऐसा होने पर ह्वाट्सएप की तरह फेसबुक पर भी आपके पोस्ट व मैसेज आदि बहुत ही सीमित लोगों तक पहुंचेंगे। फेसबुक पर लग रहे निजता हनन और डाटा चोरी के आरोपों के बीच जुकरबर्ग का कहना है कि इस बदलाव से यूजर की निजता सुनिश्चित होगी।
- हालांकि, यह योजना सोशल मीडिया की पूरी प्रकृति बदलने जैसी है। फेसबुक को डिजिटल लिविंग रूम बनाने की बात करते हुए जुकरबर्ग ने कहा, 'नए बदलाव के तहत यूजर ऐसे ही लोगों के साथ अपने पोस्ट साझा करेंगे जिन्हें वह अच्छी तरह जानते हैं।'

चीन के 'वी चैट' से होगी प्रतिद्वंद्विता

- ❶ चीनी एप 'वी चैट' पहले ही प्राइवेट शेयरिंग सोशल नेटवर्क की तरह काम करता है। 2011 में बनाए गए इस एप से लोग एक-दूसरे को मैसेज के साथ वीडियो और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर किसी ग्रुप में 500 लोगों को जोड़ा जा सकता है। फेसबुक से उलट वी चैट के यूजर को उनके न्यूज फीड में लगातार विज्ञापन नहीं दिखते।

पद्मा लक्ष्मी UNDP की गुडविल एम्बेसेडर बनीं

- ❶ यूएनडीपी प्रशासक अचिम स्टीनर ने 'गुडविल एम्बेसेडर' के तौर पर लक्ष्मी के नाम की घोषणा की।
- ❷ भारतीय मूल की अमेरिकी टेलीविजन शख्सियत और खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का 'गुडविल एम्बेसेडर' बनाया गया है। वह विश्वभर में असमानता एवं भेदभाव के खिलाफ संगठन की लड़ाई का समर्थन करेंगी।
- ❸ UNDP ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 8 मार्च 2019 को लक्ष्मी को नियुक्त किए जाने की घोषणा की। एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड टेलीविजन हस्ती और पुरस्कार विजेता लेखिका लक्ष्मी अपनी नई भूमिका में असमानता एवं भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और वीचियों को सशक्त बनाने की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के प्रति समर्थन जुटाने का काम करेंगी।
- ❹ यूएनडीपी प्रशासक अचिम स्टीनर ने 'गुडविल एम्बेसेडर' के तौर पर लक्ष्मी के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी पहले भी भेदभाव के खिलाफ और वीचित तबके के लिए आवाज उठाती रही हैं।
- ❺ लक्ष्मी ने यूएनडीपी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो इस समय हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि महिलाओं और लड़कियों को विश्वभर में सर्वाधिक भेदभाव और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
- ❻ यूएनडीपी गुडविल एम्बेसेडर के तौर पर वह इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगी कि असमानता अमीर और गरीब देशों को समान रूप से प्रभावित करती है।
- ❼ लक्ष्मी ने कहा कि कई देश गरीबी कम करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन असमानता अधिक दृढ़ प्रतीत होती है।
- ❽ लिंग, आयु, जाति और नस्ल के आधार पर असमानता की जाती है। यह खासकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों और उन अन्य लोगों को प्रभावित करती है, जिन्हें समाज में अकल्पनीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

सबसे सस्ती/तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक कार

- ❶ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (स्वाइट) राजपुरा में बीटेक फाइनल के छात्र मोहम्मद जवाद खान ने कॉलेज की लैब में मोटरों की टेस्टिंग के दौरान ही इलेक्ट्रिक कार बनाने का सपना मन में संजो लिया और इसको साकार करने के लिए कार के ऐसे मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया, जो पर्यावरण के लिए वरदान साबित हो।
- ❷ मोहम्मद जवाद ने दो वर्ष की मेहनत के बाद वोल्टा नामक इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन तैयार कर इसकी टेस्टिंग के लिए पेश कर दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- ❶ यह कार अब तक की सबसे सस्ती (2.50 लाख रुपये) और तेज रफ्तार से चलती है।
- ❷ मोहम्मद जवाद के अनुसार इस कार को तैयार करने में 15 महीने से भी अधिक का समय लग गया और इसे पूरी तरह से तैयार करने में 6 महीने का अतिरिक्त समय लगा है।
- ❸ SVIET के R & D सेल ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए ढांचागत सहायता प्रदान की। इसे सफलतापूर्वक विकसित और टेस्ट किया गया है।
- ❹ इस कार में दो लोग सवारी कर सकते हैं और इसकी बैटरी 4 से 5 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है।
- ❺ कार में सोलर से भी बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। इसमें चार्ज बूस्टर का प्रयोग किया जाता है।
- ❻ कार में गेयर मैनुअल रखे गए हैं, जबकि दूसरी कंपनियों की कारों में ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स होता है।
- ❼ कार को तैयार करने में करीब 2.50 लाख रुपये का खर्च आया है। इसकी टेस्टिंग में 110 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड किया गया। इस गति की अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक कार तैयार नहीं हुई है।
- ❽ इस इलेक्ट्रिक कार के लिए पेटेंट दाखिल करवाने की प्रक्रिया भी चल रही है।
- ❹ भारत में सबसे सस्ती निसान व महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपये है।
- ❺ इसकी स्पीड लिमिट 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं टेस्ला की कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो यूएसए की कंपनी है।

भारत में रूसी हथियारों के निर्यात में कमी

- ❶ पिछले नौ साल (2009 से 2018) में भारत में रूसी हथियारों का निर्यात 42% तक घटा है।
- ❷ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट

- ‘ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स, 2018’ में दावा किया है कि भारत और रूस की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही।
- 2009-13, 2014-18 के बीच भारत में कुल हथियारों का आयात 24% तक घटा है। भारत दूसरे देशों से भी हथियार खरीदता है।
 - भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश है। वैश्विक स्तर पर जितने भी हथियार बिकते हैं, उनमें भारत का हिस्सा 9.5 फीसदी है।
 - रूसी हथियारों की बात की जाए तो इनका अब तक सबसे बड़ा खरीदार भारत ही रहा है।
 - रिपोर्ट के अनुसार भारत में हथियारों का आयात घटने के पीछे दूसरे कारण भी हैं। 2001 में रूस से लड़ाकू विमान और 2008 में फ्रांस से पनडुब्बी खरीदने का करार हुआ था, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी नहीं हो सकी है।
 - 2009-13, 2014-18 के बीच पाकिस्तान में हथियारों का आयात 39% तक घटा है। अमेरिका अब पाक को हथियार बेचने में आनाकानी कर रहा है। अमेरिकी हथियारों का पाक में निर्यात 81% तक कम हुआ है।
 - वैश्विक स्तर पर अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस कैटेगरी में उसके बाद रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन का नंबर आता है।
 - हथियार खरीद के मामले में सऊदी अरब सबसे ऊपर है। उसके बाद भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया का नंबर आता है।
 - 2009 से 2018 के बीच हथियारों के वैश्विक निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30 से बढ़कर 36% हो गई। इस मामले में रूस से तुलना की जाए तो 2009-13 के दौरान हथियार बेचने में अमेरिका उससे 12% आगे रहा। 2014-18 में यह अंतर 75% हो गया।
 - सूत्रों का कहना है कि हथियारों के निर्यात में रूस के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह भारत और वेनेजुएला है।
 - हालांकि भारत अभी भी रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन वेनेजुएला में रूसी हथियारों का निर्यात 96% तक कम हुआ।

भारत और बांग्लादेश के मध्य चार परियोजनाओं का उद्घाटन

- दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-पट्टिकाओं का अनावरण कर चार परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
- 1. 11 मार्च, 2019 को शुरू की गई चार परियोजनाओं में बांग्लादेश सड़क परिवहन निगम (क्रेडिट की दूसरी

- लाइन के तहत) को डबल डेकर और सिंगल डेकर एसी और नॉन-एसी बसों और ट्रकों की आपूर्ति।
- 2. भारत सरकार की सहायता से भारत की सीमा से लगे पांच उत्तर और उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश के जिलों में 36 सामुदायिक क्लीनिकों का निर्माण।
 - 3. दो दक्षिण-पश्चिमी शहरों में 11 जल शोधन संयंत्रों की स्थापना।
 - 4. बांग्लादेश के लिए भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) का विस्तार।

पिनाका

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 11 मार्च को राजस्थान के पोखरण में निर्देशित शस्त्र प्रक्षेपण प्रणाली-पिनाका का सफल परीक्षण किया।
- यह हथियार प्रणाली अत्याधुनिक मार्गदर्शन यंत्र से लैस है। इसमें एक उन्नत नौवहन और नियंत्रण प्रणाली शामिल है।
- इन हथियारों ने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिशन के सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे किये गये।
- इस प्रणाली से भारतीय सेना के तोपखाने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

मोबाइल एप से दिव्यांगता मूल्यांकन

- सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित होकर ‘डिसेबिलिटी असेसमेंट’ नामक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है।
- इसके जरिये डॉक्टर कुछ ही मिनटों में दिव्यांगता का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- एप तैयार करने वाले डॉक्टर अंकुर दास के अनुसार अभी दिव्यांगों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं जिला अस्पताल में एक अर्जी देनी होती है।
- जिसके बाद डॉक्टर उनकी दिव्यांगता का मूल्यांकन करने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अलग-अलग डॉक्टर दिव्यांगता माप वैल्यू को एक कागज पर लिखते हैं।
- जिसके बाद सभी वैल्यू को जोड़कर अंतिम वैल्यू निकाली जाती है। इसी आधार पर दिव्यांग को प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। लेकिन कई बार अंतिम वैल्यू निकालते समय उसमें त्रुटियां आ जाती हैं।
- जिससे दिव्यांगों को योजना का सही लाभ नहीं मिल पाता।

साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में दिव्यांगों को प्रमाणपत्र के लिए कम-से-कम दो से तीन चक्कर लगाने पड़ते हैं।

- ❖ लेकिन एप के माध्यम से डॉक्टर आसानी से दिव्यांगता मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ एप में दिव्यांग वैल्यू को फीड करना होगा।
- ❖ इसके बाद एप खुद ही दिव्यांगता प्रतिशत की जानकारी देगा। एप में मूल्यांकन के दौरान त्रुटियों की संभावना नहीं होगी।
- ❖ उन्होंने बताया एप में वैल्यू फीड करते ही इसे सेव भी किया सकेगा। यह एप सिर्फ डॉक्टर ही इस्तेमाल कर सकेंगे।

7,000 अतिसूक्ष्म समुद्री प्रजातियों की खोज

- ❖ शोधकर्ताओं ने प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर से सात हजार नई अतिसूक्ष्म प्रजातियों की खोज की है।
- ❖ यह खोज दुनिया भर के समुद्रों के बारे में समझ बढ़ाने में मदद करेगी। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (HKUST) के शोधकर्ताओं के अनुसार उन्होंने समुद्र में पहली बार क्रिस्पर जीन एडिटिंग सिस्टम युक्त एसिडोबैक्टीरिया सहित अन्य प्रजातियों की खोज की है।
- ❖ शोधकर्ताओं को यह खोज करने में आठ सालों का समय लगा। उन्होंने इस दौरान 10 बैक्टीरियल फायला की खोज भी की।
- ❖ नेचर जर्नल कम्प्यूटेशनल प्रकाशित अध्ययन के अनुसार यह खोज उन बातों को गलत साबित करती है जिनमें यह बताया गया है कि दुनिया भर में केवल 35 हजार अतिसूक्ष्म समुद्री प्रजातियां और 80 बैक्टीरियल फायला हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस खोज के माध्यम से समुद्र की जैवविविधता के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में नई दवाएं बनाने की आशा जगी है।

एंटीबायोटिक्स बनाने में मिलेगी मदद

- ❖ नवीनतम खोजे गए सूक्ष्म जीव एसिडोबैक्टीरिका में बायोसिंथेटिक जीन समूहों के उच्च स्तर के होने के कारण इससे एंटीबायोटिक्स और एंटी ट्यूमर दवाएं बनाई जा सकती हैं।
- ❖ यह पहला ऐसा समुद्री जीव है जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग सिस्टम से लैस है। क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से शरीर में बीमारी से ग्रसित जीन को बाहर कर दिया जाता है। इसके साथ ही उसके स्थान पर नए जीन डाल दिए जाते हैं।

बोइंग 737 मैक्स विमानों पर रोक लगाई

- ❖ इथियोपिया में हुए विमान हादसे के बाद भारत समेत 45 देशों ने बोइंग 737 मैक्स विमानों पर रोक लगा दी है।

- ❖ रोक लगाने वाले देशों में 28 यूरोप के हैं। भारत में जेट एयरवेज और स्पाइस जेट के पास इस मॉडल के कुल 17 विमान हैं।
- ❖ इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी बोइंग 737 मैक्स विमानों को ग्राउंडेड करने के लिए कहा है।
- ❖ इससे पहले यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर ने पूरे यूरोप में इन विमानों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की।
- ❖ महीने में दूसरा बोइंग 737 मैक्स विमान क्रैश।
- ❖ यूरोप के 28 देशों के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ओमान, मोरक्को, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया ने उड़ान पर रोक लगाई।
- ❖ पूरी दुनिया में अब तक 40% बोइंग 737 मैक्स विमान खड़े कर दिए गए।

यूएई समेत 10 देश काली सूची में

- ❖ यूरोपीय संघ (ईयू) ने संयुक्त अरब अमीरात समेत दस देशों को 12 मार्च को कर संबंधी काली सूची में डाल दिया। एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
- ❖ ईयू ने इटली जैसे शक्तिशाली सदस्य देशों की आपत्तियों के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बरमूडा समेत दस देशों को इस सूची में जोड़कर इसका विस्तार किया। अब इस सूची में 15 देश हो गये हैं।
- ❖ यह सूची पनामा पेपर्स और लक्सलीक्स समेत कई घोटालों के मद्देनजर 2017 में पहली बार तैयार की गई थी।
- ❖ ईयू ने एक बयान में कहा कि सात देशों ने अपनी सुधार प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया था और इसलिए इन देशों को काली सूची में वापस डाला गया है।
- ❖ ये देश अरूबा, बेलीज, बरमूडा, फिजी, ओमान, वानुआतू और डोमिनिका हैं। तीन अन्य देश जिनकी कर नीतियां पिछले महीनों में अधिक महत्वाकांक्षी हो गई हैं उनमें बारबाडोस, संयुक्त अरब अमीरात और मार्शल द्वीप समूह शामिल हैं।

नाइस, वियना और लोकार्नो समझौता

- ❖ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च को निम्नलिखित समझौतों को मंजूरी प्रदान की -

 1. ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में नाइस समझौता
 2. ट्रेडमार्कों के प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए वियना समझौता
 3. औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण

स्थापित करने के लिए लोकानों समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- नाइस, वियना और लोकानों समझौतों में पहुंच स्थापित करने से वैश्विक रूप से अपनाई जा रही वर्गीकरण प्रणालियों के अनुसार ट्रेड मार्क और डिजाइन अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए वर्गीकरण प्रणालियों से तालमेल के लिए भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालय को मदद मिलेगी।
- यह भारतीय डिजाइनों, प्रतीकात्मक तत्वों और वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणालियों में शामिल करने का अवसर प्रदान करेगा। इस पहुंच से भारत में आईपी के संरक्षण के संबंध में विदेशी निवेशकों में विश्वास जगाने की उम्मीद है।
- इस पहुंच से समझौते के तहत वर्गीकरणों की समीक्षा और संशोधन के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिकारों का उपयोग करने में भी आसानी होगी।

पाक-चीन से निपटने के लिए भारत की नई रणनीति

- दुश्मन के मिसाइल और बमबारी से एयर बेस को बचाने के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई है।
- सरकार ने वायु सेना को चीन और पाकिस्तान सीमा के नजदीक लगभग 110 ठिकाने बनाने की मंजूरी दे दी है।
- केंद्र सरकार ने लगभग 110 ठिकानों के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो फाइटर प्लेन को दुश्मन की मिसाइल और बॉमिंग से बचाएगी, जिसे ब्लास्ट पेन भी कहते हैं।
- प्रोजेक्ट का खर्च 5000 करोड़ से ज्यादा होगा और ब्लास्ट पेन एयर बेस की तर्ज पर बनाए जाएंगे।
- इस कदम से वायुसेना अपने फ्रंटलाइन प्लेन को बिना जमीनी नुकसान की चिंता के फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर सकेगी।
- अभी तक इस सुविधा के बिना वायुसेना ऑपरेशन के दौरान फ्रंटलाइन प्लेन्स को पाकिस्तान सीमा के पास कुछ चुनिंदा स्थानों पर तैनात कर पाती थी।
- 26 फरवरी के एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया था।
- 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने कई विमान खोए थे, तब से एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए वायुसेना ब्लास्ट प्लेन बना रही है।
- इन 100 ठिकानों में मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाई जाएंगी जिससे यह दुश्मन के बड़े हमले से बचाएगी।
- इस रणनीति से भारत पाकिस्तान और चीन से निपटने में आसानी होगी। वर्तमान हालात को देखकर यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

‘मिशन रेट्रो-फिटमेंट’

- रेल विभाग ट्रेन की बोगी को श्री-स्टार होटल की तरह बनाने जा रहा है। इसके लिए ‘मिशन रेट्रो-फिटमेंट’ शुरू किया गया है।
- वर्ष 2022 तक 40 हजार पुराने कोचों को आधुनिक कोचों में तब्दील कर दिया जाएगा। जर्जर हो चुके कोच हटाकर नए कोच लगाए जाएंगे।
- मुरादाबाद रेल मंडल में तीन सौ कोच का आधुनिकीकरण होना है।
- ‘मिशन रेट्रो-फिटमेंट’ रेल यात्री को सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है। इसका मकसद यात्री को कोच के अंदर अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- सफर के दौरान यात्री को श्री स्टार होटल या घर जैसा महसूस हो। नए कोच में इस तरह की सुविधा दी जा रही है।
- देश भर में 40 हजार पुराने मॉडल के कोच हैं। इन सभी की नए सिरे से साज-सज्जा की जाएगी।
- रेलवे प्रत्येक कोच पर 30 लाख रुपये तक खर्च करेगा। कोच में अदृश्य पेंच, पाइप लाइन, एलईडी लाइट वाले पैनल लगाए जाएंगे।
- कोच में फायर सेंसर लगे होंगे। एसी कोच में यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
- कोच की विंडो में फाइबर ग्लास लगेगा। इसे पत्थर आसानी से नहीं तोड़ पाएगा।
- इसके साथ ही प्रत्येक कोच में वाइफाई की भी व्यवस्था की जाएगी।
- नए कोच में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। पुराने कोच में आधुनिक सुविधा के साथ सुधार किया जाएगा। इससे यात्री सफर के दौरान घर जैसा माहौल महसूस कर पाएंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार का विकास मॉडल

- ब्रिटिश संसद ने मुख्यमंत्री को न्योता भेजा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ब्रिटिश संसद में बताएंगे कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर विकास मॉडल तैयार किया जा सकता है।
- छत्तीसगढ़ सरकार का मॉडल हिट हो गया है। जल्द ही ब्रिटिश संसद के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाले मॉडल नरवा (नहर-नाले), गुस्वा (मवेशी), घुरवा (गोबर रखने का स्थान), बाड़ी (खेती का छोटा हाता) को दुनिया को समझाएंगे।
- आदिवासियों और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किस तरह से जल, जंगल, जमीन को बचाने का प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है।

- ❖ बघेल के अनुसार दुनिया में जल संरक्षण के दिशा में प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि में प्राकृतिक जल स्रोत का उपयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
- ❖ नरवा, गस्वा, घुरवा, बाड़ी मॉडल में बांधों में भरा पानी नाले के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा।
- ❖ इससे बोर का उपयोग कम होगा, तो भूमिगत जल का संरक्षण हो जाएगा। मवेशी को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादों के बाजार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ❖ गोबर से कम्पोस्ट खाद बनाया जाएगा। इससे रासायनिक खाद की खपत कम होगी। बाड़ी में पैदावार बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।
- ❖ इस मॉडल के पहले चरण में सरकार ने 1646 ग्राम पंचायतों में गौठान बनाने का काम शुरू कर दिया है। तथा मॉडल की और विस्तृत जानकारी बघेल ब्रिटिश संसद को देंगे।

प्रदूषण से मौत

- ❖ दुनियाभर में होने वाली चौथाई असमय मौतों और बीमारियों के लिए प्रदूषण और पर्यावरण को होने वाला नुकसान जिम्मेदार है।
- ❖ ग्लोबल एन्वायरन्मेन्ट आउटलुक (GEO) की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि स्मॉग, पीने के पानी में हो रहा रासायनिक प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश से कई महामारी फैल रही है। जिससे अरबों लोग प्रभावित हो रहे हैं।
- ❖ 70 देशों के 250 वैज्ञानिकों द्वारा छह साल में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन व कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) जैसे ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पूरे विश्व का भविष्य खतरे में है।
- ❖ वायु प्रदूषण के कारण सालभर में 60 से 70 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। 2015 में करीब 90 लाख लोगों की मौत हुई थी।
- ❖ पीने का साफ पानी उपलब्ध ना होने से डायरिया जैसी बीमारियों से भी हर साल 14 लाख लोगों की मौत हो रही है।
- ❖ रिपोर्ट में पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं होने पर भी चिंता जताई गई है।
- ❖ 2015 में हुए समझौते में करीब 195 देशों ने 2030 तक पृथ्वी के तापमान को दो डिग्री से अधिक न बढ़ने देने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया था।
- ❖ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सभी देशों को समान रूप से योगदान करना होगा।
- ❖ वायु प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए भारत के विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के साथ काम करेंगे।
- ❖ आइआईटी दिल्ली व बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा

संचालित दो दिवसीय कार्यशाला में इसकी घोषणा हुई।

- ❖ विशेषज्ञों के अनुसार भूकंप व आगजनी की तरह प्रदूषण को भी प्राकृतिक आपदा मानकर उनका निपटारा करना चाहिए।

भारतीय क्रिकेटर्स का डोप टेस्ट

- ❖ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपना रवैया नरम करते हुए कहा कि वह अगले छह महीने तक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के साथ काम करेगा।
- ❖ BCCI के शीर्ष पदाधिकारियों और प्रशासकों की समिति (COA) की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के चेयरमैन शशांक मनोहर के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।
- ❖ बोर्ड के अनुसार, ICC, BCCI और NADA के बीच त्रिपक्षीय करार होगा, जिसके तहत पंजीकृत पूल में शामिल खिलाड़ियों के नमूने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) में नाडा के जरिये जाएंगे।
- ❖ इससे पहले स्वीडन की IDTM नमूने एकत्र करती थी। बोर्ड ने अभी तक NADA को अपने रुख से अवगत नहीं कराया है।
- ❖ विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) ने ICC से साफ तौर पर कहा कि बीसीसीआई को नाडा के दायरे में आना होगा।
- ❖ BCCI इस शर्त के साथ तैयार हुआ है कि वह खुद मूत्र के नमूने एकत्र करके NADA को देगा।
- ❖ जिसमें 10 प्रतिशत नमूने ही मुहैया कराएंगे, जो न्यूनतम जरूरत है। इसमें शीर्ष राष्ट्रीय क्रिकेटर्स और कई प्रथम श्रेणी क्रिकेटर्स के नमूने शामिल होंगे।

नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा)

- नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) को 24 नवंबर, 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था जिसमें भारत में डोप फ्री स्पोर्ट्स के जनादेश थे।
- प्राथमिक उद्देश्यों को डब्ल्यूपीए कोड के अनुसार डोपिंग विरोधी नियम लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना और डोपिंग और इसके बीमार प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019

- ❖ भारत और अफ्रीकी देशों के लिए अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019 (AFINDEX-19) का उद्घाटन समारोह 18 मार्च, 2019 को मिलिट्री स्टेशन, पुणे में आयोजित हुआ।

- ☛ यह अभ्यास कार्यक्रम 18 मार्च से 27 मार्च 2019 तक चलेगा।
- ☛ 17 अफ्रीकी देशों - बेनिन, बोत्सवाना, मिस्र, घाना, केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के सैन्य दल के साथ मराठा लाइट इन्फैंट्री ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। मराठा लाइट इन्फैंट्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- ☛ उद्घाटन समारोह में चीता हेलिकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलिकॉप्टरों ने संयुक्त राष्ट्र, भारत और AFINDEX-19 के झंडे लहराए।
- ☛ परेड की समाप्ति पर मुख्य अतिथि और अफ्रीकी देशों के रक्षा अधिकारियों ने परेड के प्रतियोगियों के साथ बातचीत की।
- ☛ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि के अध्याय VII के तहत मानवीय सहायता और शांति स्थापना गतिविधियों के लिए योजना बनाना और इसका परिचालन इस अभ्यास के उद्देश्य है।
- ☛ यह अभ्यास प्रतिभागी राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान पर आधारित है।
- ☛ नये मिशन की स्थापना, शांति स्थापना गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए स्थल चयन, सैन्य पर्यवेक्षक के लिए स्थल चयन, नागरिकों की सुरक्षा, युद्धक तैनाती, सैन्य दल की सुरक्षा और मानवीय सहायता के लिए निगरानी के विभिन्न आयाम।

डोमिनिक थिएम बने इंडियन वेल्स चैंपियन

- ☛ रोजर फेडरर को लगातार दूसरे वर्ष इंडियन वेल्स फाइनल में हार झेलनी पड़ी है।
- ☛ डोमिनिक थिएम ने अपने पहले एटीपी मास्टर्स 1000 के खिताब पर कब्जा करने के साथ स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर को रिकॉर्ड छठा इंडियन वेल्स खिताब जीतने से रोक दिया।
- ☛ ऑस्ट्रिया के 28 साल के इस खिलाड़ी ने दो घंटे दो मिनट तक चले मुकाबले में फेडरर को 3-6, 6-3, 7-5 शिकस्त दी।

जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल नियुक्त

- ☛ भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल का गठन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष (पीसी घोष) को राष्ट्रपति ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त कर दिया है।
- ☛ जस्टिस घोष फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने लोकपाल में चार न्यायिक और

चार गैर न्यायिक सदस्यों की भी नियुक्ति की है।

- ☛ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने गत 15 मार्च को लोकपाल का अध्यक्ष और न्यायिक व गैर न्यायिक सदस्यों का चयन करके नियुक्ति के लिए नाम भेज दिये थे।
- ☛ राष्ट्रपति ने चयन समिति की सिफारिश स्वीकार करते हुए 19 मार्च को लोकपाल अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया।
- ☛ राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जबकि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहन्ती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है।
- ☛ इसके अलावा आइएएस दिनेश कुमार जैन जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हैं और पूर्व महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल अर्चना रामसुन्दरम तथा श्री महेन्द्र सिंह व डाक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है।
- ☛ इन सभी की नियुक्ति इनके पद ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- ☛ लोकपाल की पांच सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे और लोकसभा स्पीकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, नेता विपक्ष और जानेमाने कानूनविद मुकुल रोहतगी सदस्य थे।

लोकपाल चयन प्रक्रिया और कार्यकाल

- ☛ लोकपाल में अध्यक्ष और सदस्यों का पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु होने तक का कार्यकाल होगा।
- ☛ कानून के मुताबिक लोकपाल अध्यक्ष पद के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है।
- ☛ इसके अलावा कोई प्रसिद्ध शख्सियत भी लोकपाल नियुक्त हो सकता है अगर उसे 25 वर्ष तक एंटी करप्शन पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सतर्कता या वित्त बीमा बैंकिंग कानून अथवा प्रबंधन का अनुभव हो।

जस्टिस घोष का संक्षिप्त परिचय

- 1952 में जन्मे जस्टिस पी.सी. घोष (पिनाकी चंद्र घोष) उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति शंभू चंद्र घोष के बेटे हैं। 1997 में वे कलकत्ता हाईकोर्ट में जज बने।
- दिसंबर 2012 में वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 8 मार्च 2013 में वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रोन्नत हुए और 27 मई 2017 को वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए।

- अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के मात्र दो न्यायाधीशों जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत (पीसी पंत) और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (पीसी घोष) ने आवेदन किया था।
- सर्च कमेटी ने इन्हीं दोनों न्यायाधीशों के नाम चयन समिति को भेजे थे। जिसमें से चयन समिति ने जस्टिस घोष के नाम पर अपनी मुहर लगाई थी।

वीरता पुरस्कार

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों की जांबाजी, अदम्य साहस और अपने कर्तव्य के पालन में अपना परम योगदान देने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया।
- उन्होंने दो कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए। इनमें से दो कीर्ति चक्र और दो शौर्य चक्र परम बलिदान देने वाले शहीदों को मरणोपरांत दिए गए।
- भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 19 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में एक दुर्लभ घटना के तौर पर 16 साल के इरफान रमजान शेख को भी शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया।
- नाबालिग इरफान ने वर्ष 2017 में अपने घर पर हुए आतंकियों के हमले को नाकाम किया था।
- राष्ट्रपति ने CRPF की 130वीं बटालियन में कांस्टेबल प्रदीप कुमार पांडा और राष्ट्रीय राइफल्स की 22वीं बटालियन के आर्मड कॉर्प्स के विजय कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया।
- राष्ट्रीय राइफल्स की 42वीं बटालियन की मैकेनाइज्ड इनफैंट्री में सिपाही अजय कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
- असम राइफल्स की चौथी बटालियन के राइफलमैन जयप्रकाश ओरॉन ने मणिपुर में एक सैन्य अभियान के दौरान अत्यधिक साहस के साथ दो उग्रवादियों को मार गिराया था और दो अन्य को घायल कर दिया था।
- शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले अन्य वीर जवानों में मेजर पवन कुमार (राष्ट्रीय राइफल्स), कुलदीप सिंह चाहर (CRPF), जिलेप सिंह (CRPF), राइफलमैन राठवा लीलेश भाई (असम राइफल्स) शामिल हैं।
- इसके अलावा, ऑल पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के ले.कॉर्नल विक्रान्त प्राशेर, कैप्टन अभय शर्मा, मेजर रोहित लिंगवाल, नायब सूबेदार अनिल कुमार दहिया, हवलदार जावीद अहमद भट्ट, हवलदार कुल बहादुर थापा को भी शौर्य चक्र प्रदान किया गया।
- इसके अलावा, जाट रेजिमेंट के ले.कॉर्नल अर्जुन शर्मा, गोरखा राइफल्स के मेजर इमलियाकुम केत्जर को भी राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र प्रदान किया गया।

- राष्ट्रपति ने अपनी सेवाओं में विशिष्ट योगदान के लिए सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अफसरों को भी 13 परम विशिष्ट सेवा पदक, दो उत्तम युद्ध सेवा पदक और 26 अतिविशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया।
- लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट को जम्मू-कश्मीर में उनकी अगुआई में आतंकवाद-रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए 'उत्तम युद्ध सेवा पदक' राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें दिया।

उत्तम युद्ध सेवा मेडल

- उत्तम युद्ध सेवा पदक भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैन्य सम्मान में से एक है। इसे विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है।
- यह युद्धकालीन सम्मान, अति विशिष्ट सेवा पदक के समकक्ष है, जो एक शांतिकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है। उत्तम युद्ध सेवा पदक मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन

- नेपाल में 19 मार्च को तीन दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ।
- राजधानी काठमांडू में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल की साझी विरासत के तौर पर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है।
- सम्मेलन का विषय 'संस्कृत-नेपाल और भारत की एक साझा विरासत' रखा गया है।
- इसका आयोजन काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास, भारत के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय और नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।
- सम्मेलन के दौरान संस्कृत से जुड़े 45 शोध पत्र भी पेश किए जाएंगे जो संस्कृत भाषा, साहित्य और दर्शन क्षेत्र से जुड़े हैं। सम्मेलन में दोनों देश के कई शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं।

विश्व गौरैया दिवस

- हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
- कंक्रीट में बदलते शहरों में गौरैया के प्राकृतिक आवास खत्म होते जा रहे हैं। ना अब आंगन रहे और ना ही रोशनदान। हरियाली भी सिमटती जा रही है।
- ऐसे में कृत्रिम घोंसले लगाकर गौरैया को आसरा देने की मुहिम बीते कई सालों से की जा रही है।
- इन घोंसलों को चिड़िया ने अपना आशियाना बना लिया है। अब जरूरत इस बात की है कि गौरैया पार्क विकसित किए जाएं।

- ❶ यही एक ऐसी चिड़िया है जो घरों में परिवारजनों के साथ रहती है। हमारे नजदीक तक आती है, अंडे देती है परिवार बढ़ाती है।
- ❷ यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और यही वजह है कि इसका कलरव घर में खुशियां लाता है।

संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति-6

- ❶ मित्र शक्ति अभ्यास को सैनिक कूटनीति और भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य बातचीत के एक हिस्से के रूप में हर वर्ष आयोजित किया जाता है।
- ❷ वर्ष 2018-19 के लिये यह संयुक्त अभ्यास 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 तक श्रीलंका में आयोजित किया जायेगा।
- ❸ भारतीय सेना की पहली बटालियन बिहार रेजीमेंट की टुकड़ियां संयुक्त रूप से इस अभ्यास में भाग लेंगी।
- ❹ इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य घनिष्ठ संबंधों को स्थापित और बढ़ावा देना तथा कमान के तहत दोनों देशों के सैनिक दस्तों की संयुक्त अभ्यास कमांडर योग्यता को बढ़ाना है।
- ❺ इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र आदेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह की रोकथाम और आतंकवादी माहौल का मुकाबला करने के लिये युक्तिपूर्ण परिचालनों को शामिल किया जायेगा।
- ❻ मित्र शक्ति-6 अभ्यास दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने का लंबा रास्ता तय करेगा तथा दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमीनी स्तर पर समावेश और सहयोग बढ़ाने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

मोजाबिक को सहायता

- ❶ मोजाबिक में 15 मार्च को आए चक्रवाती तूफान 'इडाई' के बाद लोगों की मानवीय मदद करने और आपदा राहत प्रदान करने संबंधी मोजाबिक सरकार के अनुरोध के बाद भारतीय नौसेना द्वारा अपनी पहली प्रशिक्षण स्क्वाड के तीन जहाजों सुजाता, सारथी और शार्दूल को मोजाबिक के पोर्ट बीरा की ओर भेजा गया।
- ❷ INS सुजाता और ICGS सारथी 18 मार्च की सुबह पोर्ट बीरा पहुंचे जबकि INS शार्दूल 19 मार्च को पोर्ट बीरा पहुंचा और उसके बाद से स्थानीय प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- ❸ भारतीय नौसेना के जहाज स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिविर स्थापित करेंगे और खाना, पेयजल, कंबल और अन्य आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करेंगे।
- ❹ मोजाबिक में स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और भारतीय नौसेना मोजाबिक में स्थानीय लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं।

- ❶ चक्रवाती तूफान इडाई ने 15 मार्च की सुबह मोजाबिक के बीरा में व्यापक नुकसान किया और इसके कारण मोजाबिक के केंद्रीय और उत्तरी प्रांत में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई।

अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाईम एयरो एक्सपोजे (LIMA)

- ❶ लांगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाईम एयरो एक्सपोजे (LIMA-2019) 26 मार्च, 2019 से 30 मार्च, 2019 को मलेशिया के लांगकावी में आयोजित किया गया।
- ❷ भारतीय वायु सेना पहली बार मैरीटाईम एयरो एक्सपोजे में भाग ले रही है। इस दौरान अपने देश में विकसित LCA युद्धक विमान तेजस को दर्शाया जाएगा।
- ❸ भारतीय वायु सेना की टीम वायु सेना स्टेशन कलईकुंडा से 22 मार्च, 2019 को रवाना हुई। यह टीम म्यांमार (यंगून) होते हुए लांगकावी जाएगी।
- ❹ भारतीय वायु सेना की खेप में 2 LCA, 1 C-130J और 1 IL-76 के साथ 27 अधिकारी, 42 वायु सैनिक और 11 HAL कार्मिक शामिल हैं।

रीजेनरॉन साइंस टैलेंट सर्च

- ❶ पर्यावरण संबंधी संकटों से निपटने के लिए तकनीक विकसित करने वाली चार भारतीय-अमेरिकी छात्राओं को यहां सम्मानित किया गया है।
- ❷ ये चारों छात्राएं देश के सबसे पुराने व प्रतिष्ठित साइंस व गणित प्रतियोगिता 'रीजेनरॉन साइंस टैलेंट सर्च' के अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।
- ❸ कंटकी की अंजलि चड्ढा (16), डेलावेयर की प्रीति साई कृष्णमणि (17), उत्तरी कैरोलिना की नवामी जैन (17) और पेंसिलवेनिया की साई प्रीती ममीडाला (17) को 25 हजार डॉलर (करीब 17 लाख रुपये) की इनामी राशि भी दी गई है।
- ❹ अंजलि चड्ढा को कुएं के पानी में आर्सेनिक की पहचान करने वाला सेंसर विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। पांच करोड़ अमेरिकी अब भी कुएं के पानी पर निर्भर हैं। पानी में मौजूद हानिकारक आर्सेनिक से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
- ❺ कृष्णमणि ने धान के पौधे को आर्सेनिक से बचाने के लिए तकनीक विकसित की है। दूसरी ओर जैन बॉयो-इथेनॉल उत्पादित करने के भिन्न तरीकों पर काम कर रही हैं।
- ❻ बॉयो-इथेनॉल एक तरह का जैविक ईंधन है जिससे पर्यावरण को कम क्षति पहुंचती है।
- ❼ गार्नेट वैली हाई स्कूल की छात्रा ममीडाला की मदद से नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को सुगम बनाने के लिए शोध कर रही हैं।

‘सम्प्रीति’-2019

चर्चा में क्यों?

- भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 2 मार्च से 15 मार्च 2019 तक बांग्लादेश के तंगेल में दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास “सम्प्रीति” - 2019 संचालित किया जाएगा।
- यह आठवां अभ्यास होगा। दोनों देश वैकल्पिक रूप से संयुक्त अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है।
- इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के तहत उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक कार्रवाई का भी अभ्यास किया जाएगा।

उद्देश्य :

- इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और सहयोग के पक्षों को मजबूत और व्यापक बनाना है।
- इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग के पहलुओं को मजबूत बनाना और उनका विस्तार करना है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए मिलकर कार्य करना है।
- इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों से निपटने में रणनीतिक स्तर की कार्रवाई होगी और यह संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के अनुसार होगा।
- यह अभ्यास एक दूसरे की रणनीति को समझने के अतिरिक्त दोनों देशों की आपसी साझेदारी, मजबूत सैन्य विश्वास और सहयोग का आधार रखेगा।

संयुक्त सैन्य अभ्यास “सम्प्रीति”-2019

- यह सैन्य अभ्यास एक साल बांग्लादेश और दूसरे साल भारत में होता है।
- इसका मकसद दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना है।
- दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इसे हर साल किया जाता है।
- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों के बीच सहयोग को बढ़ाना भी मकसद है।
- यह अभ्यास वर्ष 2016 में बांग्लादेश में ढाका के समीप तंगाइल में तथा वर्ष 2015 में पश्चिम बंगाल के बिनागुड़ी में आयोजित किया गया था।
- पहला अभ्यास वर्ष 2010 में असम के जोरहाट में हुआ था।

भारत-बांग्लादेश संबंध :

- भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं, हालांकि कभी-कभी सीमा विवाद होते हैं।
- बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है। ये दोनों देश सार्क, बिस्मटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं।
- विशेष रूप से, बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांत हैं। भारत और बांग्लादेश अपने 68 साल पुराने द्विपक्षीय सीमा विवाद को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच रहे हैं।
- भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास सम्प्रीति से दोनों देशों की सेनाओं के बीच ना केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि दोनों सेनाओं के बीच आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप जारी

- दूरसंचार सचिव अरूणा सुंदरराजन ने 27 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में बंगलुरु स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी “सिग्नलचिप” द्वारा 4जी/एलटीई और 5जी एनआर माँडम्स के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को जारी किया।
- इस चिप के जारी होने को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण करार दिया जा रहा है।
- वर्तमान में केवल 8 कंपनियां और कुछ ही देश सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण कर सकते हैं और ऐसे में स्वदेशी तकनीक से निर्मित चिप का जारी होना सही मायने में विश्व के लिए मेक इन इंडिया है।
- यह अग्रगामी कार्य उत्सर्जन की शिकायतों और पर्यावरण की बढ़ती चिंताओं के आलोक में बिल्कुल नई संरचना का मार्ग प्रशस्त करेगा।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

- भारत में 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम ‘लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग’ (Science for the People and People for Science) है।
- यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। यह खोज भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकटरमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी।
- सीवी रमन को इस खोज के कारण वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबल पुरस्कार था।

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाये जाने का उद्देश्य देश में विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि में बढ़ोतरी करना है।
- इस दिन सभी विज्ञान संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय एवं अन्य विज्ञान प्रयोगशालाएं, विज्ञान अकादमियों, स्कूल और कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों के मन में कायम भ्रांतियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है तथा इसके विकास के द्वारा ही हम समाज के लोगों का जीवन स्तर अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं।
- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अनुप्रयोग के महत्व के संदेशों को लोगों के बीच फैलाना, मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र की सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना तथा विज्ञान के विकास के लिए इन मुद्दों पर चर्चा करके नई प्रौद्योगिकी को लागू करना है।
- विज्ञान और तकनीक को प्रसिद्ध करने के साथ ही देश के नागरिकों को इस क्षेत्र में मौका देकर नई उंचाइयों को हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में

- राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (NCSTC) ने वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाने के लिए केंद्र सरकार को कहा था।
- केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर नामित किया गया। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था।

श्रेयस (SHREYAS)

संदर्भ:

- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 27 फरवरी 2019 को युवाओं में कौशल विकास के जरिये उन्हें काबिल बनाने के लिए 'श्रेयस' (स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल) पोर्टल लॉन्च किया है।
- इस पोर्टल की सहायता से स्नातक की डिग्री पाने वाले छात्रों को उद्योग जगत में प्रशिक्षण का कोर्स कर उन्हें कौशल युक्त बनाया जायेगा ताकि वे रोजगार के योग्य हो सकें।
- उच्च शिक्षा प्रणाली को सीखने की प्रक्रिया में रोजगार प्रासंगिकता की शुरुआत करके छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार करना।
- स्थायी आधार पर शिक्षा और उद्योग / सेवा क्षेत्रों के बीच

घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध बनाना।

- मौजूदा समय की मांग के अनुसार छात्रों को कौशल प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में पढ़ाई के साथ-साथ कमाई की व्यवस्था को स्थापित करना।
- इंडस्ट्री को बेहतर कार्य शक्ति प्रदान करने के लिए कुशल कार्यकर्ताओं को तैयार करना।
- सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के साथ छात्र समुदाय को रोजगार से जोड़ना।

दक्षिणी तटीय रेलवे

- भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश में दक्षिण तटीय रेलवे (SCOR) नाम से एक नए रेलवे जोन की स्थापना की घोषणा की है जो आंध्र प्रदेश विभाजन के समय की घोषणा के अनुरूप है।
- इस रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। इस जोन में मौजूदा गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे।
- वाल्टेयर डिवीजन को दो भागों में बांटा जाएगा। वाल्टेयर डिवीजन के एक हिस्से को नए मंडल यानि दक्षिण तटीय रेलवे में शामिल करके पड़ोसी विजयवाड़ा डिवीजन में मिला लिया जाएगा।
- वाल्टेयर डिवीजन के बाकी हिस्से को एक नए डिवीजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका मुख्यालय पूर्वी तटीय रेलवे के अधीन रायगडा में होगा।

गुरिल्ला रेनस्टॉर्म

- आमतौर पर जापान के संदर्भ में जब प्राकृतिक आपदा की चर्चा होती है तो लोगों के मन में भूकंप पर टायफून का ख्याल आता है जो सही भी है परंतु जापान की राजधानी टोक्यो में अल्पावधि में ही कपासी मेघ छा जाता है और भारी वर्षा हो जाती है।
- स्थानीय स्तर पर अचानक व इस गहन वर्षा को 'गुरिल्ला रेनस्टॉर्म' कहा जाता है।
- टोक्यो में वर्ष 2020 में ओलंपिक होने वाला है इसलिए खेल को व्यवधान से बचाने के लिए जापानी वैज्ञानिक गुरिल्ला रेनस्टॉर्म के पूर्वानुमान के लिए नई तकनीक का विकास कर रहे हैं।

पृथ्वी के नीचे विशाल पर्वत खोजा

- अब तक पुस्तकों में हम यही पढ़ते रहे हैं कि पृथ्वी की तीन (या चार) परतें हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो कभी-कभी आंतरिक और बाहरी कोर में विभाजित होता है।
- हालाँकि यह विभाजन गलत है लेकिन इस विभाजन में कई

अन्य परतें रह जाती हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भीतर खोजा है।

- ☛ साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार प्रिंसटन भू-भौतिकीविद जेसिका इरविग और चीनी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोडेसी एवं जियोफिजिक्स वेनबो वूनेबोलीविया में एक बड़े भूकंप से मिले डेटा का इस्तेमाल पृथ्वी के नीचे पहाड़ों और अन्य स्थलाकृति को खोजने में किया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली।
- ☛ उन्हें पृथ्वी से 660 किलोमीटर (410 मील) सीधे नीचे, जो ऊपरी और निचले मेंटल को विभाजित करता है, एक पर्वत मिला है। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊँचा है।
- ☛ औपचारिक नाम के अभाव में फिलहाल इस पर्वत को 660 किलोमीटर की सीमा (the 660 km. boundary) कहा गया है।
- ☛ पृथ्वी की गहराई में जाने के लिए, वैज्ञानिक पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली तरंगों का उपयोग करते हैं, जो बड़े पैमाने पर भूकंपों से उत्पन्न होते हैं।
- ☛ बड़े भूकंप छोटे की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं—रिक्टर पैमाने के प्रत्येक चरण में वृद्धि के साथ 30 गुना शक्तिशाली हो जाती है।
- ☛ पृथ्वी के नीचे अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने बोलिविया में 1994 में आए 8.2 तीव्रता के भूकंप के कंपन का सहारा लिया— जो अब तक का रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप है।
- ☛ 660 किलोमीटर नीचे कठोरता की उपस्थिति यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा ग्रह कैसे बना और कैसे यह कार्य करना जारी रखे हुआ है। यह परत मेंटल को विभाजित करती है, जो पृथ्वी के आयतन का लगभग 84 प्रतिशत है।

विलुप्त सूची में ब्रैम्बल काय मेलोमी चूहा

- ☛ लघु कृतक या मूषक जिसका ऑस्ट्रेलिया के केवल एक द्वीप पर पर्यावास था, जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ गया है।
- ☛ ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण मंत्रालय ने फरवरी 2019 में आधिकारिक रूप से ब्रैम्बल काय मेलोमी (Bramble Cay melomys) नामक चूहा को संकटापन्न से विलुप्ति सूची में डाल दिया।
- ☛ यह कृतक ग्रेट बैरियर रीफ के पूर्वी टॉरेस जलडमरूमध्य स्थित अपने विशिष्ट पर्यावास से गायब हो गया था।
- ☛ यह जानवर अंतिम बार वर्ष 2009 में एक मछुआरा द्वारा देखा गया था, तब से इसे खोजने के सारे प्रयास विफल रहे हैं। इसी के पश्चात इसे विलुप्त मान लिया गया और अब आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की गई है।

आठ चिकित्सा उपकरण को औषधि का दर्जा

- ☛ केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के अंग प्रत्यारोपण उपकरण, सीटी स्कैन, PET एवं MRI उपकरण, डिफाइब्रिलिएटर्स, डायलिसिस मशीन एवं बोन मैरो विभाजकों को मानव के लिए औषधि का दर्जा प्रदान किया है।
- ☛ सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना अप्रैल, 2020 से लागू होगी। अधिसूचना के मुताबिक उपर्युक्त उपकरणों का आयात, विनिर्माण एवं वितरण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत विनियमित होगा। इसमें पहले से ही 27 उपकरणों को औषधि का दर्जा दिया जा चुका है।
- ☛ उल्लेखनीय है कि भारत में अधिकांश चिकित्सा उपकरण विनियमित नहीं हैं और सरकार के उपर्युक्त कदम से कुछ उपकरणों को विनियामक के अधीन लाया गया है जो मरीजों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना

- ☛ केंद्र सरकार ने 28 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री जी-वन यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दी। इसके तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेलुलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती है। के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है।
- ☛ जी-वन योजना के लिए 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 1969,50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
- ☛ इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी।
- ☛ पहला चरण (2018-19 से 2022-23) में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरे चरण (2020-21, 2023-24) में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को मदद की व्यवस्था की गई है।
- ☛ परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है। इसके लिए उसे वाणिज्यिक परियोजनाएँ स्थापित करने और अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
- ☛ EBP कार्यक्रम (इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) के तहत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मदद पहुँचाने के अलावा निम्नलिखित लाभ भी होंगे:

- जीवाश्म ईंधन के स्थानों पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।
- जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प लाकर उत्सर्जन के CHG मानक की प्राप्ति।
- बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान व समाधान और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति शृंखला में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
- बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण।
- दूसरी पीढ़ी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण।
- योजना के लाभार्थियों द्वारा बनाए गए इथेनॉल की अनिवार्य रूप से तेल विपणन कम्पनियों को आपूर्ति, ताकि वे EBP कार्यक्रम के तहत इनमें निर्धारित प्रतिशत में मिश्रण कर सकें।

हिप्पोकैम्प-नेपच्यून ग्रह के नए चंद्रमा की खोज

- वैज्ञानिकों ने नेपच्यून का हाल में खोजा गया चंद्रमा को 'हिप्पोकैम्प' (Hippocamp) नाम दिया है।
- कैलिफोर्निया के माउंटन व्यू स्थित सेती इंस्टीट्यूट (Search for Extraterrestrial Intelligence: SETI) के वैज्ञानिक शोवाल्टर ने वर्ष 2013 में इस चंद्रमा के अस्तित्व की खोज की थी किंतु तत्समय इसे S/2004 N अनौपचारिक नाम दिया गया था।
- इस चंद्रमा का नामकरण मिथकीय यूनानी दैत्याकार जानवर के नाम पर हुआ है जिसका सिर घोड़ा जैसा और शरीर मछली जैसा है।
- यह चंद्रमा अति लघु आकार का है और तारा के प्रकाश के कारण यह वर्षों तक छिपा रहा है। इस खोज के साथ ही नेपच्यून के चंद्रमाओं की संख्या 14 हो गई है।

सेहुएनकास जल मेढ़क

- वर्ष 2008 के पश्चात से सेहुएनकास जल मेढ़क (Sehuencas water frogs) को बोलिविया के प्राकृतिक पर्यावास में नहीं देखा गया था। इसका एकमात्र नर प्रजाति, जिसे रोमियो नाम दिया गया था, वहाँ के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में जीवित बचा था। इस आधार पर यह माना जा रहा था कि कुछ वर्षों में मेढ़क की यह प्रजाति विलुप्त हो जाएगी।
- इसकी आबादी को तत्समय साइट्रोडियोमाइकोसिस (chytrai-

diomycosis) नामक कवकीय रोग ने समाप्त कर दिया था। इस कवक के कारण संपूर्ण विश्व में मेढ़क की आबादी प्रभावित हुयी थी।

- सेहुएनकास मेढ़क को विलुप्ति से बचाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने दस साल जंगलों में बिताए। अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। उन्हें इस मेढ़क प्रजाति (Telmatobius yuracare) के पाँच मेढ़क उसके प्राकृतिक पर्यावास 'बोलिवियन माउंटन क्लाउड फॉरेस्ट' में मिले हैं।
- यहाँ की जलवायु आर्द्र एवं सर्द है जो साइट्रिड के लिए आदर्श माहौल उपलब्ध कराता है। यहाँ इसका मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि इस कवकीय रोग के प्रति इनमें प्रतिरक्षी प्रणाली हो या आनुवंशिक प्रतिरोध हो सकता है।
- वैसे कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सेहुएनकास जल मेढ़क प्रजाति का मिल जाना प्राकृतिक संयोग हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी मेढ़क प्रजातियाँ विलुप्त होकर फिर वापस आ गई।
- जैसे कि दिसंबर 2018 में वैज्ञानिकों ने 10 वर्ष पहले विलुप्त घोषित हो गई इक्वेडोर की मार्सुपियल हॉर्नड मेढ़क (marsupial horned frog) के पुनर्खोज की घोषणा की।

संचार उपग्रह जीसैट-31 का प्रक्षेपण

- भारत के नवीनतम संचार उपग्रह, जीसैट-31 को फ्रेंच गुयाना के स्पेसपोर्ट से 6 फरवरी 2019 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
- प्रक्षेपण यान एरियन 5 वीए-247 को फ्रेंच गुयाना के कौरू लॉन्च बेस से प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ भारत के जीसैट-31 और सऊदी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 1/हेलास सैट 4 उपग्रहों को ले जाया गया है।
- जीसैट-31 एक भुतुल्यकालिक उपग्रह है जिसका वजन 2536 किलोग्राम है। जीसैट-31 भूस्थैतिक कक्षा में कू (KU)-बैंड ट्रॉसपोंडर क्षमता को बढ़ाएगा। यह उपग्रह ऑर्बिट के कुछ उपग्रहों की परिचालन सेवाओं को निरंतरता प्रदान करेगा।
- इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन के अनुसार यह उपग्रह भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। जीसैट-31 एटीएम, स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल सैटेलाइट, न्यूज गैदरिंग (DNNG) और ई-गवर्नेंस एप्स के लिए VSAT कनेक्टिविटी और डीटीएच टेलीविजन सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।
- यह उपग्रह उभरते हुए दूरसंचार अनुप्रयोगों के होस्ट के लिए थोक डाटा स्थानांतरण के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

ग्रिड कनेक्टेड सौर पैनल

- केंद्र सरकार ने 12000 मेगावॉट की ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के

लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) परियोजना चरण-2 के कार्यान्वयन के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- ❶ इन परियोजनाओं की स्थापना स्व उपयोग अथवा सरकार के उपयोग या केंद्र और राज्य सरकारों की इकाइयों के उपयोग हेतु सरकारी निर्माताओं द्वारा 8,580 करोड़ रुपये की कम पड़ती धनराशि के प्रबंध (VGF) के साथ की जाएगी।
- ❷ 12000 मेगावॉट या उससे अधिक क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टिड सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना सरकारी निर्माताओं द्वारा 4 वर्ष की अवधि अर्थात् 2019-20 से 2022-23 में सरकारी निर्माता योजना में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप की जाएगी।
- ❸ यह योजना सौर फोटोवोल्टिक (SPV) सेल और मॉड्यूल्स दोनों के उपयोग के लिए अधिदेशित है और इसका निर्माण घरेलू स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और परीक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।
- ❹ यह योजना सरकार निर्माताओं को सौर सेल और मॉड्यूल्स घरेलू विनिर्माताओं से खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के जरिये 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी। यह योजना अगले 3 से 4 वर्षों के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित सौर पीवी सेल और मॉड्यूल्स के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न करेगी।

चतुरंगी ग्लेशियर

- ❶ हाल के एक अध्ययन के अनुसार गंगोत्री का सहायक ग्लेशियर चतुरंगी तेजी से पिघल रहा है।
- ❷ गंगोत्री गंगा के जल का मुख्य स्रोत है, जिसके सहायक ग्लेशियरों के पिघलने का असर गंगा नदी के प्रवाह पर पड़ सकता है।
- ❸ अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक करीब 27 वर्षों में चतुरंगी ग्लेशियर की सीमा करीब 1172 मीटर से अधिक सिकुड़ गई है। इस कारण चतुरंगी ग्लेशियर के कुल क्षेत्र में 0.626 वर्ग किलोमीटर की कमी आयी है और 0.139 घन किलोमीटर बर्फ कम हो गई है।
- ❹ अल्मोड़ा के जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में वर्ष 1989 से 2016 तक के उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों और काइनेमैटिक जीपीएस (एक उपग्रह नेविगेशन तकनीक) का उपयोग किया गया है।
- ❺ एक शोधकर्ता के मुताबिक चतुरंगी ग्लेशियर वर्ष 1989 तक गंगोत्री ग्लेशियर का हिस्सा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह ग्लेशियर प्रतिवर्ष 22.84 मीटर की दर से सिकुड़

रहा है और गंगोत्री ग्लेशियर से काफी पहले ही कट चुका है।

- ❶ इससे पहले के अध्ययनों में गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने के बारे में पता चला है, लेकिन उसके पिघलने की दर (12 मीटर/प्रति वर्ष) चतुरंगी ग्लेशियर से काफी कम है।
- ❷ छोटे आकार और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होने के कारण चतुरंगी ग्लेशियर के सिकुड़ने की दर गंगोत्री ग्लेशियर की तुलना में अधिक है।
- ❸ ग्लेशियरों के पिघलने की दर में बदलाव के लिए जलवायु परिवर्तन के अलावा, ग्लेशियर का आकार, प्रकार, स्थलाकृति और वहाँ मौजूद मलबे का आवरण मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है।

मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर को विदाई

- ❶ 15 वर्षों (5515 पृथ्वी दिवस) की सेवा के पश्चात नासा के मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर का पृथ्वी से संपर्क टूट गया। इसके साथ ही इसकी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी गई।
- ❷ हालांकि धूल भरी आंधी के पश्चात 10 जून, 2018 को ही नासा का संपर्क सौर चालित यान से टूट गया था परंतु उस समय से इसे फिर से जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सफलता हाथ नहीं लगी।
- ❸ जिस समय यह मंगल ग्रह की आंधी की चपेट में आया, उस समय इसकी अवस्थिति परसेवरेंस घाटी में थी।
- ❹ अपॉर्चुनिटी रोवर की डिजाइन मंगल ग्रह की सतह पर चलने के लिए बनाई गई थी। इस यान में छह पहिये लगे हुए थे और यह गोल्फ कोर्ट के आकार के बराबर था। इसे एक मील के 6 /10 वां हिस्सा (1 किलोमीटर) पर चलने के लिए बनाया गया था परंतु इसने कुल 28 मील की दूरी तय की।
- ❺ मंगल ग्रह के धरातल पर विचरण के लिए बनाए गई किसी किसी अन्य यान की तुलना में इसने वहाँ अधिक समय बिताए। मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर 7 जुलाई, 2003 को प्रक्षेपित किया गया था और 25 जनवरी, 2004 को यह मंगल ग्रह के मेरिडियानी प्लेन्स पर उतरा।
- ❻ इस रोवर ने मंगल ग्रह की स्थलाकृति, भूविज्ञान, वायुमंडल एवं इतिहास के बारे में हमारी समझ में व्यापक बदलाव किया। इसकी मिट्टी के अध्ययन से पता चल पाया कि मंगल ग्रह कभी नम था तथा वहाँ इतनी गर्मी मौजूद थी जो जीवन को आधार प्रदान कर सकता था।
- ❼ इसने वहाँ इम्पैक्ट क्रेटर की भी खोज की। इस तरह किसी अन्य ग्रह पर ऐसा क्रेटर खोजने वाला यह प्रथम यान बना।

विश्व को हरित बनाने में भारत-चीन की भूमिका

- ❶ नेचर सस्टेनेबिलिटी नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार विश्व को हरित बनाने में चीन एवं भारत नेतृत्व प्रदान कर रहा है।

- ❶ नासा के उपग्रह डेटा के आधार पर तैयार इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्ष पहले की तुलना में आज विश्व अधिक हरा-भरा है। अध्ययन के अनुसार चीन एवं भारत विश्व के हरित क्षेत्र का एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु वनस्पति से आच्छादित वैश्विक क्षेत्र का केवल 9 प्रतिशत ही यहाँ है।
- ❷ यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक खोज है क्योंकि विश्व की दो सर्वाधिक आबादी वाले देश में भू-अवनयन (डिग्रेडेशन) के आरोप लगते रहे हैं।
- ❸ वर्ष 2000 से 2017 के बीच उपग्रह आंकड़ा विश्लेषण के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष के अनुसार केवल 6.6 प्रतिशत वैश्विक वनस्पति क्षेत्र के बावजूद चीन में विशुद्ध वनस्पति क्षेत्र में 25 प्रतिशत वैश्विक वृद्धि का योगदान किया। चीन के हरित क्षेत्र में 42 प्रतिशत वन तथा 32 प्रतिशत फसल भूमि का योगदान है।
- ❹ इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के पश्चात चीन एवं भारत में खाद्यान्न उत्पादन में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और बहु-फसली के द्वारा फसल क्षेत्र में वृद्धि मुख्य कारण रहा है। उपर्युक्त अध्ययन नासा के टेरा एवं अक्वा उपग्रहों पर लगे 'मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर उपकरण के डेटा विश्लेषण पर आधारित है।

भारतीय सुंदरबन को रामसर स्थल का दर्जा

- ❶ भारतीय सुंदरबन को 30 जनवरी, 2019 को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि' का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भारत का 27 वां रामसर आर्द्रभूमि स्थल है जबकि वैश्विक स्तर पर इसकी संख्या 2370 है।
- ❷ लगभग 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला भारतीय सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और भारत का 60 प्रतिशत मैंग्रोव वन यहीं पाया जाता है।
- ❸ रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्राप्त करने के लिए 9 शर्तें रखी गई हैं जिनमें से सुंदरबन ने चार शर्तों को पूरा किया। ये चार शर्तें हैं: दुर्लभ प्रजातियों एवं संकटापन्न पारिस्थिकीय समुदायों की उपस्थिति, महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिनिधि मछलियों तथा मछलियों के अंडे देने की जगह तथा प्रवासन मार्ग की उपस्थिति।
- ❹ भारतीय सुंदरबन जो कि एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है।
- ❺ यहाँ चरम संकटापन्न उत्तरी नदी टेरापिन(बतागुर बस्का), संकटापन्न डॉल्फिन (ऑर्केल्ला ब्रेविरोस्ट्रीस) और फिशिंग कैट (प्रिनेलुरुस विवेरिनस) पाई जाती है।
- ❻ इनके अलावा यहाँ विश्व की चार में से दो घोड़े की नाल केकड़ा तथा भारत की 12 किंगफिशर में से 8 पाई जाती हैं।
- ❼ अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि अभिसमय, जिसे रामसर

अभिसमय भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं सही उपयोग को बढ़ावा देता है। किसी एक इकोसिस्टम पर केंद्रित यह एकमात्र वैश्विक संधि है।

- ❶ इस अभिसमय को ईरानी शहर रामसर में 1971 में अपनाया गया था और 1975 में यह प्रभावी हुआ।
- ❷ परंपरागत रूप से इसे अपशिष्ट भूमि या बीमारियों का प्रजन केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है परंतु वास्तव में यह ताजा जल एवं भोजन उपलब्ध कराता है तथा प्रकृति का आधात अवशोषक रहा है।
- ❸ आर्द्रभूमि, जैव विविधता के लिए अति महत्त्वपूर्ण है परंतु ये तेजी से गायब हो रहा है और 1990 से अब तक 64 प्रतिशत या इससे अधिक आर्द्रभूमि गायब हो चुकी है।

बायो-एनर्जी (TCP) का 25वां सदस्य

- ❶ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 25 जनवरी, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी बायो-एनर्जी टीसीपी का 25 वां सदस्य बना है।
- ❷ इसके अन्य सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया- गणराज्य, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विटजरलैंड, इंग्लैंड, अमरीका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- ❸ बायो-एनर्जी (आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी) संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
- ❹ इसका उद्देश्य बायो-एनर्जी अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले देशों के बीच सहयोग तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए उपाय

- ❶ केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ❷ इससे जुड़े विषयों की जाँच करने एवं वर्ष 2022 तक सच्चे अर्थों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति तैयार करने की अनुशंसा करने के लिये राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी सीमित का गठन किया गया।
- ❸ समिति ने आय में वृद्धि के 7 स्रोतों की पहचान की यथा, फसल एवं पशुधन उत्पादकता में बढ़ोतरी; संसाधन उपयोग में दक्षता अथवा उत्पादन में लगी लागत में बचत; फसल

गहनता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बहुरूपता; किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य में बढ़ोतरी एवं कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र पेशों में परिवर्तन। इस दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:

- प्रदेश सरकारों के माध्यम से कृषि विपणन व्यवस्था में संशोधन कर बाजार सुधारों की शुरुआत करना।
- मॉडल संविदा कृषि अधिनियम लागू कर प्रदेश सरकारों के माध्यम से संविदा कृषि को प्रोत्साहन देना।
- 22,000 ग्रामीण हाटों का उन्नयन की योजना जिससे वह एकत्रीकरण केंद्र के साथ ही किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीद का केंद्र बन पाएँ।
- किसानों को खरीद-फरोख्त के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) की शुरुआत।
- किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की फ्लैगशिप योजना का क्रियान्वयन ताकि उर्वरकों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- न्यूनतम जल अधिकतम फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) की पहल जिसके अंतर्गत जल के अधिकाधिक इस्तेमाल हेतु टपक सिंचाई/छिड़काव को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उत्तर पूर्व को जैविक खेती के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- एक नवीन किसान-मित्रतापूर्ण 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीज बोने से पहले से लेकर फसल कटाई तक अनेक प्रकार के जोखिम कवर किये जाते हैं एवं किसानों को बहुत सामान्य प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
- 'हर मेड़ पर पेड़' योजना के अंतर्गत किसानों की आय के न्यूनतापूर्ण, जोखिम प्रबंधन में बेहतरी एवं एकीकृत कृषि प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में जलवायु समायोज्य कृषि के लिए कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- वृक्षों की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किया गया था। इसके बाद से वन क्षेत्र के बाहर लगे बांस का पेड़ काटने एवं पारहवन संबंधी नियमन लागू नहीं होंगे।
- इसके स्वाभाविक परिणाम के तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के कदम के रूप में किसान (उत्पादक) को बाजार (उद्योग) से जोड़कर बांस की मूल्य शृंखला के विकास के लिए पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन का शुभारंभ किया गया।
- प्रधानमंत्री आशा योजना की शुरुआत जो कि तिलहन,

दालों एवं खोपरा के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करवाएगी।

- कुछ निश्चित फसलों के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया है। किसानों की आय में बड़ा इजाफा करते हुए सरकार ने 2018-19 के लिए सभी खरीफ एवं रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन में लगी लागत से न्यूनतम 150 प्रतिशत अधिक स्तर पर बढ़ोतरी को अनुमति प्रदान कर दी है।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत फसलों की उत्पादकता में परागण के माध्यम से वृद्धि करने एवं किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन दिया गया है।
- दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी तथा किसानों के लिए दुग्ध उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्रियान्वित किया गया है।
- पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने एवं उनके जेनेटिक विकास के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।
- भविष्य में मत्स्यपालन क्षेत्र में उच्च संभावनाओं को देखते हुए मुख्य रूप से अंतर्देशीय एवं सामुद्रिक दोनों स्थानों पर मत्स्य उत्पादन पर ध्यान देती बहुआयामी गतिविधियों के साथ एक नीली क्रांति का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत 8 में से एक मिनी राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA) का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के दृष्टिकोण से कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की तैयारियों में वृद्धि के लिए 2018-2030 के लिए परिशोधित रणनीति दस्तावेज तैयार किया गया था।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट-चंद्रभाग

- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन समन्वित तटीय प्रबंधन समाज भारत के 13 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए अभियान आरंभ किया था।
- इनमें से ओडिशा का चंद्रभाग तट देश का ऐसा पहला समुद्री तट हो गया है जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है।
 - चंद्रभागा तट ओडिशा के पुरी में कोणार्क तट के नजदीक है।
 - ब्लू फ्लैग प्रमाणन ऐसे स्वच्छ एवं पर्यावरणानुकूल तटों

को प्रदान किया जाता है। जो 33 पर्यावरण एवं पर्यटन संबंधित मानकों को पूरा करते हों। यह प्रमाणन डेनमार्क के कोपेनहेगेन में 1985 में स्थापित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।

- सिकॉम इस हेतु विश्व बैंक समर्थित 'समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना' के साथ 'समुद्र तट प्रबंधन सेवा' (Beach Management Service: BeaMS) का संचालन कर रहा है।
- चंद्रभागा के अलावा जिन अन्य 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए तैयार किया जा रहा है, वे हैं ताजपुर (पूर्वी मिदनापुर-पश्चिम बंगाल), कापड (कोझिकोड-केरल), राधानगर (अंडमान-निकोबार), शिवराजपुर (द्वारका-गुजरात), घोघला (दीव-दमन दीव), भोगवे (सिंधुदुर्ग-महाराष्ट्र), मिरामार (पंजिम-गोवा), पदुबिदरी (उडुपी-कर्नाटक), एमेराल्ड (कराइकल-पुदुच्चेरी), महाबलीपुरम (तमिलनाडु), रूशिकोंडा (विशाखापट्टनम-आंध्र प्रदेश) और लक्षद्वीप।

मरूस्थलीकरण पर नया विश्व एटलस

- ☞ यूरोपीय आयोग के संयुक्त अध्ययन केंद्र ने 'विश्व मरूस्थलीकरण एटलस' का नया संस्करण जारी किया जिसकी मदद से नीति निर्माता मृदा नाश एवं भू-क्षरण (Degradation) के प्रति स्थानीय कार्रवाई कर सके।
- ☞ यह एटलस वैश्विक स्तर पर भू-अपक्षय का प्रथम व्यापक साक्ष्य आधारित मूल्यांकन है और यह त्वरित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पर बल देता है। बीस वर्षों के पश्चात जारी नया एटलस से निम्नलिखित तथ्य निकलकर आए हैं;
 1. विश्व के 75 प्रतिशत भू क्षेत्र का पहले ही क्षरण हो चुका है और 90 प्रतिशत से अधिक का वर्ष 2050 तक क्षरण हो जाएगा।
 2. वैश्विक स्तर पर यूरोपीय संघ के कुल क्षेत्र (4.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर) का 50% का प्रतिवर्ष क्षरण हो रहा है। सर्वाधिक क्षरण अफ्रीका एवं एशिया में हो रहा है।
 3. यूरोपीय संघ के लिए भू-क्षरण का आर्थिक नुकसान 10 अरब यूरो वार्षिक से अधिक है।
 4. भू-क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन से वर्ष 2050 तक फसल उत्पादकता में 10% की कमी आएगी। अधिकांश कमी भारत, चीन एवं उप-सहारा अफ्रीकी देशों में देखी जाएगी जहां फसल उत्पादन आधी हो सकती है।
 5. वृद्धित निर्वनीकरण के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन कठिन हो जाएगा।

6. भू-संसाधनों में कमी से जुड़े मुद्दों के कारण वर्ष 2050 तक 700 मिलियन (70 करोड़) लोगों के विस्थापित हो जाने का अनुमान है। इस शताब्दी के अंत तक यह संख्या 10 अरब हो सकती है। जारी एटलस में कहा गया है कि भू-क्षरण एक वैश्विक समस्या है जो स्थानीय स्तर पर घटित होता है और जिसका स्थानीय समाधान हो सकता है। भू-क्षरण एवं जैव विविधता नाश को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। कृषि भूमि का विस्तृत होते रहना भू-क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसलिए भविष्य में भू-क्षरण को रोकने के लिए कृषि भूमि के विस्तार के बजाय पहले से मौजूद कृषि भूमि में ही उत्पादकता बढ़ाना, वनस्पति आधारित भोजन की ओर स्थानांतरण, सतत संसाधनों में प्राणी प्रोटीन का उपयोग तथा खाद्य नाश व अपशिष्ट में कमी पर जोर दिया जाना चाहिए। भू-क्षरण एवं मरूस्थलीकरण संकट को देखते हुए सतत विकास लक्ष्य संख्या 15.3 में वर्ष 2030 तक भू-क्षरण तटस्थ विश्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बांध सुरक्षा विधेयक, 2018

- ☞ यह विधेयक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को एकरूप बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद देगा, जिससे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इन बांधों से होने वाले लाभ सुरक्षित रहेंगे।
- ☞ इससे मानव जीवन, पशु धन और संपत्ति की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। हालांकि इस ड्राफ्ट पेपर के जारी होने के पश्चात ही विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री ने इसे संसद में पेश करने से पहले राज्यों से परामर्श लेने तथा उन्हें विश्वास में लेने का सुझाव दिया है।
- ☞ इससे पूर्व भी जब बांध सुरक्षा विधेयक 2016 जारी किया गया था। तब तमिलनाडु ने इसके कुछ प्रावधानों के प्रति विरोध जताया था।
- ☞ तमिलनाडु के अनुसार इस विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकारों में कुछ कटौती की जा रही है। इस बांध सुरक्षा विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
 - विधेयक में देश में निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रख-रखाव का प्रावधान है, जिससे उनका सुरक्षित काम-काज सुनिश्चित किया जा सके।
 - बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी।

- नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण नीति, दिशा-निर्देश और देश में बांध सुरक्षा के लिए मानकों को लागू करेगा।
- राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

- विधेयक के अनुसार यह प्राधिकरण बांध सुरक्षा संबंधी डाटा और व्यवहारों के मानकीकरण के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और बांधों के मालिकों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
- प्राधिकरण राज्यों तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा यह देश के सभी बांधों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस तथा प्रमुख बांध विफलताओं का रिकॉर्ड रखेगा।
- यह उन संगठनों की मान्यता या प्रत्ययन का रिकॉर्ड रखेगा, जिन्हें जांच, नए बांधों की डिजाइन और निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है।
- प्राधिकरण दो राज्यों के राज्य बांध संगठन के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य के बांध के स्वामी के बीच विवाद का उचित समाधान करेगा।
- कुछ मामलों में जैसे, एक राज्य का बांध दूसरे राज्य के भू-भाग में आता है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी निभाएगा और इस तरह अंतर-राज्य विवादों के संभावित कारणों को दूर करेगा।

पृष्ठभूमि

- भारत में 5200 से अधिक बड़े बांध हैं और लगभग 450 बांध बनाए जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त मझौले और छोटे हजारों बांध हैं। भारत में बांध सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत व्यवस्था नहीं होने के कारण बांध सुरक्षा चिंता का विषय है।
- असुरक्षित बांध खतरनाक हैं और इनके टूटने से आपदा आ सकती है और परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो सकता है।

भारत का प्रथम रोबोटिक टेलीस्कोप

- भारत का प्रथम रोबोटिक टेलीस्कोप लद्दाख के हान्ले स्थित भारतीय खगोलीय बेधशाला में स्थापित है जिसका नाम है 'ग्रोथ इंडिया' (GROWTH India)।
- यह एक वैश्विक सहयोगात्मक परियोजना 'ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वाचिंग ट्रांजिएंट्स हैपेन' (Global Relay of Observatories Watching Transients Happen: GROWTH) का हिस्सा है।

- यूएस, यूके, जापान, भारत, जर्मनी, ताईवान एवं इजरायल इस परियोजना के हिस्सा हैं। इस परियोजना का प्राथमिक शोध उद्देश्य 'समय पहलू खगोल' यानी 'टाइम डायमेंशन एस्ट्रोनॉमी' है जिसमें ब्रह्मांड में क्षणिक विस्फोटों एवं परिवर्तनीय स्रोतों का अध्ययन किया जाता है।

- हान्ले स्थित रोबोटिक टेलीस्कोप के लिए शोध विषय का चयन पहली बार 'मेस्सियर कैटैलॉग' से किया गया है जो चमकीले नजदीकी खगोलीय स्रोत हैं जहां तक उत्तरी गोलार्द्ध से आसानी से पहुंचा जा सकता है।
- भारत स्थित रोबोटिक टेलीस्कोप वैश्विक परियोजना का हिस्सा होने के साथ आंतरिक स्तर पर बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की संयुक्त परियोजना है।
- इस परियोजना का पूर्ण वित्तपोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (SERB) द्वारा 'पायर परियोजना' (PIRE Project) के तहत किया जा रहा है जो कि भारत-यूएस विज्ञान मंच द्वारा प्रसासित है।

रेलगाड़ियों में बायो-टॉयलेट्स

- देश के अधिकांश रेलगाड़ियों में बायो-टॉयलेट्स लगाने के पश्चात अब रेल मंत्रालय इनकी जगह उन्नत वैकम बायो-टॉयलेट्स लगाने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए 500 वैकम बायो-टॉयलेट्स का ऑर्डर दिया, जिस पर परीक्षण चल रहा है।
- 31 मई, 2018 तक रेलगाड़ियों के 37,411 कोचों में 1,36,965 बायो-टॉयलेट्स लगाए जा चुके हैं। एक बायो-टॉयलेट्स लगाने का खर्चा एक लाख रूपया है। वैसे रेल मंत्रालय मार्च 2019 तक सभी रेलगाड़ियों में बायो टॉयलेट की कीमत 2.5 लाख रूपए है। किंतु वैकम बायो-टॉयलेट की कई खूबियां हैं। जिसके कारण इसे प्राथमिकता दी जा रही है।
- एक तो यह कि इसमें बदबू नहीं आएगी। दूसरा यह कि इसमें जल की आवश्यकता में 1/20 की कटौती करेगा। इसके अलावा इसके बाधित होने की संभावना भी न्यून रहती है। ये वैकम बायो-टॉयलेट हवाई जहाजों में लगाए जा चुके हैं। जिसके कारण इनकी विश्वसनीयता की पुष्टि हो चुकी है।
- बायो टॉयलेट के तहत मानव मल के प्रसंस्करण के लिए एनोरोबिक उपापचय प्रक्रिया अपनायी जाती है। इन बायो-टॉयलेट्स से कोई भी मानव मल रेलवे ट्रैक पर नहीं फेंका जाता है। बैक्टीरिया मानव मल को जल या बायोगैस (मुख्यतः मिथेन (CH₄) एवं कार्बन डाई ऑक्साइड (CO₂)) में परिवर्तित कर देता है।

- हाल के वर्षों में बायो-टॉयलेट्स की भी कुछ खामियां सामने आई हैं और सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में इन खामियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।
- बैक्टीरिया को सक्रिय रखने लिए प्रत्येक बायोटॉयलेट को 60 लीटर का इनोकुलम (गाय का गोबर एवं जल का मिश्रण) की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा रेलगाड़ियों में बदबू आना, इनका बाधित हो जाना भी आम बात रही है। इन शिकायतों के मद्देनजर ही रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ियों में अपग्रेडेड वैकम बायो टॉयलेट लगाने की योजना बनाई है।
- बायो टॉयलेट में मानव मल की समाप्ति के लिए जिस बैक्टीरिया को रखा जाता है उसे एक रक्षा वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में पाया था। उन्होंने वर्ष 2005 में इसे संवर्द्धित कर इसका पेटेंट हासिल कर लिया।

पूर्वोत्तर परिषद की पुनर्संरचना

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद् की पुनर्संरचना को मंजूरी प्रदान कर दी। यह मंजूरी 13 जून, 2018 को दी गई। पुनर्गठित पूर्वोत्तर परिषद् की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
 - केंद्रीय गृहमंत्री को परिषद् का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है जिसका प्रस्ताव पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किया था।
 - इस परिषद में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं।
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद के उपाध्यक्ष होंगे।

पुनर्गठन का उद्देश्य

- पूर्वोत्तर परिषद राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे तथा पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। यह परिषद अंतर-राज्य विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।
- एनईसी अब मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा विवादों जैसे अंतर-राज्य विषयों पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए जा रहे कार्यों को करेगी। NEC के नए स्वरूप से यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कारगर संस्था बनेगी।
- परिषद समय-समय पर परियोजना में शामिल परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, इन परियोजनाओं

आदि के लिए राज्यों के बीच समन्वय के लिए कारगर उपायों की सिफारिश करेगी। परिषद को केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियां प्राप्त होंगी।

पूर्वोत्तर परिषद्

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद् एक नोडल एजेंसी है। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्य शामिल हैं।
- ये हैं; अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा। पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना संसद के अधिनियम 'पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971' के अंतर्गत की गई थी।
- इसकी स्थापना संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी।
- 2002 के संशोधन के बाद NEC को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और NEC इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बनाते समय दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी।
- परिषद सिक्किम के मामले में विशेष परियोजनाएं और योजनाएं बनाएगी।

ग्वाटेमाला में फुएगो ज्वालामुखी विस्फोट

- मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में 4 जून, 2018 को फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट से लगभग 75 लोगों की मौत हो गई जबकि 192 लोग लापता हो गए। इस ज्वालामुखी की राख 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। इससे पाइरोक्लास्टिक प्रवाह का भी सृजन हुआ।

फुएगो ज्वालामुखी से अधिक मौत क्यों

- हाल ही में अमेरिकी हवाई द्वीप स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ परंतु उससे एक व्यक्ति भी हताहत नहीं हुआ जबकि ग्वाटेमाला ज्वालामुखी में विस्फोट से 75 लोगों की मौत हो गई।
- ऐसा क्यों है? दरअसल दोनों ज्वालामुखियों में मुख्य अंतर लावा एवं पाइरोक्लास्टिक प्रवाह का है।
- किलाउआ में ध्वंस का मुख्य मोड लावा रहा है जबकि फुएगो में पाइरोक्लास्टिक। पाइरोक्लास्टिक, लावा की तुलना में अधिक खतरनाक होता है।
- उष्मा एवं गति, दोनों मामले में पाइरोक्लास्टिक प्रवाह कहीं अधिक होता है। फुएगो, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ आग होता है यह जिस क्षेत्र में है वहां की आबादी काफी घनी है।

(Ka-wai- a Pele) –ग्रीन लेक

- अमेरिका के हवाई द्वीप पर सक्रिय किलाउआ ज्वालामुखी के पर्यावरणीय प्रभाव अब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। इस ज्वालामुखी के लावा के कारण हवाई द्वीप के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील 'का वाई अ पेले' (Ka-Wai a Pele) जिसे ग्रीन लेक भी कहा जाता है, भाप में बदलकर गायब हो गई है।
- अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार विदर-8 से निकले लावा 2 जून, 2018 को इस झील में समा गया। महज 90 मिनट में पिघले चट्टानों ने संपूर्ण झील (जो कई जगहों पर 200 मीटर तक गहरी थी) को उबाल दिया।
- यह झील 400 वर्ष पुरानी थी और इस बड़े द्वीप पर स्थित ताजे पानी की दो झीलों में से एक थी। ज्ञातव्य है कि 3 मई, 2018 को किलाउआ ज्वालामुखी से लावा निकलना आरंभ हो गया था।
- हवाई के बिग आईलैंड पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी विगत 30 वर्षों से सक्रिय है परंतु मई 2018 में इसमें विस्फोट आरंभ हुआ। इससे निकले लावा 600 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया और 2000 से अधिक निवासियों को खाली कराया गया। यह अभी भी सक्रिय है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के माउंट हेलेन (वाशिंगटन राज्य) ज्वालामुखी के पश्चात इसे सर्वाधिक नुकसान वाला ज्वालामुखी माना जा रहा है।

विलुप्ति के कगार पर विश्व के प्राइमेट्स

- ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार हमारे सबसे नजदीकी जानवर विलुप्ति के कगार पर हैं। इस अध्ययन के अनुसार जिस दर से इन प्राइमेट्स के पर्यावास नष्ट हो रहे हैं उससे यह प्रतीत होता है कि अधिकांश गैर-मानव प्राइमेट्स विलुप्ति के कगार पर होंगे। जिन प्राइमेट्स पर विलुप्ति का सबसे अधिक खतरा है, वे हैं; गोरिल्ला, ओरंगटन एवं चिम्पांजी।
- प्रकृति संरक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय संघ (IUCN 2017) के अनुसार पूरे विश्व में गैर-मानव प्राइमेट की 439 प्रजातियां अभी मौजूद हैं। ये विश्व के 90 देशों में हैं परंतु इनमें बहुसंख्यक केवल चार देशों में ही हैं। विश्व की दो तिहाई प्राइमेट्स केवल चार देशों; ब्राजील (23 प्रतिशत), मेडागास्कर (23 प्रतिशत), इंडोनेशिया (11 प्रतिशत) और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (8 प्रतिशत) में हैं और इनमें से 60 प्रतिशत विलुप्ति के साथ संकटापन्न स्थिति में हैं।
- इन चारों देशों में सर्वाधिक खतरा इंडोनेशिया एवं मेडागास्कर में है जहां क्रमशः 83 प्रतिशत एवं 93 प्रतिशत प्रजातियां संकटापन्न हैं। शोधकर्ताओं ने इसके लिए कई कारकों को

जिम्मेदार माना है। जिनमें मानवजनित एवं सामाजिक दबाव भी शामिल है जैसे कि; पर्यावास विनाश, वन अवनयन, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, मानव आबादी विस्तार, खाद्य असुरक्षा तथा असतत पण्य अंतराष्ट्रीय व्यापार।

उपलब्ध जल के हिसाब से क्षेत्रीय फसल प्रतिरूप

- नाबार्ड द्वारा प्रायोजित तथा ICRIER (अंतराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर शोध के लिए भारतीय परिषद्) द्वारा तैयार 'प्रमुख भारतीय फसलों का जल उत्पादकता मानचित्रण', जिसे 13 जून, 2018 को जारी किया गया, के अनुसार भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन की सततता (निरंतरता) बनाए रखने के लिए उपलब्ध जल के हिसाब से क्षेत्रीय फसल प्रतिरूप अपनाने की जरूरत है।
- वर्तमान में जल आधारित धान एवं गन्ना की फसलें, जो उपलब्ध सिंचाई जल का 60 प्रतिशत उपभोग करता है, ऐसे क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं जो देश के सर्वाधिक जल अनुपलब्धता वाले क्षेत्र हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा बेल्ट में चावल की खेती तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडू और कर्नाटक में गन्ना की खेती सिंचाई जल उपयोग में असमानता का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
- महाराष्ट्र में गन्ना की खेती केवल 4 प्रतिशत फसल क्षेत्र में होती है परंतु उपलब्ध जल का यह 65 प्रतिशत उपभोग कर लेता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे भारत के पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक जल उपलब्ध है परंतु ये राज्य जल गहन फसल खरीद के प्रभावी तंत्र सृजित करने या चीनी मिलों को अपने राज्य में आकर्षित करने में नाकामयाब रहे हैं।
- इसलिए इस रिपोर्ट में भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता के बजाय किसी फसल के लिए आवश्यक जल की मात्रा के आधार पर फसल का चुनाव किये जाने की आवश्यकता जतायी गई है।
- इसके लिए पंजाब का उदाहरण दिया गया है जहां चावल की उत्पादकता 4 टन प्रति हैक्टेयर है जो कि देश में सर्वाधिक है, वहीं सिंचाई जल उत्पादकता 0.22 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है जो जल के अकुशल उपयोग की ओर संकेतित करता है। सिंचाई जल उत्पादकता (Irrigation Water Productivity-IWP) से तात्पर्य है सिंचाई जल उपयोग की प्रति इकाई की तुलना में उत्पादन।
- अध्ययन में जल एवं बिजली का प्रभावी मूल्यन, उच्च सिंचाई जल उत्पादकता वाले राज्यों में फसल खरीद हेतु व्यवस्था में सुधार तथा मूल्य समर्थन के बजाय प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण की ओर उन्मुखता ताकि फसल मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित हो, पर बल देने को कहा गया है।

संकट में अफ्रीका का बाओबाब पेड़

- ❶ बाओबाब पेड़ अफ्रीकी महाद्वीप की पहचान है। यह अफ्रीका के सबसे पुराने एवं सबसे बड़े पेड़ों में शामिल है और कई क्षेत्रों में लोगों के जीवन के आधार है ये पेड़। परंतु जलवायु परिवर्तन ने इन पेड़ों को भी नहीं छोड़ा है। इसके कारण कई प्राचीन बाओबाब पेड़ या तो मृत हो चुके हैं या मरणासन्न स्थिति में हैं।
- ❷ रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त पर्यावरणीय शोध दल वर्ष 2005 से 2017 के बीच इन पेड़ों का अध्ययन किया और अफ्रीका के 60 से अधिक पेड़ों की तिथि निर्धारित की, जिनमें सबसे पुराने एवं सबसे बड़े बाओबाब पेड़ भी शामिल थे।
- ❸ नेचर प्लस पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक अध्ययन अवधि (12 वर्ष) में ही 13 प्राचीनतम बाओबाब पेड़ों में 9 तथा 6 बड़े बाओबाब में से 5 या तो पूरी तरह निर्जीव हो गए हैं या उनमें से कुछ के हिस्सा या तना गिर चुके हैं या मृत हो चुके हैं।
- ❹ जिन नौ पेड़ों को इस अवस्था में पाया गया उनमें चार अफ्रीका के सबसे बड़े बाओबाब पेड़ हैं। सभी मृत पाए गए बाओबाब में किसी बीमारी या महामारी के लक्षण नहीं दिखे जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये पेड़ जलवायु परिवर्तन का शिकार हो गए।
- ❺ हालांकि उनका यह भी कहना था कि जलवायु परिवर्तन संबंधी अवधारणा की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की जरूरत है। उन्होंने जिंबाब्वे का 2450 वर्ष पुराना पवित्र पनकी नामक बाओबाब पेड़ का उदाहरण दिया जो 2010 और 2011 के बीच गिरकर मृत हो गया।
- ❻ सर्वाधिक लोकप्रिय बाओबाब बोत्सवाना का 1400 वर्ष पुराना चैपमैन है जो अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में पहुंचने वाला यूरोपीयन यात्री डेविड लिविंग्स्टोन का गवाह है।
- ❼ इस लोकप्रिय पेड़ के भी छह तने जनवरी 2016 में गिर गए। बाओबाब पेड़ के अध्ययन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 'ट्री रिंग पद्धति' के बजाय नई रेडियोकार्बन तिथि तकनीक का इस्तेमाल किया गया।
- ❽ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 'ट्री रिंग पद्धति' बाओबाब के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसका तना अनिवार्य रूप से वार्षिक छल्लों का निर्माण नहीं करता है।

16 राज्यों का भूजल यूरेनियम से दूषित

- ❶ यूएस के ड्यूक विश्वविद्यालय की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत के 16 राज्यों का जलभृत (एक्विफर) का भूजल यूरेनियम से दूषित पाया गया है जो विश्व स्वास्थ्य

संगठन के मानक से कहीं अधिक है।

- ❷ अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भूजल, जो कि पेयजल एवं सिंचाई का मुख्य स्रोत है, में यूरेनियम का मिलना एक व्यापक परिघटना जैसी दिखती है। अध्ययन में कहा गया है कि राजस्थान के प्रत्येक तीन कुओं में से एक यूरेनियम से दूषित पाया गया।
- ❸ ज्ञातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पीने योग्य एक लीटर स्वच्छ जल में अधिकतम 30 माइक्रोग्राम यूरेनियम की सीमा तय कर रखा है।
- ❹ संयुक्त राज्य पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी का मानक भी इसी अनुरूप है। इसके बावजूद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्वच्छ जल मानकों में यूरेनियम को दूषित पदार्थों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

पेयजल में यूरेनियम का कारण

- ❶ भारत के कई जलभृत हिमालय से निकली धाराओं से बहकर आए मृदा, तलछट एवं कंकड़ों के अलावा यूरेनियम समृद्ध चट्टानों से निर्मित हैं।
- ❷ जब भी इन जलभृतों के भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाता है तब जल स्तर में गिरावट आ जाती है। यह ऑक्सीकरण की स्थिति को जन्म देता है जिससे बचे जल में यूरेनियम की समृद्धि को बढ़ा देता है।
- ❸ हालांकि यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत तो जियोजेनिक (प्राकृतिक रूप से निर्माण) है परंतु एंथ्रोपोजेनिक कारक (मानवीय कारक) इसकी सांद्रता में और अधिक वृद्धि कर देता है। मानवीय कारकों में शामिल है: भूजल टेबल में गिरावट और नाइट्रेट प्रदूषण।
- ❹ अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार जलभृत चट्टानों में यूरेनियम की उपस्थिति के लिए अग्रलिखित कारक जिम्मेदार हैं; चट्टान एवं जल का संपर्क जिससे इन चट्टानों से यूरेनियम निष्कर्षित हो जाता है, ऑक्सीकरण स्थिति जो निष्कर्षित यूरेनियम की जल में विलेयता बढ़ाती है।

जल संसाधन मंत्रालय व गूगल में समझौता

- ❶ केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने भारत में बाढ़ पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ के अनिवार्य संकेत प्राप्त हो रहे हों तो उपयोगकर्ता गूगल मानचित्र पर यह देखने में समर्थ हो सकेंगे कि किस क्षेत्र में जल जमाव अधिक है और कहीं उनका इलाका तो खतरे में नहीं है।
- ❷ अभी तक बाढ़ संबंधी पूर्व चेतावनी केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी किया जाता रहा है और यह चेतावनी बांध के पास खतरे के निशान के आधार पर जारी की जाती रही है। विगत

वर्ष ही आयोग ने तीन दिन अग्रिम में बाढ़ पूर्व चेतावनी देना आरंभ किया था।

- ☛ इसके अलावा अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी केंद्रीय जल आयोग को यह सूचना देता है कि किन क्षेत्रों में भारी वर्षा संभावित है और क्या इस वर्षा से नदी जल के बाहर आने की संभावना तो नहीं है।
- ☛ इसी के आधार पर बाढ़ चेतावनी जारी की जाती रही है। यहां गूगल मानचित्र इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह बाढ़ का दृश्यन स्वरूप प्रदान करेगा और लोग अपने क्षेत्र में जल स्तर को देख सकेंगे।
- ☛ बाढ़ चेतावनियां हेतु केंद्रीय जल आयोग एवं गूगल आपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, भू-स्थानिक मानचित्रण एवं जलविज्ञान पर्यवेक्षण डेटा विश्लेषण पर विशेषता साझा करेंगे। गूगल अर्थ इंजन बाढ़ प्रबंधन के दृश्यन व सुधार में मदद करेगा।

सांबा मसूरी चावल की नई रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित

- ☛ भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने संशोधित सांबा मसूरी चावल (Improved Samba Mahsuri-ISM) की नई रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित की है, जो बैक्टीरिया से होने वाली ब्लाइट बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी पायी गई है।
- ☛ चावल की फसल में होने वाले ब्लाइट रोग के लिए जैथोमोनास ओराईजे (Xanthomonas oryzae) नामक बैक्टीरिया को जिम्मेदार माना जाता है। इस बीमारी के कारण फसल उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होती है।
- ☛ बेहतर उपज देने वाली सांबा मसूरी की संशोधित प्रजाति में पहले से ब्लाइट रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है, पर वैज्ञानिकों ने अब एक नए जीन एक्स 38 को उसमें सम्मिलित किया है, जिससे फसल की प्रतिरोधक क्षमता पहले से अधिक हो गई है।

जैथोमोनास

- ☛ जैथोमोनास एक खतरनाक बैक्टीरिया है, जो बेहद तेजी से फैलता है और फसल को अपनी चपेट में ले लेता है।
- ☛ यह फसल को कुछ इस तरह प्रभावित करता है कि पौधे देखने में रोग प्रतिरोधी लगते हैं, पर कुछ समय बाद उनमें बीमारी के लक्षण उभरने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, ऐसा बैक्टीरिया के रूपांतरण के कारण होता है।

क्लोरोफिल-A: प्रकाशसंश्लेषण की नई प्रक्रिया

- ☛ अब तक हम यही पढ़ते रहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के

लिए जल, श्वेत प्रकाश और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है परंतु हाल में विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित एक शोध आलेख के अनुसार कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सफेद प्रकाश की नहीं बल्कि लाल प्रकाश का उपयोग करते हैं।

- ☛ दृश्य प्रकाश या सफेद प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है और अब तक पादपविज्ञानी या जीवविज्ञानी यही मानते रहे हैं कि सभी पौधे लाल प्रकाश (680 से 700 नैनोमीटर) का उपयोग ऑक्सिजनिक प्रकाशसंश्लेषण के लिए करते हैं।
- ☛ नए अध्ययन के मुताबिक कई सायनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल अधिक लाल प्रकाश या 750 के अवरक्त प्रकाश में प्रकाशसंश्लेषण की क्रिया करते हैं।
 - अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि ये सायनोबैक्टीरिया प्रकाशसंश्लेषण के दौरान एक अलग प्रकार के क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं।
 - सभी प्रकाश संश्लेषक सजीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल-A का उपयोग करते हैं परंतु शोधकर्ताओं ने पाया कि जब सायनोबैक्टीरिया को अवरक्त प्रकाश में उगाया गया तब क्लोरोफिल-A ने काम करना बंद कर दिया और उसकी जगह क्लोरोफिल-F ने वही काम किया।
 - क्लोरोफिल-एफ को पहले प्रकाश के सृजन में मददगार माना जाता था परंतु अब जाकर यह पाया गया है कि छायांकित माहौल में प्रकाश संश्लेषण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
 - शोध से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की ऐसी प्रक्रिया की खोज करना जो लाल रंग सीमा से परे काम करे, प्रकाशसंश्लेषण के लिए ऊर्जा आवश्यकता के बारे में हमारी समझ में बड़ा परिवर्तन लाता है।
 - इस प्रकार प्रकाशसंश्लेषण की नई प्रक्रिया की खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि समझी जा सकती है क्योंकि यह प्रक्रिया पूरे विश्व को भोजन प्रदान कराने वाले फसल के जीव विज्ञान में महती भूमिका निभाती है।

अटल भूजल योजना (ABY)

- ☛ अटल भूजल योजना, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। विश्व बैंक ने 6000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को अनुमति प्रदान कर दी है। यह योजना विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पांचवर्षीय कालावधि में कार्यान्वित किया जाना है।
- ☛ देश के बड़े भाग में भूजल संसाधनों की गंभीर कमी दूर

करने के लिये अटल भूजल योजना की तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य देश में प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है। योजना के अंतर्गत गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को प्राथमिकता में रखा गया है।

- ❶ ये राज्य देश में भूजल के मामले में अत्यधिक दोहन, संकटमय एवं अर्द्ध संकटमय क्षेत्रों का लगभग 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ❷ साथ ही ये राज्य भारत में पाये जानी वाली दो बड़े प्रकार की भूजल प्रणालियों-जलोढ़ एवं हार्ड रॉक जलभृत को कवर करते हैं एवं भूजल प्रबंधन में सांस्थानिक तैयारी एवं अनुभव के मामले में यह आत्मनिर्भर है।
 - यह योजना पहचान किये गए प्राथमिक क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देकर प्रदेशों में जारी मौजूदा सरकारी योजनाओं के सम्मिलन की सुविधा भी प्रदान करेगी।
 - योजना के क्रियान्वयन से इन प्रदेशों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने की आशा है। योजना के अंतर्गत धनराशि अनुदान के रूप में भागीदारी करने वाले प्रदेशों को उपलब्ध करा दी जाएगी।
 - भूजल प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना योजना के बड़े उद्देश्यों में शामिल है।
 - योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे वॉटर यूजर एसोसिएशन, भूजल के आंकड़ों की निगरानी एवं वितरण, जलसंबंधी आय-व्ययक, ग्राम पंचायतों के अनुरूप जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी व कार्यान्वयन एवं चिरस्थायी जल प्रबंधन से संबंधित IEC गतिविधियों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी प्रस्तावित की गई है।

गंभीर जल संकट-नीति आयोग

- ❶ नीति आयोग द्वारा 14 जून, 2018 को जारी 'संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक' (Composite Water Management Index - CWMI) के मुताबिक भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की 60 करोड़ आबादी जल की गंभीर कमी का सामना कर रही है।
- ❷ भूजल संसाधन जो कि देश की जलापूर्ति में 60 प्रतिशत का योगदान करता है, असततीय दर से नीचे गिर रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि जैसे राज्य भारत की 60 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इन राज्यों में जल का कुप्रबंधन आगे चलकर भारत के लिए संकट की स्थिति ला सकता है।
- ❸ देश के तीन चौथाई परिवारों को उनकी चारदीवारी में पेयजल

उपलब्ध नहीं है। अर्थात् इन्हें पीने के पानी हेतु अपनी चारदीवारी से बाहर निकलना होता है। यही नहीं, जो जल है भी उसका 70 प्रतिशत दूषित है।

- ❶ सूचकांक में यह भी कहा गया है कि साफ जल तक अपर्याप्त पहुंच के कारण भारत में लगभग दो लाख लोग प्रतिवर्ष काल के गाल में समा जाते हैं। जैसे-जैसे भारत में आबादी बढ़ रही है वैसे-वैसे जल की मांग भी बढ़ने वाली है।
- ❷ नीति आयोग का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक जल आपूर्ति की तुलना में मांग दोगुणा होने के आसार हैं। सूचकांक के अनुसार देश का 54 प्रतिशत भूजल कूपों का स्तर नीचे जा रहा है। इसी तरह 21 बड़े शहर 2020 तक भूजल से रहित हो जाएंगे जिससे 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।
- ❸ जल संकट के कारण वर्ष 2050 तक देश की 6 प्रतिशत GDP समाप्त हो जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध जल के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होगी और इसके लिए बेहतर रणनीति की भी जरूरत होगी।
- ❹ यह रणनीति, खासतौर से राज्य सरकारों को विशेष रूप से बनानी होगी क्योंकि आखिरकार जल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सूची का विषय है।
- ❺ इस सूचकांक में जल संसाधन के कुशल प्रबंधन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को आंका गया है जिसके आधार पर वे भविष्य में इसमें सुधार कर सकेंगे। नीति आयोग के मुताबिक यह सूचकांक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों को जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करने में भी मदद कर सकता है।
- ❻ सूचकांक में कुशल जल प्रबंधन के मामले में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग 2016-17 के अध्ययन के आधार पर की गई है। जल संसाधन के कुशल प्रबंधन के लिए गुजरात को सर्वोच्च रैंकिंग दी गई है जबकि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं असम क्रमशः दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर है।
- ❼ हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि जल संसाधन के कुशल प्रबंधन के मामले में नीति आयोग के जिस सूचकांक में हिमाचल प्रदेश को बेहतर रैंकिंग प्रदान की गई है उसी की राजधानी शिमला इन दिनों गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
- ❽ इस सूचकांक में विभिन्न राज्यों की रैंकिंग निर्धारण के लिए 9 बड़े क्षेत्रों एवं 28 विभिन्न संकेतकों को आधार बनाया गया है। इनमें शामिल हैं: भूजल, जल निकायों का जीर्णोद्धार, सिंचाई, कृषि प्रक्रियाएं, पेयजल, नीति एवं शासन। सूचकांक में जल संसाधन के कुशल प्रबंधन के लिए शून्य से 100 स्कोर दिए गए हैं जिनमें 100 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है।
- ❾ गुजरात जिसे सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान की गई है, उसका स्कोर

76 है। वैसे अधिकांश राज्यों का स्कोर 50 से नीचे ही है जो यह दर्शाता है कि जल संसाधन के कुशल प्रबंधन में राज्य काफी पीछे हैं।

- दूसरी ओर पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में केवल त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश का ही स्कोर 50 से ऊपर है। इस सूचकांक में जो चिंताजनक पहलू है, वह यह कि देश के जिन राज्यों में अधिक आबादी निवास करती है वे जल प्रबंधन के मामले में काफी पिछड़े हैं।
- बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का स्कोर 38-38 है। यह गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है।

राष्ट्रीय योजनाएं एवं कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया।
- मुद्रा का अर्थ है सूक्ष्म इकाइयां विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड।
- इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता सहित अन्य सहायता के माध्यम से देश में सूक्ष्म उद्यमों का विकास है।
- वैसे बिना गारंटी के आसान कर्ज की सुविधा प्रदान कर युवाओं में उद्यमिता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
- इस योजना के तहत गैर-कार्पोरेट लघु व्यवसाय सेक्टर को तीन श्रेणियों के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। ये तीन श्रेणियां हैं; शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक) तथा तरुण (5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक)।
- योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के सभी कर्ज को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रूप में प्रदान किया जाता है।
- मुद्रा बैंक की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सोसायटी के रूप में तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में हुई है।
- आरंभ में इसकी स्थापना भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई है जिसमें 100 प्रतिशत पूंजी इसी की लगी हुई है। इसकी प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये है तथा पेड अप कैपिटल 750 करोड़ रुपये है।
- यह योजना आरंभ की गई है तब से जनवरी 2018 तक 10.38 करोड़ मुद्रा ऋण में से 4.6 लाख रुपये अनुशंसित किए गए हैं। 76% ऋण खाते महिलाओं के हैं और 50% से अधिक खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (SC/ST) एवं ओबीसी (OBC) के हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 1 अप्रैल, 2016 को आरंभ हुई।
- इस योजना को पूर्व की योजनाओं यथा; राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (NAIS), मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (MANIS) को मिलाकर आरंभ किया गया था।
- यह मांग संचालित स्कीम है इसलिए इस हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वैसे कृषि मंत्रालय के अनुसार 2018-19 के दौरान कुल फसल क्षेत्र कवरेज को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
- इस योजना का क्रियान्वयन 2017-18 के दौरान 18 सामान्य बीमा कंपनियों सहित सभी पांच सरकारी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।
- PMFBY के अंतर्गत किसानों द्वारा अधिकतम एकरूप प्रीमियम खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा सभी रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा अधिकतम सिर्फ 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
- इस योजना को प्रौद्योगिकी आधारित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य किसानों के दावों के भुगतान में होने वाली विलंब को कम करना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- इसका उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करने तथा हर खेत को पानी के उद्देश्य के साथ सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दीर्घावधिक समाधान तैयार करना है।
- जल संसाधन मंत्रालय सहित तीन मंत्रालयों द्वारा मिशन मोड में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस स्कीम को 50,000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) के लिए अनुमोदित किया गया था।
- PMKSY का मुख्य उद्देश्य फील्ड स्तर पर सिंचाई के क्षेत्र में निवेश के अवसर प्राप्त करना, आवश्यक सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना, पानी के दुरुपयोग को कम करने के लिए फार्म पर पानी के उपयोग क्षमता में सुधार लाना, सुव्यवस्थित सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) के उपयोग को बढ़ाना और संधारणीय जल संरक्षण अभ्यासों आदि को बढ़ावा देना है।
- यह मिशन मोड की परियोजना है जिस पर मंत्रिमंडल

द्वारा जुलाई, 2016 में निर्णय लिया गया।

- यह मिशन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (DAC & FW) द्वारा प्रशासित प्रति बूंद अधिक फसल घटक के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा संचालित है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

- यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है।
- इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रारंभिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है जिससे उन्हें बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद मिले।
- योजना के पहले वर्ष (2015-2016) को इस योजना के नींव को पुख्ता बनाने और आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तब से यह योजना नियोजितों, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति का एक प्रमुख स्रोत रहा है।
- वर्ष 2016-20 के लिए एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना के तहत किसी व्यक्ति के कौशल का मूल्यांकन 'रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग' (Recognition of Prior Learning: RPL) के तहत किया जाता है।
- इस स्कीम के तहत सेक्टर विशेष परिषदों की स्थापना की गई है। जैसे कि; हरित रोजगार के लिए कौशल परिषद्, टेलिकॉम क्षेत्रक कौशल परिषद्, टेक्सटाइल क्षेत्रक कौशल परिषद्, पर्यटन व सत्कार क्षेत्रक कौशल परिषद्।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Programme: NRDWP), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः निजी आपूर्ति के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहायता देना है। इसे वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था।
- 10 नवंबर, 2017 को इसके संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई थी। संशोधित योजना में कार्यक्रम की निधि का 2% जापानी इन्सेफलाइटिस/एईएस प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवंटित किया जाएगा।

- इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत फरवरी 2017 में एक उप-कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसका नाम है 'राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन' (National Water Quality Sub-Mission: NWQSM), जिसके तहत आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित 28,000 बस्तियों में त्वरित आधार पर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, खासकर निजी भुगतान के लिए कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस संचालित करने हेतु प्रशिक्षण करना है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

- प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को आरंभ हुई थी।
- PMJDY के लक्ष्यों को प्राप्त करने के 6 मुख्य स्तंभ निर्धारित किये गये थे: पहले चरण (15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त 2015) में पहले वर्ष के क्रियान्वयन के तहत तीन मुख्य स्तंभ थे; बैंकिंग सुविधाओं तक सब की पहुंच सुनिश्चित करना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम व 6 महीने बाद रुपये 5000 की ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंक खाते और एक लाख रुपये के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपया डेबिट कार्ड और रु-पे किसान कार्ड सुविधा प्रदान करना।
- दूसरे चरण (15 अगस्त, 2015 से 15 अगस्त, 2018) में भी तीन लक्ष्य रखे गए; ओवर ड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना, सूक्ष्म बीमा व स्वावलम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत कुल खाते जनवरी 2015 में 12.55 करोड़ से बढ़ाकर 16 अगस्त, 2017 को 29.52 करोड़ हुई।
- रुपए कार्ड जारी करने की संख्या जनवरी 2015 में 11.08 करोड़ से बढ़कर 16 अगस्त, 2017 को 22.17 हुई।
- लाभार्थी खातों में कुल देय राशि 65,844.68 करोड़ व प्रति खाते में औसत देय राशि जनवरी 2015 में 837 रुपये से बढ़कर 16 अगस्त, 2017 को 2231 रुपये हुई।
- इसके अन्तर्गत कुल शून्य राशि खातों की संख्या सितम्बर 2014 में 76.81 प्रतिशत से घटकर अगस्त, 2017 में 21.41 प्रतिशत हुई।

- मार्च 2014 में, 33.69 करोड़ की राशि के साथ महिलाओं के बचत खातों की संख्या 28 प्रतिशत थी। मार्च 2017 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आर.आर.बी व 40 शीर्ष बैंकों के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का योगदान 40% हो गया।
- महिलाओं के कुल 43.65 करोड़ खातों में से महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत 14.49 करोड़ खाते खोले गए।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

- केंद्र सरकार ने 23 अगस्त, 2017 को 'कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना' यानी 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।
- 14वें वित्त आयोग चक्र की वह-समाप्ति के साथ वर्ष 2016-20 तक की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से इस स्कीम की शुरुआत की गई है।
- इस स्कीम का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश के होने, 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा।
- इससे देश में ना केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि की तीव्र गति प्राप्त होगी बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दुगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत अग्रलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा; मेगा खाद्य पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना,

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन एवं संस्थान।

स्टार्ट अप इंडिया स्कीम

- भारत सरकार ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 16 जनवरी, 2016 को स्टार्ट अप इंडिया स्कीम आरंभ किया था। इसकी कार्यवाही योजना का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
- स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार पोषण का मजबूत माहौल व स्टार्ट अप का निर्माण करना है जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करे।
- पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्टार्ट अप को 'सफेद' श्रेणी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि ये अनुपालन (श्रम एवं पर्यावरणीय कानूनों के मामलों में) को स्व-प्रमाणित कर सकेंगे और कभी-कभार ही इनकी जांच हो सकेगी।
- इस स्कीम के तहत प्रश्नोत्तरी के लिए स्टार्ट अप इंडिया हब वित्तीयन के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड्स की स्थापना की गई है।

क्या है स्टार्ट अप

- DIPP के अनुसार स्टार्ट अप से आशय है भारत में पंजीकृत या निगमित ऐसी इकाई जो
 1. सात वर्षों के भीतर निगमित/पंजीकृत हुई हों, प्रौद्योगिकी सेक्टर के मामले में 10 वर्ष के भीतर निगमित/पंजीकृत हुई हों,
 2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या साझेदारी कंपनी अथवा सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में पंजीकृत हुई हों,
 3. निगमन/पंजीकरण तिथि से अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।
 4. नवाचार, विकास या उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया में काम करती हो।

स्टैंड अप इंडिया स्कीम

- इस स्कीम की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को हुई।
- इस स्कीम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य तथा एक महिला को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की सुविधा प्रदान किया जाता है।

- उपर्युक्त कर्ज व्यापार, सेवा या विनिर्माण सेक्टर में ग्रीनफील्ड उद्यम लगाने के लिए प्रदान किया जाता है।
- इस स्कीम से 2.5 लाख लोगों के लाभान्वित होने का लक्ष्य रखा गया है।

इम्प्रिंट इंडिया स्कीम

- इम्प्रिंट इंडिया अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने का कार्यक्रम (IM Pacting Research Innovotaion and Technology- IMPRINT INDIA) केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय पहल है जिसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 05 नवंबर, 2015 को आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य, राष्ट्र द्वारा समावेशी प्रगति तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आ रही मुख्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में चयनित व्यवहार्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अंतरण करना है
- यह अनुसंधान की कार्य योजना बनाने के लिए PAN-IIT और IISC का संयुक्त पहल है। इम्प्रिंट पहलों पर फोकस करने वाले विषय हैं; स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, स्थायी आवास, नैनो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, जल संसाधन और नदी प्रणाली, उन्नत सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सुरक्षा और अभिरक्षा, पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन।
- IIT कानपुर इस पहल का राष्ट्रीय समन्वयक है।
- केंद्र सरकार ने इम्प्रिंट इंडिया-2 के लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए हैं।

उन्नत भारत अभियान (VBA)

- यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी खाई को पाटने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में आधारभूत ज्ञान के प्रयोग के लिए उन्नत भारत अभियान प्रारंभ किया गया है।
- इसके तहत सभी तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में से प्रत्येक को 5 गांवों को गोद लेने के लिए; ऐसे नवाचार के लिए योजना तैयार करने और प्रौद्योगिकी अंतर की पहचान करने जो ग्रामीण क्षेत्रों में आय और विकास में निरंतर रूप से वृद्धि कर सके, के लिए कहा गया है।
- भारत में देश के 750 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है।
- IIT दिल्ली को इस अभियान के लिए राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है।
- 25 अप्रैल, 2018 को उन्नत भारत अभियान 2.0 आरंभ

किया गया।

- इस अभियान के तहत देश के 45000 गांवों को शामिल किया जाना है।

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना (PMRF)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस शोध योजना को केंद्र सरकार ने 7 फरवरी, 2018 को मंजूरी प्रदान की।
- सात वर्षों की इस योजना में 1650 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
- IISC/IIT/NIT/IISER से बी-टेक या एकीकृत एम-टेक/एम.एस.सी.का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले या अंतिम वर्ष के लगभग 1,000 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को इस योजना के तहत IIT/IISC में पीएचडी कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा।
- इन छात्रों को पहले दो वर्षों के दौरान प्रति माह 70,000 रुपये की फेलोशिप, तीसरे वर्ष के दौरान प्रत्येक माह 75,000 रुपये और चौथे तथा पांचवें वर्ष के दौरान प्रतिमाह 80,000 रुपये की फेलोशिप दी जाएगी।
- इसके अलावा पांच सालों के प्रत्येक शोधार्थी को दो लाख रुपये अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलनों में हिस्सा लेने और शोध प्रबंध लिखने में सहायता हो।
- वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाली तीन वर्षीय अवधि के लिए अधिकतम तीन हजार शोधार्थियों को चुना जाएगा।
- प्रत्येक अध्येता को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 की अवधि से प्रारंभ 3 वर्ष में अधिकतम 3000 लोगों का चयन किया जाएगा।

नमामि गंगे स्कीम

- केंद्र सरकार ने 13 मई, 2015 को नमामि गंगे फ्लैगशिप स्कीम को मंजूरी प्रदान की थी।
- यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत समन्वित गंगा संरक्षण मिशन है। इस स्कीम का उद्देश्य गंगा नदी को साफ करने तथा सुरक्षित करने के विभिन्न प्रयासों को समन्वित करना है।
- पांच वर्षों के लिए इस स्कीम हेतु 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- पूर्व के अनुभवों से सीख लेते हुए इस स्कीम के तहत सतत परिणाम प्राप्त करने हेतु गंगा किनारे रहने वाले लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। स्थानीय

- भागीदारी के लिए गंगा प्रहरी नियुक्त किए जा रहे हैं।
- इसके अलावा संबंधित राज्य, जमीनी संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं को भी इस स्कीम का हिस्सा बनाया गया है।
- इस मिशन का क्रियान्वयन स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Clean Ganga: NMCG) के द्वारा किया जा रहा है।
- क्रियान्वयन में सुधार के लिए त्रिस्तरीय तंत्र है; 1. राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला उच्च स्तरीय कार्यदल, 2. राज्य स्तर पर राज्य कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी व 3. जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी।
- स्कीम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस स्कीम के सभी प्रयासों या परियोजनाओं का 100% निधि केंद्र सरकार कर रही है।
- इस स्कीम के तहत 2015-16 व 2017-18 के बीच 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण पूरा किया जा चुका है और आरंभ हो चुका है।

आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन

- आयुष्मान भारत, भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है जिसकी घोषणा 1 फरवरी, 2018 को पेश केंद्रीय बजट में की गई थी।
- केंद्रीय कैबिनेट ने 21 मार्च, 2018 को इस योजना को मंजूरी प्रदान की थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2018 को डॉ. अंबेडकर की जयंती पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत के तहत प्रथम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर आयुष्मान भारत मिशन-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन यानी 'AB-NHPM' (Ayushman Bharat - National Health Protection Mission) को औपचारिक तौर पर आरंभ किया था।
- इस योजना में पूर्व की प्रायोजित योजनाओं-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) को समाहित कर दिया गया है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्कीम है।
- योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है तथा प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपये का लाभ कवर प्रदान किया जाना है।
- इस कवर में सभी द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस योजना का लाभ

पूरे देश में मिलेगा और योजना के अंतर्गत कवर किये गये लाभार्थी को पैनेल में शामिल देश के किसी भी सरकारी/निजी अस्पताल से नगदरहित (कैशलेस) लाभ लेने की अनुमति होगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यक्ति (महिलाएं, बच्चे तथा वृद्धजन) छूट ना जाए, इसलिए योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी।
- यह AB-NHPM पात्रता आधारित योजना है और पात्रता SECC डाटा बेस में अपवचना मानक के आधार पर तय की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा हो, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, ऐसे परिवार जिसकी मुखिया महिला है और जिसमें 16 से 59 आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसा परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य है और कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।
- अजा/जजा परिवार, मानवीय आकस्मिक मजदूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार स्वतः शामिल किये गये हैं जिनके रहने के लिए छत नहीं है, निराश्रित, खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए गये बंधुआ मजदूर हैं।
- इस स्कीम के तहत नीति निर्देश देने तथा केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय में तेजी लाने के लिए शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद (AB-NHPMC) गठित करने का प्रस्ताव है।
- मिशन के तहत 'आयुष्मान भारत राष्ट्रीय, स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन गवर्निंग बोर्ड' (AB-NHPHGB) गठित किया जाना है जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) तथा सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग द्वारा की जाएगी। आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के सीईओ सदस्य सचिव होंगे।

पोषण अभियान

- केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय के पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिला से किया गया। इस अभियान के तहत तीन वर्षों

के लिए 9046.15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस अभियान के तहत ही ई-आईएलए (e-ILA: e-Incremental Learning Approach) की भी शुरुआत की गई है जो कि एक ऑनलाइन प्रणाली है जहां कार्यक्रम कार्यकर्ता योजना के बारे में प्रभावी तरीके से जान सकेंगे व प्रत्येक कार्य का सटीक तरीके से क्रियान्वयन कर सकेंगे। इस अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं;

1. बौनापन (stunting) में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कमी,
 2. कुपोषण (under-nutrition) में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कमी,
 3. एनीमिया की शिकार किशोरों, किशोरियों एवं महिलाओं में प्रतिवर्ष 3% की कमी,
 4. कम वजन युक्त बच्चों के जन्म (low birth weight) में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कमी।
- इस मिशन का लक्ष्य 0-6 आयु समूह के बच्चों में बौनापन को मौजूदा 38.4% से वर्ष 2022 तक 25% करना है।

मोडिफाईड स्पेशल इनसेंटिव पैकेज स्कीम

- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने तथा पंगुता को समाप्त करने के लिए 27 जुलाई, 2012 को 'मोडिफाईड स्पेशल इनसेंटिव पैकेज स्कीम' (Modified Special Incentive Package Scheme: M-SIPS) अधिसूचित की गई।
- यह स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग (ESDM) में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराती है।
- यह स्कीम पूंजीगत व्यय पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है-विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश पर 20 प्रतिशत एवं गैर-विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश पर 25 प्रतिशत।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 18 जनवरी, 2017 को इस स्कीम में संशोधन किया ताकि वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के 'शुद्ध शून्य आयात' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- इस संशोधन का लक्ष्य रोजगार सृजन एवं आयात पर निर्भरता कम करना है।

रूबसिस-रबर मृदा सूचना प्रणाली

- रबर मृदा सूचना प्रणाली यानी रूबसिस (Rubber soil Information System: RubSIS) एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसके द्वारा रबर उत्पादकों के लिए विशेषीकृत बागवानी हेतु मृदा के अनुरूप उर्वरकों के उचित मिश्रण का सुझाव दिया जाता है।

- इस प्रणाली की शुरुआत 23 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में हुई थी।
- इसका विकास रबर बोर्ड के अधीन भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है।
- रबर उत्पादक मृदा के सतत एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए यह लागत प्रभावी उपकरण है।
- रासायनिक उर्वरकों के अविवेकी उपयोग एवं मृदा अवनयन को रोकने के अलावा रूबसिस से उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है, उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी की जा सकती है।

'मिशन 41K'

- रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे की ऊर्जा संबंधी पहलों पर बाह्य हितधारकों के साथ गोलमेज परिचर्चा के दौरान 'मिशन 41के' का प्रस्ताव रखा।
- इसके तहत रेल मंत्रालय ने अगले दशक में रेलवे की ऊर्जा लागत में 41,000 करोड़ रुपये की बचत करने के लिए 'मिशन 41K' तैयार किया है। विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ इस व्यापक रणनीति पर अमल के लिए नियामकीय रूपरेखाओं से लाभ उठाया जाएगा और नई प्रौद्योगिकियों पर गौर किया जाएगा।
- भारतीय रेलवे ने 1000 मेगावाट सौर बिजली और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है।
- कुल माल ढुलाई के 45 फीसदी को ढोने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब इससे ढुलाई करना किफायती साबित होगा। इसके परिणामस्वरूप रेलवे अब सड़क क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी है। मौजूदा समय में 70 फीसदी ढुलाई बिजली कर्षण (विद्युत ट्रैक्शन) पर होती है। अगले 6-7 वर्षों में 90 फीसदी ढुलाई विद्युत ट्रैक्शन पर करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- खुली पहुंच के जरिये बिजली की खरीद सुनिश्चित करने से विद्युत खरीद की लागत काफी कम हो गई है, जिसका संचालन व्यय में 25 फीसदी हिस्सा होता है।

उड़ान (उड़े देश का आम आदमी) स्कीम

- यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम है।
- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2016 को उड़ान (UDAN) नामक स्कीम आरंभ किया था।
- इस स्कीम के दो उद्देश्य हैं: संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा आम लोगों के लिए वहनीय हवाई यात्रा।

- यह योजना, जो 15 जून, 2016 को जारी राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का मुख्य घटक रही है, आगामी दस वर्षों के लिए परिचालन में रहेगी।
- योजना के तहत वैसे क्षेत्रों के हवाई मार्गों एवं हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाना है जहां हवाई कनेक्टिविटी नहीं है या कम है।
- ऐसे मार्गों पर कम लागत में आम लोगों को हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उड्डयन सेवा प्रदाताओं कंपनियों को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय राहत पैकेज प्रदान की जाती है। इसके अलावा बायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत सहायता दी जा रही है।
- स्कीम के तहत फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट पर लगभग 500 किलोमीटर की एक घंटा की यात्रा पर या हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपये होगी।

लीन विनिर्माता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम

- लीन विनिर्माता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम (Lean Manufacturing Competitiveness Scheme: LMCS) सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय के 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, 'एनएमसीपी' (National Manufacturing Competitiveness Programme: NMCP) का भाग है।
- यह स्कीम लीन विनिर्माण अवधारणा की मदद से बर्बादी में कमी के द्वारा MSME की संपूर्ण उत्पादकता में सुधार का लक्ष्य लेकर चलती है।
- यह स्कीम वर्ष 2009 में 100 क्लस्टर में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर आरंभ की गई थी। बाद में इसका विस्तार 500 और क्लस्टर में कर दिया गया।
- इस स्कीम के आरंभ से ही राष्ट्रीय निगरानी एवं क्रियान्वयक इकाई के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल) जुड़ा हुआ है।

'नारी पोर्टल'

- यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी, 2018 को आरंभ किया गया वेब पोर्टल है। इसका शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमति मेनका गांधी ने किया।
- इस पोर्टल के माध्यम से महिलाओं के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं एवं अभियानों से संबंधित सूचनाओं तक भारत की महिलाओं की सुगम पहुंच होगी।
- इस पोर्टल पर महिलाओं को केंद्रित केंद्र एवं राज्य, दोनों की योजनाओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी।

- इस पोर्टल से महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली मुद्दों के बारे में भी सूचनाएं मिल सकेंगी।

रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2018 को किशोरी लड़कियों की योजना के लिए रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (Rapid Reporting System for the Scheme for Adolescent Girls) का लाभार्थी मॉड्यूल जारी किया।
- यह मॉड्यूल SAG के लिए वेब आधारित ऑनलाइन मॉनिटरिंग है।
- RRS, आलोच्य स्कीम की निगरानी करने में मदद करेगी जिससे स्कीम को बेहतर तरीके से क्रियान्वित की जा सकेगी, वास्तविक लाभार्थी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, रिसाव को भी कम करने में मदद मिलेगी।
- ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने 16 नवंबर, 2017 को स्कूल से बाहर की किशोरी लड़कियों (11-14 वर्ष, जो कि विकास की दूसरी अवस्था होती है) की बहु-आयामी आवश्यकताओं के मद्देनजर ऐसी लड़कियों को स्कूल में दाखिले के लिए 'किशोरी लड़कियों की स्कीम' को जारी रखने को मंजूरी दी थी।
- इस स्कीम का उद्देश्य 11-14 वर्ष की किशोरी लड़कियों को एक वर्ष में 300 दिनों के लिए 9.50 रुपये/लाभार्थी/दिन का पोषण प्रदान करना है ताकि स्कूल से बाहर की किशोरियों को औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने या कौशल प्रशिक्षण केंद्र जाने के लिए प्रेरित की जा सके।
- इस स्कीम का संचालन समन्वित बाल विकास सेवा स्कीम (ICDS) के तहत किया जा रहा है।
- इस स्कीम के तहत पोषण सहायता के अलावा किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता पर सूचनाएं एवं मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- जनवरी 2018 में यह स्कीम देश के 508 जिलों में संचालित की जा रही थी। 2018-19 में देश के सभी जिलों में इसे लागू किया जाना है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम (SHC)

- यह केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय की स्कीम है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के सुरतगढ़ में इस स्कीम की शुरुआत की थी।
- इस स्कीम के तहत किसानों को उनकी खेत की मिट्टी के पोषण स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें मिट्टी के स्वास्थ्य व उर्वरता में सुधार के लिए

आवश्यक पोषक तत्वों की खुराक से संबंधित परामर्श भी दी जाती है।

- किसानों को मृदा की प्रकृति के बारे भी बताई जाती है।
- किसी खेत के लिए प्रति दो वर्षों पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी की जाती है जिससे उस खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर बराबर निगरानी रखी जा सके।
- इस स्कीम के प्रथम चरण (2015-17) में कुल 10 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके थे। इसके दूसरे चरण की शुरुआत 1 मई, 2017 को हुई जो 2019 तक चलेगी।
- मृदा में परिवर्तन पर नजर के लिए इस स्कीम के तहत (GPS) आधारित नमूना संग्रहण को अनिवार्य किया गया है।

परम्परागत कृषि विकास योजना

- इस स्कीम को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के विस्तारित घटक के रूप में 1 अप्रैल, 2015 को शुरू किया था। इस स्कीम के तहत क्लस्टर आधारित और प्रमाण के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली के द्वारा जैविक ग्राम को गोद लेकर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है।
- इस स्कीम के तहत वर्ष 2018-19 तक 20 हेक्टेयर भूमि के 50,000 समूहों को गठित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसमें जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य है।
- इसमें शामिल विभिन्न घटक हैं: एकत्रण, किसानों का प्रशिक्षण और किसान ज्ञानार्जन यात्राएं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

- यह कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय का मिशन है।
- इसे वर्ष 2007-08 में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि; मृदा उर्वरता और उत्पादकता पुनरुद्धार; रोजगार अवसर सृजन; और फार्म स्तर की अर्थव्यवस्था की वृद्धि द्वारा 11वीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दलहनों की उपज क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन (कुल 20 मिलियन टन) तक बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस मिशन में मोटे अनाज को भी शामिल कर लिया गया तथा बारहवीं योजना के अंत तक 25 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- बारहवीं योजना के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में NFSM को 29 राज्यों के 638 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की महापरिषद (जीसी) का गठन NFSM के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने और मध्यावधि सुधार कार्य करने के प्रयोजनार्थ नीति निर्धारण हेतु किया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हरित क्रांति योजना

- वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKY) नाम की उप स्कीम इस आशय के साथ शुरू की गई थी ताकि सात (7) राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल वाले पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रणालियों की उत्पादकता को सीमित करने वाले अवरोधों को दूर किया जाए।
- वर्ष 2014-15 तक कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूर्णतः भारत सरकार की सहायता से किया गया।
- वर्ष 2015-16 से इस कार्यक्रम को भारत सरकार और राज्यों के बीच 60:40 तथा पूर्वोत्तर राज्य (असम) में 90:10 के आधार पर साझा करते हुए कार्यान्वित किया जा रहा है।

समेकित बागवानी मिशन

- 12वीं योजना के दौरान वर्ष 2014-15 से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने बागवानी से संबंधित स्कीमों यथा
 1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM),
 2. पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (HMNEH),
 3. राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM),
 4. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB),
 5. नारियल विकास बोर्ड (CDB),
 6. केन्द्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड को मिलाकर एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) शुरू किया है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)

- यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2005-06 में इस आशय के साथ शुरू की गई थी कि सभी स्टोकहोल्डर्स की सक्रिय प्रतिभागिता के साथ समूहगत प्रयास के माध्यम से समग्र संबंध सुनिश्चित करके समग्र बागवानी क्षेत्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए।
- NHM के तहत 19 राज्य और 04 संघ राज्य क्षेत्रों के 384 जिलों को शामिल किया गया।
- 16 राष्ट्रीय स्तर के अभिकरणों (NLA) को भी उन

विकासगत प्रयासों के सहायतार्थ शामिल किया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आदानों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (NABM)

- पूरे देश में वर्ष 2006-07 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम DACADFW आरंभ की गई। यह वर्ष 2014-15 के दौरान समेकित बागवानी विकास (MIDH) के लिए मिशन के अंतर्गत लाई गई और जुलाई, 2015 में इसका नाम राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (NABM) कर दिया गया।

राष्ट्रीय बांस मिशन

- यह वर्ष 2006-07 में एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के तौर पर आरंभ हुई थी। इसे वर्ष 2014-15 में समेकित बागवानी मिशन नामक स्कीम में शामिल कर लिया गया।
- हालांकि यह मिशन वर्ष 2015-16 तक जारी रही।

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP)

- ऑयल पाम और वृक्षजनित तिलहन (TBO) सहित तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए तिलहन के महत्व पर विचार करते हुए भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP) का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें 2014-15 से 3 मिनी मिशन (एमएम) तिलहन (एमएम-I), ऑयल पाम (एमएम-II) और टीबीओ (एमएम-III) शामिल है।
- NMOOP योजना का कार्यान्वयन सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60:40 और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार के बीच व्यय को साझा करने के आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) उन आठ कृषि मिशनों में से एक है जिसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के तहत तैयार किया गया है।
- इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि के दस मुख्य आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 17 प्रदेशों के माध्यम से कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- इस मिशन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं;

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास:

- इसके तहत जलवायु परिवर्तन की स्थिति में उत्पादकता में वृद्धि करने और जोखिमों को कम करने के लिए

समेकित कृषि पद्धति (IFS) पर ध्यान दिया जाता है।

- इस प्रणाली के अंतर्गत फसल/फसलन प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मात्स्यिकी, कृषि- वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि जैसे कार्यकलापों से जोड़ा जाता है ताकि ना केवल किसानों को आजीविका को बनाए रखने के लिए फार्म लाभों को अधिकतम किया जा सके।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन:

- इसका उद्देश्य बृहत-सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन एवं भू-प्रकारों पर आधारित उपयुक्त भू-उपयोग के साथ-साथ मृदा उर्वरता मानचित्रों के सृजन एवं समेकन द्वारा अवशेष प्रबंधन, जैविक कृषि प्रणालियों सहित स्थान विशिष्ट व साथ ही फसल विशिष्ट सतत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना-सौभाग्य

- यह स्कीम केंद्रीय विद्युतीकृत मंत्रालय की स्कीम है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर, 2017 को आरंभ किया गया।
- इस स्कीम का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए सभी घरों में बिजली पहुंचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर विद्युतीकृत घरों में बिजली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
- घरों में बिजली कनेक्शन देने के कार्य में संबंधित घर से निकटतम विद्युत खंबे से सर्विस केबल घर तक लाना, बिजली मीटर लगाना, एलईडी बल्ब और एक मोबाईल चार्जिंग प्वाइंट के साथ एकल विद्युत प्वाइंट के लिए तार डालना शामिल है।
- यदि सर्विस केबल लाने के लिए संबंधित घर के निकट विद्युत खंबा उपलब्ध नहीं है तो कंडक्टर एवं संबंधित उपकरणों के साथ अतिरिक्त खंबा लगाया जाना भी इस योजना में शामिल है।
- इस योजना के तहत केवल 50 रुपये के भुगतान पर अन्य घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- हालांकि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भी आरंभ की गई है। परंतु ऐसे कई गांव हैं जहां काफी पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है लेकिन कई कारणों से अनेक घरों में बिजली कनेक्शन अब तक सुलभ नहीं हो पाए हैं।
- कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, लेकिन ये परिवार आरंभिक कनेक्शन चार्ज अदा करने में समर्थ नहीं हैं।

- अनपढ़ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि विद्युत कनेक्शन कैसे लिया जाता है? दूसरे शब्दों में, अनपढ़ लोगों के लिए बिजली कनेक्शन लेने के मार्ग में बाधाएं आती हैं। विद्युत कनेक्शन लेने के लिए संबंधित घरों से अतिरिक्त खर्चे एवं कंडक्टर लगाने का प्रभार लिया जाता है।
- इन सभी कमियों को दूर करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी गैर विद्युतीकृत परिवारों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराने से संबंधित प्रवेश बाधा दूर करने और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मुहैया कराने के मुद्दे को सुलझाने के लिए ही 'सौभाग्य' का शुभारंभ किया गया है।
- देश में लगभग 4 करोड़ गैर विद्युतीकृत घर होने का अनुमान लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ बीपीएल ग्रामीण परिवारों को DDUGJY की मंजूर परियोजनाओं के तहत पहले भी कवर किया जा चुका है।
- अतः कुल 300 लाख घरों को इस योजना के तहत कवर किए जाने की आशा है जिनमें से 250 लाख घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 50 लाख घर शहरी क्षेत्रों में हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

- इस स्कीम को केंद्र सरकार ने 20 नवंबर, 2014 को मंजूरी दी थी।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, सुलभ बनाने के लिए फीडर और गैर-फीडर सुविधाओं को अलग किया गया है।
- इस स्कीम में वितरण एवं उप-पारेषण प्रणाली को भी मजबूत करने पर बल दिया गया है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के तहत गांवों/घरों में बुनियादी विद्युत ढांचे का सृजन, मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत एवं विस्तार करना, मौजूदा फीडरों/वितरण ट्रांसफॉर्मरों/उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाना शामिल है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बेहतर की जा सके।
- इसके अलावा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के साथ-साथ केवल उन बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराए जाते हैं, जिसकी पहचान राज्यों द्वारा अपनी सूची के मुताबिक की जाती है।
- ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1000 दिनों में अर्थात् 1 मई, 2018 तक देश के शेष बचे 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का निर्णय

लिया था। यह लक्ष्य इसी स्कीम के तहत पूरा किया जाना था।

- 28 अप्रैल, 2018 को मणिपुर का लीसांग अंतिम ग्राम था जहां विद्युत पहुंचा दी गई। अर्थात् देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY)

- यह योजना (UDAY), जो बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय और परिचालन को घाटे से उबार कर लाभ में लाने के लिए एक योजना है, सरकार द्वारा 20 नवंबर, 2015 को आरंभ की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपये के लंबे समय से कर्ज और भविष्य में संभावित नुकसान का स्थायी समाधान करना है। इस योजना में सभी क्षेत्रों; उत्पादन, प्रेषण, वितरण, कोयला और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने हेतु उपायों की परिकल्पना भी की गई है। योजना की वैधता अवधि 31-03-2017 को समाप्त हो गई।
- UDAY के अंतर्गत प्रतिभागी राज्यों के कार्य-प्रदर्शन की गहन निगरानी सुनिश्चित करने हेतु UDAY के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यप्रणाली स्थापित की गई है।
- अब तक UDAY में 27 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हो चुके हैं।

एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (IPDS)

- इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीय 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है।
- निगरानी समिति ने दिसंबर 2017 तक 3,616 शहरों के लिए कुल 26,910 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी।
- राज्यों से संबंधित संस्थाओं को 23,448 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य दिया गया है।
- इस योजना में आईटी और तकनीकी सहायता के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 24x7 बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा, लेकिन बिलिंग और संग्रहण दक्षता में भी सुधार करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में भी कमी आएगी।
- दिसंबर 2017 तक R-APDRP के तहत 1363 शहरों को 'गो-लाइव' घोषित किया गया है, 52 शहरों में स्काडा नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की गई है।

- 20 स्काडा शहरों में कार्य पूरा कर लिया गया है और इस योजना के भाग-1 के तहत 21 डेटा केंद्रों में से 20 अधिकृत हो चुके हैं।
- भारत में 45/57 डिस्कॉम (निजी सहित) में उपभोक्तों के लिए ऑल इंडिया शॉर्ट कोड '1912' की शुरुआत हो चुकी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने 10 मार्च, 2016 को मंजूरी दी थी। 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया।
- इस स्कीम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
- स्कीम का लक्ष्य वर्ष 2019 तक पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन देना था। परंतु फरवरी 2018 में 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का संशोधित लक्ष्य वर्ष 2020 तक प्राप्त कर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के आखिर तक 3 करोड़ कनेक्शन जारी करने का मूल लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जनवरी 2018 तक 3.35 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए कर दिए गए।
- इस स्कीम के तहत प्रति बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन लिए 1600 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है। हालांकि इस पहल का नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है।
- यह शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित पहल है।
- यह अभियान आरंभ में देश के उन 100 जिलों में आरंभ किया गया था। जहां बाल लिंगानुपात सबसे कम था। नवंबर 2017 में यह अभियान देश के सभी 640 जिलों में आरंभ कर दिया गया।

- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल लिंगानुपात में बढ़ोतरी है।
- अभियान के आरंभ के समय जिन 100 जिलों का चयन किया था। उनमें 87 जिले ऐसे थे जहां बाल लिंगानुपात 918 (2011 की जनगणना) थी।
- वैसे इस अभियान का लक्ष्य कम बाल लिंगानुपात वाले 161 चयनित जिलों में पूरे देश में व्यापक अभियान तथा केंद्रीयकृत हस्तक्षेप और बहुक्षेत्रक कारवाई के माध्यम से बाल लिंगानुपात (CSR) में कमी के मुद्दे का समाधान करना है।
- इस स्कीम के विशेष लक्ष्य हैं; 1. लैंगिक पक्षपाती चयन को समाप्त करना 2. बालिका के जीवन को सुनिश्चित करना, 3. बालिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा 4. बालिका की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना।

वन स्टॉप सेंटर

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह योजना 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है।
- वन स्टॉप सेंटर मुख्यतः परिवार, समाज, कार्य स्थल सहित निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।
- इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी सहायता सेवाओं सहित समेकित सेवा सीमा की सुलभता उपलब्ध कराना है।

स्वाधार गृह

- स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए समाधान निकालना है, जिन्हें पुनर्वास के लिए सांस्थानिक सहायता की जरूरत है ताकि वे अपने जीवन को गरिमा पूर्ण ढंग से जी सकें।
- इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य की संकल्पना की गई है तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

- पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कर दिया गया और पुनः 16 जून, 2017 को इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया।
- 31 दिसंबर, 2016 को इस योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में कर दिया गया।

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।
- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित सशर्त नकद अंतरण स्कीम है, जो अक्तूबर, 2010 में प्रायोगिक आधार पर 53 चुनिंदा जिलों में ICDS के प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू की गई।
- इस स्कीम में 19 वर्ष और इससे अधिक आयु गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम जीवित शिशु के लिए 6,000/ रुपए का भुगतान स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर दो किस्तों में किया जाता है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ उपलब्ध है।
- इसमें वे महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो केन्द्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी हैं।
- इनके अलावा इस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत इसी प्रकार का लाभ पाने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के उद्देश्य हैं: (1) गर्भवती महिला के वेतन में कटौती के लिए नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना है, ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में पर्याप्त आराम कर सके; (2) नगद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन

- इस योजना का अनुमोदन 11वीं योजना (2010-11) के अंतिम वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषण सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के रूप में किया गया था।
- महिला सशक्तीकरण मिशन योजना का अनुमोदन महिलाओं के लिए केन्द्र तथा राज्य/संघशासित प्रदेश, दोनों स्तर पर कार्यक्रमों, नीतियों तथा स्कीमों के अन्तरक्षेत्रीय अभिसरण को सुदृढ़ करने हेतु तक शासनादेश द्वारा किया गया था। बाद में इस योजना का महिला शक्ति केंद्र में विलय कर दिया गया।
- भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित करने के लिए महिला शक्ति केंद्र (तत्कालीन राष्ट्रीय महिला

सशक्तीकरण मिशन योजना का विलय करके) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी।

- इस योजना के हिस्सा के रूप में 115 सबसे पिछड़े जिलों में कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदायों की भागीदारी की संकल्पना की गई है।

प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम

- ➔ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1986-87 से यह स्कीम संचालित किया जा रहा है।
- केंद्रीय क्षेत्र की इस स्कीम के तहत महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
- स्टेप स्कीम का उद्देश्य ऐसे कौशल प्रदान करना है जो महिलाओं को नियोजनीयता देते हैं और ऐसी क्षमता और कौशल प्रदान करना है जो महिलाओं को स्व-नियोजित/उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है।
- स्कीम देश में ऐसी महिलाओं को, जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, लाभान्वित करने के लिए अभिप्रेक्षित है।

समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) स्कीम

- समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) स्कीम भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा विकास के लिए चलाए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक है। यह स्कीम वर्ष 1975 में आरंभ हुई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्कीम है।
- यह स्कीम देश के बच्चों एवं धात्री माताओं के लिए एक ओर स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की चुनौती की जवाबी कार्रवाई है तथा वहीं दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता दर, कम अधिगम क्षमता व मृत्यु-दर के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमुख प्रतीक है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी 0-6 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती व धात्री माताएं हैं।

स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. 0-6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की पोषणहारीय स्थिति एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना;
2. बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की आधारशिला रखना;
3. मृत्यु-दर, रुग्णता दर, कुपोषण तथा बीच में पड़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना;
4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लेने विभिन्न योजनाओं

के बीच नीतियों तथा कार्यान्वयन में प्रभावी समन्वयन स्थापित करना;

5. समुचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य तथा पोषाहारीय जरूरतों की देखभाल करने के लिए माताओं की क्षमता का विकास करना।

पढ़े भारत बड़े भारत

- ☛ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यह स्कीम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे ट्विन ट्रैक एप्रोच पर योजनाबद्ध किया गया है; (1) समझ के साथ पढ़ने और लिखने की रुचि अपनाते हुए भाषायी विकास में सुधार करना; और (2) वास्तविक और सामाजिक जगत से संबंधित गणित में स्वाभाविक और सकारात्मक रुचि उत्पन्न करना।
 - इस कार्यक्रम के उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र पाठक और लेखक बनने में समर्थ बनाना;
 - पर्याप्त और दीर्घकालिक पठन और लेखन कौशल और अध्ययन में कक्षा का उपयुक्त अधिगम स्तर प्राप्त करना;
 - संख्या, माप और आकारों के क्षेत्र में तर्कशीलता को समझाना;
 - अंक ज्ञान और स्थानिक कौशल से समस्या हल करने में स्वतंत्र होना और पढ़ने-लिखने के शुरूआती स्तर पर गणित के साथ आनंद अनुभव और वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ना है।

वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल 'ज्ञान'

- ☛ वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) उच्चतर शिक्षा का एक कार्यक्रम है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर, 2015 को प्रारंभ किया गया।
 - इसमें शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के साथ दुनियाभर के उत्कृष्ट शैक्षिक और उद्योग से संबंधित विशेषज्ञों सहित विद्यार्थियों और संकाय के साथ परस्पर संपर्क हो सकेगा।
 - इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय संकाय भारतीय संस्थान में 1 से 2 हफ्ते का पाठ्यक्रम आयोजित करता है।
 - राष्ट्रीय महत्व के सभी विश्वविद्यालय और संस्थान राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) नामक उच्च गति के आंकड़े एकत्रित करने वाले नेटवर्क द्वारा जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित है। इस परियोजना को मंजूरी मार्च 2010 में दी गई थी।
 - NKN ज्ञान को साझा करने, इंटरनेट सुविधा के प्रावधान और सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है।

- अब तक देश के 1664 संस्थान इस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं।
- देश में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय लगभग 350 करोड़ की लागत के wi-fi नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं।
- इसके तहत सभी कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों और विद्यार्थियों द्वारा प्रायः प्रयोग किए जाने वाले स्थानों को वाईफाई हॉट स्पॉट से जोड़ा जाएगा। जिसमें 24x7 आधार पर विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक और सूचना हेतु पहुंच प्रदान की जाएगी।
- यह परियोजना NIMCET परियोजना में कार्यान्वित की जाएगी।

एकीकृत शिक्षा योजना

- केंद्र सरकार ने 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना (Integrated Scheme on School Education) बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी 28 मार्च, 2018 को प्रदान की गई।
- प्रस्तावित योजना में, सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। प्रस्तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। यह राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20% अधिक है।
- इसका लक्ष्य पूरे देश में ग्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना

- ☛ यूजीसी ने 2014-15 के शैक्षिक सत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र, के विद्यार्थियों के लिए इशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है।
- ☛ इस योजना में उन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 10 हजार छात्रवृत्तियों की परिकल्पना की गई है जिनके माता-पिता की आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रुपये से कम है और मेडिकल और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी

और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 5400 से 7800 रुपये प्रतिमाह के बीच छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

इशान विकास

- इशान विकास पूर्वोत्तर राज्यों के चुनिंदा स्कूली छात्रों को उनकी अवकाश की अवधि में IIT, IISER और NIAS के गहन सम्पर्क में लाने की व्यापक योजना है ताकि, उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी व गणित के अध्ययन तथा पूर्वोत्तर राज्यों के इंजीनियरी छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थानों में इन्टर्नशिप के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा सके।

विद्या लक्ष्मी पोर्टल

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल को 15 अगस्त, 2015 से स्थापित किया गया है।
- इस पोर्टल को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) ई-अभिशासन अवसंरचना लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक सम्पर्क द्वारा ऐसी सुविधाएं जैसे शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति और अन्य विद्यार्थी सुविधाएं प्रदान करना है। यह पोर्टल शिक्षा ऋण के लिए बैंकों हेतु एक गेटवे है और यह राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल (NESP) को भी जोड़ता है।

सर्व शिक्षा अभियान

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो आरंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की भागीदारी के साथ वर्ष 2000-2001 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह आरम्भिक शिक्षा में पहुंच, प्रतिधारण तथा गुणवत्ता सुधार को सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी जिलों को कवर करता है।
- ज्ञातव्य है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21-क और इसका परिणामी विधान, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से देश भर में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6-14 आयु वर्ष के बच्चों को कुछ अनिवार्य मानकों और मानदंडों को पूरा करने के बाद औपचारिक स्कूल में अवसर की समानता के आधार पर, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्यों में शिक्षा का अधिकार नियमों को अधिसूचित किया है।
- सर्व शिक्षा अभियान की केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित करने के प्रयास में सहायता प्रदान करती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

- यह योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदायों तथा गरीबीरेखा से नीचे की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है।
- इसे अगस्त 2004 में आरंभ किया गया था। KGBV, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल काफी दूरी पर होते हैं तथा लड़कियों की एक सुरक्षा चुनौती होती है।
- KGBV उन किशोरियों, जो नियमित स्कूल जाने में समर्थ नहीं हैं, 10+ आयु समूह की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं तक, जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं और छिंदी बस्तियों के जटिल क्षेत्रों की विस्थापित जनसमुदायों की युवा बालिकाओं, जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए सफल नहीं हो पाई, तक पहुंचता है।

महिला समाख्या योजना

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यह योजना 1986 की नई शिक्षा नीति के आलोक में वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी।
- माता-पिता और समुदाय को कम उम्र में शादी और किशोरावस्था में गर्भधारण करने के मामलों को और अधिक संवेदनशील तरीके से समझने और उस पर कार्य करने के लिए सुग्राही बनाया गया है।
- पंचायत निकायों में प्रशिक्षित संघ और संघ महिला नेताओं और समुदाय कैडर के माध्यम से बाल विवाह रोकना सुनिश्चित करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

- बच्चों के नामांकन, अवधारण और उपस्थिति में वृद्धि के साथ-साथ उनकी पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 15 अगस्त, 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना “प्राथमिक शिक्षा के लिए पौषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE)” शुरू की गई थी।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए 2008-09 के दौरान योजना का विस्तार किया गया था और योजना का नाम बदल कर “राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम” के रूप में किया गया था।
- सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत

सहायता प्राप्त मदरसों और मक़तबों में कक्षा-८ से टप्प में अध्ययनरत सभी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल किया गया है।

- प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन में 100 ग्राम अनाज (चावल/गेहूँ/पोषक अनाज), 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जी तथा 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए, 5 ग्राम तेल/वसा की मात्रा शामिल होते हैं।
- उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन में 150 ग्राम अनाज (चावल/गेहूँ/पोषक अनाज), 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी तथा 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए, 7.5 ग्राम तेल/वसा की मात्रा शामिल होते हैं।

साक्षर भारत कार्यक्रम

- यह कार्यक्रम वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था और इस कार्यक्रम का प्रधान लक्ष्य 70 मिलियन वयस्क निरक्षर महिलाओं को बुनियादी साक्षर करना है।
- यह अभियान पढ़ने-लिखने से परे जाकर सामाजिक असमानता व व्यक्ति के अपवंचन के प्रति जागरूकता भी फैलाता है।
- इस कार्यक्रम में वैसे जिलों को शामिल किया जाता है जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50% या उससे कम है।

राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना

- देश की विपुल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनरुत्थान के लिए 21 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना 'हृदय' (National Heritage Development and Augmentation Yojana: HRIDAY) का उद्घाटन किया।
- इस स्कीम का उद्देश्य विरासत शहरों का समेकित, समावेशी और सतत विकास करना है और इसके तहत केवल स्मारकों के रख रखाव पर ही नहीं जोर दिया जाएगा, बल्कि वहाँ के नागरिकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायों समेत पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा दिय जाएगा।
- इस केंद्रीय योजना के पहले चरण में चुनिंदा 12 शहरों को 500 करोड़ रुपए दिये जा रहे हैं।
- इस योजना का सारा व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। जिन 12 शहरों का चयन किया गया है, वे हैं; अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेल्लांकन्नी व वारंगल।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

- इस मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को किया था।
- इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2019 तक शत प्रतिशत स्वच्छता व खुले में शौच से शतप्रतिशत मुक्ति है। वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनायी जानी है इसलिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करता है।
- इस मिशन के दो घटक हैं; स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)।
- फरवरी 2018 तक देश के 11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुके हैं। ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं; सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, दमन व दीव, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मेघालय।
- केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार इस अभियान के तहत देशभर में मई 2018 तक 7.50 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में देश में सभी 4,041 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वयन के दो प्राथमिक घटक-100 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त (ODF) की स्थिति प्राप्त करना और ठोस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक संसाधित करने की व्यवस्था है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

- अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation: AMRUT) 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था।
- मिशन में 500 शहरों को शामिल किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाली सभी यूएलबी, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी अन्य राजधानी शहर, सभी हृदय शहर, मुख्य नदियों के किनारे बसे चयनित शहर, पहाड़ी राज्य, द्वीप और पर्यटन स्थल इसमें शामिल हैं। देश में लगभग 60 प्रतिशत शहरी आबादी को अमृत के अंतर्गत कवर किया गया है।
- यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें 50,000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सहित 1 लाख करोड़ रुपये का कुल परिव्यय शामिल है, जो कि वित्त वर्ष 2015-2016 से वित्त वर्ष 2019-2020 तक 5 वर्ष के लिए है।
- 50,000 करोड़ रुपये के शेष हिस्से का अंशदान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है।

- मिशन के जोर क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क, मोटर रहित शहरी परिवहन और क्षमता निर्माण करना है। मिशन में मिशन शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके निम्न प्रत्याशित परिणाम होंगे:

1. मिशन शहरों में हर घर के लिए पीने योग्य पानी तक पहुंच के लिए सार्वभौमिक कवरेज;
2. सीवरेज की कवरेज और शोधन क्षमता में पर्याप्त सुधार;
3. शहर के पार्कों को विकसित करना;
4. सुधार कार्यान्वयन; और
5. क्षमता निर्माण।

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)

- इस मिशन की शुरुआत 25 जून, 2015 को हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य अवसंरचना मुद्दे काटते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट' समाधान लागू करते हैं।
- किसी स्मार्ट सिटी के कुछ प्रमुख अवसंरचना तत्वों में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, विशेषतः गरीबों के लिए किफायती आवास, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, सुशासन, विशेषतः ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, नागरिकों विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है।
- स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यनीतिक घटक शहर सुधार (रेट्रोफिटिंग), शहर नवीकरण (पुनर्विकास) और शहर विस्तार (ग्रीन फील्ड विकास) तथा पैन-सिटी पहल प्रयास हैं।
- जिसमें शहर के अधिकांश भागों पर स्मार्ट समाधान लागू किया जाएगा।
- यह मिशन 100 शहरों को कवर करेगा और इसकी अवधि पांच वर्ष (वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक) है।
- स्मार्ट सिटी मिशन एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम (CSS) के रूप में संचालित किया जा रहा है और केंद्र सरकार का मिशन के लिए 5 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अर्थात् औसतन 100 करोड़ रुपये प्रति सिटी प्रति वर्ष वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

- शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, जिसे 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है।
- इस मिशन के अंतर्गत शामिल आवासों के लिए सभी वैधानिक कस्बें हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैधानिक कस्बों के संबंध में यथा अधिसूचित आयोजन क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर) तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा यथा अधिसूचित आयोजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर) को शामिल करने में छूट होगी।
- शहरी क्षेत्र सभी के लिए आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन के चार भाग हैं:
 - पात्र झुग्गी निवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके निजी विकासकों की भागीदारी के साथ स्व-स्थाने पुनर्विकास (ISSI);
 - ऋण आधारित सभी स्कीम के माध्यम से किफायती आवास (CLSS को अब EWS/LIG के लिए CLSS नाम दे दिया गया है);
 - (सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी) AHP में किफायती आवास;
 - लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/वृद्धि के लिए सब्सिडी;
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आवास का आकार कालीन क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर है लेकिन राज्यों को मंत्रालय के परामर्श से आवासों के आकार को बढ़ाने के लिए छूट है।
- EWS परिवार को ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये और LIG परिवार जिसकी वार्षिक आय 3-6 लाख रुपये के बीच है।

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान

- केंद्र सरकार ने विद्युत वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) के लिए एक मिशन प्लान अर्थात् नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (NEMMP 2020) (National Electric Mobility Mission Plan) वर्ष 2013 में तैयार किया गया।
- नई NEMMP 2020 में विभिन्न कदमों के जरिये विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों के निर्माण तथा उपयोग में सुविधा के लिए एक रोडमैप (खाका) का उल्लेख किया गया है, ताकि बैटरी प्रौद्योगिकी सहित अन्य तकनीकों में

अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता दी जा सके, इन वाहनों की मांग सृजित की जा सके और वर्ष 2020 तक इन वाहनों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके।

- NEMMP के तहत सरकार ने वर्ष 2020 तक 6-7 मिलियन हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों की बिक्री करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- इस मिशन के तहत भारी उद्योग विभाग ने 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वयन के लिए फेम इंडिया स्कीम (भारत में हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों को त्वरित ढंग से अपनाना एवं विनिर्माण -Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid & Electric Vehicles in India) को अधिसूचित किया है।
- यह योजना वर्ष 2020 तक के 6 वर्षों की अवधि के दौरान क्रियान्वित की जानी है, जिसके तहत हाइब्रिड/विद्युत वाहन बाजार के विकास के साथ-साथ इसकी विनिर्माण प्रणाली के लिए सहायता दी जाएगी, ताकि निर्धारित अवधि के आखिर तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।
- वर्तमान में इस योजना के प्रथम चरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो मूलतः 31 मार्च, 2017 तक के दो वर्षों की अवधि के लिए तय था, लेकिन इसकी अवधि 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई। यह योजना चार फोकस क्षेत्रों यथा तकनीकी विकास, पायलट परियोजना, बुनियादी ढांचे के निर्माण में नई गति लाने और मांग सृजन के जरिये क्रियान्वित की जा रही है।
- फेम इंडिया स्कीम के अनुसार तकनीकी विकास के तहत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है और वित्त पोषण के लिए स्वीकृत किया जाता है।
- बैटरी प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद के लिए वित्त पोषण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

- यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना तथा आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है।
- केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है।
- इस मिशन को 2011 में लॉन्च किया गया था।
- यह मिशन 29 राज्यों और 5 केन्द्रशासित प्रदेशों के 586

जिलों के अंतर्गत 4,459 प्रखंडों में लागू किया गया है।

- शहरी क्षेत्रों में दीनदयाल अंत्योदय-शहरी आजीविका मिशन का आयोजन आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

अटल पेंशन योजना (APY)

- अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 01 जून, 2015 को हुआ। इसका परिचालन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- यह 18-40 वर्ष के आयु समूह में भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
- इस योजना के तहत किसी भी सदस्य को 60 वर्ष की आयु से प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उसके अंशदान पर निर्भर करेगी।
- समान पेंशन संबंधित सदस्य की पत्नी/पति को मिलेगी और सदस्य एवं पत्नी/पति दोनों की ही मृत्यु हो जाने पर संचित पेंशन नामित व्यक्ति को दे दी जाएगी।
- वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक 97.05 लाख सदस्यों ने अटल पेंशन योजना (APY) के तहत नामांकन कराया है। 48.21 लाख सदस्यों की वृद्धिशील बढ़ोतरी विगत वित्त वर्ष 2016-17 में दर्ज 48.83 लाख सदस्यों के आंकड़े से 98% अधिक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में दो उप-मिशन शामिल हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और हाल ही में आरंभ किया गया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो कि 12 अप्रैल, 2005 को आरंभ हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर से कमजोर वर्गों को सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।
- NRHM के अधीन, अधिकार प्राप्त कार्य समूह (EAG) वाले राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM), जो कि वर्ष 2013 में आरंभ हुआ था, शहरी जनसंख्या विशेषकर शहरी गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों तक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा तक उनकी पहुंच बनाकर स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाएगा।
- इस मिशन के मुख्य कार्यक्रम घटक हैं; पुनर्जनन-मातृत्व-नवजात-बाल व किशोर स्वास्थ्य।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश भर में 9.15 लाख से अधिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी 'आशा'

(Accredited Social Health Activist- ASHA) को नियुक्त किया गया है जो सुविधा प्रदाता, मोबिलाइजर तथा सामुदायिक स्तर परिचर्या प्रदाता का कार्य करते हैं।

- वर्ष 2013 से जब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ हुआ था तो आशा कर्मियों को शहरी क्षेत्रों के लिए भी चयन किया गया था।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

- 1 जून, 2011 से आरंभ हुई जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्च के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक देता है।
- यह हकदारी में निःशुल्क औषध और उपभोग्य, निःशुल्क नैदानिक जांच, स्वास्थ्य संस्थानों में रहने के दौरान निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रूप से रक्त उपलब्ध करवाना, घर से स्वास्थ्य संस्थान तक रेफर के मामलों में एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक और वापस घर छोड़ने के लिए निःशुल्क परिवहन, तथा सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं शुल्क से छूट शामिल है।
- जननी सुरक्षा योजना (JSY) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सुरक्षित मातृत्व क्रियाकलाप है और इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के द्वारा मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना 12 अप्रैल, 2005 को आरंभ हुई।
- JSY को निम्न निष्पादन वाले राज्यों (LPS) पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों (UT) में कार्यान्वित किया जा रहा है। JSY एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो प्रसव एवं प्रसवोत्तर परिचर्या को नकद सहायता के साथ एकीकृत करती है।
- इस योजना में प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य सेवाकर्मी (आशा) की सरकार एवं गर्भवती महिलाओं के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में पहचान की गई है।
- यह योजना गरीब गर्भवती महिलाओं पर केन्द्रित है, जिसमें संस्थागत प्रसव दर कम होने वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम (UIP)

- व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme-UIP) बच्चों के जीवन को जोखिम में डालने वाली स्थितियों से सुरक्षा करने के

लिए एक मुख्य क्रियाकलाप है जो अनिवार्य है।

- रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को विस्तारित रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1978 में शुरू किया गया। इसे व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में 1985 में गति मिली और वर्ष 1989-90 तक पूरे देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया गया।
- UIP वर्ष 1992 में शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का एक भाग हो गया। 1997 से, रोग प्रतिरक्षण 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) के अंतर्गत एक मुख्य क्षेत्र है तथा अब यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संरक्षणाधीन है।
- व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार 11 वैक्सीन अनिवार्य रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण प्रदान कर रही है जो अप्रलिखित है: डिप्थीरिया, कुकुरखांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, बाल्यावस्था क्षयरोग, हेपेटाइटिस-बी, हिब संक्रमण, रोटावायरस, रूबेला, जापानी इन्सेफलाइटिस। मई 2017 में इसमें न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सिन (PCV) को भी शामिल करने की घोषणा की गई।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

- वहनीय/विश्वसनीय तृतीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को सही करने तथा देश में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं के संवर्द्धन करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है।
- इस स्कीम में प्रथम चरण में एम्स जैसे 6 संस्थानों की स्थापना भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पन्ना, रायपुर और ऋषिकेश में प्रत्येक में एक, दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना और PMSSY के प्रथम चरण में 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों, दूसरे चरण में 6 संस्थानों और तीसरे चरण में 39 संस्थानों के उन्नयन की संकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम

- भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था।
- वर्ष 1952 की अपनी ऐतिहासिक शुरुआत के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम ने नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुसार परिवर्तन किया है। इसमें नैदानिक दृष्टिकोण से प्रजनन बाल स्वास्थ्य

दृष्टिकोण में क्रमिक बदलाव हुआ है और इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) 2000 ने समग्र व लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण निर्धारित किया जिससे प्रजनन क्षमता को कम करने में सहयोग मिला है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) केंद्र प्रायोजित योजना है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय (MOLE) द्वारा अप्रैल 2008 में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (BPL) को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए कवर किया गया था।
- प्रारंभ में यह बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की गई थी लेकिन बाद में इसमें 11 अन्य वर्गों अर्थात् असंगठित कामगारों (UOW) (मनरेगा कामगार, निर्माण कामगार, घरेलू नौकर, स्वच्छताकर्मी, खान कामगार, लाइसेंसधारी रेल कुली, फेरीवाले, बीड़ी कामगार, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले और ऑटो/टेक्सी चालक) को इस में शामिल किया गया।
- अब ये योजना 'जहां है जैसी है' के आधार पर 01.04.2015 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित की जा चुकी है।
- इस योजना के अधीन पंजीकृत परिवार सरकारी पैनलबद्ध (प्राइवेट और सरकारी-दोनों शामिल) अस्पताल में परिवार फ्लोटर आधार पर (पांच की यूनिट) प्रसूति लाभ सहित अस्पताल में भर्ती होने संबंधी 30000/-रुपए के वार्षिक लाभ के हकदार है।
- इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और पहले दिन से पूर्व स्थिति के आधार पर ही कवर किया जाता है। इस योजना के तहत 100/-रुपए तक की ट्रांसपोर्टेशन लागत देने की भी व्यवस्था है।

मिशन इंद्रधनुष

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीकाकरण से संबंधित योजना है। इसका प्रथम चरण 7 अप्रैल, 2015 को आरंभ हुआ था।
- देश में 89 लाख से अधिक उन बच्चों, जिन्हें या तो टीके नहीं लगाए गए हैं या आंशिक रूप से लगाए गए हैं; जिन्हें विभिन्न कारणों से नियमित टीकाकरण के चरणों के दौरान शामिल नहीं किया गया है, के संपूर्ण टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष के सात रंगों को चित्रित करते हुए "मिशन इंद्रधनुष" की शुरुआत की गई है।

- उन्हें टीके द्वारा रोकथाम किए जाने वाले सात जानलेवा रोगों, जिनमें डिप्थीरिया, कुकुरखांसी, टिटनस, पोलियो, क्षयरोग, खसरा और हेपेटाइटिस-बी शामिल है; से बचाव के लिए संपूर्ण टीकाकरण किया जाएगा।
- इसके अलावा, देश के चयनित जिलों/राज्यों में जापानी एन्सेफलाइटिस और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के टीके लगाए जा रहे हैं।
- प्रथम चरण का पहला खंड दिनांक 7 अप्रैल, 2015 विश्व स्वास्थ्य दिवस को 28 राज्यों में 201 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में जहां देश के लगभग 25 प्रतिशत बच्चे हैं; जिन्हें टीके बिल्कुल ही नहीं लगाए गए हैं यह आंशिक रूप से लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)

- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) का शुभारंभ 1 अप्रैल, 2017 को नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एवं मौजूदा उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान करना है।
- इस योजना को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) नामक एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा। यह एजेंसी सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निःशुल्क देखरेख करेगी।
- ये उपकरण वरिष्ठ नागरिकों को आयु संबंधी शारीरिक दिक्कतों से निपटने में करेंगे और परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर उनकी निर्भरता को कम करने हुए उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देंगे।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 10.38 करोड़ थी। वरिष्ठ नागरिकों की 70 फीसदी से भी अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वरिष्ठ नागरिकों का एक बड़ा प्रतिशत वृद्धावस्था में होने वाली अक्षमताओं से पीड़ित है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2026 तक उम्रदराज़ लोगों की आबादी बढ़कर करीब 173 मिलियन हो जाएगी।
- केन्द्र सरकार ने वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों से पीड़ित, गरीबी रेखा से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए ही योजना शुरू किया है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

- वर्ष 2009-10 में आरंभ इस योजना का उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक 50 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चुनींदा गांवों का विकास 'मॉडल गांवों' में करना है, ताकि वहां, अन्य सुविधाओं के साथ, निम्नलिखित सुविधाएं भी हों:
 - उनके पास अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित वास्तविक एवं सामाजिक अवसरचना हो।
 - सामान्य सामाजिक-आर्थिक इंडिकेटर्स (उदाहरणार्थ, निरक्षरता दर, प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता दर, IMR/MMR, उत्पादक परिसंपत्तियों का स्वामित्व आदि) के संदर्भ में अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति की संख्या के बीच असमानता समाप्त की गई हो और इन इंडिकेटर्स को कम-से कम राष्ट्रीय औसत पर लाया जाए और सभी BPL परिवारों, विशेषतः अनुसूचित जाति के परिवारों को खाद्य एवं जीवन-यापन संबंधी सुरक्षा मिले तथा वे गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें एवं पर्याप्त आजीविका कमा सकें।
 - अनुसूचित जातियों के प्रति अस्पृश्यता, भेदभाव, पृथक्कीकरण की भावना समाप्त हो और साथ ही अन्य सामाजिक बुराइयां, जैसे लड़कियों/महिलाओं के प्रति भेदभाव, मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग आदि भी समाप्त हों और समाज के सभी वर्ग एक-दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक, समानता एवं सौहार्दता के साथ रहें।

महिला समृद्धि योजना (MSY)

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने, वर्ष 2003-04 के दौरान, माइक्रो क्रेडिट वित्त योजना की तुलना से 1 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज छूट दर पर 25,000 रुपये प्रति इकाई तक ऋण प्रदान करने के लिए महिला लाभार्थियों के लिए एक अनन्य माइक्रो क्रेडिट योजना के रूप में महिला समृद्धि योजना (MSY) आरम्भ की।
- वर्ष 2006-07 के दौरान, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रति इकाई लागत सीमा को 30,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया जिसे पुनः 2012-13 में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है ताकि महिला लाभार्थी अपेक्षाकृत अधिक निवेश के साथ आय उपार्जक कार्यकलाप आरम्भ कर सकें।
- महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण लौटा देने के बाद लाभार्थी एक बार फिर से NSFDC योजना के तहत ऋण का लाभ ले सकते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- इस योजना की शुरुआत 2 जनवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से गई थी। वैसे (महात्मा गांधी) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था।
- इस अधिनियम का अधिदेश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में से ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूर रोजगार उपलब्ध कराना है।
- आरंभ में इसे देश के 200 जिलों में आरंभ किया गया था परंतु 1 अप्रैल, 2008 से इसे देश के संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया है।
- वर्तमान में यह उन जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश को कवर करता है जिनमें 100% शहरी जनसंख्या है। मनरेगा की बेहतर निगरानी के लिए 2016-17 में जियोमनरेगा आरंभ की गई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)

- गरीबी उन्मूलन की कार्यनीति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में शामिल 500 (जनगणना-2001 के अनुसार) और इससे अधिक की आबादी वाले सड़क से न जुड़ी बस्तियों को बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तराखंड), मरूभूमि वाले क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों तथा 88 चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के संबंध में इसका उद्देश्य कोर नेटवर्क के अनुसार सड़क से न जुड़ी 250 (जनगणना 2001) और इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG)

- वर्ष 2022 तक सभी को मूलभूत सुविधाओं सहित पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 2.95 करोड़ आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत में इससे पूर्व भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कई योजनाएं आरंभ की जा चुकी हैं। मसलन;

1957 में ग्राम आवास कार्यक्रम, 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा वर्ष 1985 में इंदिरा आवास योजना।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रु. और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना जिलों में 1.30 लाख रूपए इकाई की सहायता प्रदान की जाती है।
- इसके साथ लाभार्थी को स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय के निर्माण के लिए 1200 रु. की सहायता प्रदान की जाती है।
- लाभार्थी के घर के निर्माण हेतु 70,000 रु. तक का ऋण लेने की सुविधा दी जाती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- ☞ संविधान के अनुच्छेद 41 (नीति निर्देशक तत्व) के आलोक में भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को हुई थी।
- ☞ वर्ष 2007 में इस योजना को पुनर्गठित किया गया। वर्ष 2009 में इस योजना के दो और घटक (विधवा पेंशन व विकलांगता पेंशन) शामिल किए गए।
- ☞ इस कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- ☞ वर्तमान में इस कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक हैं;

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

- 60 से 79 वर्ष की आयु के BPL व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 रूपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रूपए की पेंशन दी जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:

- यह स्कीम वर्ष 2009 में शुरू की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों की 40 से 59 वर्ष की विधवाओं को प्रतिमाह 300 रूपए की सहायता दी जाती है।
- 60 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना:

- वर्ष 2009 में आरंभ इस स्कीम के तहत BPL परिवारों के 18 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिमाह 300 रूपए की सहायता राशि/पेंशन दी जाती है।
- 60 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:

- BPL परिवार में 18 से 59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक संतप्त बीपीएल परिवार को 20,000 रूपए की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

अन्नपूर्णा:

- 1 अप्रैल, 2000 को आरंभ इस योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थियों, जो पात्र हैं तो किंतु उन्हें पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया गया, को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम (DBT)

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल है जिसके तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जाता है। लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाता है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का उल्लेख पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट में किया था। उस समय केरोसीन, एलपीजी और उर्वरकों के लिए नकद सब्सिडी का सीधे भुगतान करने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक कार्यदल बनाया गया, जिसने फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
- इसी आधार पर 1 जनवरी, 2013 को देश के 43 जिलों में प्रत्यक्ष नकद भुगतान योजना आरंभ किया गया।
- बाद में योजना का नाम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कर दिया गया है। 12 दिसंबर, 2014 को देश के सभी जिलों में यह योजना लागू कर दिया गया।
- 14 सितंबर, 2015 से इस योजना को कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया है। दिसंबर 2017 तक इस स्कीम के तहत 56 मंत्रालयों/विभागों की 400 योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम

- देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- इस पहल के चार स्तंभ हैं; नई प्रक्रियाएं, नई अवसररचना, नए क्षेत्र और नई सोच।

- इसके तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- केंद्र सरकार के मुताबिक यह पहल केवल विनिर्माण सेक्टर को ही लक्षित नहीं करता वरन् भारत में उद्यमिता के संवर्द्धन का लक्ष्य लेकर भी चलता है।
- इस कार्यक्रम के तहत भारत में विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल सृजित करना, आधुनिक एवं कुशल आधार संरचना का निर्माण, विदेशी निवेश के लिए नए सेक्टर को खोलना तथा सकारात्मक मानसिकता के द्वारा सरकार एवं उद्योग के बीच साझेदारी का निर्माण करना है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। देश भर में विकसित मॉडल ग्राम पंचायतों का सृजन करने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया।
- इस योजना के तहत मार्च 2019 तक प्रत्येक सांसद को तीन आदर्श ग्रामों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- वहीं वर्ष 2024 तक प्रत्येक सांसदों को कम से कम पांच गांवों को गोद लेकर विकसित करना है।
- इन आदर्श ग्रामों से ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य, हरियाली और सौहार्दता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ये ग्राम स्थानीय विकास एवं शासन का विद्यालय बनकर पड़ोसी ग्राम पंचायतों को प्रेरित करेंगे।
- इस क्रम में संसद सदस्य एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। जिला कलेक्टर को इस योजना के कार्यन्वयन के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।
- इस योजना के तहत लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत का चयन करना होगा।
- वहीं राज्यसभा सदस्य को उस राज्य से ग्राम पंचायत का चयन करना होगा, जहां से वह निर्वाचित है। सदस्यों को अपना या अपनी पत्नी के ग्राम को गोद नहीं लेना होता है।

